

Sixth Series, No.13

Wednesday, March 7, 1979
Phalguna 16, 1900 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

Seventh Session
(Sixth Lok Sabha)



सत्यमेव जयते

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi

Price- Rs 4.00

CONTENTS

COLUMNS

No. 13 Wednesday, March 7, 1979/Phalguna 16, 1900 (Saka)

Oral Answers to Questions :

*Starred Questions Nos. 223, 225, 227 to 229, 232, 233 and 235.	1—30
---	------

Written Answers to Questions :

Starred Questions Nos. 222, 226, 230, 231, 234 and 236 to 241.	31—40
Unstarred Questions Nos. 2201 to 2239, 2242 to 2286, 2288 to 2336 and 2338 to 2400.	41—276
Re. Question of Privilege on Alleged Leakage of Budget Reports.	276—278
Papers Laid on the Table—	279—283
Committee on Public Undertakings— Minutes	284
Message from Rajya Sabha	284—285
Merchant Shipping (Second Amendment) Bill— as returned by Rajya Sabha with Amendments.	285—287
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance Reported decision of the Additional Session Judges and Magistrates in Delhi to march to Parliament House on the 16th March, 1979.	287—306
Shri Vijay Kumar Malhotra	290
Shri Shanti Bhushan	292
Shri Anant Ram Jaiswal	295
Shri Kishore Lal	296
Shri Sharad Yadav	301
Shri M. Ram Gopal Reddy	304
Petition re. Demands of Students.	307

Matters Under Rule 377—

(1) Reported low and unremunerative prices of Jaggery	307
Shri P. Rajagopal Naidu	307

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

(ii) Reported non-allocation of wheat and rice to Bihar for "Food for Work Scheme"	307
Shri L. L. Kapoor	308
(iii) Reported bus accident in Nepal on 27-2-79	308
Shri Raj Narain	308
Shri Samarendra Kundu	310
(iv) Management and control of power distribution in the country.	311
Prof. P.G. Mavalankar	311

Railway Budget, 1979-80 —General Discussion—

Shri L. L. Kapoor	313
Shri Ram Dhari Shastri	316
Shri D. B. Patil	320
Dr. Baldev Prakash	326
Shri Daya Ram Shakya	333
Shrimati Rashida Haque Choudhury	335
Shri D.G. Gawai	337
Shri Ramanand Tiwary	340
Shri Krishna Chandra Halder	343
Shri Anant Dave	349
Shri Bhausaheb Thorat	352
Shri Tej Pratap Singh	354
Shri A. V.P. Asaithambi	358
Shri Heera Bhai	363
Shri George Mathew	366
Shri Ambika Prasad Pandey	371

Business Advisory Committee—

Thirty-first Report.	374
------------------------------	-----

LOK SABHA

Wednesday, March 7, 1979/
Phalguna 18, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

* सीमेंट उद्योग में बिजली के तेल का उपयोग

* 233 श्री अश्वन सिंह ठाकुर :

श्री सुभाष आहुता :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग में कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सीमेंट के उत्पादन पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबन्धी साब बाबब) : (क) सीमेंट का उत्पादन करने वाले 9 एककों को जिन्हें तेल से चलने वाले अतिरिक्त उपकरण प्राप्त हो गए हैं, सीमेंट उत्पादन के लिए कोयले के कम संभरण के कारण कोयले की जगह अंशतः फरनेस धायात के प्रयोग की अनुमति दे दी गई है।

(ख) ये 9 एकक फरनेस धायात का प्रयोग करके अधिकतम प्रति मास 3,37,447 मी. टन का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

श्री अश्वन सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, भट्टी है तो भट्टी के तेल की कीमत बढ़ गई है, इस लिए सीमेंट उत्पादन के तेल से सीमेंट का उत्पादन होता में खर्चा बढ़ गया है और सीमेंट की कीमत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है तथा बाजार में सामान्य जनता इसे खरीदने से बंथित है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सीमेंट उत्पादन के लिये कोयले के प्रयोग के स्थान पर भट्टी तेल के प्रयोग से सीमेंट की उत्पादन लागत में क्या कोई वृद्धि होती है? यदि हां, तो कितनी?

उपभोक्ताओं को इस वृद्धि से बचाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

क्या भट्टी तेल के उपयोग से सीमेंट की क्वालिटी में भी कोई अन्तर आता है?

कोयले की तुलना में भट्टी तेल के उपयोग से कोयले की एक की उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

3426 L.S.—

श्री जगबन्धी प्रसाद बाबब : श्रीमान्, कोयले की कमी के कारण ही फर्नेस धायात का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। धायात पता होगा, पहले जब कोयले की आपूर्ति कई कारणों से नहीं हो रही थी और सीमेंट की आवश्यकता थी तो उस आवश्यकता को महसूस करते हुए फर्नेस धायात के उपयोग की अनुमति दी गई थी। फर्नेस धायात में जहाँ सीमेंट की उपलब्धि प्राप्त मिल कर 130 रुपये तक हो जाती है वहाँ फर्नेस धायात की 1170 पड़ती है लेकिन जहाँ कोयला एक टन लगता है वहाँ फर्नेस धायात उसका भाड़ा लगता है। फर्नेस धायात से कोयले के खर्च के मुकाबले में सीमेंट का जो दाम बढ़ता है वह दुगुना होता है लेकिन ध्यान दि होल ज्यादा नहीं बढ़ता है। ध्यान दि होल 18 रुपये 53 पैसे प्रति टन दाम बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसलिए यह ज्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन आवश्यकता को देखते हुए इसकी जरूरत थी।

जहाँ तक काम की एफिसिएंसी का सवाल है, कोयले से फर्नेस धायात का काम ज्यादा अच्छा होता है परन्तु सीमेंट की क्वालिटी में कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री अश्वन सिंह ठाकुर क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बाजार में सीमेंट की कीमत क्या है और कोयले की कमी के क्या कारण हैं?

श्री जगबन्धी प्रसाद बाबब : बाजार में सीमेंट की कीमत 20 रुपये प्रति बोरी है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह भी बताना चाहूँगा कि जो मकान परमिट पर बनाते हैं उनको कन्ट्रोल रेट पर सीमेंट मिलता है लेकिन जो गलत ढंग से मकान बनाते हैं और इस प्रकार से जो गलत ढंग से आवश्यकता बढ़ती है उसका बाजार भाव में नहीं बता सकता हूँ, हो सकता है उसका दाम बढ़ जाता हो।

कोयले की कमी की जहाँ तक बात है—नाबं इडिया में वर्षों, बाढ़ के कारण बहुत सी माइन्स में पानी बला गया था तथा बैंगनों की कमी थी लेकिन अब यह संकट दूर हो गया है और अब कोयले की सप्लाई 70 परसेंट तक पहुँच गई है। जहाँ पर 700 बैग की आवश्यकता थी वहाँ पर 500 बैग की आपूर्ति की जा रही है।

श्री अश्वन सिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सीमेंट इन्फ्रस्ट्रक्चर में कोल की जगह पर फर्नेस धायात प्रयुक्त किया जाता है—यह सुना है कि कोल की जगह लिमनाइट की भी प्रयुक्त

क्या जा सकता है। सुझाव के कण्ट्रिब्यूट 4, बड़ी मात्रा में लिग्नाइट मिला है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कोल की जगह लिग्नाइट यूज किया जाये ?

श्री जगन्मोहि प्रसाद यादव : यह तो विचार करने के बाद ही ही बतलाया जा सकता है कि लिग्नाइट यूज कर सकते हैं या नहीं।

श्री जगन्मोहि प्रसाद यादव : क्या आप इस तरह विचार करेंगे ?

श्री जगन्मोहि प्रसाद यादव : इस के बारे में तो विचार करने के बाद ही पता लग सकता है।

SHRI DWARIKADAS PATEL. May I know from the hon. Minister whether in our country, many industries are suffering due to want of supply or shortage of coal? When Members ask questions the Energy Minister says that there was sufficient amount of coal.

MR. SPEAKER: He will not be able to answer about coal.

SHRI DWARIKADAS PATEL: I am coming to industry. There was sufficient amount of coal with them. But they do not get sufficient wagons and when they ask the Railway Minister for the supply of wagons, they are told that the railways have got sufficient number of wagons but for the short supply of coal, they have cancelled many goods trains and, as a result, the industries are suffering.

I would also like to know from the hon. Minister categorically as to what is the real position regarding the coal supply and, further, whether the Energy Minister is correct or the Railway Minister is correct.

MR. SPEAKER: I am sorry he will not be able to answer any one of your questions.

SHRI DWARIKADAS PATEL: The policy of the Janata Government is to shirk its responsibility.

MR. SPEAKER: He will not be able to answer.

U.S.S.R. offer of Heavy Water

*225. **SHRI PIUS+ TIRKEY:**
DR. BIJOY MONDAL:

Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that USSR has recently offered to supply 200 tonnes of Heavy Water for Rajasthan Atomic Power Project;

(b) if so, the terms and conditions on which the offer has been made; and

(c) whether Government have rejected the offer and if so, the reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, (b) and (c) Do not arise.

SHRI PIUS TIRKEY. Will the hon. Prime Minister be pleased to state whether it is correct that the supply of heavy water for Rajasthan Atomic Power Project is not forthcoming because U.S.A. demands the right of supervision? What are the alternative sources from which India plans to obtain heavy water if U.S.A. persists in its demand for inspection?

SHRI MORARJI DESAI: As I said, there is no proposal now of getting it. But, there was, in 1976, an agreement with Russia where they had agreed to supply 200 tonnes of heavy water. There, the safeguard has been accepted. The safeguard is that anything produced out of this should not be used for nuclear weapons or for any explosive devices. The safeguard is only for that purpose. And that was accepted in 1976.

SHRI PIUS TIRKEY: My second question is: will the hon. Prime Minister be pleased to state whether there is any government plan to discuss the matter with Shri Kosygin in his forthcoming visit to India?

SHRI MORARJI DESAI: It is difficult for me to say just now what I will discuss with him.

MR. SPEAKER: Dr. Bijoy Mondal. He is not here. Mr. Jagannath Rao.

SHRI JAGANNATH RAO: May I know from him as to when the Talcher Heavy Water Plant will go on stream?

MR. SPEAKER: This does not arise from this question.

SHRI MORARJI DESAI: If notice is given, I shall certainly give a reply.

Services of National Industrial Development Corporation

*227 **SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the services being rendered by the National Industrial Development Corporation in other countries this year; and

(b) the money earned due to these services?

उद्योग मंत्रालय में राख्य मंत्री (श्री जगज्योती प्रसाद यादव): : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि. द्वारा वर्ष 1978-79 में विदेशियों (फारेन कांस्ट्रक्ट) के लिए किए गये नियत कार्यों (एसाइनमेन्ट्स) की एक सूची सभा-घटन पर रखी जाती है।

(ख) 1 अप्रैल, 1978 से 31 जनवरी, 1978 की अवधि में इन नियत कार्यों (एसाइनमेन्ट्स) से 49.60 लाख रु० होने की राशि अर्जित करने का अनुमान है।

सूची

1978-79 में विदेशियों के लिए किए गये नियत कार्यों (फोरिन एसाइनमेन्ट्स) की सूची

क्र० सं०	नियत कार्य
1.	जांजीबार में इन्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना के लिए कुल परामर्शदात्री सेवाएं।
2.	सऊदी अरब में एक राजमार्ग परियोजना के लिए पर्यवेक्षण सेवाएं।
3.	अरब मित्तों की औद्योगिकीकरण तथा लीनिटेशन, अलजीरिया के लिए कामियों का अनुमोदन (सीक्रेटरीट)।

क्र० सं० नियत कार्य

4. डोंडीया में तंजानिया के लिए न्यू कैपिटल लिडी प्रोजेक्ट हेतु अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के विकास में सहायता।
5. राष्ट्रमण्डल सचिवालय, लंदन के लिए राष्ट्रीय विकास निगम की 14 कम्पनियों की क्षमता उपयोगिता का अध्ययन संबंधी कम्पनियों की मसौदा रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।
6. राष्ट्रमण्डल सचिवालय, लंदन के लिए राष्ट्रीय विकास निगम की 21 कम्पनियों का उत्पाद अध्ययन (प्रपोजेडिंग) अध्ययन—वर्ष में 4 एकको के स्थापना स्तर पर निरीक्षण किए गए हैं।
7. भूटान का तकनीकी—आर्थिक सर्वेक्षण।
8. मिसुरेट-सिरते तथा पैन-थल जफरा जेज, सीबिया के लिए क्षेत्रीय विकास योजना की रिपोर्ट।
9. राष्ट्रमण्डल सचिवालय, लंदन के लिए तंजानिया स्थित सिगरेटों के कारखाने की क्षमता उपयोगिता का अध्ययन।
10. राष्ट्रमण्डल सचिवालय, लंदन के लिए फ्राऊन कार्क कम्पनी, तंजानिया की क्षमता उपयोगिता का अध्ययन।
11. जनरल नेशनल भारगेनाइजेसन फार इन्डस्ट्रियलइजेसन, सीबिया के लिए (इंजीनियर स्तर के) तकनीकी कामियों के चयन हेतु परामर्श।
12. विद्युत निगम, बैंगाली सीबिया के लिए तकनीकी (तकनीशियन के स्तर के) कामियों हेतु परामर्श।
13. तंजानिया इन्डस्ट्रियल स्टडीज एण्ड कंसल्टिंग भारगेनाइजेसन के लिए परामर्शदात्री क्षमता का विकास करने तथा कामियों का अनुमोदन करने में सहायता।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Sir, my question was put in English. His answer is in Hindi.

MR. SPEAKER: He is not familiar with the language. If he is familiar with the language, he would have answered in English.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I shall now ask the question.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Sir, he has not said what is the amount earned due to the services.

MR. SPEAKER: In the written statement it is there—Rs. 40 lakhs and odd. You must have been supplied with the written statement. You see there—Rs. 49 lakhs and odd.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: It is not in the statement, Sir.

MR. SPEAKER: It is there: "The earnings on account of these assignments during the period from 1st April 1978 to 31st January 1979 are estimated at Rs. 49.63 lakhs." Please see the answer.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: It is not told here, Sir.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैने (ब) में बताया है कि इन एसाइनमेंट्स से 49.60 लाख रुपये की राशि अर्जित करने का अनुमान है ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I would like to know whether the Government is going to take fresh assignments to do the service in other countries this year or next year.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अभी हम 13 प्राजेक्ट्स के रहे हैं । जहाँ तक देश में इसके काम को बढ़ाने का प्रश्न है, अभी तक हमारा काम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सीमित था । अब हम वेपर के बारे में मैसूर में और हिन्दुस्तान वेपर के साथ प्रयास कर रहे हैं, जिससे इसके अधिकतम काम मिल सकें ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: What is the basis for getting money? How the return for the services is fixed?

MR. SPEAKER: Depending on the nature of the service.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: What is the basis?

MR. SPEAKER: What is the basis for receiving remuneration? It depends upon the nature of the service.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जिस तरह का काम हो, उसी के अनुसार रीमुनेरेशन होता है ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, the National Development Corporation is really doing such a com-

mendable service that many of the countries have sought the consultancy of the Corporation. In this connection, may I know whether these services rendered are mainly from the developed countries or whether any developing countries have asked us for this consultancy service and if that is so, whether in our Embassies abroad a particular wing or cell is being opened to make certain enquiries as to whether we can be of use with regard to consultancy service in those countries.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह काम हम डेवेलपिंग कंट्रीज में कर रहे हैं—करीब 32 देशों में । माननीय सदस्य ने यह सलाह दी है कि अगर हमारी एम्बेसीज में इस बारे में कोई सेल रहे, तो इसका काम और ज्यादा देशों में फैल सकता है । हम इस पर विचार कर रहे ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: He has not given a complete reply to my question.

MR. SPEAKER: He said: "The suggestion is good and we will look into it."

श्री श्री बलवीर सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बाहर जो टेकनिकल नो-हाऊ भेजा जाता है, क्या उसके लिए प्रादमियों के सिलेक्शन के लिए कोई कमेटी मुकदर है, इसके लिए क्या मैपार मुचर है और क्या इसके लिए एक्चरटाइजमेंट किया जाता है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसके लिए कोई बना हुआ है । उस बोर्ड में इंजीनियरों और टेक्नालॉजी के जानने वाले विभिन्न प्रादमी हैं, जो विदेशों में ट्रेनिंग पाये हुए हैं । जिस काम के लिए आवश्यकता होती है, उसके अनुसार लोगों को बन कर भेजा जाता है ।

Minorities in J and K

*228. **DR. VASANT KUMAR PANDIT:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Arya Pratinidhi Sabha, Jammu and Kashmir has informed Government about the serious plight of the minorities in the State of Jammu and Kashmir; and

(b) if so, the steps taken or being taken by Government on this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) Government had received a copy of the Statement read by the President of the Sabha in a press conference in Bombay.

(b) The various aspects of the problem have been taken up with the Government of Jammu and Kashmir.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Recently, particularly during Sheikh Abdullah's regime, the plight of the minorities in Jammu & Kashmir is becoming more and more difficult and about 25,000 people are still rotting in camps and they have not been rehabilitated from the refugee camps. Double standards are being practised. Even the students are not being given jobs on merits and they are not being given seats in the schools and colleges. All sorts of discrimination is there. Ladakhi Buddhists have complained of forcible conversion and all these things have led to the formation of a non-political body called "Hindu Raksha Samiti", which consists of all the Minorities' social and religious organisations. They have been writing to the Government about the various difficulties that they are facing. What steps have been taken by the Government to investigate on their own the various charges that are being made in my question. I would like to know whether the Government has undertaken any survey to find out the real plight of the minorities in Jammu & Kashmir.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: As I have stated, we did not get the statement directly, but we did get the statement through the President's Office and we have forwarded it to the Minorities Commission for investigation and of course, the Minorities Commission is the proper authority to do it. We have also asked from the State Government the factual position and as and when we know about it, if as the hon. Member says,

they are facing difficulties, we will look into them.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: When did the Government ask the Government of Jammu & Kashmir and what specific things have been mentioned in it?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: As the hon. Member has said, the specific things are: Hindu refugees are rotting, Buddhists are being converted to Islam in Ladakh, desecration of Hindu religious places and attempt to harass Dharmarth Trust.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: What about cow slaughter?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I have told you, we have asked about all these things.

श्री किरंगी प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ तथा यह भी कहना चाहता हूँ कि आज कल अपने देश में तथा विदेशों में भी जैसे साक्ष्य प्रतीका हैं, जहाँ जो सत्ता में है, वह कमजोर और निर्बल को सत्ता है, सो इस प्रसंग में मैं यह जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी को जो पत्रक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिला है, उसमें कौन-कौन सी मूल बातें हैं जिन की धोर माइनोरिटीज कमिशन का ध्यान विशेष रूप से खींचा गया है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : पत्रक में जिन बातों का उल्लेख है, मैंने उस की सूचना सदन में दे दी है। उसमें यह कहा गया है कि जो हिन्दू रिपयूजिय हैं, उनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाता है और उन के साथ ठीक सलूक नहीं किया जाता है। उसमें यह भी कहा गया है कि बुद्धिस्ट लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। उस में कहा गया है कि हिन्दुओं के जो धार्मिक स्थान हैं, वे अपवित्र किये जाते हैं और उसमें यह भी कहा गया है कि जो धर्मांधे ट्रस्ट्स हैं, उन को हिरस किया जाता है। ये सारी बातें पत्रक में कही गई हैं।

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: In view of the fact that Jammu agitation has been going on, as the minorities are suffering great hardship and also in view of the answer given by the hon. Minister last year in reply to a question that the Minorities Commission will have jurisdiction over J. & K., minorities being a relative term, I would like to ask whether the hon. Home Minister, during his recent visit to Jammu, has made any inquiry in regard to this. I

would like to know whether efforts are being made to remove the difficulties of the minorities in Jammu & Kashmir immediately, since J.&K. is a sensitive state. Otherwise, a grave crisis will follow. Will the Minister assure this House that the minorities in Jammu and Kashmir will have full liberty, safeguards, and satisfaction in all walks of life?

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, गृह मंत्री जी कहाँ कब से घोर गृह सन्धी जी से राजा समिति के लोग मिलें भी थे, उन्होंने उनको इन्टरव्यू दिया था। जहाँ तक माइनोरिटीज कमिशन के जुरिस्टिक्शन का सवाल है, इसके विरोध के बारे में हम को कोई जानकारी नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने सभी राज्यों को एक पत्र दिया था जिसमें यह कहा गया था कि माइनोरिटीज कमिशन को सभी कस्टडीयरी और सेलिसिटीय प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके विरोध में कम्प्लेयर सरकार ने हम को कुछ नहीं कहा है।

Percentage of Increase in Crimes in Delhi

*229. SHRI RAMANAND TIWARY:†

Statement

There has been an increase in crime. The number of cases and the percentage of increase in crime are as given below. The number of cases

worked out during the years 1976, 1977 and 1978 is also given in brackets:

Crime Head	1976	1977	Percentage of increase in 1977 as compared to 1976	1978	Percentage of increase in 1978 as compared to the year 1977
Dacoity . . .	5 (5)	21 (12)	+320%	70 (43)	+233%
Murder . . .	120 (94)	184 (119)	+53.3%	182 (129)	+1.08%
Attempt to murder	113 (104)	208 (185)	+84%	270 (231)	+29.8%
Robbery . . .	142 (73)	354 (203)	+149.2%	667 (263)	+88.4%
Snatching . . .	122 (50)	277 (120)	+127%	378 (130)	+36.46%
Riots . . .	38 (35)	148 (117)	+289.4%	304 (233)	+105.4%
Burglary . . .	1589 (500)	2683 (534)	+88.8%	3418 (593)	+27.3%
Thefts . . .	13234 (1384)	21678 (2081)	+63.1%	25281 (1935)	+16.6%
Misc. IPC . . .	7693 (4927)	10302 (6118)	+33.9%	12838 (6630)	+24.6%
Total IPC . . .	23106 (7378)	35855 (2559)	+55.1%	43408 (10187)	+21%

CHAUDHURY BRAHM PRAKASH:

-Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is much increase in crimes in Delhi;

(b) the percentage of increase in various types of crimes in Delhi during the last three years (year-wise),

(c) the percentage of criminals detected during the last three years, (year-wise);

(d) the reasons for increase in crimes and fall in detection of criminals, and

(e) the measures taken or proposed to be taken to bring down the crimes and apprehend the criminals and thus infuse a spirit of security among the people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) to (e). A statement is laid on the Table of the House.

2. Apart from the data in regard to number of cases worked out under the major heads, the overall position in regard to all the offences worked out is as follows:—

1976	39%
1977	26%
1978	23.6%

It had been found that the registration of crime during the emergency was on a selective basis. When cases are registered on a selective basis the percentage of cases worked out is also likely to be higher.

3. The figures of reported crime during the second half of 1978 viz., 21050 as compared to 22358 in the first half of the year, would however, indicate that the crime situation is being brought under control. This is a trend which would require to be maintained.

4. The crime situation is reviewed regularly at different levels. Adequacy of measures to strengthen police arrangements to control preventable crimes is also reviewed in such meetings. Patrolling, establishment of pickets, special drives against bad characters and persons carrying long knives and such other weapons, stepping up of extermination proceedings, developing criminal intelligence units for which a special centralized squad have also set up. Setting up of a vigilance squad to check eve-teasing and pick-pocketing are some of the other steps taken in this direction.

5. The Government are not, however, happy with the percentage of detection, particularly, in crimes like dacoity, murder, attempt to murder, robbery, snatching, burglary and thefts. It has been impressed upon the Delhi Police that more vigorous efforts should be made and more effective methods should be devised to control the crime. If the honourable Members have something concrete to suggest in this regard to im-

prove the situation, this will be most welcome.

श्री रामानन्द तिवारी : दिल्ली में बाईं विंग अपराधों में वृद्धि हो रही है। संभव के बावजूद साहूकर निकलने में अपराधों को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अपराधकर्ता पर नियंत्रण करने के लिये, लोगों को धातक और तब से मुक्त करने के लिये और लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये सरकार कौन सी व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री वनिक माल मन्त्रालय : यह तो बयान से स्पष्ट है कि दिल्ली में अपराधकर्ता में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर उन के कारणों में हम जाएं तो हमें बहुत सारे कारण मिलेंगे। महोदय, एक कारण यह भी है कि एमरजेंसी के दौरान लोग बहुत घबराये, उस समय आजादी का महसूस नहीं था, इसलिए उस समय की स्थिति की धीरे-धीरे उस समय की स्थिति को मिला देने में कुछ प्रभुत्व जरूर आयेगा। इस के साथ-साथ और भी बहुत सी बातें हैं जैसे कि दिल्ली की आबादी में वृद्धि का होना और पुलिस स्टेशनों पर मामलों का अधिक रजिस्ट्रेशन होना। लेकिन मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूँ कि दिल्ली में अपराधकर्ता में वृद्धि हुई है।

श्री रामानन्द तिवारी : जब यह राज्य सभा की इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहाँ अपराधों में वृद्धि हुई है तो मैं बड़ी चिन्मयता से इन से यह जानना चाहता हूँ कि इन को रोकने के लिये या इनमें कम से कम करने के लिए हमने अब तक कौन सी व्यवस्था की है ? दिल्ली में पुलिस की नई व्यवस्था, पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बाबजूद आज यह स्थिति क्यों है ? मैं यह जानता हूँ कि जनसभा में वृद्धि हुई होगी लेकिन क्या जनसभा में वृद्धि के अनुपात में पुलिस फोर्स में वृद्धि की गयी है यदि नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी ? क्या सभा की जो यह भी मालूम है कि आज कल अपराधकर्ता आधुनिक टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं ? उन के पास रायफल, बमरलैस सैट्स होते हैं। वे लोग विमानों से घाते करते हैं। क्या आधुनिक टेक्नीक का इस्तेमाल करने वाले अपराधकर्तियों से मुकाबला करने के लिये दिल्ली की पुलिस फोर्स को आधुनिक हथियार या आधुनिक साज-सामान जैसे जैसे भी चाहिए उसे आधुनिक टेक्नीक से लैस बनाया गया है ? इन सारी स्थितियों से निबटने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार पुलिस का आधुनिकीकरण कर रही है ? दिल्ली में पुलिस कमिश्नर और यह राज्य सभा की रहते हुए दिल्ली की जनता इतनी घबराई हुई और शयनी हो, और दिल्ली में अपराधों की इस तरह से वृद्धि होती रहे, इस को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री वनिक मन्त्रालय : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर दिल्ली में पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिस से कि पुलिस की कार्यक्षमता बढ़े। इसके साथ ही दिल्ली में दो अतिरिक्त जिलों का गठन किया गया है। उस के साथ-साथ पुलिस पोस्ट्स की बढ़ावा

क्या है और जो और जो और जो एक एक की मदद की उन को दी जा रही है। इन की बात बतासिये उन की मदद के लिये की गई है। पुलिस में जो बुद्धि की गई है। इस के साथ-साथ एक एक्सपर्ट कमेटी की भी स्थापना की गई है जो तीन और पुलिस देतो पर साक्षाती के विचार कर के अपनी रिपोर्ट देगी। जहाँ तक मार्गनाइजेसन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जो कुछ स्टैप्स लिखे गये हैं। लेकिन यह सही है कि सब काम यकबैक नहीं होंगे। जो बीजें तीन साल से सम्बन्ध हैं उन को यकबैक नहीं किया जा सकता है। यकबैक मार्गनाइजेसन भी कर दें और संख्या बल भी बढ़ा दें, सभी काम यकबैक कर दें यह सम्भव नहीं है।

श्री विजय कुमार मसहोत्रा : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हालत बहुत खराब हो रही है। सैकड़ों घातमियाँ की फ़िराती के मोटिस भाते हैं और लोग पुलिस में जाना पसन्द नहीं करते हैं। घुपघाप रुपया वे देते हैं। एक घाघ घातमी पुलिस में बहुत मुश्किल से पहुँचता है। दिल्ली में तो हालत इस कदम खराब हो गई है कि लोग दिन बड़े प्लाँट डैकोयटीज करते हैं। स्पर प्राफ़ वी मोमेंट में अगर कोई फ़ाइल होता है तो वह चीज तो समझ में आती है कि इस को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन प्लाँट डैकोयटीज जो हो रही हैं उन की संख्या बड़ रही है। एक एक रात में दस-बस जाके डाले जाते हैं। मंत्री महोदय जिस तरह से धाँकड़े पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दो साल में सब चीज नहीं हो सकती है, बहुत ही कंप्यूट बात है और यह अपराधों को बढ़ाने वाला जवाब है। क्यों मंत्री महोदय इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई फिर संभव गीता का केस हो और उस के बाद वह मीटिंगें कर और फिर कोई कार्यवाई करें। इस तरह का कोई अपराध हो जाता है तो सारी मशीनरी हिल जाती है। जब हालत इतनी खराब है तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से कम्प्लैट स्टैप्स लिए गए हैं अपराधों को रोकने के लिये ? पुलिस कमिश्नर बनाने से काम नहीं चल सकता है।

श्री धनिक लाल मन्डल : जो बैठकें इस तरह की बीजों पर विचार करने के लिये की जाती हैं उन में माननीय सदस्य को बुलाया जाता है और उन की इस की जानकारी है कि क्या-क्या स्टैप्स संख्या बल बढ़ाने के लिये या मार्गनाइजेसन करने के लिये लिए गए हैं। उन के भी सुझाव भाते रहते हैं और उन पर भी विचार किया जाता है।

SHRI BEDABRATA BARUA: I am surprised at the self-satisfaction expressed by the hon. Minister. He has stated that, in the Emergency, selective registration was there. I can understand that. But the crime rates have gone up between 1977 and 1978. In 1977 it was a rise of 320 per cent and in 1978 it has gone up by another 233 per cent—in dacoities. This plea would not work at all because the crimes have gone up in every case

by a high percentage in 1977 and in 1978. The Minister has told us that he is spending more money, is employing more men and is also having more crimes. This is no solution at all. Will the hon. Minister own up the responsibility for this type of increase in crimes in spite of more employment of policemen, more expenditure on police and more modernisation?

श्री धनिक लाल मन्डल : मैं ने कारको का उत्तर देकर देते हुए इस बात की स्वीकार किया है कि काइम्स में वृद्धि हुई है। मैं ने इस को छिपाया नहीं है।

श्री कन्वर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत से कदम उठाए हैं और पिछले दो साल से घाप यहो जबाब दें रहे हैं। पुलिस कमिश्नर बनाने के बाद और ये कदम उठाने के बाद भी कोई इस का इम्पैक्ट नजर नहीं आता है। दिन प्रति दिन बिटी रियोरेशन हो रहा है। कोई सैस प्राफ़ सिक्योरिटी नहीं है। पुलिस स्टेशन हैब बिकम डेज प्राफ़ करवाना। हीनस फ़ाइलस खास तौर से कई गुना अधिक बढ़ गए हैं। दिन बड़े डैकोयटीज होती हैं वृद्ध होती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जितनी डैकोयटीज हुई हैं और हीनस फ़ाइलस हुए हैं उन में कितने लोग पकड़े गए हैं, डिटेक्शन कितने हुए हैं। घाप ने कुछ माला है। . . .

The Government are not however, happy with the percentage of detection, particularly, in crimes like dacoity and murder. So I want to know what is the percentage of detection and what specific steps you have taken.

PROF. P. G. MAVALANKAR: What punishment is given to the guilty?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Punish the Police officials who have failed to detect these heinous crimes... (Interruptions) Let the Home Minister reply. Don't take it casually. Every body complains about the deterioration of law and order.

PROF. P. G. MAVALANKAR: It is a very dangerous thing.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL): I am rather surprised that Mr. Kanwar Lal Gupta should say that this matter is being treated casually...

SHRI VASANT SATHE: That is the home truth, Mr. Home Minister.

SHRI H. M. PATEL: I do not know if he has put the question...

MR. SPEAKER: He has not put the question. You need not answer him.

SHRI VASANT SATHE: He does not like to be told the home truth.

SHRI H. M. PATEL: I can only assure Mr. Kanwar Lal Gupta that we take this matter very seriously. We realise...

SHRI DINEN BHATTACHARYA: What you have already done—that you say.

SHRI H. M. PATEL: We realise that the crime situation is on the increase and we must see to that adequate steps are taken, and they are being taken...

SHRI DINEN BHATTACHARYA: 'Adequate' is a vague term.

SHRI H. M. PATEL:...All right, steps are being taken to see that the crime situation is brought under control...

PROF. P. G. MAVALANKAR: How?

जी बसल साठे . सर्वे बढ़ता गया ज्यों-ज्यों वा
की ।

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I do not know. What is this...on this type of an important question?

SHRI H. M. PATEL: If the hon. Members are not treating this question as an important question, they might at least be good enough to listen. After all, you have asked me what steps are being taken. The steps that are being taken are that the situation is being continuously kept under review...

SHRI VASANT SATHE: Under watch.

SHRI H. M. PATEL: Yes, under watch and for the home truth he wants to have, this is the home truth. The home truth is that the crime situation can be brought under control over a period of time. It has increased and we are taking steps and

I hope the results will show that in course of time, the situation has improved.

MR. SPEAKER: Question No. 236. SEVERAL HON. MEMBERS rose.

MR. SPEAKER: Question No. 230—absent.

Question No. 231—also absent.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Can I ask Question No. 231, Sir? I come from Ahmedabad and so I can ask if you permit.

MR. SPEAKER: Question No. 232.

SHRI NIHAR LASKAR: Question No. 232.

Technical Assistance for H.E.C.

*232, **SHRI NIHAR LASKAR:**
SHRI R. V. SWAMINATHAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Union Government have taken decision to ask U.S. technical assistance instead of Soviet assistance for HEC;

(b) the main reasons for the same; and

(c) whether the Soviet Union has agreed for this change?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

SHRI NIHAR LASKAR: Mr. Speaker, Sir, I have not heard the answer.

MR. SPEAKER: You have got the written answer—is it not? Please read the answer. He has not heard it.

SHRIMATI ABHA MAITI: (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(Interruptions)

SHRI NIHAR LASKAR: I do not know whether the Minister, before answering my question, has gone

through the entire file or not. when she says 'No'. I asked whether it is a fact that the Union Government...

MR. SPEAKER: Your question is:

"Whether it is a fact that Union Government have taken decision to ask US technical assistance instead of Soviet assistance for HEC."

SHRI NIHAR LASKAR: I would like to ask whether it is in the knowledge of the Government, particularly, the Ministry that the proposed HEC-Soviet agreement on the production of high capacity turbo generators is pending before FIB for a final decision by the Government.

SHRIMATI ABHA MAITI: Sir,...

SHRI NIHAR LASKAR: I have not yet finished my question.

MR. SPEAKER: He has not yet finished his question.

SHRI NIHAR LASKAR: If it is a fact, then, how this question does not arise? What has been the final decision of the Government in this regard?

SHRIMATI ABHA MAITI: Sir, the H.E.C. is in collaboration with the Soviet Union, Czechoslovakia and other countries for import of machine tools and heavy machine building plants.

But, the matter which was referred to by the hon. Member is under consideration in regard to BHEL. That has not been concluded. When we go for Soviet collaboration, that does not mean that we cannot go in for collaboration with other countries also.

SHRI NIHAR LASKAR: I want to know whether it is not a fact that the Soviet Union was willing to extend further assistance to the H.E.C. plants and—Hardwar Plant for the purpose of introduction of new technology? If it is so, why are you going in for the import from the multinational companies?

SHRIMATI ABHA MAITI: Mr. Speaker, Sir, I have also said that we

have new collaborations in other countries. I have said that for acquiring of more sophisticated technology it was felt that we must import new technology from other countries also. For that reason, a Negotiating Committee was formed and that Negotiating Committee addressed to different parties in U.S.A., in U.S.S.R. and some other countries also. According to the Committee, the two parties namely Messrs. Marion Power Shovel Company, U.S.A. and Bucyrus Erie Co., U.S.A. declined to collaborate with H.E.C.

MR. SPEAKER: The question is whether you have substituted U.S.A. for U.S.S.R. To this, the answer is no. But, there are several collaboration agreements with others.

SHRIMATI ABHA MAITI: His question was with regard to collaboration with Siemens by BHEL, whereas this question is in regard to H.E.C.

MR. SPEAKER: Mr. Swaminathan. He is not here. Mr. Tyagi.

बी प्रकाश त्वाणी : एच० ई० सी० के बारे में सोवियत टेक्निकल एसिस्टेंस जो मिल रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उस से भी अच्छी टेक्निकल एसिस्टेंस फ़ैडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी प्रावि देना से मिल सके तो क्या सरकार इस प्रकार का महत्व देगी और जोर देगी कि जहाँ अधिक अच्छी अप-टू-डेट एसिस्टेंस मिले, वह वहाँ से ले ।

SHRIMATI ABHA MAITI: With the Soviet Union's collaboration no doubt we have been benefited. But, Sir, due to sophisticated technology and others as already stated by me, a Negotiating Committee has been formed and that Negotiating Committee addressed to different parties for the latest technology, know-how and for that reason, as I told you, we have addressed to five manufacturing units. Two of them declined to be in collaboration with the H.E.C. But, from one unit based in U.S.S.R. M/s. Prommohexport, there is no response. With two other units the Negotiating Committee is for further

negotiations from those countries before coming to a conclusion whether we can get the latest technology. For that purpose, the Government has accepted that recommendation. It had been sent to the H.E.C. How, some of the H.E.C.'s high officials went to those countries and saw the manufacturing units. Their report will come to Government and, then, a decision will be taken by the Foreign Investment Board.

SHRI VASANT SATHE: Sir, I would like to know firstly which are those two countries and which are the units of the companies/private parties with whom Government would like to have collaboration in so far as it relates to the latest technology for the H.E.C.?

Secondly after such a report comes, you will also consult your primary collaborator, that is, the Soviet Union to see whether that technology is available with them instead of later on having the complication of your having to go for a different technology from a different country. We are carrying on with the technology from the Soviet Union. The other technology if it comes, it may create a complication. So, I would like to know which are those countries and whether you have asked the Soviets about that technology being available with them or not?

SHRIMATI ABHA MAITI: Those manufacturing units are M/s. Page Engineering Co., USA and Ransomes & Rapier Ltd., U.K. We have already collaboration with M/s. Prommash-export, USSR. We have addressed them also. We have not got any response from them. We need not also take any permission from the previous collaborator in this matter. There is no such binding rule on us.

(Interruptions)

Schemes for development of tribal areas

*233. **SHRI GIRIDHAR GOMAN-
GO:** Will the Minister of HOME AF-

FAIRS be pleased to lay a statement showing:

(a) the Central Ministries which have prepared schemes for the development of Tribal Areas and socio-economic upliftment of tribal people so far;

(b) the amount earmarked by the Ministries for the sub-plan areas for the years 1978-79 and 1979-80;

(c) the reasons for delay in earmarking allocations by the Ministries; and

(d) the initiative taken by his Ministry for earmarking money and releasing the money to the States by the Ministries since the finalisation of sub-plan?

**THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI DHANIK LAL MANDAL):**

(a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) In view of the amounts committed by various sectoral Ministries to on-going programmes adequate earmarking could not be done in 1978-79. The State and Central Plans and the items of Central Plan Schemes were settled only recently. Hence there has been delay in earmarking funds for tribal Sub-Plan.

(d) A Central Coordination Committee for the Development of Backward Classes on which all development Ministries are represented was set up under the Chairmanship of the Minister in the Ministry of Home Affairs to ensure *inter alia* the adequate flow of resources from the Central Plan programmes to the tribal areas. The matter has been emphasized at the meeting of the Committee and has also been taken up separately in discussions with each concerned Ministry.

Statement

Statement showing amounts earmarked by Central Ministries for the Tribal Sub-Plan Areas out of Central Plan Programmes

Ministry/Deptt.	Scheme	Outlay earmarked for Tribal Sub-Plan area		Remarks
		1978-79	1979-80	
(Rs. in lakhs)				
Ministry of Education and Social Welfare.	1. Non-formal adult education programmes .	28.86	150.00	
	2. Scholarships . . .	2.00	2.00	
(i) Deptt. of Education	3. NCERT—Preparation of special curricula reading material for tribal students, Orientation programme for education officers working in the tribal areas studies etc.	1.00	10.00	
	4. Non-formal education programme at school stage.	Not implemented in this year.	150.00	
	5. Vocationalisation. .	(Not quantified).	15.00	
(ii) Deptt. of Social Welfare	(i) Integrated Child Development Services .	82.51	102.75	
	(ii) Functional Literacy Programme for adult women . . .	35.48	36.70	
D.G.P&T.	Telecommunication in tribal areas. . .	750.00	750.00	
Ministry of Works and Housing	Drinking Water Schemes	Not quantified.	Not quantified.	In the absence of authentic data as to the size and extent of the problem it has not been possible yet to finalise the amount to be earmarked.
Ministry of Energy (Deptt. of Power).	Rural Electrification .	2477.00	*	*Total amount for the programmes for country as a whole has not yet been decided.
Civil Supplies and Co-operation.	National Co-operative Development Corporation (For development of Co-operatives in Tribal Areas) . .	230.00	300.00	

Ministry/Deptt.	Scheme	Outlay earmarked for Tribal Sub-Plan area		Remarks
		1978-79	1979-80	
Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing).	Central Sector Roads Scheme	900.00	1000.00	
Deptt. of Rural Development .	Drought Prone Areas Programme	1510.00	Not yet decided.	
	Development of Primary Markets in Tribal areas.	30.00	30.00	
	Hill Area Development .	35.00	Discontinued.	
	Applied Nutrition Programme (ANP)	13.66	12.26	
Deptt. of Agriculture .	Forestry	425.00	510.	
	Soil & Water Conservation	403.00	415.00	
	Animal Husbandry	297.00	160.00	
	Agricultural Inputs	2.00	Not yet decided.	
	Crop-Oriented Programmes	164.00	22.00	
	Minor Irrigation and Water Management	55.00	55.00	
	Agricultural Extension	25.00	@ The Scheme benefiting Tribals is being transferred to States.	
	Fisheries	14.00	25.00	

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Sir, I have just now gone through the statement of the Minister. The sub-plan was finalised in 1974-75 and the strategy was to earmark funds from Central Ministries. Now, we have completed one year of the Sixth Five Year Plan but the ministries at the Central level have not yet quantified the amount for the tribal sub-plan area. The reasons given by the Minister may be partly true but the main reason is that the ministries at the Centre have not gone into the depth of the problems of the tribal area. How can the States earmark the money if the Centre does not give adequate aid to the States. Sir, though repeated assurances have been given by different ministries and the Prime Minister has also written a

letter to all the ministries yet they have not quantified the amount for the tribal sub-plan area. So, I would like to know whether in the annual plan 1979-80 all the ministries will quantify the amount for the tribal sub-plan area or not?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Sir, the hon'ble Member may look into the Statement laid. He will find Education and Welfare Ministries have already done some work in earmarking and so also Housing Ministry, Irrigation and Health Ministries. It is true that there was some timelag but then it is being made up and as the hon'ble Member knows the Prime Minister has written to all the Ministries and departments that they must earmark for tribal development from their own sector and do it quickly.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Sir, the hon'ble Minister has said that the Ministry of Works and Housing has earmarked money but there are no details about that in the statement. It has been stated that some Ministries, like Ministry of Works and Housing, have earmarked some money for the tribal areas. The working group on tribal sub-plan development has already submitted their report and they have gone into the problems in detail and have said about the allocation of money and implementation of the various programmes. They have said that all the Ministries will earmark money for these areas, but we find that only a few Ministries have quantified the amount; and that amount is very small. Out of thousands of crores, they would get only a few lakhs of rupees. In this way, how do you expect the development of tribal areas?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Sir, I agree that the position is not satisfactory at all. In this context, I have already stated that the hon. Prime Minister had written last year to all the Ministries and Department's that they must earmark money out of their own sector for the development of the tribal areas. They should either take up a new programme or modify the on-going programmes and do something for the tribal areas.

बी छोड़ जाई जाति: अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरियाज के लिये जो ग्रान्ट सरकार की ओर से दी जाती है वह सारी ग्रान्ट प्रमग प्रमग विभागों के अधिकारियों की ही जाती है। ऐग्रीकल्चर की ग्रान्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर की, एनीमल हस्वीरी की एनीमल हस्वीरी के अधिकारी की, रोड के लिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की इस तरह प्रमग प्रमग विभागों की ग्रान्ट प्रमग प्रमग अधिकारियों की ही जाती है। यह सारी ग्रान्ट ट्राइबल ऐडमिनिस्ट्रेटर के पास न होने से यह ग्रान्ट अच्छी तरह से खर्च नहीं होती और कितने ट्राइबल में खर्च होनी चाहिये उतने ट्राइबल में खर्च नहीं होती। इसमें जो अच्छा संकलन होना चाहिये वह संकलन ही नहीं होता। इसी कारण वह ग्रान्ट खर्च नहीं की जाती। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूरे वर्ष की जो ग्रान्ट होती है वह सारी ग्रान्ट किता कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट आफिसर के पास रखी जायेगी, क्या गवर्नमेंट ऐसा नियम करे

जा रही है? जिससे वह ग्रान्ट अच्छी तरह से इस्तेमाल ऐडमिनिस्ट्रेटर निश्चित समय के अन्दर वृद्धिवाज कर सके?

बी ग्रामिक सल मण्डल: अध्यक्ष महोदय, जो इंटी-सेक्टर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस को जो पैके मिलते हैं सब-प्लान के लिए संबंध सरकारों से वह डिपार्टमेंट से मिलते हैं। यह माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल ठीक है कि ऐग्रीकल्चर वाले ऐग्रीकल्चर की वेतें हैं, एनीमल हस्वीरी वाले एनीमल हस्वीरी के काम के लिये वेतें हैं। लेकिन सब को मिला कर एक कोषाडिनेशन कमेटी होती है और उस के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट आफिसर होता है जिस का काम यह देखना होता है... (स्वयंचाल)

बी हुकम चन्द कछबाय: वह कुछ नहीं करता।

बी ग्रामिक सल मण्डल: उस में जो खासियां हैं उन को दुरुस्त करने के लिये हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

बी हुकम चन्द कछबाय: माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि काम सतोषजनक नहीं है और विलम्ब हुआ है इस बात को भी स्वीकार किया है। इन दोनों बातों का सतोष बिलाने के लिये उन्होंने प्रधान मंत्री जी के पास का उल्लेख भी किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि देश के प्रन्दर प्राप ने कितने ऐसे प्राविवासी क्षेत्र बनाए हैं और क्या यह बात सत्य है कि जो पैसा दिया जाता है वह बहुत थोड़ा है और वह भी लैप्स हो जाता है, खर्च नहीं होता है? यह पैसा पूरा खर्च हो और पैसा बड़े उस क्षेत्र के विकास के लिए उस के लिए क्या कोई ठोस कदम प्राप ने उठाया है? प्रधान मंत्री जी ने जो पैसा लिखा है उस पर किन राघव सरकारों ने प्रयत्न किया है और किन किन ने नहीं किया है यदि किया है तो उस में कितनी प्रगति हुई है? क्या प्रापें धाने वाली छठी पंच वर्षीय योजना में उनके लिए प्रमग से पैसा रखा गया है? यदि रखा गया है या रखने का विचार है तो कितना रुपया रखने का विचार है? ... (स्वयंचाल) ...

अध्यक्ष महोदय: बहुत बड़ा क्वेश्चन है?

बी हुकम चन्द कछबाय: ठीक उस का विकास हो उसके लिए कौन से कदम सरकार उठाते जा रही है?

बी ग्रामिक सल मण्डल: छठी पंच वर्षीय योजना में कुल भिन्ना कर 3 हजार करोड़ रुपया इस मद में खर्च होगा। उस में स्टेट सिक्रेटरी हमारा अनुमान है 18 तो करोड़ खर्च होगा, स्वेमल सेंट्रल बजिस्ट्रि के खर्च में साढ़े तीन तो करोड़ खर्च होगा और जो इंटीग्रेटिड प्रमग कार्यक्रम है उस को भी हम ध्यान में रखते हैं, उधर से भी पैसे या छा: भी करोड़ खर्चा जाएंगे। सब मिला कर 3 हजार करोड़ खर्चा पूरे देश में संभवान पर खर्च होगा। प्रधान मंत्री जी के पास की बातों की वैसे कहो है वह स्टेट गवर्नमेंट्स के लिये नहीं बल्कि केंद्रीय लेवल बजिस्ट्रीय का पैसा है। न केवल हीय डिस्ट्रिक्ट को जो कि इस काम की करता है बल्कि

कभी किसानों की समस्याओं को इस कदम से धिक्क करने की बात नहीं है, बल्कि जनरोधक मोर्चा में भी प्रतिष्ठाई करने या न ? स्वीय की की का सवाल है। इसलिये इस में पेसे का कोई सवाल नहीं है, पैसा पयान्त आ रहा है।

श्री धनिक लाल मण्डल : क्या सली जी बतावेंगे कि चूक जन-जातिवों के सामाजिक तथा जायिक उत्थान के लिये जो पैसा दिया जाता है वह पूरा पैसा खर्च नहीं होता है तथा विधिवत् खर्च नहीं होता है मतः इसकी जांच की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री धनिक लाल मण्डल : इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस बात को जानते हैं कि स्टेट बजट में इस मद में जो सब-प्लान्स हैं वह पहले डाइरेक्टिवल थे, दूसरी मदों में वह पैसा खर्च कर दिया जाता था लेकिन गत वर्ष से हम ने कदम उठाया है, राज्य सरकारों की सहमति से, कि इसको नान-डाइरेक्टिवल बनाया जाये। अब यह पैसा किसी दूसरी मद में खर्च नहीं होगा। अगर साल के अन्त में पैसा रह जाता है तो उस को सरेन्डर न किया जाये बल्कि बैंक में जमा करने के बाद फिर उसको ले लिया जाये। इसलिये जैसा मैं ने कहा, इस तरह हमारा ध्यान है, जो खानियां हैं उन को पूरा कर दिया जायेगा।

Proposal to discontinue Pension to Freedom Fighters

*235. SHRI JANARDHANA
POOJARY:
SHRI VIJAY KUMAR N.
PATIL:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to discontinue pension to freedom fighters; and

(b) if so, the reasons for discontinuing the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b) The Freedom Fighters Pension Scheme, 1972 is under review but no final decision has yet been taken.

SHRI JANARDHANA POOJARY: The answer is very evasive. We must honour the freedom fighters who fought and struggled for the freedom of our country. Most of the freedom fighters are aged and infirm. Unfortunately, in a letter addressed to Mr.

Upadhyay Ravi by the Prime Minister which was published in "The Tribune" on 25th June, 1977, it has been mentioned—it has been reported also—as having been stated by the Prime Minister to the effect that the Prime Minister never liked the pension scheme for the freedom fighters, and also that in fighting for freedom, nobody obliged anybody. These are the wordings of the Prime Minister. Under these circumstances, there is a doubt in the minds of freedom fighters, whether the pension scheme would be stopped or discontinued, as stated by the Prime Minister or by the Ministry concerned.

The freedom fighters now want a clarification as to what is the stand of the Janata Government—whether it is taking a very narrow view of the matter.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: At present there is no question of stopping the freedom fighters' pension. (Interruptions).

PROF. SAMAR GUHA: Then what is the meaning of review?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: There is no question of stopping the freedom fighters' pension scheme altogether. But certain things have been brought to the notice of the Government, and Government has not taken any final decision. Therefore, I am not in a position to say everything; but then, a review is there.

SHRI VASANT SATHE: What is the review for?

PROF. SAMAR GUHA: What is the purpose of this review? You must make it clear. There are many apprehensions...

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Have you reviewed any case? (Interruptions).

SHRI KRISHAN KANT: In the view of the House, there should not be any stoppage.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: There is no question of stoppage.

MR. SPEAKER: The Question Hour is now over.

SHRI EDUARDO FALEIRO: I have given two notices...

MR. SPEAKER: We will come to that.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Manufacture of Automobile Components in Public Sector

*222. **SHRI S. R. REDDY:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have examined the feasibility report for the manufacture of automobile components in the public sector;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the location where the production units are likely to be set up and at what cost?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) The studies taken up for examining the question of setting up manufacture of automobile components in the public sector have not yet been completed.

(b) and (c) Do not arise.

Recommendation of Task Force on Science and Rural Development

226. **SHRI P. V. PERIASAMY:** Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to lay a statement showing:

(a) the recommendations of the Task Force on Science and Rural Development of the Indian Science Congress; and

(b) the action taken by Government on one of the principal recommendations that the Government should change its personnel policies to encourage scientists and technologists to work in rural areas?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The principal recommendations of the Task Force on Science and Rural Development, constituted by the Indian Science Congress Association (ISCA) at its 63rd Session held at Waltair in 1976, were:

(i) Formulating strategy for rural development covering: involvement of all scientific agencies; provision of necessary financial inputs to create infra-structure in some institutions; particularly voluntary agencies and educational institutions; blending of agricultural and non-agricultural operations for an integrated approach.

(ii) Council of Scientific and Industrial Research was entrusted with the task of preparing an inventory of voluntary organisations and their functioning.

(iii) Need for training of a whole cadre of scientists and technologists to work in rural areas; for this the creation of at least 1000 fellowships of Rs. 500 per month for technically trained rural development workers was recommended.

(iv) Communication strategy involving the mass media, particularly AIR, for dissemination of information.

(v) Tree planting—UGC to initiate action for establishment of nurseries in educational institutions of appropriate trees and shrubs to enable them to be used for large scale plantations in that area.

(b) One of the recommendations, which it is learnt was made at ISCA, Hyderabad in January, 1979, was that

the Government should change its personnel policies to encourage scientists and technologists to work in rural areas. No formal communication has been received by Government from ISCA so far. However, various scientific institutions, agencies, government departments and voluntary organisations have initiated a large number of programmes on rural development, ensuring maximum participation of scientific community. Government has laid great stress in involving scientists in most of the developmental projects, and also in utilising the existing infrastructure of the country without waiting for the creation of new cadre of workers and structures for the purpose. As soon as the ISCA recommendations are received, Government will have them examined.

Departmental Promotion Committees

*230. SHRI K. RAMAMURTHY.
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have come across the views expressed by the former Chairman of Union Public Service Commission (Dr. A. R. Kidwai) who retired only in the first week of February, 1979 deploring the massive ad-hocism in Government appointments which has led to widespread frustration in services, inordinate delays and administrative lapses;

(b) if so, the action initiated by Government to tune up the Departmental Promotion Committees which are reported not to have met for years; and

(c) the action proposed to be taken by Government to restore confidence among officers who are reported not to have got promotion for years?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) Government have issued instructions from time to time asking Ministries to ensure that Departmental

tal Promotion Committees are convened every year to select officers for promotion against vacancies likely to arise in the next one year. Ministries have also been asked to finalise expeditiously Recruitment Rules and Seniority Lists. Instructions have also been issued to set up Special Cells to up-date Confidential Reports for the purpose of Departmental Promotion Committees.

(c) Government propose to reiterate instructions to all Ministries/Departments that Departmental Promotion Committees meetings may be convened regularly every year. However, it is possible that inspite of these instructions delays may occur necessitating ad-hoc appointments in cases where officers have taken recourse to a court of law and orders staying the proceedings have been granted by the courts.

Closure of Textile Mills in Ahmedabad for want of Coal

*231. SHRI KUMARI ANANTHAN:
Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ahmedabad Millowners' Association and the Gujarat Government have sent SOS to the Government of India that 30 textile mills in Ahmedabad are on the verge of closure for want of coal; and

(b) if so, the steps taken to ensure that these 30 textile mills are not closed for want of coal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b) Government have been receiving representations drawing attention to the difficult supply position of coal. No textile mill in Ahmedabad has however been reported to have been closed due to coal shortage. Efforts have been made to step up loading of coal from Central India Coal Fields and Panch

Valley Coal Fields which usually supply coal to the industries in Gujarat. Ministry of Industry has taken up the matter with Ministries of Energy and Railways. The average daily loading of coal has been increased in February, 1979 as compared to earlier months. Government are keeping a watch over the situation.

Production of Bivoltine Silk

*234. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details regarding the production of Bivoltine silk in the State of Karnataka during the last three years;

(b) whether it is a fact that the import of this type of silk is adversely affecting the prospects of indigenous producers in Karnataka; and

(c) if so, whether Government propose to rescind the decision to import this type of silk?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The estimated production of Bivoltine silk in Karnataka during the last three years is as under:—

Year	Production (Metric tons)
1975-76 . . .	28
1976-77 . . .	49
1977-78 . . .	100

(b) The import of Bivoltine silk which is mostly replenishment against export of silk textiles has so far not adversely affected the indigenous sericulturists producing this type of silk.

(c) Does not arise.

Reservation of Items for Small Scale Industries

*236. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) production of how many industrial items exclusively reserved for the small scale sector;

(b) a list of items reserved for the small scale unit in which large houses and the multi-national companies even now hold dominating position and

(c) what steps, if any, have been or are being taken to restrict/eliminate this domination?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) 807 items have been reserved for exclusive development in the small scale sector through Government notification of April 26, 1978.

(b) and (c) Some foreign MRTP companies are engaged in the manufacture of items such as Soaps, Footwear, Matches, Tooth paste etc. which are reserved for small scale sector.

Paragraph 19 of the Statement on Industrial Policy laid before Parliament in December, 1977 clarifies Government's policy in regard to manufacture of items reserved for the small scale sector by the large scale units. It has been clarified that where large scale units are already engaged in the manufacture of items since reserved for the small scale sector, there will be no expansion of capacity. On the other hand, the share of these units in the total capacity for the item will be steadily reduced and that of the small scale and cottage sector increased. This policy is strictly enforced while considering applications for grant of industrial licences in areas reserved for small scale industries.

Production in the large scale sector of items reserved for small scale sector is regulated in the following manner.

(i) Undertakings already licensed are not allowed to expand their capacity.

(ii) In case an item is exempted from industrial licensing procedure and is reserved for small scale sector, a Carrying-on-Business Licence is issued in case an entrepreneur has taken effective steps/ commenced production before the date of reservation.

(iii) The facility to increase production beyond 25 per cent of the licensed capacity is not extended in respect of items reserved for small scale sector.

(iv) Fresh industrial licences for manufacture of items reserved for small scale sector are not normally issued unless the proposal is for hundred per cent exports on a continuing basis.

Panchayat Type of Representations for Minicoy Islands and Lakshadweep

*237. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Union Government propose to give Panchayat type of representation for Minicoy Islanders and Lakshadweep;

(b) if so, when the final decision is likely to be taken; and

(c) whether the Prime Minister assured the people during his visit to the Lakshadweep that this will be done soon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) A proposal for promulgating a Regulation under article 240 of the Constitution to provide for constitution of panchayats in the

Union territory of Lakshadweep is under consideration.

(b) As soon as possible.

(c) The Prime Minister, while addressing a public meeting in the Minicoy Island on 1st February, 1979, indicated that the Government was thinking in terms of associating the people of Lakshadweep with the administration by granting democratic representation through small panchayats.

Largest Tool Room of Asia

*238. SHRI DHARMAVIR VASISHT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi State has the distinction of having the largest tool room in Asia; and

(b) if so, the details and the size of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). A big Tool Room involving a financial outlay of Rs. 524.05 lakhs has recently been set up in Delhi with the assistance of the Danish Government. The capital outlay on machinery and equipment for this project is of the order of Rs. 250 lakhs. The Tool Room has been located in Wazirpur Industrial Area. The main objectives of the Tool Room are to provide training facilities, produce quality tools, jigs, fixtures etc. for small scale units, and to render technical consultancy services relating to tools for small scale units. The Tool Room was registered under the Societies Registration Act, 1860 on 11th March, 1976.

Expenditure on Computer Imports

*239. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to lay a statement showing

(a) the amount spent on computer imports during the period 1-4-78 to 31-12-78, (Category wise);

(b) the amount spent for replacement purposes and to acquire for the installation of new projects out of the above; and

(c) whether the same types of computers are also manufactured in the country; if so, the reasons for importing such computers?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Import of computers worth about Rs. 16 crores has been approved during this period.

(b) Approximately Rs. 12.50 crores on import of new computer systems to replace older ones; and Rs. 3.50 crores on new projects.

(c) Import of computers is permitted only in cases where indigenous systems cannot meet identified user requirements.

हथकरघा उद्योग को सहायता देने के लिये कार्यवाही

* 240. श्री चमूना प्रसाद साम्बो : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने हेतु हथकरघों को दी गयी प्रियायतों के परिणामस्वरूप 1978 में सांख्यिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कितने लाख मीटर हथकरघा कपड़ा वितरित किया गया,

(ख) हथकरघों की संख्या बढ़ाने, बुनकरों को प्रशिक्षण देने तथा हथकरघा का उत्पादन बढ़ाने के लिये नया कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, जबलपुर, रीवा, सतारा, सागर और रायपुर में बुनकरों को प्रशिक्षण देने तथा हथकरघा उद्योग का पुनर्विलोकन करने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयबन्नी प्रसाद जयवंत) : (क) समाज यह जाता है कि इस से

तात्पर्य हथकरघा क्षेत्र में तैयार किये गये जनता कपड़ा तथा राब सहायता प्राप्त मुम्बई पर बेचे जाने से है। जनता कपड़े के उत्पादन तथा विपणन की व्यवस्था जनता कपड़ा उत्पादन योजना के एक अंग के रूप में राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। सामान्यतः जनता कपड़े के विपणन हेतु हथकरघा शीर्षस्थ सहकारी समितियों, राज्य हथकरघा विकास निगमों, राष्ट्रीय वस्त्र नियम तथा राष्ट्रीय भारतीय सहकारी उपभोक्ता संघ के कूटकार विक्रय केन्द्रों की सहायता की जाती है तथा कुछ राज्यों में इस प्रयोजन के लिये सिविल सप्लाय विभाग द्वारा चलाये जा रहे राज्य विक्रय केन्द्रों की सहायता की जाती है। इस प्रकार एजेन्सीवार बेचे गये जनता कपड़े को अलग अलग कपड़े केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) हथकरघा विकास कार्यक्रम के एक अंग के रूप में अपर्याप्त मांग के कारण कठिनाई का सामना करने वाले विद्यमान बुनकरों के निरन्तर लाभप्रद रोजगार दिलाने पर जोर दिया गया है, ताकि उन की कुल आय बढ़ सके। ऐसी परिस्थितियों में हथकरघों की संख्या बढ़ाने की गुंजाइश कम ही लगती है। बुनकरों को प्रशिक्षण देने के प्रयोजन से समस्त देश में वाराणसी तथा सलेम के दो हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के अलावा 21 बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इन संस्थानों के अलावा प्रशिक्षण राज्यों में भी राज्य सरकारों के अन्तर्गत बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र हैं। हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये समस्त देश में हथकरघा सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने सहित हथकरघा परियोजनाएँ तथा निर्यातानुसूध परियोजनाएँ हाथ में ली गई हैं।

(ग) जहाँ तक मध्य प्रदेश का संबंध है, बुनकरों के प्रशिक्षण के लिये रायपुर में एक केन्द्र की स्थापना कर दी गई है। अन्य स्थानों में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है हथकरघा उद्योग संबंधी प्रशिक्षण तथा पुनरुत्थान का कार्य राज्य के सामान्य हथकरघा विकास कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किया जा रहा है।

घातम हत्या की घटनाएँ

* 241. श्री हरमोहन्य बर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घातमहत्या की घटनाएँ दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं और इन की दृष्टि रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कथन उठाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसकि लाल मल्हान) : (क) सूचित की गई घातमहत्याओं की वर्षवार संख्या

अस प्रकार है :—

वर्ष	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
सूचित की गई घातमहत्याएँ	48428	43675	43601	40807	46008	42890	41415

वर्ष 1974 के अन्तर्गत घटनाओं के रूप में कभी दिखाई देती है।

वर्ष 1977 तथा 1978 के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा जितनी जल्दी संभव होना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सामान्यतः आत्महत्या की घटनाओं के निम्नलिखित कारण हैं :—

- (1) घरेलू झगड़े।
- (2) लम्बी तथा असह्य बीमारियाँ।
- (3) प्रेम सम्बन्धी मामले।
- (4) पागलपन।
- (5) दिवाला।
- (6) सामाजिक सम्मान में गिरावट।
- (7) परीक्षा में असफलता।
- (8) निर्धनता।

बूक लोग आत्यधिक हताश होने, खिल होने तथा मानसिक दबाव तथा तनाव की हालत में आत्महत्या करते हैं अतः घटनाओं को रोकने के लिये, कोई कारगर उपाय करना संभव नहीं है।

न्यू ओपाल टेक्स्टाइल मिल द्वारा घरेलू उपयोग के कपड़े की बिक्री

2201 श्री हुकम लाल कडवाल : क्या उद्योग संघी 18 अगस्त, 1978 के तारोक्त प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यू ओपाल टेक्स्टाइल मिल ने जनवरी, 1976 से अक्टूबर, 1976 के दौरान, पार्टीवार, वर्षवार तथा महीनेवार, कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का घरेलू उपयोग का कपड़ा बेचा;

(ख) उपरोक्त मिल ने निर्यात के लिए कितने कपड़े का उत्पादन किया और उपरोक्त अवधि के दौरान किन-किन पाटियों को कितने-कितने मूल्य का कपड़ा बेचा;

(ग) प्रत्येक पार्टी ने कितनी-कितनी अवधि के भीतर तथा किन-किन तारीखों को इस विधित्त कपड़े के लिए अधायरी की, कितनी राशि अभी बचल होनी बाकी है और उसे बचल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और क्या कुछ राशि बहुते जाते में हाल की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी पार्टीवार आंकड़े क्या हैं?

उद्योग संश्लेष में राज्य संघी (श्री जगदम्बी अस्वत्थ दाम्ब) (क) क्रमांक: दिनांक 19-4-78

ब 10-5-78 की छूटे गए अंतराकित प्रश्न सं 7460 व 9827 के उत्तर में दिए गए आश बावर्द्ध को पूरा करने हेतु जनवरी, 1976 से मार्च, 1978 तक की अवधि की जानकारी संसद के पुस्तकालय में रखी जा रही है। अनुभव से पता चलता है कि सूचना सकलित करने में जितना परिश्रम बिहित है परिश्रम उसके अनुरूप नहीं निकलता है।

(ख) श्री (ग) इस प्रश्न के इन भागों के उत्तर देना अनहित व आर्थिक हित में नहीं होगा।

Survey of India Shore

2202. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sixty Sixth Science Conference held at Hyderabad in the first and second week of January 1979 have recommended to Government thorough survey of 200 miles Indian Shore; and

(b) if so, reaction of Government thereon?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Government have not received any recommendation in this regard from the Indian Science Congress; but it is learnt that a Resolution to this effect was passed at the Indian Science Congress (1979).

(b) Government, in any case, are proposing to undertake a thorough survey of the Exclusive Economic Zone extending upto 200 miles from the coast line of India.

Cotton Purchase

2203. SHRI F. P. GAEKWAD: SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of bulk purchases of cotton bales from Punjab, Haryana and other areas by the Cotton Corporation of India;

(b) the number of cotton bales purchased from Gujarat which tops in cotton production;

(c) whether Government are aware that large number of bales will remain unsold in Gujarat as in last year in view of the poor off take; and

(d) if so, steps proposed to be taken to make bulk purchases of cotton from Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) State-wise details of purchases made by the Cotton Corporation of India in various cotton growing States upto end of February, 1979 are as under:

State	Quantity purchases (In bales)
Punjab	1,56,172
Haryana	62,334
Rajasthan	91,634
Gujarat	77,000
Maharashtra*	61,278
Madhya Pradesh	60,607
Andhra Pradesh	15,883
Karnataka	20,036
Tamil Nadu	23,615

* With the revival of cotton monopoly procurement scheme in Maharashtra with effect from 16th December, 1978, the Cotton Corporation of India is not now operating in Maharashtra.

(b) In Gujarat, Cotton Corporation of India has purchased so far 77,000 bales; Gujarat cotton season commences later than Northern States.

(c) and (d). No, Sir. The mill consumption during the current cotton season is expected to be higher than that of the previous year with various measures taken by Govern-

ment like permission of exports of cotton, withdrawal of stipulation for 10 per cent compulsory use of non cotton fibres and increase in stock limits etc. CCI has planned for purchase of nearly 4 lakhs bales in Gujarat and they are operating in 27 centres.

National Demand of Cement

2204. SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the entire national demand of cement at present;

(b) the quantity produced inside the country i.e. in India;

(c) the quantity which is produced at present in our country; and

(d) the name of the countries from where cement is at present imported to India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMB PRASAD YADAV): (a) The demand for cement during the year 1978-79 has been estimated at about 24 million tonnes.

(b) and (c). The production of cement in the country during this year is estimated to be about 19.6 million tonnes.

(d) Cement has been imported from the following countries:—

- (1) Poland
- (2) Rumania
- (3) North Korea
- (4) South Korea
- (5) Japan.

नरीया में परमाणु संयंत्र

2205. श्री नवान सिंह चौहान: क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरीया, दुलहनगर में स्थापित किये जा रहे परमाणु संयंत्र सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) किस फर्म को इसकी स्थापना का काम सौंपा गया है और उसको कितने मूल्य का ठेका दिया गया है; और

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान दिए गए अन्य ठेकों का झोरा क्या है और वे किन-किन फर्मों को दिए गए ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मुख्य संयंत्र भवनों के सिविल निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी है। न्यूक्लीय एवं परम्परागत किस्म के प्रमुख उपस्कर तैयार किए जा रहे हैं और प्राकृतिक हवा के झोकों से ठंडा करने वाले टावर बनाने के लिए खुदाई की जा रही है। पाइप लाइनों से सम्बद्ध नक्शे बनाने का काम और पाइप लाइनों का निर्माण करने और उन्हें लगाने के लिये आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के सम्बन्ध में आवश्यक प्रलेख तैयार करने का काम काफी हद तक पूरे हो चुके हैं।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रश्न किस चीज की स्थापना के बारे में है। इस समय संयंत्र-स्थल पर मुख्य रूप से सिविल निर्माण कार्य चल रहा है। कार्य के संबंध में अब तक दिये गये बड़े ठेके निम्नलिखित हैं :

(i) मुख्य संयंत्र के भवनों के सिविल निर्माण के लिए 10.04 करोड़ रुपये का ठेका मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन क० को दिया गया है।

(ii) प्राकृतिक हवा के झोकों से ठंडा करने वाले टावरों के निर्माण के लिए 3.68 करोड़ रुपये का ठेका मैसर्स तैमन इंडिया को दिया गया है।

(iii) संरचना-कार्यों में इस्तेमाल होने वाले इस्पात और अंतःस्थापित किये जाने वाले भाग तैयार करने के लिए मैसर्स लिबेनी स्ट्रक्चरल्स को एक ठेका दिया गया है जिसकी मियाद और रकम काम के साथ-साथ बढ़ती रहेगी और जिसका भुगतान किए जाने वाले काम के अनुसार होगा।

(ग) वर्ष 1977-78 में मुख्य संयंत्र से सम्बद्ध निर्माण-कार्य का कोई बड़ा ठेका नहीं दिया गया है।

Grant of Licence to Mohan Ortman

2206. SHRI DHARMASINH BHAI PATEL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mohan Ortman was licensed to manufacture dairy equipment and juice equipment;

(b) how many dairy machines they were licensed to manufacture;

(c) how many juice machinery they were licensed to manufacture; and

(d) how many machines for juice, dairy and soft drink have been manufactured?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (c) M/s. Mohan Ortman are licensed for the manufacture of complete automatic bottling plants (including bottle washers, fillers, intermix and accessories) for soft drinks, beer, milk, fruit juices etc. upto a capacity of 25 units per annum.

(d) The company commenced production from November, 1977 and their production up to November, 1978 was to a value of Rs. 50 lakhs, consisting of two complete bottling plants and some parts of these plants.

Instrumentation Limited, Palghat

2207. SHR C. K. CHANDRAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Instrumentation Limited, Palghat, Kerala is employing only about 200 employees while its capacity is to employ 600 persons;

(b) whether it is also a fact that the management is getting the work done for the plant through subcontractors, while the installed capacity of the plant remain underutilised;

(c) if so, the reasons thereof; and

(d) what are the steps Government contemplate to take to overcome this situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir. Commensurate with its present installed capacity, the Palghat unit of Instrumentation

Ltd., has two hundred and seventy one employees on its rolls.

(b) The unit procures certain required components, for which facilities have not been created in its plant, from other units. This is in line with Government's policy on encouragement of ancillary industries.

(c) and (d) Do not arise in view of the replies to parts (a) and (b)

Visit of Delegation from E.E.C.

2208. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the European Economic Community delegation which have visited recently has urged India to provide attractive opportunities for the transfer of technology from the E.E.C. countries; and

(b) if so, the names of the EEC countries with whom India has areas of cooperation and anxious to increase its export to the EEC countries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) An E.E.C. delegation participated in the seminar on trade and industrial co-operation between India and E.E.C. organised by the Engineering Export Promotion Council. The leader of the E.E.C. delegation stated that the Generalised System of Preferences (GSP) encourages transfer of technology and that India, as a beneficiary of the GSP could prove sufficiently attractive to enable commercial and industrial exchanges to reach an appropriate level.

(b) India's areas of cooperation with E.E.C. include the following countries:

1. Belgium
2. Denmark
3. Federal Republic of Germany
4. Holland

5. Italy

6. U.K.

7. France

Efforts are being made to step up exports of engineering goods to these countries.

Deployment of C.R.P. in States

2209. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many State Governments have requested the services of C.R.P. during period 1977-78;

(b) on how many occasions C.R.P. went into action; and

(c) how many people died, with State-wise break up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c) The requisite information is given in statements I & II enclosed.

Statement I

1. Andhra Pradesh
3. Bihar
2. Assam
4. Gujarat
5. Haryana
6. Jammu and Kashmir
7. Kerala
8. Karnataka
9. Maharashtra
10. Madhya Pradesh
11. Manipur
12. Meghalaya
13. Nagaland
14. Orissa
15. Rajasthan
16. Tamil Nadu
17. Tripura
18. Uttar Pradesh
19. West Bengal
20. Sikkim

Statement II

State	Firing	Teargasing	Lathi Charge	No. of Civilians		No. of CRP Persons	
				Killed	Injured	Killed	Injured
Assam . . .	2	..	3	..	2	..	10
Andhra Pradesh .	1	..	1	1	..	..	..
Bihar . . .	7	1	19	2	6	..	49
Haryana . . .	1	..	1	3	2	..	..
J. & K. . . .	3	7	22	2	74	..	104
Manipur . . .	3	..	1	3	1	..	..
Nagaland . . .	..	..	2	..	..	..	..
Tamil Nadu . .	..	..	2	..	..	..	..
U.P.	1	..	..	..	..	..	..
West Bengal . .	2	..	..	1	1	..	..

Past and Future Supply and Demand of Paper

2210. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the requirement of newsprint paper in the country and production for the last 3 years—year-wise and State-wise and important quantity and value—made to meet the home consumption;

(b) what is the year-wise estimated requirement of newsprint for the next 5 years and the details of production proposals state-wise approved so far during the last two years;

(c) details of sale price revisions allowed by the Government during the last 5 years; and

(d) whether Government have received a proposal for allowing rise in sale price of newsprint; details thereof and a final decision taken in the matter and changes effected proposed in the distribution system among the newspapers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The statewide consumption of newsprint during the year 1975-76, 1976-77 and 1977-78 is given in the statement attached.

At present National Newsprint and Paper Mills, Nepanagar (Madhya Pradesh) is the only unit in the country manufacturing newsprint. The production of newsprint by this undertaking during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 is indicated below:—

Year	Quantity (tonnes)	(Rs.)	
		(lakhs)	
1975-76 . . .	52873	14	19.53
1976-77 . . .	57619	15	91.22
1977-78 . . .	55503	15	00.40

Balance requirements are met by imports.

(b) The current annual requirement of newsprint is about 2.90 lakh tonnes and by the end of 1982-83 the annual requirement is expected to

be of the order of 3.20 lakh tonnes. Since the requirements of newsprint is based on the circulation of newspapers, normally newsprint requirements are assessed for every following year on the basis of past consumption. Therefore year-wise break up of requirement for the next 5 years are not available.

The existing unit M/s. National Newsprint and Paper Mills (Madhya Pradesh) are implementing their expansion of the capacity to 75,000 tonnes per year. Hindustan Paper Corporation is implementing a newsprint project at Kerala with a capacity of 80,000 tonnes/annum and this is expected to go into commercial production by the end of 1979.

During the year 1977 and 1978, M/s. Mysore Paper Mills (Karnataka) were granted industrial licence for the manufacture of 75,000 tonnes/annum of newsprint and this is expected to be commissioned in 1980-81. M/s. Punalur Paper Mills were permitted to manufacture newsprint within their existing capacity licensed for the manufacture of other varieties of paper.

(c) The sale price of newsprint manufactured by M/s. National News-

print and Paper Mills was revised as indicated below:—

(i) Rs. 1362 per tonne for supplies made upto 30-9-73.

(ii) Rs 1500 per tonne with effect from 1-10-73 for the quantity of newsprint supplied in 1972-73 from Nepa Mills and Rs. 1800 per tonne for supplies over and above the aforesaid quantity

(iii) Rs. 1800 per tonne with effect from 1-4-1974.

(iv) Rs. 2700 per tonne with effect from 12-6-1975.

(d) A request has been received from M/s. National Newsprint and Paper Mills for revision of the price to Rs. 3200 per tonne. No decision has been taken so far.

At present there is no change in the distribution system except that those newspapers whose annual entitlement is 400 tonnes and above are to obtain 15 per cent of their requirement from National Newsprint and Paper Mills during 1978-79 instead of 25 per cent taken during 1977-78.

Statement

	(Qty. in M. Tonnes)		
	1975-76	1976-77	1977-78
1. Andhra Pradesh	7098	8012	12196
2. Assam	1149	971	1213
3. Bihar	3676	3232	3795
4. Gujarat	14680	16024	18143
5. Haryana	9	..	4
6. Himachal Pradesh	2	3	1
7. Jammu & Kashmir	89	12	6

1	2	3	4
8. Karnataka	12772	12291	14708
9. Kerala	18604	18603	22572
10. Madhya Pradesh	4578	4838	5531
11. Manipur	34	..	27
12. Maharashtra	42692	47708	57848
13. Orissa	1288	1333	1741
14. Punjab	3812	4009	5394
15. Rajasthan	1841	2174	2913
16. Tamil Nadu	24235	24423	31873
17. Tripura	52	14	67
18. Uttar Pradesh	9158	7079	12743
19. West Bengal	23373	21115	27663
20. Chandigarh	2636	3100	4397
21. Delhi	24491	29637	38667
22. Goa, Daman & Diu	454	468	490
23. Pondicherry	3	..	..
24. Andaman & Nicobar	7	..	..
	196733	205136	261932

Setting up of a Paper Industry in H.P.

2211. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to unstarred Question No. 4204 on 20th December, 1978 regarding setting up of paper industry in Himachal Pradesh and state:

(a) the details of the various proposals for setting up pulp newsprint/paper projects in Himachal Pradesh which were approved and when each proposal was approved;

(b) the reasons for which no tangible progress was made with regard

to implementation of these schemes; and

(c) by when these projects are being taken up for implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c) A statement indicating details of the approved proposals for setting up pulp/paper/newsprint projects in Himachal Pradesh, and the position of implementation thereof, is attached.

Statement

Details of Approved Schemes for Setting up of Pulp, Paper and Newsprint Project in Himachal Pradesh

Name of Party	Item of manufacture	Capacity tonnes per annum	Date of issue of letter of intent/ industrial licence/ Registration	Date by which the project was initially expected to be commissioned	Reason
1	2	3	4	5	6
(1) M/s. Allied Produce Co. Ltd., Poanta Sahib.	Wood Pulp & Speciality Paper.	10,000	Industrial Licence dt. 4-11-75	4-11-1977	Initially the party informed that in view of their negotiation with Financial Institutions for obtaining a loan they wanted extension of time. Later the party has informed that they are still negotiating with the State Govt. for allotment of land and raw material. Hence extension granted till 31-5-1979.
(2) Shri H.L. Mehra Forest Industries Pvt. Ltd. (Poanta Sahib).	Sack Kraft Paper.	10,000	Do. dt. 10-9-76	10-9-1978	No tangible progress has been made. The party has not also furnished the progress report indicating the reasons for delay.
(3) Shri Mukhinder Singh, Teh. Nalagarh, Distt. Solan.	Wood Pulp	22,000	Letter of Intent 7-11-77.	of dt. from the date of issue of Industrial Licence (It will be issued after the party finalises supply of raw material, import of machinery etc.)	Two years The party has informed that they are negotiating with the State Govt. for obtaining raw material.
(4) M/s. Punalur Paper Mills Ltd., Poanta, Distt. Sirpur.	Sack Kraft Paper.	20,000	Letter of Intent dt. 3-10-78.	Two years from the date of issue I.L. (Industrial Licence will be issued	Progress has not been reported.

1	2	3	4	5	6
				ed after the party finalise supply or raw material, import of machinery etc.).	
(5) V. Podar	Sack Kraft Paper.	1,000	Registration certificate dt., 27-6-78.	Commercial production should be commenced within 24 months from the date of issue of registration (in this case within 1980)	Progress not reported by the party.
(6) Taj Board Pvt. Ltd., (Registration Certificate).	Straw Board, Mill Board, Pulp Board	750, 562.5 187.5	Registration certificate dt., 11-8-78.	Do.	Do.

शेफी तीन और चार के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रुब द्वारा भूख हड़ताल

2212. श्री बहा राम साहब :
श्री छीतु माई गानित :

क्या भूख मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेफी तीन और चार के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में माई ब्लाक के सामने 6 फरवरी, 1977 को भूख हड़ताल प्रारम्भ की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या थी और उनमें से कितनी मांगों को स्वीकार किया गया ?

भूख मंत्रालय तथा शिक्षा, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. जी. पाटील) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Creation of Intermediate Sector of Industry to Safeguard Interests of Small Scale Sector

2213. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Small and Developing Industries Association of India has pleaded for the creation of intermediate sector of industry to safeguard the interests of those units in small scale sector which have either crossed investment limit or may cross it in near future; and

(b) if so, his reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) In the Press Note issued on 19th May, 1975 by the Ministry of Industry, it had been clarified that all small scale units which cross the limit of investment in the revised definition of small scale industries i.e. Rs. 10 lakhs and Rs. 15 lakhs in case of ancillary units by way of normal growth will need registration with D.G.T.D. or with other concerned technical authorities; and units engaged in the manufacture of items which are exclusively reserved for the

small scale sector will need a Carrying on Business Licence before crossing this limit. Such units are required to submit their applications in the prescribed manner to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry. While granting the registration with D.G.T.D./technical authorities or the Carrying on Business Licences, the Government might impose export obligations on such units consistent with the policy of protection to the small scale sector. Directors of Industries of State Governments have been asked to keep a special watch over the units which are about to cross the upper limits so as to facilitate a smooth transfer of units to the D.G.T.D./technical authorities. A grace period of up to two years is allowed during which period such units continue to enjoy facilities for small industries. However, the representation sent by the Small & Developing Industries Association recently is receiving attention.

Departmental Promotion Committee in Howrah Works of Burn Standard Company Limited

2214. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any Departmental Promotion Committee for staff to higher posts in Howrah Works of Burn Standard Company Limited; and

(b) if so, the names of the personnel of that committee and whether there was any Public Notification about the formation of Departmental Promotion Committee to Howrah Works?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b) There is no standing Departmental Promotion Committee at Howrah Works of M/s. Burn Standard Co. Ltd., for promotion to higher posts. As and when an occasion arises, a Departmental Promotion Committee is nominated comprising of suitable offi-

cers at appropriate levels for judging the suitability of the candidates. Whenever Departmental Promotion Committees are constituted, no Public Notifications are issued as the composition and deliberations of the Departmental Promotion Committees are confidential in nature and the recommendations of the Committee are submitted to competent authorities for approval.

Setting up of Industries in Public Sector in Jammu and Kashmir

2215. SHRI ABDUL AHAD VAKIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the industries centrally set up in Public Sector in Jammu and Kashmir State, region-wise (Kashmir—Jammu and Ladakh) from 1954 to date and the cost thereof region-wise;

(b) what is the total employment potential of the industries;

(c) whether of late Government have undertaken any survey of Kashmir for setting up new industries; if so, details thereof; and

(d) whether district industries scheme has started in Kashmir and what industrial units are expected to come up in Baramulla district in 1979 and where?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). HMT Watch Factory, Zainakot (Baramulla District) and a unit of the Indian Telephone Industries Limited (Srinagar) are the central public sector industries in the State. Both the units are located in Kashmir. The capital investment as on 31-3-1978 and the employment potential in these 2 factories are as under:

Unit	Capital Investment (Rs. in crores)	Employment (Numbers)
HMT Watch Factory	4.25	1100 approx.
I.T.I. Factory	0.18	100 approx.

(c) The state Government have intimated that their Directorate of Industries and Commerce had conducted in 1974, in collaboration with the Small Industries Service Institute, potential surveys for each District. The State Bank of India, which is the lead Bank for the State, had also undertaken similar surveys. The District Industries Centres which have been set up in all the Districts of the State are now preparing project profiles based on these surveys.

(d) Yes, Sir. The action plan for the DTC, Baramulla is being prepared, which will provide information on the type of industrial units and their locations. According to the targets fixed by the State Government, the number of new small scale units likely to be set up during 1979-80 in Baramulla District is 100. Their locations have not been decided yet.

In the Large & Medium Industries sector, during 1979, the capacity of HMT Watch Factory is proposed to be expanded and an apple processing project is likely to be set up in the private sector, near Sopore.

Licences Issued for Setting up Industries in West Bengal

2216. SHRI DINEN BHATTACHARYA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of industrial licences/letters of intent issued for the setting up of industries in West Bengal, during the last 3 years; year-wise;

(b) particulars of licences, including the particulars of the parties who have been given licences during 1977-78;

(c) whether progress in this sphere is satisfactory; and

(d) if not, factors responsible for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The number of Letters of Intent and Industrial Licences issued for setting up of new undertakings in West Bengal during the last 3 years are indicated below:—

Year	Letters of Intent	Industrial Licence
1976	14	15
1977	12	9
1978	8	4

(b) Details of all Industrial Licences and Letters of Intent including name of the party, item of manufacture, capacity, location of the unit etc. issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 are published in the "Weekly Bulletin of Import Licences, Export Licences and Industrial Licences" and in the Supplement to the "Monthly News-Letter" published by the Indian Investment Centre. Copies of these publications are available in the Parliament Library.

(c) and (d) An Industrial Licence is issued with an initial validity period of two years, which can be extended for another two years on the basis of adequate justifications. It generally takes about 3 to 4 years for an industrial licence to fructify. As such, it is too early to indicate whether the progress of implementation of industrial licences issued during 1977-78 is satisfactory or not.

वैकल्पिक परमाणु ईंधन के लिये परीक्षणी जर्मनी तथा फ्रांस से बातचीत

2217. श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैकल्पिक परमाणु ईंधन के लिये परीक्षणी जर्मनी तथा फ्रांस से बातचीत करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके कमलवस्त्र तारापुर के लिये आवश्यक प्रकीर्षित यूरेनियम की समस्या हल हो सकती है ?

प्रश्नकर्ता (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) की, नहीं। तारापुर परमाणु विद्युतघर के लिए वैकल्पिक जोड़ों से समूह सुरक्षित होने का प्रश्न सहयोग-कारर के मन होने की स्थिति में ही उठ सकता है।

Per Capita Expenditure

2218. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) what has been per capita expenditure in the country during the past Five Year Plans;

(b) what per capita expenditure is likely to be spent in the Sixth Five Year Plan of the country; and

(c) how much growth rate is expected during the Sixth Five Year Plan?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Member is presumably referring to public sector plan outlays. The per capita expenditure on this account in the past Five Year Plans was as under:

	Rs.
First Five Year Plan . . .	51.99
Second Five Year Plan . . .	112.31
Third Five Year Plan . . .	184.85
Annual Plans 1966-69 . . .	130.93
Fourth Five Year Plan . . .	285.33
Fifth Five Year Plan (anticipated expenditure 1974-78)	460.18

(b) The per capita outlay in the public sector proposed in the draft Five Year Plan 1978-83 works out to Rs. 1005.55.

(c) The growth rate expected during the Sixth Five Year Plan is 4.7 per cent per annum.

Paper Project in North Tripura

2219. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has turned down the proposal for the paper plant to be set up in North

Tripura on the ground that this would cause the State plan to suffer a lot; but has agreed to examine the scheme for inclusion of the paper project in the Central plan with enhanced outlay and greater viability;

(b) if so, proposed enhanced dimensions of the project to be included in the Central plan and decision taken thereon; and

(c) whether any foreign aid is contemplated for this project, if so, the details of the offers received in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (c) No final view on the proposal of the Tripura Government to set up a pulp/paper project has been taken so far. Till recently, the project was being considered largely as an export oriented project for which the possibilities of obtaining external assistance were also being explored. However, the prospects of exports and linked financing from an external agency for the project appear to be rather poor. The scope of the project has, therefore, now to be considered in relation to meeting domestic requirements. In this connection studies relating to viability, size, mode of financing, etc., would need to be undertaken. These are under consideration.

Selection of Candidates by UPSC

2220 SHRI A. MURUGESAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many candidates were selected during the last 5 calendar years and upto January 1979 by Union Public Service Commission and if so, State-wise, Cadre-wise and year-wise details;

(b) how many Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates were among them, and how many among them have been selected as per relaxed standards, and how many SC/ST candidates have been selected against general quota;

(a) how many SC/ST candidates possessing high qualifications and academic career have been selected against reserved quota instead of open quota; and

(d) how many departmental officers have been given relaxation from the respective Recruitment Rules and if so, State-wise and Department-wise details during the last 5 years and how many SC/ST are among them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) and (b). The available information, which relates to financial years, is annexed. The information is not maintained for calendar years, nor are State-wise and Cadre-wise particulars available.

For posts reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, candidates

are required to be assessed by relaxed standards and this procedure is followed. No information is maintained in the UPSC's office about the number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates selected against unreserved posts.

(c) The Union Public Service Commission has not compiled information in terms of candidates possessing 'high qualifications and academic career', as these are relative terms.

(d) In as far as filling of posts by promotion from lower grades is concerned, relaxation of the provisions of the Recruitment Rules in regard to promotion cases is generally either with reference to the length of service or the educational qualifications, if any, prescribed in the rules. Information about officers recommended for promotion in relaxation of the Recruitment Rules is not being maintained.

ANNEXURE

Period	No. of candidates recommended by the UPSC on the basis of Examination				No. of candidates recommended on the basis of interview and selection			
	General Candidates	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Total	General Candidates	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Total
1973-74	2436	218	58	2706	2144	230	38	2412
1974-75	2595	232	73	2900	2570	310	76	2956
1975-76	1836	218	43	2097	1699	292	70	2066
1976-77	3315	436	88	3839	1754	327	85	2166
1977-78	3387	297	70	3754	1514	214	69	1797

Confirmation of Officials

2221. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there are cases of administrative delay in confirming officials in absence though they have

completed the required number of service for confirmation; and

(b) what steps Government propose to take to remove the anomaly of clause 'In absence'?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW,

JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) The cases of confirmation are considered by the respective appointing authorities/cadre controlling authorities. According to the present policy the officers who are away on deputation or foreign service are considered and approved for confirmation *in absentia*, but the actual orders of confirmation are issued only on their reversion to their parent cadre/post, etc.

(b) The present orders regarding confirmation *in absentia* are being reviewed.

Reservation Quota for S.C./S.T. for Promotion of Gr.-II Officers in Delhi Administration

2222, SHRI MAHILAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) criteria now adopted by Delhi Administration for promotion of Grade-II (Executive) officers to the rank of Grade-I (Executive) posts;

(b) total number of persons promoted to Grade-I (Executive) during

(b): Year Persons Promoted to Grade-I (Executive) (including on *ad hoc* basis).

the last three years, year-wise; and the number of SC/ST out of them;

(c) total number of grade-II (Executive) and number of SC/ST out of them; and

(d) whether quota reserved for SC/ST is complete in both the grades of posts if not, the reasons for the backlog and when it will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): Information furnished by Delhi Administration is given below:—

(a) Grade-II (Executive) Officers are promoted to the rank of Grade-I (Executive) posts in accordance with the provisions laid down in Rule 6 of Delhi Administration Subordinate Services Rules, 1967.

	General Category	Sch. Caste	Sch. Tribe	Total
1976	19	..	..	19
1977	..	..	..	..
1978	12	..	..	12

(c) Number of Grade-II (Executive) officials (including officials working on *ad-hoc* basis)

General Category	Sch. Caste	Sch. Tribe	Total
513	41	..	554

(d): There is a back-log of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Grade-I (Executive). The vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes could not be filled during 1976-1977 and 1978 as there was only one Scheduled Caste candidate in the zone of consideration adopted by the Departmental Promotion Committee and since departmental proceedings were pending against him, the recommendations of the Departmental Promotion Committee were placed in a sealed cover in his case. There was no Scheduled Tribe candidate within the zone of consideration. No vacancy reserved for Scheduled Tribe could, therefore, be filled.

✓ Efforts are being made to complete the back-log in respect of Scheduled Caste officials in the matter of recruitment to Grade-II (Executive) by direct recruitment and by departmental competitive examination. As regards Scheduled Tribe officials efforts are being made to complete the back-log in matter of recruitment to Grade-II (Executive) by direct recruitment.

For promotion to Grade-I (Executive), Grade-II (Executive) is a feeder service.

आदिवासी क्षेत्रों का विकास

2223. श्री राधक जी : क्या गृह मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे कि :

विवरण 1

राज्यवार अनुसूचित जनजातियों की संख्या

[अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार संशोधित आरक्ष की जनगणना, 1971 के अनुसार]

जनसंख्या लाखों में

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	435.03	22.26	5.12
2	असम	146.25	16.07	10.99

(क) विविध राज्यों की पुष्क-पुष्क कुल जनसंख्या कितनी है और उसमें से आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है तथा यह कितने प्रतिशत है;

(ख) प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा, सड़कों, बिजली, औद्योगिक तथा अन्य सुविधाओं का समुचित विकास और प्रसार सुनिश्चित करने तथा आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं; और

(ग) उसमें कितनी सफलता मिली ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सूचना का व्योरा विवरण - 1 में दिया गया है ।

(ख) 50 प्रतिशत तथा अधिक आदिवासी आबादी के क्षेत्रों के लिए उपयोगाएँ तैयार कर ली गई है । इन जनजाति उपयोगाओं को 180 समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है तथा शिक्षा, सड़कें, बिजली सुविधाएँ आदि के मामले में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परियोजना के लिए असम-असम कार्यक्रम तैयार किये गये हैं । जनजाति उप योजना के लिये राज्य योजना से धनराशि की मात्रा प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है और यह राशि अपवर्तनीय नहीं है । केन्द्रीय सरकार जनजाति उपयोगा के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता देती है । मध्यम अवधि योजना 1978-83 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि 350 करोड़ रुपये होगी ।

(ग) जनजाति उप योजना क्षेत्रों के निवेश में वर्ष दर वर्ष प्रगतिशील प्रगति हुई है जो अनुसूचक-II से देखी जा सकती है ।

1	2	3	4	5
3	बिहार	563.53	49.33	8.75
4	गुजरात	266.97	37.57	14.07
5	हरियाणा	190.37	—	—
6	हिमाचल प्रदेश	34.60	1.42	4.10
7	जम्मू तथा कश्मीर	46.17	—	—
8	कर्नाटक	292.99	2.62	0.89
9	केरल	213.47	1.93	0.90
10	मध्य प्रदेश	416.57	98.15	23.56
11	महाराष्ट्र	504.12	38.41	7.62
12	मणिपुर	10.73	3.34	31.13
13	मेघालय	10.12	8.14	80.43
14	नागालैण्ड	5.16	4.58	88.76
15	उड़ीसा	219.45	50.75	23.13
16	पंजाब	135.51	—	—
17	राजस्थान	257.66	31.35	12.17
18	सिक्किम	2.10	0.52	24.6
19	तमिलनाडु	412.00	4.50	1.09
20	त्रिपुरा	15.56	4.51	28.99
21	उत्तर प्रदेश	883.41	1.99	0.23
22	पश्चिम बंगाल	443.12	26.03	5.87
23	अण्डमान व निकोबार	1.5	0.18	15.65
24	अरुणाचल प्रदेश	4.68	3.69	78.85
25	अरुणाचल प्रदेश	2.57	—	—
26	दादरा और नगर हवेली	0.74	0.64	86.49
27	दिल्ली	40.66	—	—
28	गोवा, दमन और दीव	8.58	0.07	0.82
29	लक्षद्वीप	0.32	0.30	93.75
30	मिजोरम	3.32	3.13	94.28
31	पाण्डिचेरी	4.72	—	—
	भारत	5481.69	411.48	7.36

संयुक्त सभा — II

(इसके करोड़ों में)

	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
राज्य योजनाओं से अवरसित	109.11	191.78	257.22	344.12
विशेष केन्द्रीय सहायता	20.00	40.00	55.00	70.00
जोड़	129.11	231.78	312.22	414.12

Alleged Mismanagement and Corruption in Delhi Small Industries Development Corporation

2224. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:
SHRI PRADYUMNA BAL:
CHAUDHURY BRAHM PRAKASH:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the demand of the employees of the Delhi Small Industries Development Corporation for an inquiry into the alleged mismanagement and mis-appropriation of the Corporation's finances which run into lakhs of rupees and an inquiry against the erring officers of the Corporation; and

(b) the reaction of Government towards this and the action taken so far and proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDEEP PRASAD YADAV): (a): Yes, Sir.

(b) Enquiries are being made by the Central Bureau of Investigation, the

Anti-corruption Department of Delhi Administration and the Vigilance Department of Delhi Small Industries Development Corporation into cases of alleged irregularities and mismanagement. Some of the enquiries have reached advanced stage. It has also been decided to set up a special cell comprising of Police officials and officers of the Delhi Administration to look into all cases in which the Corporation has suffered losses.

Growth Rate Achieved by Karnataka

2225. SHRI S. B. PATIL: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Dr. J. D. Sethi, member of the Planning Commission made a particular note of the facts that Karnataka has registered the highest growth rate and social justice pertaining to Janata having scheme etc. in the country surpassing even progressive State like Punjab; and

(b) if so, what are the basis for his observations regarding the above and what is latest economic survey regarding the percentage of growth of each State?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) (a) and (b): The Member of the Planning Commission

said in a Press Conference on 17th December, 1978 that the State officials had told him that Karnataka had for 1977-78 one of the highest growth rates in the country and if so it was a matter of great satisfaction. There is no index of social justice and hence the question of making such a statement did not arise. What the Member further said in that Press Conference was that the State has shown good progress in the field of social services sector.

राजस्थान में सिंचाई योजनाओं में सिलेक्ट की कमी

2226. श्री मीठालाल पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि राजस्थान को बीप्र ही सीमेंट सप्लाई नहीं किया गया तो उक्त राज्य में लगभग घाट करोड़ रुपए से अधिक परिश्रम वाली विभिन्न मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य ठप्प हो जाएगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इन निर्माण कार्यों के लिए अब तक कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया गया है और सीमेंट की भरोसेवर सप्लाई कब तक किये जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रताप शास्त्री) : (क) और (ख). विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता का अनुमान कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है और इन परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा सिफारिश की सीमेंट की पूरी मात्रा सीमेंट नियंत्रक द्वारा दी गई है। राजस्थान में कमांड एरिया डेवलपमेंट व छोटे सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई परियोजनाओं के लिए कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा किए गए आबंटन निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	प्रवधि	सीमेंट की मात्रा
		की. टन.
1	जनवरी—मार्च, 1979	64,000
2	अप्रैल—जून, 1979	92,000

Strength of Central Para-Military Forces

2227. SHRI RAJE VISHVESHWAR RAO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) present strength of BSF, ITBP, CRP, PAC, SIB and other allied forces; and

(b) the annual outlays and expenditure of each of these forces during the last three years, year-wise separately?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) (a):

The present strength is as follows:

B.S.F.	84762
ITBP	13578
CRPF	73712

Assam Rifles is also allied para-military force. The strength is 36753.

PAC is a State armed Police force. As such, details about the strength, outlay and expenditure are not available.

Strength of I.B. is 11,718.

(b) The annual outlay and expenditure on each of these forces during the last three years year-wise is shown in the statement.

Statement

(Rs. in thousands)

Name of the Organisation	Present B.E. strength 76-77	Actual Expend. 76-77	B.E. 77-78	Actual Expend. 1977-78 (Provisional)	B.E. 78-79	R.E. 78-79
1. Central Reserve Police Force	79712	53, 17,58	54,82,40	56,29,61	57,73,76	56,77,55
2. Border Security Force	8476	25, 78,61	69,81,69	70,76,71	71,90,15	73,95,82
3. Indo-Tibetan Border Police	13578	12,22,82	12,21,70	12,95,51	11,95,32	12,96,98
4. Assam Rifles	36753	2724.57	33,34.74	29,12,11	32,75.43	34,37.99
5. Intelligence Bureau	117181	11,87.45	12,53.04	12,40,11	12,86.48	13,54.01
						13,80,78

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा
रियायत का उपयोग किया जाता

2228. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या गृह
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974-77 के चार वर्षों के समूह (ब्लाक)
के लिए 31 दिसम्बर, 1978 तक छुट्टी यात्रा रियायत
का उपयोग करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों
की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को छुट्टी यात्रा रियायत के
दुरुपयोग करने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसका राज्यवार व्यौरा क्या
है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अधिष्ठा में छुट्टी यात्रा रियायत (एन०
टी०सी०) का दुरुपयोग न हो, इसे सुनिश्चित करने
के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश/निदेश
क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कानून कार्य
मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० डी० शर्मा) :
(क) छुट्टी यात्रा रियायत के शर्तों को,
वेब नर में केबे हुए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों
में, यात्रा भत्तों के बिलों को पास करने के लिए प्राधि-
कृत अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है।
इस प्रकार, धाकड़ें कार्मिक और प्रशासनिक सुचारु
विभाग द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा
सामान्य रूप से, छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधाओं के
दुरुपयोग की कोई शिकायत कार्मिक और प्रशासनिक
सुचारु विभाग की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को अधिक सहायता देने के लिए गाइडलिन फार्मूले
में परिवर्तन

2229. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या योजना
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य को योजनाओं के विकास के
लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
गाइडलिन फार्मूले में पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन राज्यों को विकसित
राज्यों की तुलना में, जनकी प्रति व्यक्ति आय औसतन
राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से कम है, तुलनात्मक रूप से
अधिक धनराशि देने के लिए कोई नई कसौटी निर्धारित
की गई है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जा सके;
और

(ग) यदि हाँ, तो फार्मूले का व्यौरा क्या है और
पिछड़े अविकसित राज्यों को उनके पिछड़ेपन और
उनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम होने
के आधार पर धनराशि की प्रतिभत्ता में कितनी
वृद्धि की जायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से
(ग) : राष्ट्रीय विकास परिषद् की 24 और 25
फरवरी, 1979 की हुई बैठक में यह निर्णय किया गया
कि विशेष समस्याओं से संबंधित नापवड के धनाढ्य
गाइडलिन फार्मूले में निर्धारित किए गए विविध माप-
दंडों के आधार पर चलने वाले चार वर्षों के लिए राज्य
योजनाओं के लिए उपलब्ध कुल केन्द्रीय सहायता में से
1800 करोड़ रुपए विशेष क्षेत्रों के राज्यों के लिए
आरक्षित रखे जाने चाहिए, 600 करोड़ रुपए राज्यों की
विशेष समस्याओं के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए
और 4200 करोड़ रुपए विशेष क्षेत्रों से इतर 14
राज्यों के बीच में वितरित किए जाने चाहिए। इनके
अलावा यह भी निर्णय किया गया कि केन्द्रीय प्रा-
योचित स्कीमों में कुल प्रायोजनों को करके चलने वाले
वर्षों में ही जाने वाली 2000 करोड़ रुपए की राशि
को हरेक राज्य की आय समायोजित कुल जनसंख्या

(बा.ब.क.ब.) के माध्यम पर, घरायश-सहायता द्वारा युक्ति राज्य की प्रति व्यक्ति आय के विशेष के माध्यम पर, विशेष भेजी से इतर 14 राज्यों के बीच में वितरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए, उत्तर-पूर्व परिषद के कार्यक्रम के लिए और विशेषी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

गावगल फार्मूले के अंतर्गत, सहायता का एक भाग (राष्ट्रीय शीत से नीचे प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को) प्रति व्यक्ति आय के माध्यम पर और राज्यों की विशेष समस्याओं के माध्यम पर दिया जाता है। इस व्यवस्था से अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों को लाभ होता है। पहले चार वर्षों में 2000 करोड़ रु. के वितरण के लिए आय समायोजित कुल जनसंख्या के फार्मूले को प्रयुक्त करने से कई कम विकसित राज्यों को अधिक लाभ पहुंचेगा।

Use of Scientific and Industrial Research Institutions for Research Projects

2230. SHRI EDUARDO FALEIRO: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Western Countries, particularly the U.S.A. have been using some of our scientific and industrial research institutions for "research projects" which cover wide ranging intelligence activities and this has been disclosed more than once before the American Senate Foreign Relations Committee;

(b) if so, what is the reaction of Government to this situation; and

(c) steps taken by Government in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Some complaints of this type have been brought to the notice of Government.

(b) and (c). Keeping in view information that has come to the notice of Government, and particularly in the light of past discussion in the Parliament and in the Public Accounts Committee, suitable mechanisms have been worked out for proper scrutiny and clearance of Research and Development projects carried out in Indian Scientific and Industrial Institutions involving collaboration/co-operation

with foreign Governments and Institutions so as to ensure that national security and such other aspects are not jeopardised.

Harijans deprived of Drinking Water in Delhi

2231. SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a report in *Patriot* dated the 25th January, 1979 to the effect that a number of Harijan families have been deprived of drinking water by landlords in Delhi villages;

(b) if so, whether any enquiry has been made; and

(c) the action taken against the culprits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) (a) and (b): Yes, Sir.

(c). The Delhi Administration made enquiries and found that the allegations were not substantiated.

Issue of Licences for Manufacture of Tyres and Tubes

2232. SHRI VINODBHAI B. SETH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) licences issued for the manufacture of tyres from April 1975 to December, 1978;

(b) whether Government are aware that there is likely to be acute shortage of tyres in view of large number of infructuous licences issued; and

(c) what steps Government propose to take to check shortage of tyres and tubes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) A statement is attached.

(b) and (c). At present the annual installed capacity for the manufacture of tyres excluding moped and bicycles tyres in the organised sector is 79.29 lakh nos. whereas the production during the year 1978 has been 69,68,627 nos.

the requirements of automotive tyres by 1982-83 are estimated to be 116.86 lakh nos. To produce 116.86 lakh nos. of tyres at 90 per cent efficiency, an installed capacity of 129.84 nos. of tyres is required by 1982-83.

It is expected that by 1979-80 additional capacity of 19.6 lakh nos. of

automotive tyres will be implemented. The cumulative capacity likely to be available by 1979-80 and 1982-83 will be 98.89 lakh numbers and 112.79 lakh numbers respectively. Even with the implementation of the additional capacity which has been already approved, the gap in installed capacity and the capacity required to meet the demand for tyres and tubes by 1982-83 is likely to be 17.05 lakh numbers. With a view to bridging the gap between demand and the supply, additional capacity is proposed to be created by allowing substantial expansion of the available capacity to the existing units.

Statement

Details of industrial Approvals for Tyres and Tubes issued from April, 1975 to December, 1978.

S.No.	Name of the party and location	Type of approval and date	Annual capacity and type of tyres and tube approved
2		3	4
1.	M/s. Webstar, Burdwan	Industrial Licence dated 23-7-75.	4.00 lakh tons of automotive tyres and tubes.
2.	M/s. Orissa Tyres Ltd., Bhubaneshwar .	Industrial licence dated 26-7-75.	Do.
3.	M/s. APATT, Guntur	Industrial Licence dated 23-7-75.	Do.
4.	M/s. Gujarat Tyres, Baroch	Industrial Licence dated 23-7-75.	Do.
5.	M/s. Punjab Tyres Ltd., Chandigarh .	Industrial Licence dated 23-7-75.	Do.
6.	M/s. MRF, Goa	Industrial Licence dated 1-10-75 for substantial Expansion.	Do.
7.	M/s. Ceat Tyres of India, Bomoay . .	Industrial Licence for substantial expansion dated 9-6-76.	1.60 lakh nos. of automotive tyres and tubes.
8.	M/s. U.P. Scooter Ltd., Raibareilly .	Industrial Licence 19-3-77.	5.00 lakh nos. of scooter tyres.
The following units are registered with D.G.T.D.			
1.	M/s. Sainik Tyres, Jind (Haryana) . .	DGTD Registration dated 16-6-77.	1.20 lakh nos. of scooter and motorcycle tyres.

1	2	3	4
2.	M/s. Ajanta Rubber, Bharoch	DGTD Registration dated 23-12-78.	0.84 lakh nos. of scooter and motor cycle tyres.
3.	M/s. Falcon Tyres Ltd., Mysore	DGTD Registration dated 26-12-78.	4.00 lakh nos of automotive tyres and tubes

Increased Allocation for Hilly and Backward States

2233. SHRI RAJ KESAR SINGH: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Chief Ministers of Hill States have demanded increased allocation for the Hilly and backward states from the outlay of the sixth plan during the meeting of NDC held in the 3rd week of January, 1979; and

(b) if so, reaction of Government thereto?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). At the meeting of the NDC on 24th and 25th February which followed the meeting of the Committee of the N.D.C. held in January, 1979 it was decided that out of the total Central assistance available for State plans for the next four years, Rs. 1800 crores should be reserved for special category States, and Rs. 600 crores for special problems of States, and Rs. 4200 crores should be distributed among the 14 non-special category States on the basis of the Gadgil formula. Besides, and amount of Rs. 2000 crores is to be released over the next four years through certain modifications in the Centrally sponsored schemes and distributed among the 14 non-special category States on the basis of income adjusted population of each State (IATP), i.e. the inverse of per capita income of State multiplied by population. Besides, additional Central assistance is to be given for Hill and Tribal areas and the programme of the North-Eastern Council.

Meeting of Chairman of I.A.E.A., Vienna with P. M.

2234. SHRI D. D. DESAI: SHRI DHIRENDRA NATH BASU:

Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Chairman of the International Atomic Energy Agency, Vienna met the Prime Minister recently;

(b) if so, whether he expressed his reservations about chairing the joint scientists committee to examine full-scope safeguards; and

(c) if so, whether the committee will still be set up?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) The Director-General of the IAEA promised to give his decision after considering the matter further.

(c) Does not arise.

Introduction of Bill re. Declaration of Assets by M.P.s. & Ministers

2235. SHRI SHYAM SUNDER GUPTA:

DR. BIJOY MONDAL: SHRI PIUS TIRKEY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the present position of the proposed legislation to make it obligatory for all the Members of Parliament including Ministers to declare their assets, liabilities and business interests;

(b) whether the proposal has been dropped; if so, the reasons therefor; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, the time by which a Bill on the subject is likely to be introduced in Parliament?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c) It has been decided that the specific issues in the proposed legislation may be discussed with the Leaders of the Opposition Parties in Parliament before it is finalised. The Government have since initiated the process of holding such consultations.

Attempt on the Life of Former Home Minister

2236. **SHRI MANOHAR LAL:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an attempt on the life of Chaudhry Charan Singh, Deputy Prime Minister and Minister of Finance was made by a youth;

(b) if so, the full details thereof and action taken by Government in the matter; and

(c) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) On 24th December 1978, at 11.45 A.M., when Shri Charan Singh was busy meeting members of the public on the laws on his house one Jai Narain belonging to West Champaran District, Bihar took out an iron spear-shaped sharp weapon without handle measuring about 24.3 Cms. from his bag and charged at Shri Charan Singh pointing the weapon towards his abdomen and uttering threats. Before the culprit could cause any physical harm to Shri Charan Singh he was overpowered and taken to police Station

Tughlak Road where a case FIR No. 849 dated 24th December 1978 u/s 452/506/397 IPC and Sections 25 and 27 of the Arms Act was registered. The investigation of the case was handed over to the C.B.I. The investigation is progressing. The accused is in judicial custody.

Objection Re: Gradation and Promotion List of I.A.S. Officers

2237. **SHRI G. S. REDDY:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any IAS officer of Andhra Cadre of 1956 has raised an objection about gradation and promotion list of IAS officers;

(b) if so, whether any litigation occurred in this connection;

(c) whether the order of the appropriate High Court in this matter was given effect to;

(d) if not, reasons for delay; and

(e) when will the order be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) An IAS officer of the Andhra Pradesh cadre has represented that a review of the Select Lists earlier prepared for promotion of State Civil Service officers to I.A.S. be made for the purpose of fixation of his seniority.

(b) to (e) Consequent upon the direction of the Andhra Pradesh High Court in Civil Writ Appeal No. 258 and 284 of 1972 decided on the 18th April, 1973, a review of promotions to the categories of Deputy Collectors, Special Deputy Collectors and selection grade Deputy Collectors was made and finalised in October, 1975. Thereafter, on the basis of the finalised gradation

list of State Civil Service officers. It was decided to review promotions of State Civil Service officers to the I.A.S. Certain information was called for from the State Government on the basis of which the review has been completed by this Department and the matter is now under consideration in consultation with the Union Public Service Commission. A final decision is likely to be taken shortly.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा सम्मोचित रेली

2238. श्री राज नारायण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अप्रैल मास के समय में 31 जनवरी, 1979 को दिल्ली में एक विशाल रेली का आयोजन किया था, और

(ख) यदि हा, तो सरकार ने उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कानून कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० वाटल) :

(क) कुछ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा 30 जनवरी, 1979 को बोट क्लब मैदान में दोपहर के भोजन के समय एक बैठक की गई बताया जाता है।

(ख) औपचारिक रूप में कोई मांग पत्र सरकार की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशों के सरकारी दौरों के दौरान उच्चरी विधे गये उपहार

2239. श्री प्रभुलाल सिंह कौरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विदेशों के सरकारी दौरों के दौरान गत 2 वर्षों में उक्त देशों की सरकारी अथवा सगठनों के द्वारा उनको विधे गये उपहारों का व्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें से कितने उपहार सरकारी खजाने में जमा कराये गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल कानून) : (क) और (ख) उपहारों की प्राप्ति और निपटारा विदेशी अधिवाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 8 के अन्तर्गत (घ) के अनुसरण में कराए गए हैं। विदेशी अधिवाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 और विदेशी अधिवाय (दोनों या कानून) की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियमन 1978 द्वारा नियमित किया जाता है। विदेशी विनिष्ठा अधिनियमों के केन्द्रीय मंत्रियों को प्राप्त उपहारों और उनके निपटार के संबंध में व्यौरा देना जोर दिया है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत जो प्रशासकीय होने की संभावना है।

नौकरियों की समस्याएँ

2242. श्री सुखदेव : क्या मंत्री इस बातों की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम जनता को नियमित मूल्यों पर छोटा कपड़ा कपड़ा करने की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के उन बरीब बोधी को बोधी, साड़ी आदि कपड़ा उपलब्ध करने का है जो मरीची की रेखा से नीचे निर्बाह कर रहे हैं;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान इन दोनों किस्मों के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि हुई है और यदि हा, तो उनमें औसतन कितनी वृद्धि हुई, और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से भाग (ग) तक का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो छोटे तथा सीमान्त किसानों और कुचि और औद्योगिक धर्मियों को नियमित कपड़ा कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा और यदि यह कपड़ा उन्हें सप्लाई करने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (घ) नियमित कपड़े के नाम से जाने वाले धोती, साड़िया लट्टा (लांग क्लाय) कमीज का कपड़ा तथा फुल नामक ग्राम जनता के उपयोग के विभिन्न किस्म के कपड़े के सभरण की योजना चलती रहेगी। पिछले दो वर्षों में नियमित कपड़े के मूल्यों में उपभोक्ता-स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों का जनसंख्या के प्रतिव्यक्ति आधार पर अनुपातिक मासिक धाबटन किये जाते हैं और राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कपड़े के वितरण की व्यवस्था और व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। फिर भी, राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को मांगें बर्ती सिद्धान्त जारी कर दिये गए हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि नियमित कपड़ा व्यक्तियों के उन कमजोर बर्तों के उन व्यक्तियों तक पहुंच सके जिनके लिए यह बनाया गया है। उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसान भी शामिल हैं।

Rayon Industry

2243. SHRI SUKHDEO PRASAD VARMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the Rayon industry in the country is facing serious dislocation due to the shortage of one of the main raw materials sulphur; and

(b) if so, the immediate necessary steps Government proposed to take for the regular supply of sulphur?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b) Rayon Industry is one of the industries which would be affected by shortage of Sulphur for its Chemical Plants. As against 1.10 lakhs tonnes of Sulphur for 1977-78, only 0.88 lakhs tonnes of sulphur have been supplied to Rayon industry from April to December, 1978. A further 0.35 lakhs tonnes of sulphur is expected to be supplied during January to March, 1979. It is expected that with this supply full requirement of sulphur of the Rayon Industry will be met.

2. Sulphur is imported through MMTC. Due to political disturbances in Iran, supply of sulphur from Iran has stopped. Iraq and Poland have also not been able to supply sulphur against the contracted quantities. As such since November, 1978 a shortage has developed MMTC is seized of the problem and is taking steps to ensure deliveries of sulphur from Poland, Iraq and USSR.

Recommendations of Committee on Growth of T.V. Industry

2244. **SHRI K. T. KOSALRAM:** Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) the principal recommendations made by the Committee which studied the handicaps in the growth of T.V. Industry; and

(b) the action taken by Government on them?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No such Committee has been set up. A Committee has however been appointed to review the development of Electronics in India.

(b) Does not arise.

Shortage of Coal faced by Industrial Units, Textile Mills and Factories in Ahmedabad

2245. **PROF. P. G. MAVALANKAR:**

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that industrial units, textile mills and several other factories in Ahmedabad and other places in Gujarat are often finding very acute shortages of coal;

(b) if so, what steps both short term and long term are being taken to remedy the said situation;

(c) whether Government are co-ordinating the operations in this regard, particularly between the Ministry of Railways and his own; and

(d) if so, how and with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b) Quite a few industrial units in Gujarat are experiencing shortage of coal and representations have been received from the affected units. The following steps have been/are being taken to remedy the situation:—

Short-term steps:

(i) Industrial units affected by shortage of coal and having dual firing system (coal and oil) have been given the option to use fuel oil to meet the short-fall in coal supply;

(ii) Coal production has increased from the level of 320,000 tonnes/day in October 78 to 370,000 tonnes/day in February 79 and this tempo of increased production would continue during 1979-80;

(iii) Facilities have been offered to consumers experiencing shortage to move coal by road.

Long-term steps:

(i) Steps have been taken for higher production out of the existing mines and by opening up new mines;

(ii) Infrastructure is being added/enlarged/modified for higher and quicker loading of coal at pit-heads;

(iii) Railways are actively examining the steps through which line capacity could be improved for meeting increased demand for movement of coal.

(c) Frequent consultations are being held between officials of Department of Coal, Ministry of Railways and coal consuming departments for finding out how best and to what maximum extent coal demand of consumers could be met.

(d) Coal movement which was 8283 wagons/day in October, 78 has been increased to about 9850 wagons/day in February 79 and indications are that this is likely to be further improved in the coming months. There has been substantial higher movement of coal by road.

Indo-US Workshop on Oceanography held in Goa

2246. SHRI MUKUNDA MONDAL: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that an Indo-US Workshop on Oceanography was held in Goa in November, 1978;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) what is the attitude of the Government in regard thereto?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The US Workshop was held at the National Institute of Oceanography, Goa, for 13th to 17th November, 1978. It was attended by fifteen US and thirtyseven Indian participants.

The Workshop was organised on the basis of a decision taken at the 3rd (June 1977) meeting of the Indo-US Sub-Commission on Science and Technology with the objective of working out possible areas and projects for joint research in oceanography. Research proposals evolved as a result of discussions at the Workshop are being examined.

People living below poverty line

2247. SHRI UGHAN SINGH THIAKUR;
SHRI SUBHASH AHUJA,
SHRI D. AMAT.
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA;

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for bringing the people living below poverty line at par with common citizens;

(b) whether cooperation from States has also been sought in this regard; and

(c) if so, the outline thereof and the number of the people living below poverty line in the country at present and after the implementation of the scheme?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The whole strategy of development adopted in the Draft Five Year Plan 1978-83 is directed towards eradication of poverty and removal of unemployment within a time frame of about 10 years and schemes have been drawn up accordingly.

(b) The Draft Plan was broadly endorsed by the National Development Council, which represents State Governments also, in March, 1978.

(c) Various measures and programmes for achieving the objective of removal of poverty are spelt out in the Plan document. The highest priority has been accorded to agriculture and allied sectors, irrigation and village and cottage industries which have the greatest capacity to absorb surplus labour. An expanded Minimum Needs Programme has also been provided for so that the living standards of the poor people can be directly supplemented by the provision of certain minimum basic amenities.

The number of people living below poverty line in the country in 1977-78 is estimated to be about 290 million. It is hoped that production planning will progressively provide for a consumption pattern which tends to abolish poverty altogether by the early 90s.

Change of options by employees of Cement Controller's Office

2248 SHRI R. N. RAKESH Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the staff working in the Cement Controller's Office were asked for their options on becoming this office as a Non-participating attached office of the Ministry of Industry;

(b) whether some options have been changed later on; and

(c) when options once made cannot be changed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) One person, who first opted for absorption in the Cement Controller's Office, changed his position and request for reversion to his parent Department. His request was accepted before he was relieved. He was allowed to continue in the Cement Controller's Office as per his final option.

(c) Yes, Sir.

सयुक्त उद्योगों तथा जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना विशेषकर मध्य प्रदेश में

2249. श्री लक्ष्मी नारायण नायक :
श्री सुबोध सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताना की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1971 में संसद में उन के द्वारा सभा पटल पर रखी गई औद्योगिक नीति में किये गये वायदे के अनुसार गुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना में अब तक कितना सफलता प्राप्त हुई है,

(ख) मध्य प्रदेश में ये केन्द्र किन-किन जिलों में चालू बंधे हैं, और

(ग) मध्य प्रदेश द्वारा उक्त (मन्त्री) द्वारा किये गये उक्त पत्र पर क्या नये-नए कार्य शुरू किए गए हैं जिसमें क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू द्वारा आरम्भ होने वाले निरालने कृषि - मंदिर द्वारा रखी गयी मध्य की छठ मंजी के लिए औद्योगिक लाई । न की प्रक्रिया चल रहा है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (ग) सरकार ने प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में 22 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये हैं। इस प्रकार जिला उद्योग केन्द्र वायव्य मध्य प्रदेश में 23 अतिरिक्त जिला उद्योग स्थापित किये गए हैं। राज्य सरकार ने कमचारियों की भर्ती, कार्यालय आवास, भवन, तथा जिला उद्योग केन्द्रों की क्षमताओं का प्रयासोजन संबंधी प्रारंभिक कार्य पूरे कर लिए हैं। प्रारंभ में स्वीकृत 22 जिला उद्योग केन्द्रों में 366.44 लाख रु० के पूंजीगत निवेश से 4156 मनुष्यको की स्थापना की जा चुकी है जिनमें 31-12-78 तक 100,071 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश में स्वीकृत किए गए 45 जिला उद्योग केन्द्रों की एक विवरण संलग्न है।

(ग) माननीय सदस्य महोदय को उद्योग मंत्री द्वारा 11-1-79 को सलाह दी गई है कि वे नागर पोष से तेल निकालने के लिए 10,000 रु० की रायस्वी फीस में छूट हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम दिल्ली से संपर्क करें।

विवरण

मध्य प्रदेश में जिला उत्तर केन्द्रों की सूची

1. रायगढ़
2. बिलासपुर
3. छतरपुर
4. गुना
5. भिंड
6. सरगुजा
7. मंडला
8. सिवनी
9. मरसिहपुर
10. सागर

11. बुरिया
12. मन्त्रालय
13. राजमंड
14. सीहोर
15. उज्जैन
16. छाप्पडा (पूर्वी निमार्)
17. कारागांव (पश्चिम निमार्)
18. दुर्ग
19. रायपुर
20. राजनन्दगांव
21. रीवा
22. सतना
23. इन्दौर
24. धार
25. देवास
26. जहदुस
27. साजपुर
28. रतलाम
29. रयसन
30. भोपाल
31. बिदिशा
32. बेताल
33. ग्वाल्पर
34. सिवपुरी
35. बालय
36. सिद्धी
37. टीकमगढ़
38. साहबोल
39. गुना
40. जबलपुर
41. छिन्दवाड़ा
42. दीनोद
43. बालवाट
44. बासतर
45. होसंगाबाद

Compensation for Victims of Emergency

2250. SHRI SAUGATA ROY: Will Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Shah Commission had recommended compensation for victims of emergency; and

(b) if so, the steps taken by the Government to implement the recommendation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). Yes, Sir. In its Third and Final Report submitted to Government on 6th August, 1978, the Shah Commission has recommended that;

(i) Government may extend to the victims of family planning drive such relief as is possible; and

(ii) Government should act expeditiously with a view to extending relief to persons affected by demolitions in Delhi. It has also been recommended that State Governments should look into demolition cases individually in an effort to see what steps can be taken to redress the grievances, if any, of the affected persons.

2. In the matter of giving relief to the victims of the family planning drive, the Ministry of Health and Family Welfare has taken the following steps with a view to giving relief to the acceptors of sterilization who develop post-operative complications or die as a consequence of sterilization operation:

(i) In case of post-operation complications which require further treatment whether as in-door or out-door patients, the actual amount of expenditure on the purchase of medicines, for hospitalisation and treatment as prescribed by the Medical Officer is payable in full to the acceptors.

(ii) If an acceptor of sterilisation dies as a result of sterilisation operation, an amount of Rs. 5000/- is payable to the surviving spouse or if no spouse is living, to the natural heir.

(iii) In case any person who has undergone sterilisation seeks re-canalisation, facilities may be provided free of cost. The ex-gratia payment of Rs. 5,000/- is also admissible in case of any unfortunate death as a result of re-canalisation operation.

3. In view of the vast financial implications involved no general decision with regard to the relief to the victims of the family planning drive during the period of emergency, as envisaged by the Shah Commission, could be taken.

4. The Ministry of Works and Housing/Delhi Administration have taken the following steps to implement the recommendation regarding giving relief to victims of demolitions:—

(i) The Delhi Administration has set up a Cell under the overall in-charge of Commissioner (Re-settlement) to examine cases of demolition of houses and occupation of private lands during the emergency without due process of law. Applications received in response to a public notice are under examination in this Cell.

(ii) A scheme for giving alternative plots by way of rehabilitation and compensation out of court for houses demolished has been prepared and is awaiting implementation.

(iii) 3657.48 acres of private land occupied by Government without due process of law during emergency have been identified. Out of this 3360.79 acres of land have been acquired under the Land Acquisition Act, 1894, and the remaining land will be acquired soon. Compensation for the land acquired has been assessed at Rs. 5,70,70,894.59 paise. This money has been deposited in the courts and a sum of Rs. 2,46,91,719.61 paise has already been disbursed. The remaining amount will be disbursed, according to the provisions of the Land Acquisition Act.

(iv) It has been decided to restore status quo-ante to the extent possible in respect of the colonies demolished during the emergency. The schemes for this purpose are already under execution in areas like Turkman Gate, Arjun Nagar and Krishna Nagar.

5. Further, attention of all State Governments/Union Territory Administrations was invited to the findings,

observations and recommendations of the Shah Commission and they were requested to take immediate action on the suggestion of the Commission in the matter of grant of relief to the victims of demolitions.

राजस्थान की आदिवासी उप-योजना पर किया गया व्यय

2251. श्री हीरा भाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की आदिवासी उप-योजना पर कितना व्यय किया गया है और उन जिलों के नाम क्या हैं जहाँ से इसे लागू किया गया है;

(ख) इस योजना के प्रारंभ होने से इस पर किये गये व्यय की जिलावार प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या इस योजना के लिये आवंटित की गई राशि जयपुर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में इमारतों के निर्माण पर खर्च की गई थी; यदि हाँ, तो उस पर कितने प्रतिशत राशि खर्च की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे जिलावार आदिवासी क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहाँ यह राशि खर्च की गई थी और इन क्षेत्रों की जनसंख्या कितनी है और इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की गई थी और क्या इस बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण जोड़ सभा के पटल पर रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) बांसवाड़ा, डुमरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के जिलों में आदिवासी उप-योजना के अधीन किया गया व्यय इस प्रकार है:—

(रुपए लाखों में)	
1974-75	466.26
1975-76	973.60
1976-77	1260.04
1977-78	1497.10
1978-79	790.29
(जनवरी, 1979 तक)	

(क) व्यय की विवरण प्रस्तुतता निम्नलिखित है:—

प्रतिवर्षावधि		
	1977-78	1978-79
बाँसवाड़ा .	14.93	22.80
बुधपुर .	15.88	16.50
बिस्फीड़गढ़ .	6.14	11.07
उदयपुर .	20.46	17.29
प्रशासन (जल और बिजली विकास)	42.59	32.34

(ख) बुधपुर और उदयपुर नगर बाँसवाड़ी उप-योजना क्षेत्रों के अंग नहीं हैं। इन नगरों में हमारतों के निर्माण के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

(ग) राज्य सरकार ने बताया है कि बाँसवाड़ी उप-योजना क्षेत्रों में यकनों पर राजस्व व्यय के अंशों उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु बाँसवाड़ी उप-योजना क्षेत्र में यकनों के निर्माण पर खर्च की गई कुल राशि निम्नलिखित है:—

(रुपए लाखों में)			
1974-75 .	.	.	5.39
1975-76 .	.	.	4.10
1976-77 .	.	.	8.76
1977-78 .	.	.	7.35
1978-79 .	.	.	6.25

राजस्वधान के बाँसवाड़ी उप-योजना क्षेत्रों में बिजली, तहसीलों, गांवों की संख्या और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का व्योम विवरण में दिया गया है।

विवरण 1

बिजली / तहसीलों, गांवों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का विवरण

जिला/तहसील/खण्ड		गांवों की संख्या तहसीलों की संख्या		अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या
	1	2	3	4
1. जिला बाँसवाड़ा . . .	.	1464	5	4,77,369
2. जिला बुधपुर . . .	.	836	3	3,77,489
3. जिला उदयपुर . . .	.	.	.	.
3.1 पलासिया . . .	.	256	1	55,573
3.2 खेड़वाड़ा . . .	.	234	1	85,770
3.3 कोटड़ा . . .	.	304	1	64,314
3.4 सारवा . . .	.	157	1	62,319
3.5 साजुम्बर . . .	.	213	1	49,891
3.6 लसाहिया . . .	.	248	1	71,580
3.7 गिरवा (खण्ड) . . .	.	156	1	59,892
4. जिला बिस्फीड़गढ़ . . .	.	.	.	.
4.1 प्रतापगढ़ . . .	.	530	1	78,895
5. जिला धिरोहि . . .	.	.	.	.
5.1 भाकू रोड . . .	.	83	1	32,469

Report by Minorities Commission

2252. SHRI BHAI SAHEB
THORAT:

SHRI VIJAY KUMAR N.
PATIL:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the action/decision taken by Government on the report of the Minorities Commission;

(b) the total expenditure incurred on the commission so far; and

(c) the extension, if any, proposed for completion of pending/follow-up work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) The Minorities Commission has so far submitted three reports on (i) The Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, 1978 (ii) Communal trouble in Pernambut and (iii) Communal disturbances in Aligarh (U.P.) Government have considered the report of the Commission on Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, 1978 and a copy of the report together with a memorandum explaining the decisions taken in the report of the Commission will be laid on the Table of the House.

The report on the riots in Pernambut had been sent to the Government of Tamil Nadu. The State Government have since sent their comments to the Minorities Commission, and these are under the consideration of the Commission.

Information regarding action taken on the Report of the Minorities Commission on communal disturbances in Aligarh was given in answer to Unstarred Question No. 336 answered on 21-2-1979, which is attached for ready reference.

(b) The Commission has incurred an expenditure of Rs. 5,72,679/- upto

28-2-1979. In addition, commitment has been made for an expenditure of Rs. 2,53,753/-. Thus, the total expenditure of the Commission works out to Rs. 8,26,432/-.

(c) The Minorities Commission is a permanent Commission, and, therefore, does not require any extension.

Production of Cement and study for setting up of Cement Plants

2253. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the total quantity of cement produced indigenously during 1977-78 and expected production during 1978-79; and the quantity imported against each year;

(b) whether according to the study by the Cement Research Institute the mini Cement plants are technically feasible and economically viable and that the study has spelt out certain advantages of establishing mini cement plants in the country; and

(c) what action have Government taken on the recommendations of report of the Cement Research Institute?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a)

(In lakh tonnes)

Year	Indigenous Production	Imports
1977-78	193.80	3.12
1978-79 (Estimated)	196.00	15.47

(b) Yes, Sir.

(c) On the recommendation of two Working Groups—one relating to Choice of Technology and other for fiscal incentives to be given to the entrepreneurs for setting up of mini cement plants, the Government have announced the following schemes of incentives for setting up mini cement plant with capacity not exceeding 200 tonnes per day (66,000 tonnes per annum):—

(i) The ex-works price of cement produced by the mini cement plants would be the same as the price admissible to new large sized plants viz., Rs. 296/- per tonne. This price will be assured for a period of five years from the date of going into commercial production;

(ii) Mini cement plants will be allowed a rebate the payment of excise duty upto 50 per cent for a period of five years;

(iii) While mini cement plants will be subject to price control under the Cement Control Order and shall not sell cement at a price higher than the controlled price, they will be exempted from distribution control under the cement Control Order, 1967. The mini cement plants will bear their own distribution costs and will not be required to adjust the freight element with the Cement Regulation Account. The other elements in the F.O.R. destination price of cement will, however, be subject to adjustment with the Cement Regulation Account as per the existing provisions;

(iv) Mini cement plants set up in hilly and remote areas will be eligible for additional excise duty relief and/or cash subsidy on merits;

(v) Mini cement plants will also be eligible for all other existing incentives and facilities available under the Income Tax Act and/or under other schemes offered by the State Governments.

Clearance for new Irrigation Projects in Madhya Pradesh

2254. SHRI SUKHEENDRA SINGH: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Commission has given clearance for new irrigation projects in Madhya Pradesh to be included in the Annual Plan for 1979-80;

(b) if so, details thereof; and

(c) expected expenditure to be incurred on those projects and share of Central Government therein?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (c). Some new major and medium irrigation schemes in Madhya Pradesh have been approved recently by Planning Commission, the details of which would be indicated in their Annual Budget for 1979-80

Alleged setback of Industrial Production in 1978

2255. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether industrial production got a setback during 1978 due to increasing power failures and strikes and lock-outs;

(b) if so, remedial measures being taken to step up production; and

(c) growth rate of industrial production during 1978 as compared to 1976 and 1977?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) According to the index of industrial production released by C.S.O., the rate of growth of industrial production

during January—November 1978 was 6.6 per cent as compared to 5.3 per cent and 9.8 per cent during the calendar years of 1977 and 1976 respectively.

Complaints re. harassments by Taxi and Auto-Rickshaw drivers in Delhi

2256. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of complaints received by the Delhi Police during 1978 on alleged harassment to the public by taxi and auto-rickshaw drivers;

(b) the number of mobile checks conducted by the Delhi Police during 1978 to detect faulty meters;

(c) whether Government are aware that the auto-rickshaw and taxi drivers are charging exorbitant rates from outsiders coming to Delhi by trains;

(d) whether Government are aware that the auto-rickshaw drivers refuse to take passengers to certain localities in the city in complete disregard to the traffic rules; and

(e) if so, the steps proposed to be taken by Government to curb such activities of the taxi and auto-rickshaw drivers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) 7717 such complaints were received during 1978.

(b) 1614 mobile checks were conducted to detect faulty meters.

(c) and (d). Complaints have been received from time to time in this regard.

(e) Complaint booths have been set up at selected places such as New Delhi Railway Station, Delhi Main Railway Station and the Inter State Bus Terminal and they function round the clock.

Officers of the traffic police at these booths assist passengers in getting taxis/two seater rickshaws. They also register complaints against offending drivers. The cases of habitual offenders are referred to the concerned authorities for suspension/cancellation of driving licences and permits. They are also prosecuted u/s 112 of the Motor Vehicles Act. The holder of the licence is also disqualified for a specific period. The co-operation of the representatives of the auto-rickshaw and taxi Unions have also been sought to contain this problem.

Price of Plain Glasses for Frames

2257. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that plain glasses required for use in frames have become costlier than 1977; and

(b) what are the reasons for increase in prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b). Spectacle lenses are made out of ophthalmic glass. While the prices of ophthalmic blanks manufactured by M/s. Bharat Ophthalmic Glass Ltd., have not been increased, there has been an increase in the prices of imported ophthalmic blanks due to increase in prices effected by the foreign suppliers and also on account of higher customs duty. Imports are being allowed under Open General Licence.

साजाना और अन्य कार्यों को कम कर के सीमेंट के मुख्य बुद्धि की राशि को पूरा किया जाना

2258. श्री स्वामिनारायण बर्बे: क्या उद्योग मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सीमेंट के मुख्यों में बुद्धि की गई है जिसका उपयोगकर्ताओं पर सीधा प्रभाव पड़ा है; और

(क) यदि हाँ, तो मुख्य में इस बुद्धि की राशि को समायोजित कर अन्य क्षेत्रों को कम करके पूरा न करने में क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : हाल ही में 7 दिसम्बर, 1978 से अनुसूचित मुख्य बुद्धि सीमेंट का अतिरिक्त आयात करने में शायी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने, सीमेंट कर्मचारियों की वेतन बुद्धि से सम्बन्धित विवादों के पंच-निर्णय को कार्यान्वित करने तथा सीमेंट उत्पादकों द्वारा कोचने के स्थान पर कुछेक ईंधन तेल (फरनेस आयल) का प्रयोग करने पर राजसहायता देने के लिये है। चूंकि सीमेंट का मुख्य निर्यात है, अतिरिक्त लागत को किसी और तरह से समायोजित करना संभव नहीं है।

सीमेंट के मुख्य में बुद्धि

2259. श्री सारबेन्द्र दत्त :

श्री भारत सिंह चौहान

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के मुख्य हाल ही में बढ़ाया गया है और अतिरिक्त भार सीधा उपभोक्ताओं पर पड़ गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और यह बात सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इस बुद्धि का भार उपभोक्ताओं पर न पड़े और इसका समायोजन अन्य किसी रूप में किया जाये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : हाल ही में 7 दिसम्बर, 1978 से अनुसूचित मुख्य बुद्धि, सीमेंट का आयात करने में शायी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने, सीमेंट कर्मचारियों की वेतन बुद्धि से सम्बन्धित विवादों के पंचनिर्णय को कार्यान्वित करने तथा कुछ सीमेंट उत्पादकों द्वारा कोचने के स्थान पर ईंधन तेल (फरनेस आयल) का प्रयोग करने पर राजसहायता देने के लिए है। चूंकि सीमेंट का मुख्य निर्यात है, अतिरिक्त लागत को किसी और तरह से समायोजित करना संभव नहीं है।

Automation Systems in Industries

2260. SHRI C. R. MAHATA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to implement

the automation system in industries such as metals, power, cement, machine tools, heavy engineering etc.; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). As per the recommendations of the Dandekar Committee on Automation every case for introduction of automation in an industrial establishment should be preceded by consultation with the representatives of the workers and agreement should be reached with workers on this aspect. It has also to be made sure that there is no retrenchment of employees arising out of introduction of automation and that all the interests of the existing employees including their promotional prospects are protected

Plan for the Welfare of Women

2261. SHRI CHHITUBHAI GAMIT: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Planning Commission has framed any plan for the welfare of women while allocating the money to the States, particularly in the backward and Adivasi areas; and

(b) if so, the details regarding the developmental efforts of Government in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). There are no schemes especially directed towards the welfare of women in Backward Areas and Adivasi Areas. Programmes for the welfare of women are interwoven in the various sectors of the five year plan. These programmes could broadly be classified into three groups (1) special schemes for women e.g. socio-economic programmes for women, functional literacy for adult women, Hostels for working women, Mahila Mandals, etc., (2) Composite schemes e.g. maternity and child care services, family and

child welfare projects, integrated child development services, projects and (3) general schemes, benefiting, among others, women e.g. sub-plan schemes in the tribal areas, scholarships for general and technical education, family welfare programmes etc.

Imparting Industrial Skills to Women

2262. SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Union Government are considering a plan to impart industrial skills to women;

(b) if so, what are the details of the proposed plan;

(c) whether any action for its implementation has started; and

(d) if so, in what States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (d). At present a number of schemes are being implemented by various Ministries and Departments to impart industrial skills to women. The impartional programmes which have been under implementation by the Labour Ministry, cater to women applicants also in the normal course. Under the Craftsmen Training Programme, implemented by the various State Governments through Industrial Training Institutes (ITIs), four States/UTs have set up special institutes for women trainees. These are functioning in Tamil Nadu, U.P., Chandigarh and Delhi. In the 1973-83 State Plans, besides strengthening the existing ITIs for women, three more States (Kerala, Madhya Pradesh and Orissa), propose to set up such institutes specially for women. Under the Apprenticeship Training Scheme (Labour Ministry), care is being taken to ensure a fair measure of opportunities to women.

A separate scheme for Vocational Training for Women in some specially

chosen trades has been launched under the Central Sector Plan with the assistance from the Swedish International Development Authority (SIDA), to provide basic, higher, intensive and instructor-training to women, in suitable trades, to increase their job potentials. This scheme was initiated in May 1977. It is proposed to expand it further in the 1979-80 Annual Plan. Training would be imparted in the apex institute at Delhi and at the two regional institutes set up in Bombay and Bangalore during the first phase of the scheme.

The Office of the Development Commissioner for Small Scale Industries has been conducting training programmes for women entrepreneurs in various parts of the country, through the Small Industries Service Institutes (SISIs). It is also providing active assistance to women for setting up their own enterprises. Notable work in this direction has been made by the SISIs in Madhya Pradesh, New Delhi, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, U.P., Andhra Pradesh, Kerala and Jammu and Kashmir.

A scheme for the conduct of demonstration-cum-training courses for women entrepreneurs/workers in such fields as are suitable to them has come into operation in November 1978. Proposals for conducting such courses have been received from SISIs Bangalore, Agra, Ludhiana, Trichur and Madras.

Repeal of Detention Act by States

2263. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Government has advised the State Government to repeal the detention acts;

(b) if so, the number of States which have responded; and

(c) if not, the reasons thereof?

**THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI DHANIK LAL MANDAL):**

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) State Governments are competent to frame preventive detention laws under the legislative powers available to them under the provisions of the Constitution. It is not considered desirable to interfere with the discretion of the States in this matter.

Problems faced by Handloom Industry

2264. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether handloom industry is facing a serious crisis due to the shortage and high prices of yarn;

(b) whether a large number of handloom units have been forced to close down in various States;

(c) if so, reasons for the shortage and high prices of yarn required by the handloom industry; and

(d) what steps have been taken to meet the situation?

**THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI
JAGDAMBI PRASAD YADAV):** (a) and (b). In the last two months some reports have been received from handloom pockets of some States complaining about non-availability and/or high prices of cotton yarn causing difficulties to handloom weavers. This Ministry has no report to the effect that a large number of handloom units have been forced to close down in various States.

(c) It has been ascertained from Indian Cotton Mills Federation and South Indian Millsowners' Association that production of cotton yarn in different counts has been more or less steady. There have been shortages in some particular counts of yarn in some pockets due to difficulties in distribution compounded by the recent agitation by Bank employees and their go-slow methods. The matter is kept

under constant review in consultation with Directors of Handlooms in States.

(d) Since shortage and high prices of yarn appear to be localised in certain pockets Government held discussions with representatives of the textile industry who agreed to make available immediately adequate quantities of yarn of all varieties direct to the Handloom Development Corporations/Apex Cooperatives at ex-mill prices. In fact State Governments of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal who had approached the Central Government for making necessary arrangements were assisted through establishing a direct contact with representatives of textile industry. The State of Tamil Nadu has also offered to enter into long term agreements with Uttar Pradesh for supplying yarn of finer counts.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के परिवारों की सुविधायें

2265. श्री बीलत राम सारण : क्या यह सही यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के परिवारों को बड़ी सुविधाएँ दी जाती हैं जो स्थल सेना के जवानों के परिवारों की दी जाती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके बराबर कारण है और

(ग) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की स्थल सेना के जवानों की मिलने वाली पेंशन से कम पेंशन मिलती है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्याख्या क्या है ?

युद्ध अंशालय में राज्य बंधी (और अश्विक लाल मन्जुल) : (क) और (ख) : स्थल सेना, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को दी जाने वाली सुविधायें लगभग समान हैं। किन्तु स्थल सेना के जवानों के बच्चे, इसके अतिरिक्त, बर्फी समेत स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकों का जर्बा, भोजन और निवास के हकदार हैं। अधिकांशतः और बिना बच्चों वाले विधुरों की अवस्था में स्थल सेना के जवानों के माता-पिता उनके द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन के बराबर परिवार पेंशन प्राप्त करते हैं जब कि सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की अवस्था में माता पिता शामिल पेंशन उनके द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन का 3/4 भाग प्राप्त करते हैं।

(ग) की हों, कीमत् । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल को पेंशन केन्द्रीय लिखित सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार गत 10 महीनों के दौरान प्राप्त परिवर्धनों के औसत के आधार पर दी जाती है जबकि स्वतः सेना के एक जवान की पेंशन सेना पेंशन विनियमों द्वारा नियमित की जाती है जिसमें पेंशन की मात्रा निर्धारित करते समय पद, वर्गीकरण इन्हें सेवा की अवधि समयपूर्व सेवानिवृत्ति के महत्व आदि को ध्यान में रखा जाता है।

Probe into death of Shri L. N. Misra

2266. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to hold a fresh probe into the death of Shri L. N. Misra a former Union Minister; and

(b) if so, what has necessitated Government in reopening this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Allocations for Project in Upper Kan Canal

2267. SHRI NARENDRA SINGH: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently Planning Commission has given clearance for certain irrigation projects in Madhya Pradesh in preference to the long pending demand for construction of a project in Upper Kan Canal in the Panna District of the State; and

(b) if so, reasons therefor?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). No proposal has been received so far from the Government of Madhya Pradesh relation to Upper Kan Canal in the Panna District of Madhya Pradesh.

Publication of 'Yojana' in Oriya language

2268. SHRI PRADYUMNA BAL: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the languages in which the journal entitled 'YOJANA' is being published;

(b) the reasons for its not being published in Oriya language;

(c) whether there is a proposal to publish the journal in Oriya also; and if so, from when; and

(d) if not, reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (d). 'YOJANA' is at present published in 9 major languages i.e. Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Tamil and Telugu. Publication in other languages has not been taken up, because most of the present editions are running at a loss. The question of expansion of coverage is under consideration.

Closure of a Unit of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad

2269. SHRI R. MOHANARANGAM: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one unit of the nuclear fuel complex at Hyderabad is closed because of delay in supply of enriched Uranium;

(b) the economic loss caused to the nation by the closure; and

(c) the steps proposed to see that our national effort in nuclear field is not jeopardized?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No unit of the Nuclear Fuel Complex at Hyderabad is completely closed because of delay in supply of enriched uranium. However, one Plant, viz., the Enriched Uranium Oxide Plant, is operating at only 1/5th of the normal capacity.

(b) The loss on account of underutilisation of the Enriched Uranium Oxide Plant is estimated at Rs. 1.5 lakhs per month.

(c) Necessary measures have been planned to see that the national efforts in nuclear field are not jeopardised.

Supply of Guns to Harijans to fight Atrocities on them in Bihar

2270. SHRI A. K. ROY:

SHRI C. N. VISVANATHAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the report that the Bihar Government is giving guns to the Harijans to fight atrocities; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

**THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI DHANIK LAL MANDAL):** (a)
and (b). According to the information
received from the Government of
Bihar, the proposal of giving arms to
certain Scheduled Caste families in
selected districts of the State after
giving them preliminary training is
still under their active consideration.

छोटा नागपुर का विकास

2271, श्री रीतनाथ प्रसाद वर्मा : क्या योजना नहीं यह बतानी कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोगों का मूल उद्देश्य केवल योजनाओं द्वारा प्रस्तुत की गई नई योजनाओं को मंजूरी देना ही है अथवा देश के पिछड़े क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं की अपेक्षा तैयार करना भी उसका एक कार्य है; और

(क) यदि पिछले क्षेत्रों के बहुमुखी विकास पर ज़रूरत महसूस की जा रही है तो बिहार के छोटे नागपुर विभाग के, संसाधनों के सम्पन्न होते हुए, आर्थिक पिछड़ होने से, क्या कारण हैं और इस के विकास के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री बीरारजी देसाई) : (क) विपक्ष की स्थिति सामान्य रूप से बोधना आयोग के पदार्पण से राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा तैयार की जाती है। आयोग पिछले शीलों की आवश्यकताओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देता ही है।

(ख) किसी विशिष्ट क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास एक समावृत्ति में कई उपादानों की संक्रिया का परिणाम होता है।

छोटा नागपुर क्षेत्र जिनजि संसाधनों में समृद्ध है, परन्तु वहाँ की कृषि उत्पादकता कम है। उत्तम वृक्ष रूप से जनजातों को बचाना चाहिए। जल क्षेत्र में कृषिबलित कृषि, इस्पात, रसायन और इंजीनियरी उद्योग हैं। केन्द्र ने सरकारी क्षेत्र में इनमें से कुछ उद्योगों को विकसित करने में बड़े निवेश किए हैं। तथापि, इस क्षेत्र की औद्योगिक क्षेत्रों के बाहुराष्ट्रीय धन का स्तर कम ही बना हुआ है। छोटा नागपुर में कृषि उत्पादन को बढ़ाने, और वन-मानव समुदाय, कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करने के उपाय राज्य की छठी योजना के प्राकृतिक विवरण में दिए गए हैं। राज्य सरकार ने छोटा नागपुर के लिए एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापित किया। इस क्षेत्र के विकास की व्यवस्था एक जनजातीय उपयोगिता के रूप में की गई है, जिसके लिए राज्य योजना के लिए संसाधनों की उपलब्धता में विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा सहायता की जाती है। इस क्षेत्र में प्राथमिकता और प्रगति शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण सड़कों और बिजलीकरण की ग्यूनतम प्रावश्यकताओं की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जा रहा है।

Police Firing in Pondicherry

2272 SHRI M. KALYANASUN.

DARAM:

SHRI UGRASEN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the police opened fire against the people of Pondicherry in their agitation against the Centres move to merge the Union Territories with the neighbouring States;

(b) if so, the number of people killed thereby:

(e) the number of cases filed in connection with the agitation; and

(d) the compensation given, if any, to the bereaved families?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) and (b) Yes, Sir. The Police had to open fire so as to disperse unruly mob of agitators as a result of which two persons died.

(c) One hundred and fifty one cases of rioting arson etc. have been registered in this connection.

(d) Rupees two thousand each has been paid as compensation to the two bereaved families. Besides, the widow of one of the persons killed in the firing has been appointed in Government in a suitable capacity.

Use of Chandigarh as Capital by Haryana and Punjab

2273. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that both Haryana and Punjab State Governments want Chandigarh for use as their Capital;

(b) if so, what is the attitude of the Central Government;

(c) whether Government have received any representation from either of these two Governments; and

(d) if so, the details thereof and what action has been taken by the Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) and (b). The arrangement of Chandigarh continuing to serve as the Capital of both Punjab and Haryana Governments was decided upon in 1970 to enable the Haryana Government to build its own capital. This arrangement has therefore to continue for some more time.

(c) and (d). The Punjab Government have urged early transfer of Chandigarh. There have been differences between the two State Governments in regard to the matters arising out of the Central Government's decisions announced in 1970. These differences can be resolved only on the basis of mutually acceptable arrangements. The Central Government would extend all assistance and guidance to enable them to arrive at such solutions.

Production of Industrial Explosives

2274. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the present production of industrial explosives in the country vis-à-vis their requirements;

(b) the names of the producing firms and what are their installed and utilized capacities; and

(c) whether it is a fact that some explosive manufacturing companies have recently been given permission for expansion and some new joint venture projects are being set up to augment the production of industrial explosives; if so, full details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The production of industrial explosives during the year 1978 was 55,886 tonnes. Requirements during 1978-79 have been estimated as 69,500 tonnes.

(b) The names of the producing firms together with their installed

and utilised capacities are as under:—

S.No.	Name of the firm	Installed capacity	Production during 1978 (in tonnes)	Percentage of capacity utilisation
1	Indian Explosives Ltd., Gomia, Bihar	36,000	30,845	85%
2	IDL Chemical Ltd., Rourkela, Orissa	22,500	20,981	70%
3	IDL Chemicals Ltd., Hyderabad, Andhra Pradesh	7,500		
4	Indo-Burma Petroleum Co. Ltd., Korba, M.P.	5,000	1,645	33%
5	Haichem Ltd., Pattancheru, Andhra Pradesh	2,500	31	..
6	Narendra Explosives Ltd., Dehra Dun, U.P.	1,000	231	23%
7	Indian Oxygen Ltd., Bihar	2,000	2,153	107%
		76,500	55,886	%

(c) No existing manufacture has been given permission expansion of capacity. Details of schemes approved for manufacturers of industrial explosives are as under:—

S.No.	Name and location of the unit	Type of venture	Type of explosives	Annual capacity	Remarks
1	Narendra Explosives Lalitpur, Jhansi	Private	NG	10,000	Likely to be implemented by Middle of 1981.
2	Coal India/DGOF, Bhandara	Govt.	NG	5,000	Likely to be implemented by middle of 1979.
3	Indo-Burma Petroleum, Korba, Jabalpur, Itarsi, Kudremukh.	Public Sector	Slurry	20,000 5,000 in each location	Likely to be implemented by 1981-82.
4	Karnataka Explosives, Mangalore	Private	Slurry	20,000	Likely to be implemented by middle of 1979 for 10,000 cap. remaining in Mid. 1981.
5	Rajasthan State Development Corporation, Dholpur.	Joint Venture	Slurry	10,000	Likely to be implemented in 1980.
6	Brig. Uma & Associates, Medak, Hyderabad.	Private	Slurry	10,000	Not likely to be implemented.
			Total .	75,000	

Small Scale Industries in West Bengal

2275. SHRI RAJ KRISHNA DAWN:
Will the Minister of INDUSTRY be
pleased to state:

(a) whether Government are aware that small scale industries in West Bengal are in very bad shape, many are closed and others are in a moribund State; and

(b) if so, what are the major problems obstructing the growth of the existing industries and forcing the premature death of the new industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI
JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a)
and (b) No Sir, the Government is
not aware of the bad shape of the
small scale industries as a whole in
West Bengal. However, the Govern-
ment are aware that the number of
working units in West Bengal has
been increasing since 1974. In 1978,
according to information received
1888 units were given additional per-
manent registration. The problems
obstructing the growth of small scale
industries in West Bengal as in other
States are management deficiencies,
untimely availability of finance and
raw material, lack of marketing faci-
ties, absence of quality control, delay
in payment of bills, power shortage
etc. The unprecedented floods in
West Bengal also caused damage to
small scale industrial units in the
State.

**Pension to Freedom Fighters of
Amritsar and Ferozepur**

2276. DR. BALDEV PRAKASH:
Will the Minister of HOME AFFAIRS

be pleased to state:

(a) whether any cases of freedom
fighters belonging to Amritsar and
Ferozepur districts were submitted to
his Ministry by the Punjab State Gov-
ernment between 13-11-77 and 31-12-
78 for grant of pensions under the
Pension Scheme, 1972;

(b) if so, the list of freedom fighters
concerned along with the date when
each of these cases were received in
his Ministry;

(c) whether in any cases referred
to above there was delay of more than
6 months; and

(d) if so, what were the reasons
for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI DHANIK LAL MANDAL):
(a) and (b) Yes, Sir. 27 cases of
Amritsar and 4 cases of Ferozepur
Districts were received. A statement
of the cases with dates of receipt is
attached.

(c) and (d). All these cases have
been scrutinised without delay. Pen-
sion has been sanctioned in 6 cases.
3 were late applications which could
not be accepted without evidence
supported by official records. In 9
cases, the State Government has been
informed that it has not been possible
to accept their recommendations in the
absence of adequate documentary evi-
dence. In the remaining 13 cases, fur-
ther clarifications have been sought
for from the State Government. These
are awaited.

Statement

List of Freedom fighters of Amritsar and Ferozepur Districts received from the Govt. of Punjab, between 13-11-77 and 31-12-1978 for grant of Central Pension

Amritsar District.

Name of Freedom Fighters	Date of receipt of MHA
1 Shri Gurdip Singh S/O Dharam Singh, Distt. Amritsar	5-4-1978
2 Smt. Labh Kaur W/O Sh. Wasakha Singh	Do.
3 Shri Hari Singh S/O Shri Ganga Singh	Do.
4 Smt. Mohinder Kaur W/O Tara Singh	Do.
5 Smt. Kartar Kaur W/O Sri Sohan Singh	5-6-1978
6 Shri Attar Singh S/O Ajit Singh	Do.
7 Smt. Kailash Wati W/ O Shri Piara Lala Sarpal	Do.
8 Shri Budh Singh S/O Sh. Chanda Singh	Do.
9 Shri Lal Chand S/O Shri Amar Nath	Do.
10 Smt. Harnam Kaur W/O Sh. Phagga Singh	Do.
11 Shri Bahadur Singh S/O Sh. Sunder Singh	Do.
12 Shri Dalip Singh S/O Shri Sunder Singh	Do.
13 Smt. Beant Kaur alias Bachint Kaur W/O Sh. Pura Singh	Do.
14 Shri Khem Singh S/O Sh. Wadhawa Singh	2-9-1978
15 Shri Kharak Singh S/O Sh. Hakam Singh	Do.
16 Smt. Kartar Kaur W/O Sh. Sohan Singh	Do.
17 Sh. Mohinder Singh S/O Sh. Lachman Singh	6-12-1978
18 Sh. Mohinder Singh S/O Sh. Bhagat Singh	20-1-1978
19 Shri Sant Jaspal Singh S/O Sh. Jai Singh	24-5-1978
20 Smt. Avtar Kaur Wd/O Sh Achhar Singh	27-12-1978
21 Shri Harnam Singh S/O Jassa Singh	27-9-1978
22 Shri Vaishnu Das S/O Shri Badri Nath	16-12-1978
23 Shri Udham Singh S/O Shri Ganda Singh	16-12-1978
24 Shri Jagan Nath S/O Shri Nihal Chand	16-12-1978
25 Shri Thakar Singh S/O Arjan Singh	4-4-1978
26 Shri Mohan Singh S/O Shri Nihal Singh	12-7-1978
27 Shri Mehar Singh S/O Shri Bhagat Singh	27-12-1978

Ferozepur District.

1 Shri Mehar Singh S/O Chanchal Singh	16-12-1978
2 Shri Natha Singh S/O Shri Mehar Singh	20-3-1978
3 Shri Shamsher Singh S/O Shri Hakam Singh	5-5-1978
4 Shri Makhan Singh S/O Shri Ajaib Singh	17-10-1978

सबू क्षेत्रों के उद्योगों के उत्पादन पर
गुणवत्ता नियंत्रण

2278. श्री रम विनायक पातकन : क्या
उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
कि :

(क) सबू क्षेत्र उद्योगों के उत्पादों के गुणवत्ता
नियंत्रण के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) उन सबू उद्योगों के नाम क्या हैं, जिन के
बारे में इस समय गुणवत्ता नियंत्रण अनिवार्य रूप में
लागू है; और

(ग) सविषय में इस बारे में सरकार की क्या नीति
होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी
प्रसाद यादव) : (क) सविषय सरकार सबू क्षेत्र
में बनायी जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में
चिन्तित रही है, पर कुछ चुने हुए उद्योगों में अनिवार्य
गुणवत्ता नियन्त्रण अभ्युपाय किये गये हैं ।

(ख) बिजली के घरेलू उपकरण (किस्म
नियन्त्रण) आदेश, 1976 के अन्तर्गत बिजली के
ऐसे घरेलू उपकरण तथा केबल्स तथा ऐसे
उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले सहायक
सामान के क्षेत्र में अनिवार्य किस्म नियंत्रण लागू किया
गया है । इस आदेश के अधीन 41 वस्तुएं आती हैं ।
1955 के आठ पदार्थ आदेश (यथा संशोधित
अवतार) के अन्तर्गत संशोधित आठ पदार्थों की
अनेक वस्तुएं आती हैं । सबू क्षेत्र में बनाई जाने
वाली शीशियों तथा बोतलों का किस्म नियंत्रण
श्रीमति अधिनियम के द्वारा किया जाता है जिसे
अल्प शीश्वि नियंत्रण द्वारा लागू किया जाता है
इसी प्रकार कीटनाशी शीश्वि (पेस्टोसहर्त) बनाने
वाले एकल केन्द्रीय कीटनाशी शीश्वि बोर्ड द्वारा
प्रशिक्षित कीटनाशी शीश्वि अधिनियम के अन्तर्गत
आते हैं ।

(ग) विशेष क्षेत्रों में अनिवार्य गुणवत्ता नियन्त्रण
लागू करने के प्रश्न पर जहां कहीं आवश्यक
होगा, समय-समय पर विचार किया जायेगा ।

Reduction in Central Plan Size

2278. SHRI AMAR ROYPRADHAN:

Will the Minister of PLANNING be
pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gov-
ernment have decided to cut Central
Plan size; and

(b) if so, details in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI
MORARJI DESAI): (a) and (b). The
Draft Five Year Plan (1978-83) in-
cluded provision for about Rs. 6,000
crores of outlay on schemes to be in-
cluded in the Central Plan for imple-
mentation by the States. The Na-
tional Development Council at its
meeting on the 24-25th February,
1979, decided on certain modifications
in the Centrally Sponsored Schemes,
which would imply that a sum of
Rs. 2,000 crores would be transferred
from the Central sector to the States'
Sector during the period 1979-83.

Pandey Committee Report on Industrial Development of Rajasthan

2279. SHRI S. S. SOMANI: Will the
Minister of INDUSTRY be pleased to
state:

(a) whether a committee was ap-
pointed by the Central Government in
1969 to study and submit its report on
the Industrial Development of Rajas-
than;

(b) if so, whether the Pandey Com-
mittee has supported the idea of dec-
laring the Rajasthan as an industrially
backward State; and

(c) if so, the reaction of Central
Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI
JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a)
The Central Government had set up
a Working Group under the Chair-
manship of Shri B. D. Pandey, in
November 1968, for identification of
backward areas, which submitted its
report in February, 1969.

(b) Yes, Sir.

(c) On the basis of a fixed set up
criteria, 16 districts of Rajasthan have
been selected as industrially back-
ward to be eligible for concessional

finance from the term-lending institutions and out of these, 6 districts have been selected to qualify for the Central Scheme of Investment Subsidy.

Representation for Minority and SC/ST in Central Police Forces

2280. SHRI RUDOLPH RODRI. GUES: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there has been any increase in the percentage of Minority and Scheduled Caste/Tribe representation in the Central Government Police Forces in 1977-78 and 1978-79; and

(b) if so, the details of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). No Statistics of percentage of minority are maintained in the Central Government Police Forces as there is no provision for reservation in respect of any particular minority. However, during 1977-78 and 1978-79, there has been a little increase in the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes representation in the Central Government Police Forces as indicated below:

	Year	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
B.S.F.	1977-78	14.27%	7.13%
	1978-79	14.29%	7.17%
C.R.P.F.	1977-78	11.29%	4.63%
	1978-79	11.67%	4.91%
C.I.S.F.	1977-78	18.76%	7.63%
	1978-79	18.30%	7.56%
I.T.B.P.	1977-78	11.49%	7.01%
	1978-79	12.23%	7.37%
Assam Rifles	1977-78	Information being collected.	
	1978-79	-do-	

Importing of Technical Know-how to Rural Areas by Research Organisations

2281. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether some of the Research Organisations have started their own schemes of imparting technical know-how to the rural areas; and

(b) if so, the financial implications of the project?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Yes Sir. Some research organisations in the country, both official and non-official, have undertaken schemes for imparting technical know-how to the

rural areas; and many more are under formulation. The Indian Council of Agricultural Research, through its own institutions and Agricultural Universities has extension departments/cells for organising training programmes in selected villages/blocks for demonstrating technical know-how to farmers. There are three centrally sponsored schemes of ICAR at present whose financial outlays for the Fifth Five Year Plan period are:—

1. National Demonstration—
Rs. 206.04 lakhs
2. Operational Research Project—
Rs. 233.94 lakhs
3. Krishi Vigyan Kendra—
Rs. 207.00 lakhs

The Council of Scientific and Industrial Research has prepared a detailed report on Integrated Rural Technology Delivery Systems which is under examination. The National Laboratories (notably CIMAP, NBRI, NEERI, CFTRI, HCL, CLRI, SERC and the RRLS) and Polytechnology Transfer Centre under it are engaged in extensive programmes of technology delivery systems to rural areas. For example, know-how transfer in the cultivation of aromatic and medicinal plants resulted in production worth Rs. 7.6 crores in 1977-78. Additionally there are specific programmes of CSIR such as the Karimnagar Project and the "Gaon Ke Karigar aur Science" programme.

The Indian Council of Medical Research has programmes for the improvement in the delivery of health services in rural areas; some feasibility studies involving participation of school teachers have been undertaken by National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi; Institute of Rural Health and Family Welfare, Gandhigram, Tamilnadu; and Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha. Under the two specific projects of the Department of Science and Technology, viz. the All India Coordinated Projects on Algae and Biogas Technology costing Rs. 10 lakhs and 25 lakhs respectively, the technology of using blue-green algae in rice fields has been demonstrated successfully in Tamilnadu and some other states and is now being extended. Different designs of biogas plants are being installed under varying agro-climatic conditions to observe their field performance. There are programmes being executed by educational institutions and non-governmental bodies also e.g. the projects in Yantra Vidyalaya, Borodli; Centre of Science, Wardha; Tilonia, Rajasthan; and at Hoshingabad in Madhya Pradesh.

Terms of Production to be delinked from Major Industries

2282. SHRI A. BALA PAJANOR:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the precise progress made in identifying the terms of production to be delinked from the major industries and to be developed in the small scale and tiny sector; and

(b) particulars of time bound plan; if any, in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The Government have in its Industrial Policy Statement of December, 1977 stated that whatever can be produced by small industries must be produced by that sector. For this purpose items which are capable of being produced in the small scale sector are identified and reserved for that sector. The list of items reserved for production by this sector is continually reviewed so that capacity creation does not lag behind the requirements of the economy. The list of items reserved for this sector is also continually expanded as new products and new processes capable of being manufactured in the small scale sector are identified. In April, 1978 this list was expanded to include 807 items.

Law regarding Husk Control

2283. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kerala State Government have sought the Union Government's permission to bring about changes in the law relating to husk control;

(b) if so, details thereof;

(c) whether Government are aware that the delay in giving the permis-

sion is standing in the way of introducing monopoly procurement of husk through a centralised agency in the State; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The Government of Kerala have represented that Central Government orders notifying Coconut Husk and Coir fibre as essential commodities under the Essential Commodities Act may be withdrawn so that it would enable the State Government to issue appropriate orders under the State Act.

(c) Government is not aware of any proposal of the State Government to introduce monopoly procurement through a centralised agency in the State.

(d) Does not arise.

Condition of Scheduled Castes in Sikkim

2284. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a deputation of All Sikkim Scheduled Caste Joint Action Committee met him and also handed over a memorandum to Government;

(b) whether it is a fact that the condition of Scheduled Castes in the Sikkim is far from satisfactory and stepmotherly treatment is being meted out to them;

(c) whether it is also a fact that the voters lists do not include the names of Scheduled Castes and only one seat has been made reserved for Scheduled Castes though according to their population there must be ten reserved seats in the Assembly; and

(d) whether Government propose to give time to Scheduled Castes to get their names registered in the

voters list, and give them justice before the commencement of the Assembly poll?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. However, if any specific cases of unfair treatment are brought to the notice of the Government, these will be looked into with a view to redress them.

(c) and (d). The electoral rolls are at present under revision and claim for inclusion of names including those from the Scheduled Castes are under scrutiny. One month's time has been allowed to all concerned to register their claims for inclusion in the electoral rolls. In the existing State Assembly one seat is reserved for the Scheduled Castes. The entire question of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the legislative Assembly of Sikkim is under review.

Suggestion of Maharashtra Government for modification of Central Subsidy Scheme

2285. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government of Maharashtra has suggested to the Central Government any proposal for the modification of the Central subsidy scheme for promoting industrialization of backward areas;

(b) if so, when was the proposal submitted and what are its main features; and

(c) what decision, if any has been taken by Government with respect to the said proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). According to the Central Subsidy Scheme as existing at present, industrial units set up in 3 districts of Maharashtra viz. Aurangabad, Chanderpur and Ratna-

girl are eligible to 15 per cent subsidy on fixed capital investment. The Planning Commission, who deal with re-demarcation of the investment subsidy areas, have stated that Maharashtra Government had suggested to the Central Government in April, 1974, that instead of the 3 districts selected to qualify for investment subsidy scheme, 53 Panchayat Samiti Blocks constituting 13 growth centres might be selected for the scheme from out of the 13 districts of the State Selected as industrially backward to qualify for concessional finance facilities (at the rate of one growth centre from each of these 13 districts). As the proposal was not found to be inconformity with the accepted norms evolved in pursuance of the decision of the NDC Committee of State Chief Ministers, the inability of the Planning Commission to agree to it was conveyed to the Maharashtra Government on 16th May, 1974.

The Maharashtra Government had approached the Planning Commission again in May, 1975 seeking approval to their earlier proposal of April, 1974 for re-demarcation of investment subsidy areas. After detailed consideration, the Planning Commission had given a reply to the State on 31st July, 1975 that as the existing subsidy scheme had the approval of National Development Council, any change in the policy therefor would need a careful scrutiny and approval of the same Committee.

A National Committee on Backward Areas has already been constituted under the Chairmanship of Shri B. Sivaraman, Member, Planning Commission. One of the terms of reference of the Committee is to review the working of the existing schemes for stimulating industrial development in backward areas such as schemes for concessional finance, investment subsidy, transport subsidy, sales tax concessions, etc., similar sche-

mes in the agricultural and allied fields like DPAP and general measures for tackling the problems of poverty and unemployment with a view to finding out their efficacy in the removal of backwardness. Modifications, if any, in the Central Subsidy Scheme can be considered only after the report of this Committee is made available.

Reopening of Cases of Political Pensioners

2286. **SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2478 on 6th December, 1978 regarding reopening of cases of political pensioners and state:

(a) the number of political pension cases reopened since April 1, 1977, how many were disposed of, how many are pending disposal and since how long and in how many cases the pension was cancelled;

(b) whether in a large number of cases the pension has been suspended only because the date of release has not been mentioned in the certificates given by the district authorities, even though the date of conviction and the term of the sentence is there; and

(c) in the absence of the jail records, which have been weeded out, what type of evidence are the political sufferers expected to produce to establish their bonafides?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) No. of cases reopened: 15,119.
No. of cases disposed of: 12,152.
No. of cases pending: 2,967.
No. of cases cancelled: 371.

(b) and (c). Under the Scheme, minimum actual imprisonment for not less than six months is essential.

During review of sanctioned cases, it has been noticed that during the earlier stages, pension had been sanctioned on the basis of conviction and incomplete jail evidence. Before allowing such pensioners to continue to draw the pension they are being asked to furnish complete evidence. If in the absence of jail record, the persons produce other acceptable evidence such as co-prisoner certificates, their cases will be reconsidered and finalised after verification through the State Governments.

Agreement between BHEL and SIEMENS

2288. DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Ministry has recommended to the Government a broad-based agreement between BHEL and SIEMENS;

(b) the cost of manufacture of turbines of rating 210 MW and below presently, and the estimated cost if the proposed agreement is implemented;

(c) the present capital-labour ratio of manufacture of the said turbines, and the likely level under the agreement; and

(d) when the Ministry has ascertained the opinion of the Ministry of Energy and the various State Electricity Boards on the proposed agreement, and if so, their reactions to the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SIRIMATI ABHA MAITI): (a) The proposal for a collaboration agreement between the BHEL and Siemens is under examination of the Foreign Investment Board which includes the representatives of this Ministry. Their recommendation is awaited.

(b) Disclosure of the cost of manufacture of turbines in this Govern-

ment of India Undertaking would not be in the public interest. However, the cost of manufacture of turbines under the proposed agreement is expected to be comparable with those manufactured at present under equivalent levels of indigenisation.

(c) In this type of industry, it is difficult to work out such a ratio in the case of each product because the manufacturing facilities often overlap from one product to the other. However, in the turbines manufactured to the new design the material content and work content are anticipated to be less.

(d) The broad-based agreement covers products and a range of system engineering know-how of interest to a number of Ministries and utilities and industrial users. In such cases it is not possible to consult all the likely customers. In the case of the Ministry of Energy, however, their representative, as a Member of the Board of Directors of BHEL, was associated with the evaluation and the approval of the proposal at the Board level.

घादिकासियों पर अत्याचार

2289. श्री गोविन्द मुन्हा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घादिकासियों पर अकारण अत्याचारों की खबर प्रतिदिन समाचार पत्रों में छप रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1978-79 में ऐसे कितने मामले की सूचना मिली ;

(ग) क्या सरकार ने इन अत्याचारों की बकली हुई घटनाओं की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की है और

(घ) यदि हाँ, तो उस का व्यौरा क्या है और इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वसिष्ठ लाल मन्ना) : (क) तथा (ख) , अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की रिपोर्टें समाचार पत्रों में छापी रही हैं। राज्य सरकारों द्वारा बेजी हुई

सूचना के अनुसार वर्ष 1978-79 के दौरान, नवम्बर 1978 के अन्त तक अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की 1235 बारवात हुई है।

(ग) तथा (घ). अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रायोग के विचारार्थ विषयों में से एक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध किये जाने के लिए सामाजिक प्राधिक तथा अन्य परिस्थितियों का गना लगाना है। भारत सरकार ऐसी घटना के लिए उत्तरदायी मूल्य तथ्यों को दूर करने के लिए उपायों को शोध करने और सुलभ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को विभिन्न सुझाव भी दे रही है।

रई के मूल्य में कमी

2290 श्री मोती साई प्रार० जोशी : क्या कृषीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में इस वर्ष कपास की बहुत अच्छी फसल हुई है और क्या गत वर्ष उत्पादित रई की अभी तक बिक्री नहीं की गई है जिस के परिणामस्वरूप रई के मूल्य में भारी गिरावट आई है और इसका कारण किसानों की दबा बहुत खराब है, क्या गुजरात सरकार और किसान संघ ने इस के निवारण किये जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और रई की किरानी गांठों का निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी ;

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जायेगी कि रई विन ही रई की पूरी मात्रा की खरीद करे; और

(घ) क्या प्रत्येक जिले में खरीद केंद्र, जोसे जामने जहाँ जले और छोटे रेवे वाली रई का उत्पादन किया जा सके विले किसान अपने उत्पाद की अपने जिलों में बिक्री कर सकें ?

कृषीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयबन्दी प्रताप साहब) :

(क) और (ख). कपास उत्पादक बोर्ड ने 16 जनवरी, 1979 को हुई अपनी बैठक में अनुमान लगाया था कि गुजरात में इस वर्ष (1978-79) कपास का उत्पादन लगभग 19.50 लाख माँटे होगा। पिछले मौसम में बिना थिडे स्ट्रेच कपास के निर्यात की अनुमति देने सम्बन्धी गुजरात सरकार के अनुरोध पर सरकार ने स्ट्रेच कपास की एक लाख माँटे निर्यात करने की अनुमति दे दी थी। इसमें ही मैं, सरकार ने कपास की 1.5 लाख माँटों के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है, जिसका राज्य-भार समर्थन अभी निश्चित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). भारतीय कपास नियम, गुजरात में कपास तथा अच्छी तरह से दबाई गई गांठें खरीदता रहा है। वालू वर्ष में, नियम 27 केखों में कार्य कर रहा है। गुजरात सरकार के विचार निमन करने के पश्चात् वालू वर्ष में लगभग 4 लाख गांठें खरीदने का सुनिश्चय किया गया है। यदि और केंद्र खोलने का कोई शोचित होगा तो नियम इस पर विचार करेगा।

Setting up of Cement Plants for Irrigation Projects

2291. SHRI K. KUNHAMBUR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Centre has advised the States to set up certain cement plants for speeding up the construction of irrigation projects; and

(b) if so, the names of States which applied for licences and action taken on them so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) At the Fourth Conference of State Ministers of Irrigation held at Trivandrum in February 1979 a proposal was mooted that the State Governments may consider setting up of captive cement factories for large irrigation projects.

(b) The Government of Gujarat have suggested that the proposed grinding unit of M/s. Narmada Cement Co. to be located at Magdalla should be treated as a captive plant for the construction of Navagam Dam. When this grinding unit is set up allocation of maximum quantities produced by it for the construction of Navagam Dam would be considered.

सीमेंट की कमी

2292. श्री जयबन्दी प्रताप साहब : क्या कृषीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विसम्बर, और जनवरी के महीनों में दिल्ली में सीमेंट की प्राथमिक कमी की और यह कमी अभी तक बनी हुई है; और

व) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा चुके हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद बाबू) : (क) जीर (ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि दिल्ली में सीमेंट की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) मकान बनाने के स्वीकृत मकानों पर मकान बनाने ठेके प्राप्त सीमेंट को पूर्व निर्धारित करना, छोटी-मोटी मरम्मत के काम तथा विभिन्न परमिट जारी रखने सीमेंट की प्रसाधारण जरूरतों को पूरा करने सहित वितरण व्यवस्था को सुगमशी बनाना ;

(2) जनता की सुविधा के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों में स्थित सार्वजनिक कार्यालयों को मरम्मत के काम के लिए सीमेंट के परमिट जारी करने के अधिकार दे दिये गये हैं ;

(3) रेलवे लाइनों के न मिलने से माल की जो कमी हो जाती है, उसे पूरा करने के लिए कारखानों से सड़क द्वारा सीमेंट को ढुलाई करने की व्यवस्था कर दी गई है ।

People Living below Poverty Line

2293. SHRI SURENDRA JHA SIMAN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the number of people living below the poverty line; and

(b) the progress made by Government during the years 1977 and 1978 for the removal of poverty from the country in 10 years?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) According to the norm adopted by the Planning Commission 46.33 per cent of the people, that is about 290 million persons, were estimated to be living below the poverty line during 1977-78.

(b) Detailed schemes for poverty removal from the country in about 10 years have been formulated and indicated in the Draft Five Year Plan 1978-83. It is too early to assess the impact of the Plan on the problem of poverty.

Distribution of Financial Resources between Centre and States

2294. SHRI DHIRENDRA NATH BASU: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the distribution of financial resources between the Centre and States have run into major difficulties and the main difference is about sharing the Central aid between the States;

(b) whether West Bengal Government after the two-day meetings of the National Development Committee recently have communicated the Centre about their displeasure as well as disapproval in connection with the 'sharing pattern of Central aid'; and

(c) if so, the reactions of the Government thereto and the details thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, Sir.

(b) and (c). In the N.D.C. Committee, the Chief Minister of West Bengal made certain suggestions in regard to the distribution of Central assistance. The whole matter was considered by the National Development Council which met on 24th and 25th of February, 1979. The Council decided that of the total assistance available for State Plans for the next four years, Rs. 1800 crores should be reserved for special category States, Rs. 600 crores for special problems of States and Rs. 4200 crores distributed among the 14 non-special category States on the basis of the various criteria laid down in the Gadgil formula, except the one relating to special problems. Besides, it was decided that an amount of Rs. 2000 crores to be released over the next four years by certain modifications in the Centrally sponsored schemes should be distributed among the 14 non-special category States on the basis of income adjusted total population of each State (IATP), i.e., the inverse of per capita State income.

multiplied by population. Further, additional Central assistance is being given for hill and tribal areas, the programme of the North-Eastern Council and externally-aided schemes.

Treasure Box belonging to Netaji Subhas Chandra Bose

2295. **SHRI HARI VISHNU KAMATH:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the name and designation of the official who brought the treasure box from Tokyo to Delhi in November, 1952;

(b) whether the box had been opened during the period from November, 1952 till December, 1953 when it was in the custody of Ministry of External Affairs;

(c) if so, when by whom and under whose orders;

(d) the reasons for opening the box then;

(e) whether an inventory of the then contents of the box had been made;

(f) whether it is a fact that not one box, but two, had been brought from Tokyo to India;

(g) if so, the present whereabouts of the other box;

(h) the reasons why Members of Parliament are debarred from having a look at the contents of the box when some not so very senior officers of Government could inspect them on October 9, 1978;

(i) whether the treasure is proposed to be kept permanently in the National Museum or utilized for a National purpose; and

(j) if so, the details thereof

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Shri K. R. Dumble, then Joint-Secretary, Ministry

of Agriculture, who happened to be in Tokyo at the time in connection with official work.

(b), (c), (d) and (e). During the period the box remained in the custody of the Ministry of External Affairs, around the 1st December 1952 the contents were checked and weighed and a list prepared. The then Prime Minister inspected the articles on 9th January, 1953 and directed that the articles be kept as they were. On the then Prime Minister's suggestion that the Ministry of Education take charge of the treasure after inspection, the then Secretary, Ministry of Education, Superintendent, Central Asian Antiquities Museum (National Museum) and Joint Secretary (Administration), Ministry of External Affairs inspected the treasure on 27th November, 1953. The Ministry of Education decided that the treasure would be deposited in the National Museum, which was done on 30th December, 1953 after the box was opened, contents checked re-locked and re-sealed alongwith the key of the box.

(f) Only one box was brought from Tokyo.

(g) Does not arise.

(h) The box was opened for inspection in the presence of officers and it is only they who saw them. The box has also been resealed by them. There is no bar on Members of Parliament seeing them. Arrangements can be made for the purpose and re-sealing it.

(i) and (j) The treasure is proposed to be kept in the National Museum until its final disposal is decided upon.

इसकीकॉपीएन प्रोसेस (इन्डिया) लिमिटेड के कॉपीएन
ऑफिसरों की प्राप्ति की पर
काम में हुई

2296. जी क्या राज काका : क्या उन्होंने
किसी यह वस्तु की कृपा करने की :

(क) "हिन्दुस्तान" दिनांक 25 जनवरी 1979 में (पृष्ठ 3 पर) छत्रे इस समाचार के बारे में क्या सूचनाएँ हैं कि इजीप्टियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों को इस परियोजना में नियुक्ति के पूर्व उनकी भास्तिवों की तुलना में उनकी वर्तमान भास्तिवों और आय में वृद्ध हुई है;

(ख) क्या उपरोक्त परियोजना के कर्मचारियों की युनियन ने उपरोक्त मामले के प्रत्येक पहलू की केंद्र सरकार द्वारा जांच की मांग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन बारे में क्या कार्रवाई की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आशा बारील) : (क) इस समाचार में छत्रे आरोप स्पष्ट नहीं हैं। इसमें इजीप्टियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड के किसी भी अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार को इजीप्टियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड की अधिक युनियन से ई० पी० आई० के कार्यों की एक उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए कोई भी सम्पादकन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Brahmaputra Bridge

2297. SHRI BEDABRATA BARUA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the work for the construction of the Brahmaputra Bridge at Silghat has commenced;

(b) what is the total cost of construction of the bridge; and

(c) when is the bridge expected to be completed?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir. Preliminary arrangements to start the work of road bridge over the Brahmaputra at Bhomoraquri near Tezpur have been taken up.

(b) The total estimated cost of the Bridge is Rs. 29.58 crores.

(c) The Project is expected to be completed in 6 years' time.

Preparation of Liquid Fertilizer from Sea Weed

2298 PANDIT D. N. TIWARY: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Central Salt and Marine Chemicals Institute at Bhavnagar, Gujarat have developed a technology to prepare liquid fertilizer from sea weed;

(b) whether they have standardised it also; and

(c) whether Government are thinking of setting up plants for the manufacture of liquid fertilizers through this process?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes Sir, The Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar, Gujarat has developed a technology to prepare liquid fertilizer—from a rown sea weed known as Sargassum.

(b) Yes Sir, but at present only on pilot plant scale.

(c) The Question of setting up plants for the manufacture of liquid fertilizers using this process will be taken up after the results are available of the field trials being carried out at present by Tamil Nadu Agricultural University, Tamil Nadu Agricultural University, Tamil Nadu and Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

Incurring of Expenditure on UNIDO Conference

2299. SHRI V. ARUNACHALAM: SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the expenditure proposed to be incurred by Government of India on the projected UNIDO Conference to take place in India; and

(b) the justification for such expenditure in the face of other trying needs of our economy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The main facilities to be provided by Government of India, as the host Government, and the estimated expenditure (where available) thereon is indicated below:—

Facilities to be provided	Estimated expenditure
(i) The actual additional cost, both direct or indirect, involved in holding the Conference away from Vienna, the established headquarters of UNIDO.	Presently estimated at Rs. 41 lakhs.
(ii) To make available at its expense conference premises (halls and conference rooms with simultaneous interpretation arrangements in six languages with facilities for sound recordings) and office accommodation adequate to house the Conference Secretariat along with local personnel to be provided by Government of India.	The CPWD is implementing a project for the renovation of Vigyan Bhavan at an estimated cost of Rs. 184 lakhs. A proposal for revision of these estimates is under consideration of Government.
(iii) Reproduction equipment for in-session documentation, durable items of office supplies, utility services like telephones, telex machines etc.	Necessary details are being worked out by a working group and an idea of the costs involved will be available after its report is received.
(iv) Local staff at the expense of Government of India for reproduction/distribution of documents, typists, clerks, messengers, security guards, store keepers, conference room personnel, staff for custodial and maintenance services for equipment and premises.	-do-
(v) Suitable hotel/hostel accommodation for delegates and international staff.	The ITDC is implementing a scheme for the expansion of hotel accommodation at an estimated cost of Rs. 875 lakhs. Similarly the CPWD is implementing a project for the construction of a 800 two-roomed hostel at an estimated cost of Rs. 621 lakhs.
(vi) Other facilities, such as cafeteria, transport, medical cover, banking, publicity cover etc. as would be appropriate for the Conference.	Necessary details are being worked out by a working group and an idea of the cost involved will be available after its report is received.

The Government of India would also have to incur expenditure on temporary staff for organisational arrangements for the Conference as well as office equipment/supplies, telephones etc. Details with cost estimates are being worked out by a Working Group.

A provision of Rs. 81 lakhs has been proposed in the budget grant for the Ministry of Industry for 1979-80. Where necessary, provisions have also been proposed by other Ministries with reference to the facilities which are within their spheres of responsibility.

(b) Government of India's offer to provide most facilities for the Third General Conference of UNIDO was made in March, 1975 during the Second General Conference held in Lima (Peru); the offer has been reiterated in other international forums. The offer has been accepted by the UN General Assembly and it is, therefore, necessary to take steps to provide facilities expected of the host Government. In any case, a large part of the expenditure is on capital works, e.g. the renovation of Vigyan Bhavan, the construction of a 800 two-roomed hostel and the augmentation of hotel accommodation.

Legislation to make destruction of property an offence

2300. SHRI P. VENKATASUB-
BALAH: Will the Minister of HOME
AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to enact a legislation making destruction of property a cognizable offence; and

(b) whether State Governments have been consulted in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1978, as passed by the Rajya Sabha on 23rd November, 1978, and now pending in this House, has substituted new sections for the existing sections 426 to 432 and 434 to 440, pertaining to mischief. These new sections contain many new offences prescribing deterrent punishment for destruction of property, namely, mischief causing damage to public property or machinery (clause 179—new section 427); mischief, with intent to destroy place of worship, house, etc., (clause 179—new section 430A); sabotage, i.e., acts committed with intent to impair the efficiency or impede the working of, or to cause loss, damage or destruction to any building, installation or other property used in connection with the production, distribution or supply of water, light, power or energy; any sewage work; any mine or factory; any laboratory or institution where scientific or technological research is conducted; any means of public transportation or of telecommunications or any building, installation or other property used in connection therewith (clause 180—section 437) and making preparation to commit sabotage (clause 180—section 438). The offences under new section 427, 430A, 437 and 438 are to be punishable with the punishment upto three years, or more.

After the Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1978 is enacted certain consequential amendments will be necessary in the Code of Criminal Procedure. Among these will be amendments pertaining to the classification of these offences as cognizable and non-cognizable. The question of classification of these offences will therefore be considered at that time.

(b) Does not arise.

Coral Reefs

2301. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several places on the coast of India and off shore islands have exquisite reefs of coral are found in existence;

(b) whether it is a fact that National Institute of Oceanology has drawn the attention of Government that these rare coral ranges are in danger of extinction and degradation due to industrial pollutants, dredging operations and other causes; and

(c) if so, what action has Government taken to protect the coral reefs and preserve its natural growth particularly in places like Lakshadweep and on the western coast of Maharashtra?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) The National Institute of Oceanography (NIO) had made a study of the coral reefs and submitted a report to the World Wildlife Fund, India, who had sponsored the work. The World Wildlife Fund, India have drawn the attention of the Ministry of Agriculture to the findings of the NIO. The Institute has also drawn the attention of the Administrator, Lakshadweep Islands to the preservation of coral reefs in that area.

(c) The Ministry of Agriculture have brought the observations of the World Wildlife Fund-India to the notice of the State Governments of Gujarat and Tamilnadu and requested them to—

- (i) declare a moratorium on all dredging within half a mile radius of the spring tide low-water mark around the coral formation;
- (ii) to stop exploitation of the marine flora and fauna; and
- (iii) establish marine national parks to protect the marine flora and fauna.

The Government of Tamilnadu have since commissioned the Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin to prepare a detailed Project Report for the establishment of a Marine National Park in the Gulf of Mannar.

The Lakshadweep Administrator has a proposal for the setting up of a national park in one of their lagoon islands.

Export of Salt

2302. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to export salt;

(b) whether it is a fact that there is shortage of salt in the country; and

(c) if so, whether there is any proposal to ban salt export to maintain the stocks and prices level?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) Yes Sir, to a limited extent.

(b) The production of salt in the country during 1978 was 66.91 lakh tonnes against the estimated offtake of about 61 lakh tonnes for domestic and industrial consumption. There is no shortage of salt in the country, although temporary shortages occasionally arise in certain areas due to inadequate transport facilities.

(c) Does not arise.

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

2303. श्री अमल राम जायसवाल : क्या योजना संघी यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाचू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चिरकालीन बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 43.7 लाख से बढ़ कर 50 लाख हो जायेगी; जबकि 1983 तक अथम शक्ति 26.5 करोड़ से बढ़ कर 29.5 करोड़ हो जायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो 31 जनवरी, 1979 तक प्रत्येक राज्य में अथम शक्ति कितनी-कितनी है तथा प्रत्येक राज्य में बेरोजगार व्यक्तियों में से चिरकाल के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) पाचू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य में चिरकाल तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी तथा यह राज्य में कुल अथम शक्ति की कितने प्रतिशत होगी; और

(घ) 1983 तक प्रत्येक राज्य में अमिकों की संख्या कितनी होने की सम्भावना है तथा प्रत्येक राज्य में सरकारी गैर-सरकारी सेव में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1978; 83 की योजना के प्राप्ति में 31 मार्च, 1978 को दीर्घकालिक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 43.7 लाख का अनुमान लगाया गया है। इस योजना के अंत में इस संख्या के काफी कम हो जाने का अनुमान है।

(ख) एक द्विवर्षीय संलग्न है जिसमें प्रमुख राज्यों के संबंध में 1978 और 1983 के लिए अमिकों की संख्या के और मार्च, 1978 में दीर्घकालिक बेरोजगारों की संख्या के राज्यवार अनुमान दिए गए हैं।

(ग) आग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्तित्व नहीं होता।

(घ) 1978-83 की योजना के अन्त में 493 लाख मानक अथम-वर्षों के प्रतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने की परिकल्पना है। राज्यवार का सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए अथम से अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

विवरण

मार्च, 1978 और 1983 में श्रमिकों की संख्या के और मार्च, 1978 में दीर्घकालिक बेरोजगारों के राज्यवार अनुमान ।

राज्य	श्रमिकों की संख्या		दीर्घकालिक बेरोजगार
	1978	1983	1978
	(दस लाख)	(दस लाख)	(हजार)
1. माध्य प्रदेश	24,94	27,32	358
2. असम	5,40	6,31	45
3. बिहार	23,20	25,79	444
4. गुजरात	13,00	14,51	141
5. हरियाणा	4,59	5,13	93
6. हिमाचल प्रदेश	1,95	2,16	11
7. जम्मू और कश्मीर	2,10	2,38	16
8. कर्नाटक	15,81	17,60	236
9. केरल	9,30	10,35	986
10. मध्य प्रदेश	23,69	26,66	113
11. महाराष्ट्र	27,68	29,60	459
12. छत्तीसगढ़	11,24	12,51	134
13. पंजाब	6,22	6,80	74
14. राजस्थान	16,12	18,49	86
15. तमिल नाडु	22,12	23,84	463
16. उत्तर प्रदेश	88,38	42,33	244
17. पश्चिम बंगाल	17,68	20,01	703

टिप्पणी :— ये अनुमान 1973-75 की अवधि में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के निष्कर्षों (27वाँ और) और सरकारी जनसंख्या अनुमानों पर आधारित हैं । छोटे राज्यों के लिए विश्वसनीय अनुमान बताता संभव नहीं है ।

Representation from Maharashtra to
amend Criminal Procedure code ,

2304. SHRI R. K. MEHALGI: Will
the Minister of HOME AFFAIRS be
pleased to state:

(a) whether Government have
received a representation dated the
17th January, 1979 from Maharashtra
in regard to the proposed amendment
to Section 125 of criminal procedure
Code 1973;

(b) if so, the nature of the proposed amendment; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) No representation on the subject has been received from the Government of Maharashtra. However, two representations, both dated the 17th January, 1978 have been received from certain Advocates from Maharashtra.

(b) The first representation seeks to insert the following two new sections after Section 125 Cr. P.C. [Order for maintenance of wives, children and parents]:—

"125-A. On an application, if the court is satisfied that the opponent is related to the applicant, and that there is no source of income to the applicant, to maintain himself or herself or to spend for the proceedings, then the court may order an interim maintenance allowance not more than Rs. 200/-.

125-B. Proceedings under this section shall as far as possible be terminated within six months from the date of appearance of the opponent."

The second representation seeks changes in the relevant sections 125, 126 and 127 Cr. P.C., so as to provide that old men of 55 years and above may not be sent to jail for failure to pay maintenance to their modern young childless wives.

(c) The Government do not propose to accept the amendments proposed in these two representations.

Feasibility report for setting up of Mini Cement Plant at Dharamkot (District Kangra)

2305. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of INDUSTRY be pleas-

ed to refer to the reply to Unstarred Question No. 4080 on 22nd March, 1978 regarding technology for setting up of mini cement industries and state:

(a) the progress so far made in preparing a feasibility report by the Cement Research Institute for setting up of a mini cement plant at Dharamkot (District Kangra) of Himachal Pradesh;

(b) by when the plant will be set up with its capacity and cost involved; and

(c) whether Government propose to make use of lime stone reserved in Himachal Pradesh apart for this mini plant if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) It has been reported by Cement Research Institute of India that a team visited the site during August 1978. The raw materials samples were received from the sponsor only on 12th December, 1978. The feasibility report would be ready by the 3rd week of March, 1979.

(b) The plant is likely to be commissioned by December, 1980 with a capacity of 50 TPD at an estimated cost of Rs. 140 lakhs.

(c) The State Government is exploring the possibility of utilizing 754.8 million tonnes of reserves (both proved and inferred) of lime stone deposits in the State, to the maximum extent possible.

Memorandum from Khasi Jaintia Delegation

2306. SHRI MADHAVRAO SON-DIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Khasi Jaintia delegation has submitted a Memorandum to Government recently regarding reservation of jobs in the central offices located there;

(b) if so, details of the memorandum; and

(c) Government's reaction thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MAN-DAL): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Investment of Money in Burn standard Co. Ltd.

2307. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the amount of money invested in Burn Standard Co. Ltd. since the take-over;

(b) the total out-turn out of the sum so invested and whether the said out-turn is encouraging; and

(c) if not, whether Government are contemplating to set up any committee to enquire into the entire affairs of the company and proper utilisation of the money so far invested and suggest remedies thereof.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) The total money released by the Central Government to M/s. Burn Standard Co. Ltd., Calcutta since take-over of the management of the undertakings of M/s. Burn & Co. and M/s. Indian Standard Wagon Co., is of the order of Rs. 35.19 crores, including loan of about Rs. 28.32 crores.

(b) and (c). The production performance of the company since take-over of the management of the undertakings, from December, 1973 has been gradually increasing. As against the production of Rs. 10.61 crores during 1973-74, the Company expects to achieve a production of about Rs. 33.00 crores during the current year. Although the production performance of the company has been gradually on the increase, yet the Company has been incurring losses, mainly due to unremunerative back-log of wagon orders, which they had to execute at old uneconomic prices according to the terms of the contract. Further, the labour over-heads are on the high side, mainly due to a large percentage of labour having to be kept idle, with a view to avoiding retrenchment. Corrective remedial measures are being taken to avoid losses and to make this Company a viable unit. The Government do not contemplate to set up any committee of investigation at this stage.

कल्याणमल मिल द्वारा से कपड़े की बिक्री

2308. श्री हुसैन बन्द कलनाव : क्या उद्योग मंत्री 16 अगस्त, 1978 को प्रसारित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की इच्छा करते हैं कि

(क) "कल्याणमल मिल" ने जनवरी, 1978 से अक्टूबर, 1978 तक से कपड़े की बिक्री किन-किन फर्मों को की तथा इसकी कितनी कीमत और मात्रा से बिक्री की गई;

(ख) क्या फर्मों को कुछ प्रथम घनराशि जमा करना आवश्यक होता है और यदि हाँ, तो नियम से व्यापारियों के लिए क्या नियम और शर्तें निर्धारित की हैं और क्या कुछ ऐसी फर्में हैं जो नियम से बड़ी मात्रा में कपड़ा करीवती हैं और उनकी स्वयं बिक्री करने का प्रयास करती हैं और क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है और यदि हाँ, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन कर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने सैन्य (सेक्टर) और वे कर्मों की नियम से सैन्य की सेक्युरिटी की डिप्लोमटी अपने नियम स्थान पर नहीं की और इसके परिणामस्वरूप नियम को कितनी हानि हुई और क्या नियम ने इन कर्मों को छूट दी है; और यदि हाँ, तो इस बारे में कर्मचार की गई छूट की रशि क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ग) प्रश्न: दिनांक 15-4-78 व 10-5-78 को पूछे गए अंतराक्षित प्रश्न संख्या 7460 व 5827 के उत्तर में दिए गए आश्वासनों का पुरा करने हेतु, जनवरी, 1976 से म.प. 1978 तक की अवधि की जानकारी सदन के प्रश्नमाला में रखी जा रही है। अनुभव से पता चला है कि दुष्पना समाप्त करने में जितना परिश्रम निहित है, परिणाम उसके अनुसंधान नहीं निश्चिता है।

(ख) छुटी गई दुष्पना इतनी अधिक है कि वह नियम वाले परिणाम से कम लाभप्रद सिद्ध होगी।

Payment by Management of Burn Standard Co. Ltd.

2309. SHRI DINEN BHATTACHAR- YA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a total sum of Rs. 20 lakhs have been paid by the management of Burn Standard Co. Ltd. to some electric and building contractors prior to execution of job; and

(b) if so, the reaction of Government?

"THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b). An advance of Rs. 25.9 lakhs has been paid by M/s. Burn Standard Co. to the Bankers of seven civil contractors for execution of the sanctioned projects of the company. The Bankers have also agreed to release the money to the contractors only on getting a clearance from the Company.

Progress of Rare Earth Project, Gopalpur, Orissa

2310. SHRI GIRIDHAR GOMAN- GO: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) the progress made and programmes prepared for the year 1979-80 for Rare-Earth Project at Gopalpur, Orissa; and

(b) the steps taken by his Ministry for early clearance of Gopalpur minor port for transportation of raw materials of the project?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Site development, levelling and fencing for setting up the Orissa Sands Complex (OSCOM) Project of the Indian Rare Earths Limited have been completed. Orders have been placed for most of the long-delivery and critical items of equipment. Civil and structural works for work-shop and other ancillary buildings are in progress. Arrangements have been made for power and water supply.

During 1979-80, major items of plant and machinery including imported equipment are expected to be received at site and erection work will be taken up. Work on plant buildings will continue and civil work on ancillary buildings will be more or less completed.

(b) The matter is engaging the attention of the Government.

Declaration of Hill areas in Orissa

2311. SHRI GIRIDHAR GOMAN- GO: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the districts declared as hill areas by his Ministry, State-wise;

(b) the districts suggested by the Government of Orissa to his Ministry for declaration as Hill Areas of that State;

(c) the names of the districts declared by the Ministry for that State as Hill District/Areas; and

(d) the facilities to be provided for these areas by his Ministry for the development of the areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The Ministry of Industry have not declared any district as hill area. However, the Committee of the National Development Council on Hill Areas had identified the following districts of some States as hill areas:—

Uttar Pradesh: Uttar Kashi, Chamoli, Pithoragarh, Tehri Garhwal, Pauri Garhwal, Almora, Nainital and Dehradun Districts.

Assam: Mikkir Hill and North Cachar Hills.

Tamil Nadu: Nilgiris.

West Bengal: Darjeeling.

Besides these districts, the following States/Union Territories were defined as entirely hilly:

1. Himachal Pradesh
2. Jammu & Kashmir
3. Manipur
4. Meghalaya
5. Nagaland
6. Arunachal Pradesh.

(b) The Government of Orissa have not sent any proposal to the Ministry of Industry nor to the Planning Commission for declaration as hill areas of that State.

(c) None of the districts of Orissa has been declared as hill district/areas.

(d) The industrial units set up in the districts identified as hill areas, except Nilgiris and Darjeeling, are eligible to 50 per cent subsidy on transport cost of raw materials which are brought into and finished goods which are taken out of "selected areas" between the selected rail-heads and location of the industrial units.

Allocations made for sub-plan areas and its utilisation

2312. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the allocation earmarked by the States and Centre for Sub-Plan Areas for the year 1978-79 and the amount utilised State-wise;

(b) the amount earmarked for the year 1979-80 by the States and Centre;

(c) the achievements made by the States; and

(d) how far the exploitation of tribal people has been eliminated so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) A statement showing the state-wise allocations for 1978-79 is enclosed. As the financial year has not come to a close, expenditure figures are not available.

(b) The amount of Special Central Assistance for the tribal sub-plan for the year 1979-80 has been fixed at Rs 70 crores. The allocations from State Plan for sub-plans have not yet been finalized.

(c) While state-wise comparable individual item-wise achievements are not available, reports indicate that considerable progress has been achieved in the tribal sub-plan areas, particularly in the extension of minor irrigation facilities, co-operative Credit and horticulture developments.

(d) Elimination of exploitation has been given the highest priority. The excise policy has been reviewed, the problem of land alienation is being tackled as a time-bound programme and credit and marketing facilities strengthened. There has been a varying degree of success in all these areas.

Statement

Tribal Sub-Plan 1978-79.

Name of the State/U T	ALLOCATION	
	State Sub-Plan	Special Central Assistance
	(Rs. in lakhs)	
1. Andhra Pradesh .	1473.00	268.00
2. Assam. . .	1000.00	325.00
3. Bihar . . .	6125.00	985.00
4. Gujarat . .	3350.14	606.00
5. Himachal Pradesh	590.35	130.00
6. Karnataka . .	203.00	28.00
7. Kerala . . .	91.00	26.00
8. Madhya Pradesh .	6354.00	1846.00
9. Maharashtra .	4851.81	498.00
10. Manipur . . .	1434.34	177.00
11. Orissa. . . .	4751.60	980.00
12. Rajasthan . .	1374.00	347.00
13. Tamil Nadu . .	159.00	54.00
14. Tripura . . .	722.50	115.00
15. Uttar Pradesh .	58.00	18.00
16. West Bengal . .	1354.60	268.00
17. A& N Islands . .	75.00	43.00
18. Goa Daman & Diu	45.00	22.00
TOTAL	34412.00	6736.00
		264.00
		(Reserve)
GRAND TOTAL . . .	34412.00	7000.00

Acceptance of Recommendations made by working group for Tribal Development

2313. SHRI GIRIDHAR GOMAN-GO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the recommendations of Working Group for Tribal Development have been accepted by the Government of India;

(b) if so, the Ministries which have accepted the recommendations and prepared the schemes so far; and

(c) the measures taken by his Ministry for early finalisation of the recommendations with concerned Ministries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MAN-DAL): (a) to (c) The Working Group recommendations are intended as guidelines for the formulation of the medium term plan 1978-83. Copies have been sent to all concerned Ministries so that they could be taken into account while finalizing their sectoral programmes. These Ministries have undertaken the exercise of formulation of schemes and quantification of funds out of their sectoral programmes to be incurred in the tribal sub-plan areas. The exercise is being pursued as a part of the formulation of the medium-term plan 1978-83.

सरकारी रोजगार के लिये चुने हुए अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त की पुलिस द्वारा जांच

1214 डा० रम्वजी सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी रोजगार के लिए चुने गये अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त के सत्यापन का कार्य पुलिस संस्थापना को देने का कोई प्रीक्षित है जो स्वयं अधिकतर प्रष्ट है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य को उन शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाध्यापकों अथवा अध्यापकों को न सौंपने के क्या कारण हैं जहां ये अभ्यर्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली में सुधार करने और अभ्यर्थियों की पुलिस के भ्रमों से बचाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का है और यदि हाँ, तो ऐसी कार्यवाही कब तक की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

यह बजालय तथा विधि, म्याग और कम्पनी कार्य बजालय में राज्य मंत्री (श्री सुसो डी० पाटिल) : (क) सरकार को अपनी यह समुचित करनी होती है कि सरकार के अधीन आने वाले उम्मीदवार सभी तरह से उपयुक्त हैं और उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उम्मीदवार के विरुद्ध नैतिक प्रभावता के दृष्टिकोण पर रायों के लिए शोधसिद्धि सहित, ऐसा कुछ नहीं है जो उसे सरकारी रोजगार के लिए अनुपयुक्त ठहरना हो। ऐसी सूचना सामान्यतः केवल विभिन्न जिलों के अधिनियमों में ही उपलब्ध होती है। अतः ऐसी जांच सरकारी एजेंसियों से ही की जानी होती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उक्त पत्रित को मयासम्भव सरल बनाने के लिए सरकार समय-समय पर चरित्र और पूर्वजन्त के सत्यापन की प्रणाली की पुनरीक्षा करती रही है। इन्वील-मालवा यूनाइटेड लिमिटेड द्वारा बोधा गया नियोजित कपड़ा

2315. श्री हुकम चन्द कछावः क्या उद्योग मंत्री 18 अगस्त, 1978 के तारकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिससे इन्वील मालवा यूनाइटेड लिमिटेड, इन्दौर में, जनवरी, 1976 से अक्टूबर, 1978 के दौरान किस किस पार्टी को, किस किस किस्म का, कितनी कितनी मात्रा में तथा कितने कितने मूल्य का बरजू (नियोजित) कपड़ा बेचा ;

(ख) क्या इन पार्टियों को पहले पैसा जमा कराना पड़ता है; यदि हाँ, तो कितना और यह निगम किन शर्तों पर व्यापारियों को उक्त कपड़ा बेचता है ;

(ग) क्या ऐसी पार्टियाँ भी हैं जो निगम से बोक में माल खरीदती हैं और स्वयं ही उसे बेचने की कोशिश करती हैं, यदि हाँ, तो ऐसी पार्टियों का नाम क्या है; और

(घ) उन पार्टियों की संख्या तथा नाम क्या हैं, जिन्होंने निगम से तैयार कपड़ा तो खरीद लिया परन्तु अपने यहाँ उसके पहुँचने पर उसे बसूल नहीं किया, और इस कारण निगम को कितनी हानि हुई और क्या इन कर्मों को निगम ने छूट भी दी थी; यदि हाँ, तो पार्टीवार कितनी राशि की छूट दी थी ?

उद्योग बजालय में राज्य मंत्री श्री (अग्रजन्धी प्रसाद शर्मा) : (क) तथा (घ) जनवरी, 1976 से मार्च, 1978 की अवधि की जानकारी दिनांक 19-4-78 तथा 10-5-78 के अतारकित प्रश्न संख्या क्रमशः 7460 तथा 9827 सम्बन्धी आस्था-सर्गों को पूरा करने हेतु संसद् के पुस्तकालय में रखी जा

रही है। पता चला है कि यह संकलन आकार में बड़ा होया। अप्रैल, 1978 से अक्टूबर, 1978 को जानकारी सम्बन्धी होती होगी और इसके निकलने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) तथा (ग) मांगी गई जानकारी संबंधी चौकी है और तथा उसके निकलने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

Loan given to Central Government Employees Consumer Cooperative Society Limited

2316. CHAUDHURY BRAHM PRAKASH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have advanced some money to Central Government Employees Consumer Cooperative Society Limited, New Delhi as loan and if so, the amount thereof, when advanced and the rate of interest being charged by Government;

(b) whether it is a fact that the Society's financial condition is very bad and it is running into heavy loss;

(c) whether the Society is returning the loan amount in yearly instalments of Rs. 2 lakhs despite heavy loss with interest; and

(d) whether in the interest of more than 60,000 members of the Society and in the interest to strengthen Co-operatives, the Ministry propose to request the Finance Ministry or the Home Ministry not to press upon the repayment of the loan amount and extend a helping hand by advancing more amount to Society to keep it alive as is the position with Super Bazar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) Yes, Sir. A statement showing details of the loans advanced to the Society and the rate of interest being charged by Government is enclosed.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The Government have received a request from the Society for additional financial assistance, and this is under consideration.

राज्यों की गत बस वर्षों में दिया गया प्रति व्यक्ति अनुदान

2317. श्री रामानन्द तिवारी : क्या योजना यंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को उनके विकास के लिए गत बस वर्षों में कितना प्रति व्यक्ति अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछड़े तथा आर्थिक रूप से दुर्बल राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में अनुदान कम दिया गया है ,

(ग) क्या आर्थिक विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देते समय राज्यों के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात ध्यान में रखी जाती है ,

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करना चाहती है, और

(ङ) यदि हाँ, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) इन खण्डों के उत्तर में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके उपलब्ध हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद् की 24 और 25 फरवरी, 1979 को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि विशेष समस्याओं से सम्बन्धित मापदण्ड के अलावा गाइडलिन्स फार्मूले में निर्धारित किए गए विभिन्न मापदण्डों के आधार पर अगले चार वर्षों के लिए राज्य योजनाओं के लिए उपलब्ध कुल केन्द्रीय सहायता में से 1800 करोड़ रुपये विशेष क्षेत्रों के राज्यों के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिये, 600 करोड़ रुपये राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिये और 4200 करोड़ रुपये विशेष क्षेत्रों से हटकर 14 राज्यों की बीच में वितरित किये जाने चाहिये । इनके अलावा यह भी निर्णय किया गया कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में कुल भागोदनों को करके अगले चार वर्षों में दी जाने वाली 2000 करोड़ रुपये की राशि को हर एक राज्य की आय समायोजित कुल जनसंख्या (आ० स० पु० ज०) के आधार पर, अर्थात् जनसंख्या द्वारा गुणित राज्य की प्रति व्यक्ति आय के वित्तीय के आधार पर, विशेष क्षेत्रों से हटकर 14 राज्यों के बीच में वितरित किया जाना चाहिये ।

इसके अलावा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए, उत्तर-पूर्वी परिषद् के कार्यक्रम के लिए और विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

गाइडलिन्स फार्मूले के अन्तर्गत, सहायता का एक भाग (राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और राज्यों की) विशेष समस्याओं के आधार पर आवंटित किया जाता है । इससे अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों को लाभ होता है । आय समायोजित कुल जनसंख्या के फार्मूले के अन्तर्गत, कई कम विकसित राज्यों को और अधिक लाभ पहुंचेगा ।

Take over of Family Industries

2318. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to take over family industries, and

(b) if so, when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Eradication of Poverty

2319. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of PLANNING be pleased to refer to his public statement on January 25, 1979 that "The Government was not complacent about the situation and would direct its future strategy to shift resources for development of under-developed areas to attack the problem of poverty and unemployment and improve agriculture and provide facilities in rural areas" and state:

(a) the manner in which Government propose to proceed on eradication of poverty and development of under-developed areas;

(b) whether undeveloped areas of

the country will be ignored while developing the under developed areas; if any, how this gigantic problem will be tackled; and

(c) whether Government are aware of the fact that many undeveloped areas of the country are being continuously neglected in spite of so many reminders to State and Central Governments; if so, Government's reaction thereon?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The principal objectives of the new phase of development launched in 1978-79 are the removal of poverty, unemployment and under-employment in about a decade. The highest priority has been accorded to agriculture and allied sectors, irrigation and village and cottage industries which have the greatest capacity to absorb surplus labour. An expanded Minimum Needs Programme has also been provided for so that the living standards of the poor people can be improved by the provision of certain minimum basic amenities.

(b) and (c) These programmes are expected to benefit all parts of the country. They include certain measures directed towards the development of remote and especially backward areas, and areas with special problems such as drought-prone areas and deserts, hill areas and areas of tribal concentration.

A National Committee on the Development of Backward Areas has also been constituted to make further recommendations in relation to these areas.

Hoisting of flag by son of former Ruler of Jaipur

2320. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the fact that Shri Bhawani Singh, son of former ruler of Jaipur was flying the flag of the former princely

family on the city palace, Jaipur, his residence; and

(b) whether this was permitted by the authorities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b) The Government of Rajasthan have intimated that Shri Bhawani Singh, former ruler of Jaipur has been hoisting flag of the former princely family on the city Palace, Jaipur, although no such permission has been granted, the position is that although the former rulers are not debarred from exercising such rights as are available to them as ordinary citizens, the flying of flags by them as a matter of privilege has ceased to exist on the commencement of the Constitution (28th Amendment) Act, 1971, on 28th December, 1971.

Equity of N.T.C

2321. SHRI R. V. SWAMINATHAN: SHRI M. V. CHANDRA-SHEKHAR MURTY: SHRI P. M. SAYEED:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether five State Governments have refused to participate in the equity of the National Textile Corporation and have demanded immediate repayment of loans given by them to the Corporation;

(b) if so, what are the main reasons for the same; and

(c) how many State Governments have offered their cooperation after the take over of the management of the sick textile mills?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGADAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b) Six State Governments did not agree to participate in the equity capital of the subsidiary Corporations of the National Textile

Corporation. Most of these State Governments have asked for repayment of their loans, mainly due to their difficult ways and means position.

(e) Eight State Governments and two union territories have agreed to convert their loans into equity capital of the subsidiary corporations.

Foreign Delegations visited Engineering fair at New Delhi

2322. SHRI DHARM VIR VASISTH:

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number and status of foreign delegations who visited the Engineering Fair at Pragati Maidan, New Delhi;

(b) the turn over of mutual trade transactions effected so far with enquiries from delegation of prospective future deals, if any; and

(c) the quantum of domestic trade transactions together with the number of daily visitors up to date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) Delegates from 51 countries visited the Engineering Trade Fair at Pragati Maidan. This includes 8 delegations led by Ministers.

(b) Actual orders booked from overseas customers is Rs. 43.04 lakhs and enquiries worth Rs. 78 crores approximately were generated from overseas markets.

(c) Orders worth Rs. 60 lakhs were booked from domestic customers and business enquiries worth Rs. 32.5 crores approximately were generated from domestic market. In the two weeks, when it was open more than a lakh of visitors saw the fair.

कच्ची ऊन का आयात

2323. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्ची ऊन का विदेशों से आयात किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को कच्ची ऊन पर शुल्क कम करने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं जिससे कालीनो का उत्पादन बढ़ेगा और उनके निर्यात में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या नीति निर्धारित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : कच्चे ऊन पर आयात-शुल्क कम करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा इन अभ्यावेदनों को जाच की गई है किन्तु 1979-80 के बजट में किसी प्रकार की कमी करने का प्रस्ताव नहीं है।

लघु, कुटीर एवं हथकरघा उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं

2324. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु, कुटीर तथा हथकरघा उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और क्या लघु उद्यमियों को उससे उचित लाभ प्राप्त हो सकेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। सरकार ने लघु, कुटीर व हथकरघा उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन करने हेतु कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Projects for Upliftment of backward sections of Society

2325. SHRI SUKHDIO PRASAD VERMA: Will the Minister of

PLANNING be pleased to state:

(a) the details of the projects Government propose to take up during the year 1979 for the uplift of the backward sections of the society; and

(b) the total funds allocated for the projects?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The main thrust to the development of Backward Classes, as envisaged in Draft Five Year Plan 1978-83, will come from general sectors of development. In 1979-80 the Integrated Tribal Development Projects as part of the sub-plans for areas of tribal concentration will continue. Additional areas of above 10,000 population with at least fifty per cent tribal concentration will be identified to cover larger tribal population under the integrated development programmes of tribal sub-plans. Further, the State Governments have been requested to prepare Special Component Plans for Scheduled Castes within the State Plans. Under the Special Component Plan, the States have been requested to identify schemes in the different sectors which can directly benefit these groups and quantify the investment on these groups. Besides this, the Integrated Rural Development and other area-based programmes like Hill Area Plans, Small Farmers Development Agency, Drought Prone Area Development, etc., Revised Minimum Needs Programme, Social Welfare Programmes including schemes for health care, nutrition and schemes under Development of Backward Classes sector are designed to benefit the backward sections of the society.

(b) The total flow of funds to Tribal Sub-Plans and Special Component Plans for Scheduled Castes is still to be worked out in consultation with the concerned State Governments/ Union Territory Administrations.

Engineers & Architects of Engineering unit of CSIR

2326. **DR. RAMJI SINGH:** Will the Minister of SCIENCE AND TECH-

NOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Engineers and Architects of Engineering Unit, Council of Scientific and Industrial Research Headquarters have been classified as Administrative and not technical, if so, the reasons thereof; and

(b) whether it is also a fact that representations from Engineers and Architects of CSIR have been sent to the Hon'ble Prime Minister, being President of Council of Scientific and Industrial Research, and if so, the action taken thereon?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir. The Governing Body of the CSIR felt that as the Engineers and Architects of the Engineering Unit at CSIR Headquarters are not contributing towards research, they may be classified as 'Administrative'.

(b) Yes, Sir. The matter is under consideration.

Gift Land (Amendment) Bill of Kerala

2327. **SHRI M. N. GOVINDAN NAIR:**

SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Union Government have sent back the Kerala State Government's Gift Land (Amendment) Bill,

(b) if so, reasons therefor;

(c) whether the Kerala State Government has requested the Centre to reconsider its decision in this regard; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b) Presumably, the question is referring to the Kerala

Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1978. The Government of Kerala had proposed certain amendments to the Kerala Land Reforms Act, 1963. The Government of India had no objection to most of the amendments, but felt that the State Government should reconsider the amendments to sections 84 and 85. The proposed amendment to Section 84, it was pointed out to the State Government, was not in accordance with the land reforms policy which had consistently sought to invalidate with retrospective effect, transfers made with a view to defeating the ceiling law. The amendment proposed to Section 85 is consequential to that proposed in Section 84.

(c) and (d) The State Government have suggested that the Central Government reconsider their views. The matter is under consideration.

Plan of Re-Cycling Industrial Waste

2328. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister for SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Dr. H. N. Sethna, Chairman of the Atomic Energy Commission has given a warning of indiscriminate exploitation of natural resources,

(b) whether Government propose to appoint a study group of Scientists and Technologists to draw a plan of re-cycling Industrial waste;

(c) whether the United Nations has set up a Committee of Experts to prepare a plan of action study on "Waste re-cycling for development"; and

(d) if so, the contribution of Indian Scientists on the above subject?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir: in his Presidential Address at the Indian Science Congress held in Bhubaneswar in January, 1977.

(b) The National Committee on Science and Technology (NCST) appointed a Panel of experts to make a study for re-cycling of industrial, community, agricultural and other

wastes. The panel, in its reports identified areas for further R&D in this field and these are being pursued. No study group is required at present.

(c) Government is not aware of any such Committee.

(d) Does not arise.

Spinning Mills for Polyester fibre

2329. SHRI S. R. REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have examined the feasibility reports for setting up of spinning mills for polyester fibre;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the location where these mills are likely to be set up and at what cost?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Spinning industry of man-made fibre has been de-licensed with effect from 25-11-1978 subject to certain conditions. The question of examining feasibility report for setting up spinning mills for polyester fibre does not, therefore, arise.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना

2330. डा० रामजी सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश से बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी योजना लागू करने का है और यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में पहले आश्वासन देने का है;

(ख) क्या एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को रोजगार और अन्य परिवारों के किसी सदस्य को रोजगार न मिलने से सामाजिक असमानताओं में वृद्धि होती है, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या समस्या के इस पहलू पर सरकार का विचार करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) भारत सरकार का इस समय कोई रोजगार गारंटी शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। यह माना जाता है कि किसी परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या परिवर्तनीय है अधिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं और यह आशा है कि चालू पंच वर्षीय योजना से, जो मूल रूप से रोजगारोन्मुख है, बेरोजगारों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

Achievements in Public sectors during Five Year Plans

2331. SHRI PIUS TIRKEY:

DR. BIJOY MONDAL:

SHRI SHANKER SINGHJI
VAGHELA:

SHRI SHYAM SUNDER
GUPTA:

SHRI G. M. BANATWALLA.
SHRI MUKHTIAR SINGH
MALIK:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment relating to the progress made in all the Five Year Plans;

(b) if so, whether there has been greater expansion and achievements

in the private sector as compared to the public sector during all the Five Year Plans; and

(c) if so, reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Every Five Year Plan document contains an assessment of the progress made in the previous Five Year Plan. The Draft Five Year Plan 1978-83 also contains an overall review of progress made since the First Five Year Plan as well as a more detailed assessment of the period 1960-61 to 1976-77.]

(b) The relative expansion of the public and the private sector during the Five Year Plans can be measured either by (i) the rate of growth in income generated by each sector, or by (ii) their respective shares in investment.

Data on a comparable basis of income generated in the two sectors is available only from 1960-61. This shows that the net domestic product of the public sector (at current prices) increased faster than that of the private sector in each of the Five Year Plans. The details are given in Statement I.

In terms of investment, while the share of the public sector has shown some fluctuations over the different Plans it has expanded over the period as a whole. Statement II indicates the respective shares of the Public and the private sectors during the different Plans.

(c) Does not arise.

Statement I.

Net Domestic Product : Public and Private (At Factor Cost)

Year	Net Domestic Product (at current prices)			Index (with 1960-61=100) for selected years		
	Public	Private	Total	Public	Private	Total
1960-61	1422	11913	13335	100.00	100.00	100.00
1961-62	1602	12783	14085			
1962-63	1836	13067	14903			

Year	Net Domestic Product (at current prices)			Index (with 1960-61 = 100) for selected years		
	Public	Private	Total	Public	Private	Total
1963-64	2133	14956	17089			
1964-65	2381	17767	20148			
1965-66	2743	18058	20801	192.90	151.58	155.99
1966-67	3068	21010	24078			
1967-68	3465	24847	28312			
1968-69	3939	24923	28862	277.00	209.21	216.44
1969-70	4471	27406	31877			
1970-71	5029	29667	34696			
1971-72	5643	31376	37019			
1972-73	6235	34458	40693			
1973-74	7238	43583	50821	509.00	365.84	381.13
1974-75	9584	50112	59696			
1975-76	11370	50494	61864			
1976-77	13140	53653	66793			
1977-78	14298	59091	73389	1005.49	496.02	550.35

- Source :— 1. For 1960-61 to 1969-70 : White Paper CSO (Oct. 1976).
2. For 1970-71 to 1974-75 : White Paper CSO (Jan. 1978).
3. For 1975-76 to 1977-78 : Quick estimates CSO (Jan. 1979).

Statement—II

Shares of public and private sectors in the total investment under the Five Year Plan

	Share of public sector	Share of private sector	Total
First Plan : 1951-56	33.0	67.0	100.0
Second Plan : 1956-61	43.0	57.0	100.0
Third Plan : 1961-66	50.4	49.6	100.0
Three Annual Plans 1966-69	41.8	58.2	100.0
Fourth Plan : 1969-74	41.1	58.9	100.0
Fifth Plan : 1974-79** (estimates)	52.7*	47.3	100.0
Actuals 1974-77	49.9	50.1	100.0
Sixth Plan 1978-83** (estimates)	55.8*	44.2	100.0

*Excluding inventories in the Public Sector.

**Source : Plan Document.

Source :—C.S.O. National Accounts Statistics.

Amount spent on Developmental Planning during the Five Year Plans

2332. SHRI PIUS TIRKEY:

DR. BIJOY MONDAL:

SHRI SHANKAR SINGHJI

VAGHELA:

SHRI SHYAM SUNDER

GUPTA:

SHRI G. M. BANATWALLA:

SHRI MUKHTIAR SINGH

MALIK:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have seen the Press report in the Blitz dated the 27th January, 1979 under the heading "30 years after freedom half of India starves"; and

(b) if so, total amount spent by the Government in First, Second, Third, Fourth and Fifth Five Year Plans for developmental planning in public and private sectors of the country and the results achieved?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir. Government consider that the assessment is not factual. Over this period substantial advances have been made in expanding the economy, improving agricultural Productivity and diversifying the country's industrial base. Despite the rapid growth of population, a modest growth of per capita income has been maintained. However, the members of unemployed and under-employed are still very high. More than 40 per cent of population lives below the poverty line though

not at starvation levels. Eradicating poverty and unemployment are the stated aims of the new Five Year Plan, which calls for a radical restructuring of investment priorities and appropriate supporting policies.

(b) Two statements, one indicating the Plan Outlays and Expenditure incurred from the First Plan onwards and the other indicating achievements in physical terms, are placed on the Table of the House.

Statement I

Plan Outlay/Expenditure from First Plan onwards

Period	Amount (Rs. crores)
First Plan	1960.0
Second Plan	4672.0
Third Plan	8577.0
Annual Plans :—	
1966-67 to 1968-69	6625.0
Fourth Plan	15779.0
1974-75 Actuals	4928.4
1975-76 Actuals	6416.9
1976-77 Actuals	8081.7
1977-78 Anticipated	9564.4
1978-79—Outlay	11650.2
1979-80—Outlay	12510.6

Statements II

Principal Targets and Achievements.

Item	Unit	First Plan (1951-56)		Second Plan (1956-61)		Third Plan (1961-66)		Ann. Plans (1966-69)		Fourth (1969-74)		Fifth Plan (1974-78)	
		Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.
		(55-56)	(55-56)	(60-61)	(60-61)	(65-66)	(65-66)	(66-67)	(66-67)	(73-74)	(73-74)	(78-79)	(77-78)
Foodgrains	. Mill. Tonns.	62.6	66.9	81.8	82.0	101.6	72.3	94.0	129.0	103.6	125	121.00	
Cotton	. Mill. bales	4.1	4.0	6.4	5.3	6.9	4.6	5.1	8.0	5.8	8.0	6.4	
Oilseeds	. Mill. tonns.	5.6	5.7	7.7	7.0	10.0	6.4	6.4	10.5	8.7	12.0	9.2	
Jute	. Mill. bales	5.4	4.2	5.5	4.1	6.1	4.5	2.9	7.4	6.2	7.7	N.A.	
Tea	. '000 tonns.	285	22.8	318	322	408	366	402	450	..	..	N.A.	
Net area Irrigated	Mill. Hect.	..	..	27.5	24.6	36.4	26.3	83.1	..	32.0	..	N.A.	
Iron Ore	. Mill. tonns.	4.1	4.4	12.7	11.0	32.5	18.1	59.6	51.4	34.4	56	43.00	
Coal	. Do.	39.6	39.0	61.0	55.7	98.6	70.3	218.3	93.5	81.2	124	103.20	
Finished Steel	. Do.	1.7	1.3	4.4	2.4	6.8	4.5	13.2	8.1	4.4	9.4	N.A.	
Aluminium	. '000 tonns.	12.2	7.4	25.4	18.3	80.0	62.1	298.6	220.0	148.0	310	180	
Sugar	. Mill. tonns.	1.5	1.9	2.3	3.0	3.5	3.6	8.0	4.7	..	5.4	N.A.	
Cement	. Mill. tonns.	4.9	4.7	13.2	8.0	13.0	10.8	34.8	18.0	14.7	20.8	19.20	

Setting up of Rural Growth Centres

2333. SHRI P. V. PERIASAMY:
Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number and State-wise break-up of Rural Growth Centres established under the auspices of district industries centres;

(b) the quantum of financial assistance given to them by the Financial Institutions of both the Central and State Governments; and

(c) the number of Rural Growth Centres that have started production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Rural Growth Centres depending upon the growth potential are identified by the State Governments. However, the Centrally sponsored Scheme of District Industries Centres was launched in May, 1978 for the effective development of small scale and cottage industries and for their dispersal towards rural areas. 263 District Industries Centres in 22 States and 6 Union Territories have been approved so far under the Scheme. The remaining districts are likely to be covered in a phased manner during the next financial year.

(b) Information in regard to provision of credit facilities by the financial institutions is available for 144 District Industries Centres. The financial institutions have provided credit facilities amounting to Rs. 41.16 crores in the reporting District Industries Centres.

(c) The production units are to be established at the growth centres. The growth centres by themselves are not engaged in production activities.

Take over of Cement Factory, at Sawai Madhopur

2334. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU:
SHRI S. S. SOMANI:
SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal with the Government to take over the cement factory (Jaipur Udyog) at Sawai Madhopur in Rajasthan; and

(b) if so, at what stage the proposal stands?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir. The cement unit of Jaipur Udyog at Sawai Madhopur in Rajasthan is proposed to be taken over under the control of Cement Corporation of India.

(b) Necessary legislation in this regard will be introduced in the Parliament.

Duty on Import of Spare Parts for Watches

2335. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the total number of small and medium scale units engaged in the manufacture of watches and their spare parts;

(b) whether the current policy of Government allows 75 to 250 per cent duty for importing raw materials for spare parts and accessories for watches, while the duty on finished imported spare parts is only 50 per cent; and

(c) whether Government propose to produce indigenously spare parts for watch industry and allow them equitable distribution of raw material required?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) 24 units in the small scale sector and 13 units in the organised sector were engaged in the manufacture of watches and their spare parts upto the end of 1978.

(b) Horological brass, which is one of the raw materials used in the manufacture of watch components attracts a customs duty of 60 per cent plus 15 per cent auxiliary duty under the current notification. Similarly, super alloy steel strips, another item used in the manufacture of watch components attracts duty of 220 per cent ad valorem. Synthetic ruby for watch jewels attracts customs duty aggregated to 75 per cent. In addition, countervailing duty has been prescribed separately for these raw materials. On the other hand, the import duty on watches and watch parts is 50 per cent for the manufacturing units whose production programme has been duly approved by the Government.

(c) No, Sir.

Training of boys in I.T.Is. sponsored by H.M.T.

2336. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state whether the H.M.T. has drawn up a scheme to train young boys in rural I.T.Is. to be sponsored by the H.M.T.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI MATI ABHA MAITI): HMT have in all their units full-fledged training centres for training young boys (Matri-ulates) as apprentices under the Apprenticeship Act.

Year-wise Demand, Supply and Price of paper

2338. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) internal demand and production of paper in the country (year-wise) from 1976 to 1978; and

(b) average retail price of paper per Kg. year-wise from 1976 to 1978?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI

JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The production of paper and paper board in the country from 1976 to 1978 is as follows:—

Year	Production of Paper and Paper Board (in lakh tonnes)
1976	8.80
1977	9.37
1978	10.00

The domestic production and the demand of common varieties of Paper and Paper Board were evenly balanced in 1976 and 1977 and it was necessary to resort to import only in respect of speciality varieties of paper such as electrical insulation papers, filter paper etc. The imports were of the order of about 5000 tonnes per annum. However, during 1978-79 the demand for writing and printing papers has not been fully met from domestic production, and taking into account the scale of imports required, the total demand for paper and paper board for the year 1978-79 may be estimated as 10.5 lakh tonnes.

(b) As there are a large number of varieties and qualities of Paper, no authentic data about the average retail price of Paper per Kg. are available. According to the data of wholesale prices compiled by the office of the Economic Adviser Ministry of Industry, the wholesale Index Number of Paper and Paper Board was 179.7 in December, 1976, 185.4 in December 1977 and 198.1 in December 1978.

Committee set up to review the operations of Investigating Agencies

2339. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether in the wake of the Shah Commission's report the Gov-

ernment set up an informal Committee to review the operations of the intelligence and investigating agencies—the IB and CBI mainly;

(b) if so, when the Committee was set up, composition of the Committee, designation and particulars of the members of the Committee and terms of reference of the Committee;

(c) whether the report of the Committee will be laid on the Table of the House; and

(d) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir.

(b) The Committee was set up on 7th August, 1978 and its composition is as follows:—

- | | |
|--|-------------------|
| (i) Shri L.P. Singh, Governor of Assam, Manipur, Meghalaya Nagaland and Tripura | Chairman. |
| (ii) Shri M.M.L. Hooja, Retired Director, Intelligence Bureau | Member. |
| (iii) Shri D.P. Kohli, Retired Director, Central Bureau of Investigation | Member. |
| (iv) Shri B.S. Raghavan, Additional Secretary, Ministry of Agriculture and Irrigation, (Deptt. of Food), Government of India | Member-Secretary. |

The Committee has been asked to review the working of the Intelligence Bureau and Central Bureau of Investigation in the light of the observations contained in the first two interim reports of the Shah Commission and recommend suitable measures for their proper functioning in the national interests safeguarding the rights of individuals and preventing harassment to citizens.

(c) and (d) The Government will consider the matter after the Report is received.

Per Capita Plan Outlay

2340. SHRI JYOTIRMOY BOSU:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) per capita plan outlay, (State-wise and Union Territory-wise) during the Fifth Plan period;

(b) per capita outlay (State-wise and Union Territory-wise) in the Sixth Five Year Plan;

(c) per capita Central Plan assistance, (State-wise and Union Territory-wise) during the Fifth Plan period and in the Draft Sixth Plan;

(d) whether regional imbalance in per capita plan expenditure is on the increase; and

(e) if so, factors responsible for the same?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) A statement giving the per capita Plan outlay State-wise and Union Territory-wise during the Fifth Plan (1974—78) is attached.

(v) Five Year Plan 1978—83 (Sixth Plan) of States and Union Territories have not been finalized so far.

(c) The per capita Central assistance State-wise and Union Territory-wise during the Fifth Plan (1974—78) period is shown in the attached statement. The distribution of Central assistance during the Sixth Plan is being worked out.

(d) and (e) Since the Five Year Plans of States and Union Territories for 1978—83 have not been finalized so far, it is not possible to answer these parts of the question at this stage.

Statement

FIFTH PLAN 1974-78.

Per Capita outlay and Central Assistance

(Rs.)

State/Union Territory	Per Capita Expenditure	Per Capita Central Assistance
1	2	3
1. Andhra Pradesh	236	80
2. Assam	190	152
3. Bihar	155	73
4. Gujarat	376	84
5. Haryana	481	114
6. Himachal Pradesh	467	340
7. Jamm u & Kashmir	603	794
8. Karnataka	276	80
9. Kerala	224	94
10. Madhya Pradesh	254	74
11. Maharashtra	372	56
12. Manipur	646	464
13. Meghalaya	705	515
14. Nagaland	1359	1047
15. Orissa	207	114
16. Punjab	531	104
17. Rajasthan	237	105
18. Sikkim	1163	1493
19. Tamil Nadu	201	83
20. Tripura	320	275
21. Uttar Pradesh	237	91
22. West Bengal	200	57
TOTAL—STATES	262	95

1	2	3
1. Andaman & Nicobar	1856	1056
2. Arunachal Pradesh.	907	907
3. Chandigarh	1059	565
4. Dadra and Nagar Haveli	773	773
5. Delhi	609	444
6. Goa, Daman and Diu	700	635
7. Lakshdweep	1191	1191
8. Mizoram	1027	1027
9. Pondicherry	522	9
TOTAL—UNION TERRITORIES.	699	561

Supply of Essential Raw Material at subsidised rates

2341. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI A. R. BADRI:
NARAYAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Union Government propose to make available essential raw materials to the small units at subsidised rates;

(b) if so, when the final decision is likely to be taken; and

(c) whether Union Ministry have prepared any scheme in this regard and have discussed this with other concerned departments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c) While action to facilitate the availability of essential raw materials to the small units is being taken from time to time, there is no proposal at present to make available raw materials at subsidised rates to the small scale units.

Cooperation in Nuclear Research Projects with Other Countries

2342. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI R. V. SWAMINATHAN:

Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India is cooperating with a number of Asian countries including Pakistan and Bangladesh in a series of nuclear research projects;

(b) if so, the details of the fields in which India is cooperating; and

(c) India's contribution towards it?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) The cooperation is within the framework of the IAEA Regional Co-operative Agreement for research, development and training related to nuclear science and technology. India is cooperating in the fields of neutron scattering techniques in applied research, radiation preservation of fish, grain legume production, industrial radio-isotope applications, health related environmental research and improving domestic buffalo production.

(c) India's contribution towards these programmes is mainly through research activities in these areas, provision of the services of experts and hosting research coordination meetings.

Manufacture of Paper from Bagasses

2343. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI M. V. CHANDRA-
SHEKHARA MURTHY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Union Cabinet has cleared a scheme to explore possibilities of manufacturing paper and news print from bagasses;

(b) if so, what are the details of the same; and

(c) whether implementation of this scheme will make available paper and newsprint valued at Rs. 800 crores?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c) The need for encouraging the increased use of bagasse in the manufacture of paper and newsprint has been accepted in principle. Details of the scheme are yet to be finalised.

Industrial Cooperation with E.E.C.

2344. SHRI DHARM VIR VASISHT:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to seek augment and maintain industrial cooperation with E.E.C. countries; and

(b) whether some preferential treatment had been accorded by EEC in respect of certain industries/products?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b) Various steps have been taken including bridging the communication

gap, dissemination of information and publication of Indian capabilities and expertise for strengthening industrial cooperation between India and the E.E.C. countries. Recently a seminar was held by the Engineering Export Promotion Council on Trade and Industrial Cooperation between India and E.E.C. countries which included participants from the E.E.C. countries. The main facility accorded by the E.E.C., is the Generalised System of Preferences (GSP). Exports of engineering goods from India are benefiting from these facilities.

Pottery Industry

2345. SHRI DHARM VIR VASISHT:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government had introduced power in pottery industry;

(b) if so, with what results;

(c) whether there were still complaints of shortage of coal from potters; and

(d) if so, steps taken by Government to give relief to the industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Power is used in pottery industry by mangalore tile units, whiteware pottery producers and traditional potters using power-driven wheel.

(b) The production capacity of artisans using power-driven wheel has increased by 50 to 100 per cent.

(c) No complaints have been received from individual potters about shortage of coal.

(d) Does not arise.

Staff Categorisation by CSIR

2346. SHRI DHARM VIR VASISHT: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Council of Scientific and Industrial Research had taken decisions on staff categorisation; if so, the nature of the same;

(b) whether some sections of its employees were agitating or protesting against the decisions taken; if so, by which sections and why; and

(c) the steps taken to pacify them?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir. The staff in CSIR has recently been classified into 3 categories as scientific, technical and administrative against four categories of 'Scientific', 'Technical', 'Auxiliary Technical' and 'Administrative' existing earlier.

(b) and (c) Yes, Sir. The Civil Engineering, Architectural and Stores and Purchase staff who have been categorised as 'administrative' have represented that they should be classified as technical. The matter is being considered.

Chief Ministers' Conference on curbing Communal Virus

2347. SHRI ABDUL AHAD VAKIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the concrete conclusions arrived at in the recent Chief Ministers' Conference for fighting and curbing communal virus in the country; and

(b) whether any special machinery will be set up to implement the decisions of the above conference?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b) At the Chief Minister's Conference held in December, 1978 it was decided to set-up a Committee to deal with the problem of communalism. The Home has already been informed

of the composition of the Committee in reply to Unstarred Question No. 364 answered on 21-2-79. (Copy enclosed for ready reference). The first meeting of the Committee was held on 24-2-1979. The Committee will consider whether there is need for any special machinery for implementing and monitoring its decisions.

Applications for Import of Computer Systems

2348. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) the number of applications received for the import of computer systems during the current year;

(b) the number of applications processed by the Department out of them; and

(c) the names of the organisations for whom the computer systems (applications) have been cleared during the current year?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (c) Of the 47 enquiries for import of 86 computer systems received, approvals have been given to the following 11 users for the import of 12 systems between April 1, 1978 and February 28, 1979:—

1. M/s. Informatics, Bombay.
2. Shri S. K. Punwani, Bombay.
3. M/s. Electronics Technology Co. Ltd., Bangalore.
4. The Central Machine Tool Institute, Bangalore.
5. M/s. Rading Cybernetics Pvt. Ltd., Hyderabad.
6. The Societe Internationale De Telecommunications Aeronautique, Bombay.
7. M/s. Computer Maintenance Corporation, Bombay.
8. Jaslok Hospital, Bombay.

9. Radar Communications and Project Office, Ministry of Defence, New Delhi. (2 systems).

10. M/s. M. A. S. Services Pvt. Ltd., New Delhi.

11. Systems Group, Department of Electronics, New Delhi.

Reservation of Goods for Small Scale Industries

2349. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether his Ministry are considering a proposal to reserve the manufacture of certain goods exclusively for small scale sector;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what would be the impact on the existing large scale units which have been producing the same goods by the proposed reservation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c) The Government have in its Industrial Policy Statement of December, 1977 announced that whatever can be produced by small and cottage industries must only be produced by these sectors. The list of industries which are to be exclusively reserved for the small scale sector has been expanded from time to time and is continually reviewed so that capacity created does not lag behind the requirements of the economy and also to ensure that the reservation accorded to this sector is efficient and is expanded as new products and new processes capable of being manufactured in the small scale are identified. Once an item is reserved for production by these sectors, further licensing of capacity in large and medium scale units is not allowed, except on considerations of 100 per cent exports on a continuing basis. Further, when an item is reserved for the small scale

sector, such of those units which did not require an industrial licence but were engaged in the manufacture of such items are required to take Carrying on Business Licences. While fixing capacities in the C.O.B. licences, the production achieved by these units prior to the reservation is taken into account.

Agreements for Cooperation in the field of Electronics

2350. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) the names of the countries with whom agreements for cooperation in the field of electronics have been signed during the current year; and

(b) the details in respect of the value of exports, imports and provisions for joint ventures in third countries as enunciated in those agreements?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The European Economic Community USSR, Bulgaria GDR and Hungary.

(b) The agreements relate to Trade and Technical Cooperation in Electronic materials, components and equipment between India and the respective countries, and contain provisions regarding exploration of possibilities of cooperative ventures in third countries.

एम. पी. एन. टी. सी द्वारा बचा गया निर्यात का कपड़ा

2351. श्री हुकम चन्द कच्छबाव: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. पी. एन. टी. सी. द्वारा कुछ पाटियों को बचा गया निर्यात का कपड़ा वापिस लेना पड़ा था क्योंकि वह बिका नहीं था और पाटियों ने उसके लिए भुगतान नहीं किया था, यदि हाँ, तो ऐसा कितना कपड़ा, पाटीवार वापिस लिया गया

(ब) क्या कारपोरेशन ने इस कण्डे पर सारे सारा प्रतिफल की छूट दी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो कारपोरेशन ने इस प्रकार किसकी राशि धरा की ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगज्जन्धी प्रसाद बाबू) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सत्रासप्तत पर रख दी जाएगी ।

बड़े उद्योगों पर लघु एककों के लिए भारित वस्तुओं का उत्पादन करने पर रोक

2352. श्री बभुना प्रसाद साहू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग द्वारा उत्पादनायें भारित 504 उपशोभता वस्तुओं में से उन वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनके उत्पादन के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों पर वर्ष 1978 के अन्त तक पूरी रोक लगा दी गई है; और यदि उनके किये इनमें से किसी वस्तु के उत्पादन पर प्रतिबन्ध अभी तक नहीं लगा है तो फिर उसके उत्पादन को लघु उद्योग के लिए भारित करने का क्या अभिप्राय रह जाता है; और

(ख) क्या बमड़े, साबुनो, माचिसों तथा कपड़ों का उत्पादन भी वित्त वर्ष 1979-80 तक पूरी तरह लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग के लिए भारित कर दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगज्जन्धी प्रसाद बाबू) : (क) और (ख) सरकार की 26 अप्रैल, 1978 की प्रधिसूचना द्वारा केवल लघु क्षेत्र में विकास किए जाने हेतु 807 वस्तुओं को भारित कर दिया गया है। इनमें बमड़े के जूते, कपड़े धोने का साबुन, एवं दिया सलाई शामिल हैं। औद्योगिक नीति विवरण का अनुच्छेद 14 यह स्पष्ट करता है कि सरकार वस्तुओं के उत्पादन में कांजी संख्या में लगे लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले हथकरवा व विद्युतकरवा क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से संगठित क्षेत्र की निम्नो व विद्युत-करवा क्षेत्र में बुनाई समता के विस्तार की अनुमति नहीं देगी ।

सरकार ने लघु उद्योगों के लिए भारित वस्तुओं का विद्यमान बड़े एककों द्वारा उत्पादन करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ।

औद्योगिक नीति विवरण के अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बड़े वृहत् से संबद्ध या गैर-सम्बद्ध ऐसे बड़े एककों को, जो लघु क्षेत्र के लिए भारित वस्तुओं का पहले से उत्पादन कर रहे हैं, उनकी समता में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर इन वस्तुओं की कुल अमता में इन एककों के अंश को घटि-घटि कर दिया जाएगा और लघु तथा कुटीर क्षेत्र के अंश को बढ़ाया जाएगा ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2353. श्री बभुना प्रसाद साहू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, देश के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को आकर्षक में रियायत तथा रियायती दरों पर पानी, बिजली तथा भूमि देने के बारे में सरकार द्वारा घोषित नीति के अधीन वर्ष 1978-79 के दौरान देश के प्रत्येक पिछड़े जिले में स्थापित किये गये उद्योगों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगज्जन्धी प्रसाद बाबू) : पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1978 में कुल 146 आवाय-यन तथा 103 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे जिनका राज्यवार और विवरण II में दिया गया है। वर्ष, 1978 में पिछड़े क्षेत्रों के कुल 172 औद्योगिक एकक तकनीकी विकास के महामन्त्रालय द्वारा पंजीकृत किए गए थे, जिनका राज्यवार और विवरण-III में संलग्न है ।

केंद्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1978 में विभिन्न राज्यों के उद्योग निवेशियों में 7741 लघु एकक पंजीकृत किये गये थे । लघु क्षेत्र में पंजीकृत एककों का राज्यवार और विवरण-III में दिया गया है ।

विबरण — 1

वर्ष 1978 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किये गये आश्वासनों (पा० प०) तथा औद्योगिक लाइसेन्सों (सी० ला०) के आव्यवार जारी की गयानिवाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	एल० आई०	आई० एल०
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	8	9
2	अरुणाचल प्रदेश निकोबार	1	1
3	आसाम	1	1
4	बिहार	1	4
5	दादर एण्ड नगर हवेली	—	—
6	गोवा, दमन एण्ड डीव	3	2
7	गुजरात	22	10
8	हरियाणा	5	2
9	हिमाचल प्रदेश	9	3
10	जम्मू एण्ड काश्मीर	3	2
11	कर्नाटक	2	7
12	केरल	3	2
13	मध्य प्रदेश	15	2
14	महाराष्ट्र	14	19
15	मणिपुर	—	—
16	मेघालय	—	—
17	नागालैण्ड	—	—
18	उड़ीसा	4	—
19	पश्चिम बंगाल	1	—
20	पंजाब	3	2
21	राजस्थान	19	5
22	तमिलनाडु	13	10
23	त्रिपुरा	—	—
24	उत्तर प्रदेश	8	10
25	पश्चिमी बंगाल	11	11
कुल योग : .		146	103

* राज्य निर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

विवरण—II

1978 में तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत पिछड़े क्षेत्रों के एवको का राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य	संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	9
2	बिहार	4
3	गुजरात	29
4	गोवा, दमन एण्ड दीव	3
5	हिमाचल प्रदेश	3
6	हरियाणा	3
7	जम्मू एण्ड कश्मीर	3
8	केरल	4
9	कर्नाटक	8
10	महाराष्ट्र	28
11	मध्य प्रदेश	18
12	तमिलनाडू	15
13	उड़ीसा	2
14	पंजाब	8
15	राजस्थान	15
16	उत्तर प्रदेश	13
17	पाण्डिचेरी	1
18	पश्चिमी बंगाल	6
कुल योग		172

विवरण—III

1978 में विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के पंजीकृत लघु एवको की संख्या दर्शानेवाला विवरण।

राज्य	एवको की संख्या
1 आन्ध्र प्रदेश	521
2 आसाम	उ० न०
3 बिहार	121
4 गुजरात	247
5 हरियाणा	उ० न०
6 हिमाचल प्रदेश	6
7 जम्मू एण्ड कश्मीर	उ० न०
8 कर्नाटक	274
9 केरल	221

10 मध्य प्रदेश	1463
11 महाराष्ट्र	55
12 मनीपुर	उ० न०
13 मेघालय	उ० न०
14 नागालैण्ड	उ० न०
15 उड़ीसा	54
16 पंजाब	517
17 राजस्थान	1502
18 सिक्किम	उ० न०
19 तमिल नाडु	367
20 त्रिपुरा	उ० न०
21 उत्तर प्रदेश	1440
22 पश्चिमी बंगाल	749
23 अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप	उ० न०
24 अरुणाचल प्रदेश	उ० न०
25 दादर एण्ड नगर हवेली	3
26 गोवा दमन एण्ड दीव	75
27 लक्षद्वीप	उ० न०
28 मिजोरम	7
29 पाण्डिचेरी	119
कुल योग	7711

उ० न०—उपलब्ध नहीं

६ द्वीय जाच भूरो द्वारा मामलों की जांच

2154 श्री हरमोहिन्द वर्मा क्या गृह मंत्री यह बयान की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय जाच भूरा न गत नवम्बर, 1978 में कितने मामलों का जाच की,

(ख) जाच से कितन राजपत्रित अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और अन्य व्यक्ति सम्बन्धी है, और

(ग) सरकार ने इन व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (एच० डी० पाटिल) तथा निधि, न्याय और कार्य मंत्रालय

(क) 932।

(ख) 758 राजपत्रित स्तर के अधिकारी, 447 अन्य सरकारी कर्मचारी और 791 गैर-सरकारी व्यक्ति।

(ग) उपर्युक्त में से कुल 287 मामलों में ही अब तक जांच पूरी हुई है जिनमें 709 व्यक्ति अन्तर्गत है और उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई कार्रवाई निम्न प्रकार है —

क्रम सं० कार्रवाई हेतु सिफारिश / की गई कार्रवाई	राजपक्षित स्तर के अधिकारियों की संख्या	अन्य सरकारी कर्मचारियों की संख्या	गैर-सरकारी व्यक्तियों की संख्या	योग
1	2	3	4	5
1 न्यायालय में विचारण के लिए भेजे गए।	39	44	71	154
2 सम्बन्धित मंत्रालय / विभाग को नियमित विभागीय कार्रवाई किए जाने के लिए भेजे गए।	1 38	123	19	280
3 सम्बन्धित मंत्रालय / विभाग की उचित समझी जाने वाली कार्रवाई किए जाने के लिए भेजे गए।	25	11	—	36
4 वे मामले जिन्हें बन्द कर दिया गया / समाप्त कर दिया गया / अन्यथा निपटा दिया गया।	39	16	116	221
5 न्यायालय में विचारण के लिए और नियमित विभागीय कार्रवाई किए जाने के लिए भेजे गये।	4	3	5	12
6 न्याय निर्णयन के लिए भेजे गए।	—	—	6	6
योग	245	197	267	709

Closure of Indian Tool Manufacturers Ltd., Bombay

2355. SHRI C. K. CHANDRAPPA. Will the Minister of INDUSTRY be please to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Tool Manufacturers Ltd., 101 Sion Road, Bombay, one of the largest and most important firms in engineering cutting tool industry, belonging to the House of Birlas had given notice of closure some time ago, rendering 1000 workmen unemployed;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the financial position of this firm was quite sound when they threatened closure;

(d) if so, what action Government had taken against this firm;

(e) whether Government received a memorandum urging for nationalisation of this Birla firm from Mumbai Kamgar Union; and

(f) if so, what was the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (f) On 1st November, 1978 the Indian Tool Manufacturers Ltd., Bombay, gave a notice of its intention to close its unit at Sion, Bombay on or after 4-2-1979 on grounds of heavy wage burden as a result of demands of workers for increased dearness allowance. With the intervention of the Government of Maharashtra a settlement has been reached on 24th January, 1979 between the management and representative labour union as a result of which the notice of closure has since been withdrawn. The agreement has been filed with the State Government.

Expansion of I.S.R.O. at Thumba

2358. SHRI C. K. CHANDRAPPAN:
Will the Minister of SPACE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration for further expansion and development of the ISRO at Thumba in Kerala;

(b) if so, the details thereof;

(c) what are the types of space research activities going on in this station at present; and

(d) what are the results of it?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) To achieve the goals and objectives of the Indian space programme, certain facilities would need augmentation in ISRO Centres including the Vikram Sarabhai Space Centre.

(b) Details have still to be finalised.

(c) and (d) The space research activities at the Vikram Sarabhai Space Centre are geared mainly towards indigenous development of sounding rockets and satellite launch vehicles with their associated control and guidance systems and electronics. The major activities and achievements of this Centre are set out in the Annual Report of the Department of Space for the year 1977-78 and in the Performance Budget for 1978-79 copies of which are available in the library of the Parliament.

Attacks by Nagas

2357. SHRI BHAUSAHEB THORAT:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) at how many places Nagas made attacks during the last six months; and

(b) the steps taken by Government to safeguard the lives and properties of the people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Setting up of Mini Cement Plants in Public Sector

2358. SHRI BHAUSAHEB THORAT:
Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have any plan to set up mini-cement plants in the public sector to increase the production of cement; and

(b) if so, capacity and locations of each plant and also the approximate period by which they will go into production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) Cement Corporation of India is examining Techno-economic feasibility for setting up mini cement plants with the capacities of 208 TPD based on dry process rotary kiln technology at the following places:—

Sl. No.	Location	Capacity (in tonnes)
1	Dharamkot	Himachal Pradesh . 66,000
2	Lumpshnong	Meghalaya . 66,000
3	Garampani	Assam . 66,000

Five letters of intent have been granted to Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation, Jaipur.

1. Jaiteran, Dt. Pali . . . 33,000
2. Bilera, Dt. Jodhpur . . . 33,000
3. Kotputli, Dt. Jaipur . . . 33,000
4. Abrol Akhva, Dt. Sirohi . . 33,000
5. Nim-Ka Thana, Dt. Sikar . . 33,000

D.G/T.D. has registered one mini cement plant scheme of Orissa State Industrial Development Corporation.

1. Kiringsera, Dt. Sundergarh 33,000
- The gestation period for setting up of mini cement plant would be about 2-3 years.

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना —
के कार्य में प्रगति

- 2359 श्री रामानन्द तिवारी :
श्री के 0 लक्ष्मी :
श्री माधव राव सिधपाय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 में कितने जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि लक्ष्मी की तुलना में प्रगति की गति धीमी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं, और इस बारे में क्या उपचारार्थक कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनमोहन प्रसाद खन्ना) : (क) आगामी वित्तीय वर्ष में देश में सभी जिलों की प्राथमिकता के

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन शामिल कर लिये जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) कार्यक्रम के प्राथमिकता क्रमानुसार को देखते हुए प्रगति संतोषजनक हुई है । विसम्बर, 1978 के अंत तक विद्यमान जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चलता है कि सूचना देने वाले जिला उद्योग केन्द्रों ने विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए 36,288 उद्योगों का पता लगाया गया है । 9,790 परियोजनाओं की विषय स्पष्टता तयार की गई है और इसके परिणामस्वरूप विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र में 22,894 एकक स्थापित किये गये हैं जिसमें करीब 30 प्रतिशत सचु एकक हैं । सूचना देने वाले जिला उद्योग केन्द्रों में जिन एककों का अनन्तिम अथवा स्थायी पंजीकरण किया गया है, उनकी कुल संख्या 30,012 है और इन जिला उद्योग केन्द्रों में औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ जाने से अब तक 79,771 प्रतिरिक्त व्यक्तियों की रोजगार मिला है ।

(ग) जिला, राज्य, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्य का समय समय पर निरीक्षण तथा समीक्षा की जा रही है । जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों के प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, और प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र के लिए एक कार्य सम्पन्न की कार्यक्रम तयार किया जा रहा है तथा जिला उद्योग केन्द्र, एकीकृत ग्रामीण विकास खण्ड व । विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ।

आय वितरण में असमानता

2360. श्री रामानन्द तिवारी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 30 वर्षों में आय वितरण में असमानता बढ़ी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार इन प्रांकों में दवायी गई स्थिति से सतुष्ट है, और

(ब) यदि नहीं, तो क्या प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) समस्त जनसंख्या को समाविष्ट करने

सारिणी

भारत में की जनसंख्या के दुबल समूहों के उपभोक्ता व्यय में प्रतिशत भाग

दुबल समूह	1960-61	1965-66	1969-70	1973-74
ग्रामीण				
सबसे नीचे के 20 प्रतिशत	8.2	9.0	8.9	9.3
सबसे नीचे के 50 प्रतिशत	28.4	29.9	30.2	31.5
ऊपर के 20 प्रतिशत	41.1	38.8	39.4	38.0
शहरी				
सबसे नीचे के 20 प्रतिशत	7.6	8.2	7.9	9.0
सबसे नीचे के 50 प्रतिशत	26.6	27.3	27.0	29.2
ऊपर के 20 प्रतिशत	43.4	42.8	43.4	40.6

उपयुक्त प्रांकों से दिखाई देना है कि उपभोग व्यय में असमानताएँ बढ़ी नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत इस अवधि में कुछ कम हुई हैं।

(ग) 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप के प्रधान उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है ग्राम और संपत्ति की वर्तमान असमानताओं में पर्याप्त कमी करना, और इस दस्तावेज में इस प्रयोजन के लिए अनेक नीति सम्बन्धी उपायों की रूपरेखा दी गई है।

(घ) सरकार ऐसे सर्वेक्षण की आवश्यकता को प्रति जागरूक है। इसको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के एक भागीदार में शामिल करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण समूह की अध्यक्षता परियोजना के रूप में विचार कर रही है।

Check on Investment by Industrial Units in Creating New Subsidiaries

2361. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state what action Gov-

ने वाले परिवारिक धन से सम्बन्धित कोई व्यापक और विश्वसनीय प्रांकें अब तक उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 1960-61 से लेकर 1973-74 तक की अवधि के लिए विभिन्न दौर में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण समूह द्वारा एकत्र किए गए पारिवारिक उपभोग व्यय से सम्बन्धित प्रांकें से विभिन्न दुबल समूहों के सम्बन्ध में उपभोग व्यय का निम्नलिखित वितरण दिखाई देना है :—

ernment have taken to ensure that one industrial unit does not invest in another thereby creating its subsidiaries and branches?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): Inter-corporate investment by Companies registered under the Companies Act, 1956 are governed by Section 372 of the said Act. Further tightening of these restrictions and also imposition of an absolute limit on such investment and purpose for which investments could be made have been suggested by the Sachar Committee in Chapter IX of its report. The report of the said Committee was laid on the Table of Lok Sabha on 30th August, 1978.

Facilities for Setting up of Heavy Industries in Hill Areas of U.P.

2362. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any scheme under which facilities are given to those interested in setting up of heavy industries in hill regions; and

(b) if so, the details thereof and whether these facilities have been given to some one?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):

(a) and (b) There is no specific scheme under which facilities are given to those interested in setting up of heavy industries in hill regions of U.P. However, under the Transport Subsidy Scheme, all industrial units set up in hill districts of U.P. viz. Dehra Dun, Nainital, Almora, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Pithoragarh, Uttar Kashi and Chamoli are eligible to subsidy at the rate of 50 per cent of the transport costs of raw materials and finished goods from the nearest specified rail head to the location of the industrial unit and *vice-versa*.

Almora district is also included in the list of districts eligible for Central Investment Subsidy. Industrial units set up in this district are, therefore, eligible to investment subsidy at the rate of 15 per cent of the fixed capital investment subject to a maximum of Rs. 15 lakhs.

Almora, Chamoli, Pithoragarh, Tehri Garhwal and Uttar Kashi are also included in the list of industrially backward districts and the Central Government offers the following incentives for industrial development:

(i) Concessional Refinance Scheme of Industrial Development Bank of India.

(ii) Deduction in income-tax.

(iii) Consultancy for Technical Services.

(iv) Registration of new units and expansion of existing units in res-

pect of items which are otherwise banned in the country.

(v) Interest Subsidy.

(vi) Supply of machinery on concessional terms by the National Small Industries Corporation Limited.

(vii) Special facilities for importing raw materials.

Rs. 115 crores for Development of Rural Industries

2363. SHRI K. PRADHANI:
SHRI DALPAT SINGH
PARASTE:
SHRI CHHITUBHAJ
GAMIT:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has decided to release Rs. 115 crores for the development of rural industries in the country; and

(b) if so, the details regarding its utilisation and distribution, State-wise?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) A total outlay of Rs. 234.45 crores has been provided for village and small industries in the Annual Plan for 1978-79 consisting of Rs. 154.93 crores under the Central Plan and Rs. 79.52 crores under the States and Union Territories Plans. This sector includes rural industries (viz. handlooms, khadi and village industries, handicrafts sericulture and coir industry), powerlooms, modern small scale industries and industrial estates.

(b) A Statement showing approved outlays and anticipated expenditure during 1978-79, State-wise/Union Territory-wise, for (i) total for village and small industries (ii) rural industries viz. handlooms, khadi and village industries, handicrafts, sericulture and coir industry, is attached.

Statements

Approved outlays and anticipated expenditure for Annual Plan 1978-79 under States/Union Territories
Plans for Village & Small Industries.

(Rs. lakhs)

Sl. No.	State/Union Territories	1978-79			
		Approved outlay		Anticipated Expenditure	
		Total (Village & Small Industries)	Rural Industries*	Total (Village & Small Industries)	Rural Industries*
1	2	3	4	5	6
I. States.					
1	Andhra Pradesh	235.00	133.00	334.75	186.75
2	Assam	284.00	186.50	284.00	186.50
3	Bihar	536.00	180.00	513.00	180.00
4	Gujarat	365.00	214.95	613.55	215.50
5	Haryana	191.00	40.00	190.50	39.50
6	Himachal Pradesh	120.00	32.50	82.50	32.00
7	Jammu & Kashmir	224.00	180.00	268.29	174.82
8	Karnataka	447.00	277.00	444.50	297.00
9	Kerala	400.00	215.00	510.00	242.00
10	Madhya Pradesh	196.00	115.00	204.96	125.59
11	Manipur	150.00	129.00	182.52	130.16
12	Meghalaya	65.00	42.00	63.50	41.50
13	Maharashtra	583.00	106.80	758.49	106.65
14	Nagaland	46.00	24.50	46.00	20.55
15	Orissa	240.00	106.00	329.93	155.16
16	Punjab	420.00	30.00	358.69	56.12
17	Rajasthan	187.00	70.00	213.31	60.00
18	Sikkim	46.00	25.60	40.81	24.80
19	Tamil Nadu	566.00	440.00	737.43	552.01
20	Tripura	87.00	49.00	87.40	49.00
21	Uttar Pradesh	1294.00	787.00	1616.00	1009.00
22	West Bengal	549.00	378.00	969.54	743.53
	TOTAL	7231.00	3761.85	8849.67	4628.14

1	2	3	4	5	6
II. Union Territories :					
23	Andaman & Nicobar Islands	12°00	3°20	12°00	3°20
24	Arunachal Pradesh	50°00	26°00	51°50	34°90
25	Chandigarh	30°00	0°65	32°15	0°65
26	Dadra & Nagar Haveli	7°00	2°00	7°00	2°45
27	Delhi	488°75	33°75	466°29	13°88
28	Goa, Daman Diu	25°00	8°00	34°54	26°14
29	Lakshadweep	5°14	4°22	5°46	4°54
30	Mizoram	70°00	29°00	70°00	29°00
31	Pondicherry	33°00	11°61	34°69	12°65
TOTAL		720°89	118°43	713°63	127°41
GRAND TOTAL I + II		7951°89	3880°28	9563°30	4755°55

*Rural Industries', viz., handlooms, khadi and village industries, handicrafts, sericulture and coir industry.

बनारस में साड़ी उद्योग

2364. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विनांक 16 जनवरी, 1979 के "नव भारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आक्षेप के समाचार की ओर बिसाया गया है कि बिचौलिये बनारस में साड़ी उद्योग में सगे 20 हजार श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं;

(ख) उनका शोषण रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कारगर और तात्कालिक कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) बनारसी साड़ियों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रताप साहब) (क) जी हाँ, । साहब माननीय सदस्य का मतलब रेगमी साड़ियों से है क्योंकि बनारस में मुख्यतः रेगमी साड़ियों का ही उत्पादन होता है।

(ख) यह सच नहीं है कि बनकरों को पूर्णतया मजदूरों की क्या पर छोड़ दिया गया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने इस हेतु घनेक धनमुद्रा किए हैं जिससे बनकरों को मंत्री के मौसम में सम्भार मुहूर्त में अपना सामान रखकर सरकार से सम्भार 60—70 प्रतिशत मूल्य प्राप्त करने की

सुविधा सरकार द्वारा राज्य हथकरघा विकास निगम व उत्तर प्रदेश ग्रिटिंग कारपोरेशन के माध्यम से हथकरघों पर बने रेगमी उत्पादों की बड़े पैमाने पर प्राप्ति करने जैसे धन्यता धाते हैं । राज्य सहकारी समितियाँ बनाने का कार्य तेजी से धामे बढ़ रहा है और इससे बनकरों द्वारा धनपे उत्पाद सीधे सहकारी समितियों की बेचने में सहायता मिलती है । सरकार ने नाम्ब वर्ष के दौरान रेगमी कपड़ों पर भी 20 प्रतिशत निमोष रियायत देने की योजना साम्ब कर दी है और इससे बिचौ बड़ाने में सहायता मिलेगी । केन्द्रीय रेगम बोर्ड भी मूल्यों में स्थिरता लाने हेतु एक योजना चला रहा है ।

(ग) भारत सरकार रेगम से बनी वस्तुधों पर जहाज भाड़ा मुक्त मूल्य पर 15 प्रतिशत नकद प्रोत्साहन और जहाज भाड़ा मक्त मूल्य पर 20 प्रतिशत प्रतिभूति साहस से देती है । यह योजना 31 मार्च, 1979 तक वैध है ।

Abolition of Orderly System for Senior Police Officers

2365. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Police Commission in Delhi has sent an interim report to the Government and

recommended for abolition of orderly system for senior police officers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government have accepted the recommendation in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir

It has recommended abolition of orderly system as it exists at present and has suggested another system of attaching constables to officers for attending to specific official work, such as, (i) Attend to petitioners, complainants and other visitors who come to see the officer, (ii) telephone calls particularly during the officer's absence and furnish helpful replies; (iii) pass on messages to subordinate officers; and (iv) accompany officer on his field work to afford him necessary security and assistance.

(b) and (c) The Report submitted by the National Police Commission will need examination in consultation with State Governments.

सिबिल सेवा परीक्षाओं के लिए विषय

2366 श्री सुरेन्द्र सिंह क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ऐसे विषयों के नाम क्या हैं जो पुरानी योजना के अन्तर्गत आई.एस. परीक्षा के लिये सम्मिलित थे परन्तु अब भारत सरकार को सिबिल सेवा परीक्षा की नई पद्धति के अन्तर्गत वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित नहीं किये गये हैं,

(ख) क्या साक्ष्य की एक ऐसा विषय है जो अब तक आई.एस. परीक्षा के लिये विषय था परन्तु नई योजना के अन्तर्गत इसे विषयों की सूची में से निकाल दिया गया है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) सभी भाषाओं और विषयों को समान महत्व देने की नीति अब तक अपनायी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल

मण्डल): (क) पुरानी योजना के अधीन, 1978 तक, भारतीय प्रशासनिक सेवा यदि परीक्षा में शामिल किए गए वैकल्पिक विषय और अतिरिक्त विषय तथा सिबिल सेवा परीक्षा की नई योजना के अधीन प्रारम्भिक परीक्षा तथा प्रधान परीक्षा में शामिल किए गए वैकल्पिक विषय अनुबन्ध में दिए गये हैं। निम्नलिखित विषयों को, जिन्हें पुरानी योजना में शामिल किया गया था, नई योजना में विलुक्त कोई स्थान नहीं दिया गया है—

(1) चीनी साहित्य

(2) पाकी साहित्य

(3) नृ-विज्ञान

(4) धर्म तथा फारसी साहित्य आदि में मध्यकालीन संस्कृति।

(ख) और (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा में पुरानी योजना के अधीन साक्ष्य की, निम्न वैकल्पिक विषयों में से एक विषय या नई योजना में इसे एक अलग विषय के रूप में स्थान न दे कर मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा के वेपर में शामिल किया गया है। यह अथवा नहीं समझा जाता कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय को सिबिल सेवा परीक्षा में शामिल किया जाए, क्योंकि फार्मल तथा विश्वविद्यालयों में व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं। अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं, श्रेणी-1 में भर्ती के लिए भर्ती नीति एवम चयन पद्धति पर कोठारी समिति ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश की—

“सिबिल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची बनाने समय हम एक जटिल समस्या का सामना करते हैं। ऐसा कि पहले अद्यय का कहा गया था, प्रारम्भिक और प्रधान परीक्षाओं के लिए यह सूची इतनी सीमित नहीं होनी चाहिए जिससे इसमें बैठने वाले उम्मीदवारों को विषय चुनने में ही कठिनाई हो। इसके विपरीत, अगर सूची काफी लम्बी हो गई तो भी स्तर में एककृपा बनाए रखना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जब वैकल्पिक विषयों की सूची काफी लम्बी हो जाती है तो लिखित विषयों में देने वाले की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक ही परीक्षा देने के अलग अलग परीक्षाओं में विभाजित हो जाती है। इसलिए, जिन विषयों में प्रतियोगी उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है, अगर इसके विपरीत कोई सबल कारण न हो तो उनकी पाठ्यक्रम में रचना नहीं चाहिए।

यह स्पष्ट है कि सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का निर्धारण करने के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता। हमने प्रधान परीक्षा में अधिक सामान्य विषयों में से लगभग सभी को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है—केवल उन्हीं विषयों को छोड़कर जो विशेष रूप से व्यावसायिक या प्राविधिक होते हैं। विभिन्न सेवाओं को सामान्य आवश्यकताओं को भी हमने धृष्टि में रखा है।

तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की सूची बनाने में अनेक परम्परा विरोधी आवश्यकताओं और अवरोधों के बीच में समझौता करना पड़ता है। हमारा विश्वास है कि विशेषज्ञों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करने के बाद प्रारम्भिक और प्रधान परीक्षाओं के लिए हमने जो विषय सूचियाँ तैयार की हैं, सामान्य रूप से वे सन्तोषजनक पाई जाएंगी। इन सूचियों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के

प्राध्वर्ष से, समय समय पर आयोग द्वारा पुनरीक्षा होनी चाहिए।”

आयोग सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची की पुनरीक्षा समय समय पर करता रहेगा।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि उम्मीदवार, सिविल सेवा परीक्षा 1979 से प्रधान परीक्षा के लिए भाषा के प्रश्न पत्र तथा अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का छात्र, सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर सविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं। सविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं। सविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई भाषाओं की सूची में से उम्मीदवार को पसन्द की किसी भी एक भाषा का भी प्रश्न लिखित परीक्षा में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में प्राप्त, एक अंको का उम्मीदवार के प्रतिभांगिना रैंक में शामिल नहीं किया जाएगा, किन्तु उम्मीदवार के लिए अर्हता अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

विवरण

पुरानी योजना के अधीन 1978 तक भा० प्र० से० प्रावि परीक्षा में शामिल किए गए विषय
(1)

सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना में शामिल किये गए विषय
(2)

वैकल्पिक विषय

विषय	कोड संख्या
शुद्ध गणित	01
अनुप्रयुक्त गणित	02
सांख्यिकी	03
भौतिकी	04
रसायन	05
वनस्पति विज्ञान	06
प्राणि विज्ञान	07
भूविज्ञान	08
भूगोल	09
अंग्रेजी साहित्य	10
निम्नलिखित में से एक —	
असमिया	11
बंगला	12
गुजराती	13
हिन्दी	14

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

वैकल्पिक विषयों की सूची
कृषि विज्ञान
वनस्पति विज्ञान
रसायन विज्ञान
सिविल इंजीनियरी
वाणिज्य शास्त्र
अर्थ शास्त्र
विद्युत इंजीनियरी
भूगोल
भू-विज्ञान
भारतीय इतिहास
विधि
गणित
यांत्रिक इंजीनियरी
दर्शन
भौतिकी

(1)
(2)

कन्नड़	15	राजनीति विज्ञान
कश्मीरी	16	मनोविज्ञान
मलयालम]	17	समाज शास्त्र
मराठी	18	प्राणिशास्त्र
उड़िया	19	
पंजाबी	20	नोट —(i) दोनों ही प्रश्न पत्र वस्तुपरक (बहु-विकल्प
सिंधी देवनागरी	21	प्रश्न) होंगे ।
सिंधी अरबी	22	
तमिल	23	(ii) प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में
तेलुगु	24	तैयार किए जाएंगे ।
उर्दु	25	
निम्नलिखित में से एक —		(iii) ऐच्छिक विषयों के लिए पाठ्य विवरणों
अरबी	26	की पाठ्यक्रम सामग्री विभी स्तर की होगी ।
चीनी	27	
फ्रेंच	28	
जर्मन	29	
पाली	30	
फारसी	31	
रूसी	32	
संस्कृत	33	
भारतीय इतिहास	34	(ख) प्रधान परीक्षा
ब्रिटिश इतिहास	35	
यूरोपीय इतिहास	36	वैकल्पिक विषयों की सूची :—
		कृषि विज्ञान
विश्व इतिहास	37	वनस्पति विज्ञान
सामान्य अर्थ शास्त्र	38	रसायन विज्ञान
राजनीति विज्ञान	39	सिविल इंजीनियरी
दर्शन शास्त्र	40	वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा-विधि
मनोविज्ञान	41	अर्थ शास्त्र
बिधि—I	42	विद्युत् इंजीनियरी
बिधि—II	43	
बिधि—III	44	भूगोल
अनुप्रयुक्त बाणिज्य	45	भू-विज्ञान
समाज शास्त्र	46	इतिहास
		बिधि

जात यह है कि विशेष वैकल्पिक विषयों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू होंगे :—

- (i) संवादाओं पदों के किसी वर्ग के लिए कोड 01, कोड 02, तथा कोड 03, वाले विषयों में से दो से अधिक विषय नहीं चुने जा सकते ।

निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक का साहित्य :—

असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दु, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी तथा अंग्रेजी ।

(1)

(2)

- (ii) कोड 11 से 25 तक के विषयों में से केवल एक ही लिया जा सकता है ।
- (iii) भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं/पदों के उम्मीदवार ऊपर कोड 26-33 तक दी गई भाषाओं में से एक से अधिक न चुनें। केवल भारतीय विदेश सेवा के उम्मीदवारों को इन भाषाओं में से कोई दो चुनने की अनुमति है लेकिन किसी भी उम्मीदवार को पाली (कोड 30) और संस्कृत (कोड 33) दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (iv) सेवाओं / पदों के किसी भी वर्ग के लिए इतिहास के विषयों कोड 34, 35, 36, तथा 37 में से दो से अधिक नहीं चुने जा सकते । लेकिन किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास (कोड 36) और विश्व इतिहास (कोड 37) दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- (v) कोड 40 और 41 में उल्लिखित विषयों में से सेवाओं / पदों के किसी वर्ग के लिए केवल एक ही विषय लिया जा सकता है ।
- (vi) किसी भी वर्ग के लिए बिधि के विषय कोड 42, 43, और 44 में से दो से ज्यादा नहीं चुने जा सकते ।
- (vii) वर्ग के अन्तर्गत सेवाओं / पदों के लिए कोड 45 विषय न चुना जाए ।

अतिरिक्त विषय

विषय	कोड संख्या
उच्च मुद्रा गणित	50
अथवा	
उच्च अनुप्रयुक्त गणित	51
उच्च भौतिकी	52
उच्च रसायन विज्ञान	53
उच्च वनस्पति विज्ञान	54
उच्च प्राणि विज्ञान	55
उच्च भू-विज्ञान	56]
उच्च भू भोल	57
अंग्रेजी साहित्य	58

(1798—1935)

भारतीय इतिहास—I 59
(कम से कम दो से हरे तक)
या

प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन
गणित
यांत्रिक इंजीनियरी

दार्शन शास्त्र
भौतिकी
राजनीति विज्ञान तथा
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
मनोविज्ञान
समाज शास्त्र
प्राणि विज्ञान

नोट (i) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी —

(क) राजनीति विज्ञान तथा उर्ध्व राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन

(ख) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन

(ग) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत् इंजीनियरी तथा यांत्रिक इंजीनियरी में से एक से अधिक विषय नहीं ।

(ii) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत निम्न शर्तों के होंगे ।

(iii) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घण्टे की अवधि का होगा ।

(iv) प्रश्न पत्रों के उत्तर सविधान की भावना अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में अथवा अंग्रेजी में देने की उम्मीदवारों को कृप्य होगी ।

(v) सभी प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे ।

(1)	(2)
भारतीय इतिहास-II (मुगल महान 1526-1707) अथवा	60
भारतीय इतिहास-III (1772-1950) अथवा	61
ब्रिटिश सांविधिक इतिहास (1603 से 1950 तक) अथवा	62
यूरोपीय इतिहास (1871 से 1945 तक)	63
उन्नत अर्थशास्त्र अथवा	64
उन्नत भारतीय अर्थशास्त्र	65
द्वय से अन्त तक के राजनीतिक सिद्धान्त अथवा	66
राजनीतिक संगठन और लोक प्रशासन अथवा	67
अन्त राष्ट्रीय सम्बन्ध	68
उच्च तत्व भीमासा	69
ज्ञान भीमासा सहित अथवा	
उन्नत मनोविज्ञान II जिसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान भी शामिल है।	70
भारतीय सांविधिक विधि अथवा	71
न्यायशास्त्र	72
भारतीय साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570-1650 ईस्वी) अथवा	73
भारतीय साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्य युगीन सभ्यता (570-1650 ईस्वी) अथवा	74
प्राचीन भारतीय सभ्यता और वर्तमान शास्त्र	75
मानव विज्ञान}	76
उन्नत समाज शास्त्र	77

विशिष्ट प्रतिरिक्त विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू किए जायेंगे :—

- (1) किसी भी उम्मीदवार को भारतीय इतिहास-I (कोड-59) तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और वर्तमान (कोड 75) दोनों ही विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (2) किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास (कोड 63) तथा अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध (कोड 68) दोनों विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Employment to Children of Deceased Central Government Employee

2367. SHRI DAYA RAM SHAKYA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether in the event of death of a Central Government employee as well, his wife, there is a provision to employ the eldest child, who may be even 12 to 14 years old, in Government service; and

(b) if not, the arrangements made to look after the dependant children of such an employee and to provide for their livelihood?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) and (b) The minimum age limit for entry into Central Government Services is 18 years. In the event of death of a serving Government employee, whose family is left in indigent circumstances, there is a provision for appointing his son/daughter/near relation in a Group 'C' or 'D' post by relaxing the normal procedure of appointment through the

Employment Exchange/Staff Selection Commission. If the ward/dependent of the deceased government servant does not satisfy the provisions of the Recruitment Rules, the question of relaxing the provisions, including the minimum age limit for entry into Government service is considered provided such a relaxation does not attract the provisions of any other law.

श्री सरकारी क्षेत्र में बड़ी का निर्वाह करने वाले
एककों की स्थापना

2368. श्री दयाराम शाक्य क्या उद्योग यंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 1978 में सरकार ने शीर सरकारी क्षेत्र में बड़ी का निर्वाह करने वाले 83 एककों की स्थापना करने हेतु संजूरी दी है; और

(ख) यदि हा, तो इन एककों की स्थापना कब की जाएगी और यह एकक कहाँ-कहाँ स्थापित किए जाएंगे तथा प्रत्येक एकक में कितना पूँजी निवेश किया जावेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जी नहीं ।

(ख) वर्ष, 1978 के दौरान जिन 5 बड़ी उत्पादक एककों की स्वीकृति दाव की गई थी उनके व्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

क्रम सं०	एकक का नाम	स्थापना स्थान	उत्पादन शक्ति का संभावित समय	परियोजना में किया जाने वाला प्रस्तावित निम्नीय
1	2	3	4	5
बड़े पैमाने के एकक				
1	सर्वोर्षी नॉर्सा बांध प्रा० लि०	गुजरात	दो वर्ष से तीन वर्ष के भीतर ।	670 लाख रुपये
2	सर्वोर्षी ब्राह्म प्रवेश इन्वैस्टिगल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ।	ब्राह्म प्रवेश	—बड़ी—	348 लाख रुपये
3	श्रीमती दुर्गा परियोजना	दिल्ली	—बड़ी—	230 लाख रुपये

1	2	3	4	5
सर्व-भारत एकक				
1 सर्वश्री रॉजल वाच कं०	बड़ीगढ़	एक बर्ष के भीतर		
2 सर्वश्री मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स	हरयाणा	—वही—		
3 सर्वश्री कमल टाइम इण्डस्ट्रीज	मध्य प्रदेश	—वही—		
4 सर्वश्री असरानी टाइम इण्डस्ट्रीज	मध्य प्रदेश	—वही—		
5 सर्वश्री नरयान टाइम इण्डस्ट्रीज	मध्य प्रदेश	—वही—		
6 सर्वश्री माधव टाइम इण्डस्ट्रीज	मध्य प्रदेश	—वही—		
7 कॉलिका वाच इण्डस्ट्रीज	प० बंगाल	—वही—		
8 सर्वश्री जे० बी० एंटरप्राइसेज कं०	प० बंगाल	—वही—		
9 सर्वश्री हिन्द कॉरपोरेशन	प० बंगाल	—वही—		
10 सर्वश्री जॉली इन्टरनेशनल	प० बंगाल	—वही—		
11 सर्वश्री अनन्त राय बी० मेहता	गुजरात	—वही—		
12 सर्वश्री एल० पी० कृष्णानी	गुजरात	—वही—		
13 सर्वश्री इम्प्लेक्स वाच कं०	गुजरात	—वही—		
14 सर्वश्री प्रवमन कृष्ण कौल	गुजरात	—वही—		
15 सर्वश्री यूनिवर्सल टाइम कं०	हरयाणा	—वही—		
16 सर्वश्री हिन्द प्रेसिडियन कं०	हरयाणा	—वही—		
17 सर्वश्री मिलूना वॉचिज	हरयाणा	—वही—		
18 सर्वश्री टाइम टेक्नालॉजी	हरयाणा	—वही—		

अनुमान है कि पिछले बर्ष में प्रत्येक एकक लगभग 15 लाख रुपये का विनियोग करेगा और तत्पश्चात् यह विनियोग 10 लाख रुपये तक बढ़ जाएगा ।

Exchange List of Industries between India and Saudi Arabia

2369. SHRI A. R. BADRI NARAYAN:
SHRI M. V. CHANDRA
SHEKHARA MURTHY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether an exchange list of Industries between India and Saudi Arabia for taking up joint venture projects in that country has been prepared;

(b) if so, the details of the same.

(c) what are the industries mentioned in the list;

(d) when the final decision is likely to be taken; and

(e) whether any agreement has also been signed in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (e) During the visit of the Union Minister of Industry to Saudi Arabia in December 1978 modalities were agreed to for joint ventures, participation of Indian firms in several identified Saudi Arabian projects including electrification schemes where the initiative taken by BHEL in their on going project of elec-

trification has been commended. It was also arranged that Saudi Arabian delegations would visit India in order to be apprised of the expertise, technology and capability developed in India for undertaking projects in Saudi Arabia. Several other important matters of industrial and economic cooperation relating to oil supplies, financing of agriculture, irrigation and electricity projects in India, exports of commodities from India and deputation of Indian personnel were discussed for implementation. The specific industrial projects to be taken up as joint ventures would depend on the progress of contacts between Saudi Arabian organisations and Indian organisations.

Progress in Programmes of Industries

2370. SHRI A. R. BADRINARAYAN. Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how far the approach of Government towards rural development in the industrial sector has materialised;

(b) the various places and programmes envisaged; and

(c) whether sufficient headway has been made in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):

(a) The main thrust of the new Industrial Policy is on providing larger employment opportunities through development of village and small industries in the rural sector. To achieve this objective the Government launched a centrally sponsored scheme of District Industries Centres in May, 1978. 263 District Industries Centres have been approved in 22 States and 6 Union Territories so far. The remaining districts are likely to be covered in a phased manner during the next financial year. These Centres have been set up as focal agency to deal with all the requirements of small and village industries under a single roof and there will be close linkage with

the existing institutions like Khadi and Village Industries Commission, Handicrafts Board and Handloom Board. The Centres will also interface closely with activities of Integrated Rural Development Blocks.

(b) A list of 263 districts already covered under the District Industries Centres Scheme is enclosed. Detailed instructions have been issued to the State Governments/UT Administrations for preparation of Action Plans and work programme for each of the District Industries Centres by March, 1979. Action Plans spell out the material resources, skills and demand and status of existing industries, list out candidate industries for a District, provide information in regard to the requirements of entrepreneurs, capital and other inputs for the identified opportunities and marketing assistance required. Besides, preparation of project profiles for the proposed industries form another part of the Action Plans.

(c) Yes, Sir. All the State Governments had been requested to send a report on the progress of work done in the District Industries Centres upto the end of December, 1978. The information has been received in respect of 144 District Industries Centres. The average number of entrepreneurs identified per District Industries Centre works out to be 331 and for assisting them to choose appropriate industrial opportunities 90 project profiles have been prepared in each District Industries Centre, which have resulted in establishment of creating additional employment for 736 persons. The number of units granted registration in each District Industries Centre stands at 234. Credit assistance provided by financing institutions on an average in a District Industries Centre Accounts to Rs. 28.58 lakhs, seed margin money at Rs. 0.93 lakhs and cash subsidy at Rs. 5.69 lacs. The number of sick units assisted per District Industries Centre is 3 and other assistance have been provided to 249 units.

List of District Industries Centres

S.No. 1	Name of the State 2	Name of the DIC 3
1	Andhra Pradesh	1 Ananthapur 2 Cuddapah 3 Chittoor 4 Guntur 5 Hyderabad 6 Karimnagar 7 Khammam 8 Medak 9 Nalgonda 10 Srikakulam 11 Visakhapatnam
2	Assam	1 Cachar 2 Dibrugarh 3 Goalpara 4 Kamrup 5 Nowgong.
	Bihar	1 Aurangabad 2 Bhagalpur 3 Bhojpur Arrah 4 Champaran East (Molihari) 5 Champaran West (Betiah) 6 Darbhanga 7 Katihar 8 Gaya 9 Madhubani 10 Muzaffarpur 11 Nalanda 12 Nawadah 13 Palamau (Daltonganj) 14 Patna 15 Purnea 16 Ranchi 17 Samastipur 18 Santhal Parganas (Dumka)
1	Gujarat	1 Amreli 2 Banskantha 3 Bahroach 4 Bhavnagar 5 Junagarh 6 Kutch 7 Mahana 8 Panchmahal 9 Sabarkantha 10 Surendernagar.

1	2	3
5	Himachl Pradesh	1. Bilaspur. 2. Chamba 3. Hamirpur 4. Kangra 5. Kinnaur 6. Kulu 7. Lahaul & Spiti 8. Mandi 9. Simla 10. Solan 11. Sirmur 12. Una.
6	Haryana	1. Ambala 2. Bhiwani 3. Gurgaon 4. Hisar 5. Jind 6. Karnal 7. Kurukshetra 8. Mohindergarh 9. Rohtak 10. Sirsa 11. Sonapat
	Jammu & Kashmir	1. Anantnag 2. Baramulla 3. Doda 4. Jammu 5. Kathua 6. Ladhak 7. Poonch 8. Rajauri 9. Srinagar 10. Udhampur.
3'	Karnataka	1. Belgaum 2. Bidar 3. Bijapur 4. Dharwar 5. Hasan 6. Shimoga 7. Tumkur.
	Kerala	1. Alleppey 2. Cannanore 3. Ernakulam 4. Itukki 5. Kottayam

1	2	3
		6. Kozhikode
		7. Palghat
		8. Malapuram
		9. Quilon
		10. Trichur
		11. Trivandrum
10 Madhya Pradesh		1. Bhind
		2. Bilaspur
		3. Chhatarpur
		4. Durg
		5. Guna
		6. Khandwa (East Nimnar)
		7. Khargaoon (West Nimnar)
		8. Mandla
		9. Mandlaur
		10. Morena
		11. Narsinghpur
		12. Raipur
		13. Rajanandgarh
		14. Rewa
		15. Rajgarh
		16. Raigarh
		17. Satna
		18. Sehori
		19. Sarguja
		20. Seoni
		21. Sagar
		22. Ujjain
		23. Indore
		24. Dhar
		25. Dewas
		26. Jhabua
		27. Shajapur
		28. Ratlam
		29. Raisen
		30. Bhopal
		31. Vidisha
		32. Betul
		33. Gwalior
		34. Shivpuri
		35. Datia
		36. Sidhi
		37. Tikamgarh
		38. Shahdol
		39. Panna

1	2	3
		40. Jabbalpur 41. Chhindwara 42. Damoh 43. Balaghat 44. Bastar 45. Hoshangabad
11	Maharashtra	1. Ahmednagar 2. Aurangabad 3. Bhandara 4. Bhir 5. Buldhana 6. Chandarpur (Chanda) 7. Colaba 8. Dhulia 9. Jalgaon 10. Nanded 11. Osmanabad 12. Parbhani 13. Ratnagiri 14. Wardha 15. Yeatmal 16. Thana 17. Nasik 18. Pune 19. Satara 20. Sangli 21. Kolhapur 22. Sholapur 23. Nagpur 24. Akola 25. Amaravati
12	Manipur	1. East District 2. Central District 3. North District 4. South District 5. West District 6. Tenganappal
13	Meghalaya	1. Garo Hills
14	Nagaland	1. Kohima 2. Mokokchung 3. Phek 4. Tuensang
15	Orissa	1. Bolangir 2. Balsara 3. Cuttack 4. Dhenkanal 5. Gunjam 6. Kolahandi 7. Korapat 8. Keonjhar 9. Mavurbhanj 10. Phulbani 11. Puri 12. Sambalpur 13. Sundergarh
16	Rajasthan	1. Alwar 2. Banswara 3. Bhilwara

1	2	3
		4. Churu 5. Jhalwar 6. Jodhpur 7. Nagaur 8. Tonk 9. Udaipur 10. Jaipur 11. Ajmer 12. Kotah 13. Bikaner 14. Bharatpur 15. Pali 16. Sri Ganganagar
17	Sikkim	1. West District
18	Tamil Nadu	1. Chingleput 2. Dharmapuri 3. Kanyakumari 4. Pudukottai 5. Ramanathapuram 6. Salem 7. South Arcot 8. Tirunelveli
19	Tripura	1. Tripura North 2. Tripura South 3. Tripura West
20	Uttar Pradesh	1. Allahabad 2. Almora 3. Ballia 4. Deoria 5. Fatehpur 6. Ghazipur 7. Jhansi 8. Lucknow 9. Moradabad 10. Mathura 11. Rai Barcilly 12. Saharanpur 13. Unnao
21	West Bengal	1. Bankura 2. Birbhum 3. Burdwan 4. Cooch Behar 5. Darjeeling 6. Hooghly 7. Howrah 8. Jalpaiguri 9. Malda 10. Midnapur 11. Murshidabad 12. Nadia 13. Purulia 14. West Dinajbad 15. 24-Parganas
22	Arunachal Pradesh.	1. Kameng 2. Lohit 3. Subansiri 4. Siang 5. Tirap

23	Mizoram	1.	Aizawal
24	Pondicherry	1.	Pondicherry
25	Dadra & Nagar Haveli	2.	Silvassa
26	Andaman & Nicobar Islands	1.	A. & N. Islands
27	Goa, Daman and Diu	1.	Entire U.T.
28	Punjab	1.	Hoshiarpur
		2.	Sangrur
		3.	Bhatinda
		4.	Gurdaspur
		5.	Jullundur
		6.	Amritsar
		7.	Ludhiana
Total number of D.L.Cs		263	

Constitution of Western Ghats Development Committee

2371. **SHRI A. R. BADRI NARAYAN:**
SHRI M. V. CHANDRA SHEKHARA MURTHY:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) when was the Western Ghats Development Committee constituted and with what object;

(b) the work so far achieved; and

(c) the norms under which the area is identified?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) A High Level Committee for the Development of Western Ghats was set up in 1973 for formulating strategy, policies and programmes for the development of this region.

(b) The Committee in a series of meetings decided upon a broad strategy and the programmes to be implemented for the integrated development of Western Ghats. Against a provision of Rs. 20 crores of Special Central

Assistance during the Fifth Plan period, a sum of Rs. 11.92 crores have been spent during 1974-78 and an outlay of Rs. 7.26 crores has been provided for 1978-79.

(c) For implementation of Western Ghats programmes during the Fifth Five Year Plan, the talukas identified by the Second Irrigation Commission as the Western Ghats Areas were adopted.

Naxalites being tried

2372. **SHRI C. R. MAHATA:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Naxalites and the names of the States in which they are now being tried under the law of the country; and

(b) the present scheme of Government for their welfare?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):
 (a) A statement is attached.

(b) Government have no such scheme.

Statement

The number of Naxalites being tried under the Law of the Country in various States as on 31st December, 1978

Serial No.	State	No. of under trial Naxalite prisoners in jail	No. of Naxalite under trials on bail	Total
1	2	3	4	5
1	Andhra Pradesh	15	147	162
2	Bihar	29	60	89
3	Kerala	20	9	32
4	Orissa	2	..	2
5	Punjab	1	..	1
6	Tamil Nadu	2	56	58
7	Uttar Pradesh	9	10	19
8	West Bengal	40	415	455
9	Delhi	..	3	3
		121	700	821

NOTE.—There are no Naxalite undertrials in the remaining States and Union Territories.

Abolition of Capital Punishment

2373. SHRI C. R. MAHATA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have any proposal to abolish the capital punishment in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) and (b) There is no proposal at present being considered by the Government to abolish capital punishment altogether. The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1978, as passed by the Rajya Sabha on 23-11-78, and pending consideration in this

House, seeks to amend section 302 (punishment for murder) so as to provide that the normal punishment for murder shall be imprisonment for life, and that only in certain aggravating circumstances will the court have discretion to award death sentence.

The effect of the proposed section 302 when it becomes law, read with subsection (3), of section 354 Cr.P.C., which requires that special reasons should be given by judge if a sentence of death is awarded, will be that the sentence of death will be an exception.

Shortage of Tyres

2374. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is a great shortage of motor

car, tractor and heavy vehicle tyres in the open market;

(b) what is the installed capacity for tyres and tubes in the country at present and what is their annual production as against demand;

(c) how many companies have been given licences for installing additional production capacities;

(d) what will be the additional capacity likely to mature by 1980-81 out of the licences already given;

(e) whether there is any gap between the demand and supply; and

(f) if so, steps taken to improve the position?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Government have received reports of shortage of tractor tyres and certain other categories of tyres/tubes in some parts of Punjab during the months of January and February, 1978.

(b) At present the annual installed capacity of automotive tyres and tubes in the country is 79.29 lakh nos. whereas the production during the year 1978 has been 69,88,627 nos.

(c) Additional capacity by way of substantial expansion and new units to the extent of 47.50 lakh nos. of tyres and tubes has been licensed in respect of 13 companies.

(d) The additional capacity likely to materialise by 1980-81 is 25.50 lakh nos. per annum.

(e) and (f). Although there is no gap between demand and supply, reports of shortages in certain areas are due to consumer preference for a particular brand of tyres. A working Group has been constituted by the Planning Commission in order to formulate targets and programmes for the Tyres Industry.

Analysis of Samples of Water and silt from Himalayas

2375. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Bhabha Atomic Research Centre has completed analysing the samples of water and silt obtained from the area in the Himalayas where the CIA of the United States had planted the Plutonium device;

(b) if so, the results thereof; and

(c) if not, when is it likely to be completed and the reasons for delay?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) The results showed no detectable contamination of plutonium.

(c) Does not arise.

Allotment to Gujarat for Annual Plan

2376. SHRI CHHITUBHAI GAMIT: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the details regarding the money allotted by the Central Government for the Gujarat State regarding its Annual Plan;

(b) whether Government have given any special consideration to the backward areas while earmarking the money to the States;

(c) if so, the details regarding the money demanded by Gujarat State; and

(d) whether there has been any cut in the demanded money?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) An outlay of Rs. 392 crores has been fixed for the Annual Plan 1979-80 of Gujarat. Sectoral break up of the Annual Plan 1979-80 outlay of Gujarat by major heads of development is given in the attached statement.

(b) The Central assistance to the State for implementing the Plan has been determined on the basis of the Gadgil Formula which gives some weightage to the relative economic backwardness of States as measured by their per capita incomes.

(c) and (d). The Gujarat State Government had proposed an outlay of Rs. 487 crores for their Annual Plan 1979-80.

Statement

Annual Plan 1979-80—Gujarat

(Rs. lakhs)

	Proposed outlay	Agreed outlay
I. Agriculture and Allied Services	6848	5928
II. Co-operation	482	430
III. Water and Power Development	25480	20630
IV. Industry and Minerals	2720	1962
V. Transport and Communications	3700	4000
VI. Social and Community Services	7370	6124
VII. Economic Services	100	86
TOTAL	46700	39200

कानपुर जूट उद्योग लि० का अग्रिमग्रहण

2377 श्री सुबराज क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर जूट उद्योग लि० को पुनर्जागू करने की दृष्टि से, जो 21 दिसम्बर, 1978 से बंद है, अग्रिमग्रहण करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या इस एकक के बंद होने से 1200 क्षमिक बेरोजगार हो गये हैं, और

(ग) यदि हा, तो इसके कब तक जागू हो जाने की संभावना है और यदि ऐसा करने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ग) कानपुर जूट उद्योग, जिसमें लगभग 1200 कामगार हैं, 21 दिसम्बर, 1978 से बंद पड़ा हुआ है। इस एकक के पुनरारम्भ के प्रश्न पर केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से इस एकक का एक क्षम्यता अध्ययन करने के लिए धनुरोध किया गया है। निगम की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसकी जांच करने के बाद निर्णय लिया जा सकेगा।

Proposal for setting up of National Electronic Research Institute

2378. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether the proposal to set up a national level Electronic Research Institute on the lines of the Bhabha Atomic Research Centre has been finalised by Government;

(b) if so, the main facts thereof;

(c) the estimated cost of the proposal; and

(d) the location of the proposed institute?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Utilisation of Idle Capacity for creation of Posts

2379. SHRI DHARMASINH BHAI PATEL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) which are the industries in which the unutilised capacity is less than 40 per cent; and

(b) does his Ministry intend to give consideration to the fact that in such industries additional jobs can be crea-

ted by decreasing excise duty and enabling the industry to utilise idle capacity without any additional capital expenditure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) A statement comparing capacity utilization during the past 5 years in 70 selected industries looked after by the Directorate General of Technical Development has already been laid on the Table of the House in reply to Starred Question No 37 on 21-2-1979

(b) Some of the important reasons for under utilization of capacity are long gestation periods, lack of demand, power cuts, excess capacity already created, scarcity of raw materials, labour troubles, mechanical breakdowns, technological constraints and inability to exploit the available market. In appropriate cases, under-utilization of capacity in the concerned industry is also one of the criteria taken into consideration for reducing the rates of excise duty.

Recommendations of Committee on Tractor Industry

2389. **SHRI S. B. PATIL:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:-

(a) whether a high level expert Committee on Tractor Industry has recommended nationalisation of the tax structure for stimulating demand for tractors in the country and also recommended a reduction in the margins and interest rates charged by institutions lending agencies for purchase of agricultural tractors; and

(b) if so, what is the reaction of Government to the recommendations of the high level expert committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI-MATI ABHA MAITI): (a) and (b) The Working Group on Transport, Earthmoving Equipment and Agricultural Machinery, set up to formulate

programmes of development for the Five Year Plan period 1978-83, has submitted its report recently. The recommendations include various measures to be undertaken by the industry regarding research and development, standardisation, rationalisation, product mix and strengthening of after sale service. The thrust of these recommendations regarding the industry has been accepted by Government. The group *inter alia* also recommended rationalisation of tax structure, lowering of margin and rate of interest. These recommendations have been examined by Government in the context of totality of fiscal measures, taxes and incentives. Decisions in respect of overall policy have been indicated in the budget proposals presented to the Parliament.

राजपति अधिकारियों के चयन से सम्बन्धित नियमों का पुनरीक्षण

2381 श्री नबाब सिंह चौहान क्या गृह मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुछ मंत्रालयों ने राजपति अधिकारियों के चयन से सम्बन्धित नियमों का पुनरीक्षण करने की सफाई की है,

(ख) यदि हा, तो उनके नाम क्या हैं और ये सफाई किन-किन पदों के लिये की गई है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

(ग) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ऐसी कोई सफाई की है और यदि हा, तो तत्सम्बन्धी शीर्षक क्या है, और

(घ) क्या सरकार का विचार स्वयं प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अधिक कड़े नियम बनाने की है ?

गृह मंत्रालय और विभिन्न व्यापारिक कंपनियों कायं मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील)

(क) तथा (ख) राजपति अधिकारियों के चयन से सम्बन्धित नियमों का पुनरीक्षण के संबंध में कोई सामान्य प्रस्ताव किसी मंत्रालय/विभाग से गृह मंत्रालय के कार्यालय और प्रशासनिक सुधार विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, उन्हें विभिन्न समक्ष क, ख सेवाओं/पदों के लिए नवीन नियमों में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, संशोधन/पुनरीक्षण/दील देने के प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्यालय और प्रशासनिक सुधार विभाग और सच लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन संशोधनों पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

यदि किसी विशिष्ट अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इस मामले में प्रातः कोई शीर्षक देना संभव नहीं है।

(ग) बुकि किसी विशिष्ट अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे देना संभव नहीं पाया गया है। फिर भी, कोई ऐसा प्रस्ताव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के विचारार्थ इस समय सम्मिलित नहीं पड़ा है।

(घ) कड़े धर्ती नियम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धर्ती नियम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रशासन में कुशलता को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं।

Profiteering Trade Mark of Trade

2382. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn at the news-items at page 43 and 46 of "Business India" 2nd to 15th October, 1978, under the respective captions of "Profiteering Trade Mark of the Trade" and "Price Stamping—A fraud"; and

(b) if so, the reaction of Government and measures taken in that regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) Movements of wholesale price index reflect an upward trend in prices of mill-made cotton cloth in contrast with the downward trend in case of cotton prices. Price-movement is conditioned by a multiplicity of factors, important of which are raw material costs, production costs and demand and supply. Apparently, the marginal upward trend in prices of cotton cloth is mainly due to termination of sluggish demand faced by the industry during the years 1975, 1976 and part of 1977, during which prices of cloth had not moved in relation to the upward trends in prices of cotton.

Mills are at present required to stamp only ex-mill prices plus excise incidence and are debarred from stamping maximum retail prices so

that the consumer is in a position to exercise his bargaining power. Since manufacture is not always based on prior sales contracts, divergence of ex-mill price and invoice price may not be ruled out.

As regards stamping of fibre content in mill-made cotton textiles, mills are required to stamp the fibre content taking into account the use of fibre in the product, as per Textile Commissioner's notification on "marking regulations".

Meetings of N.D.C.

2383. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) number of meetings of National Development Council which are generally held in a year;

(b) number of meetings of NDC, held during 1978-79;

(c) agenda of those meetings and conclusions arrived at; and

(d) when next meeting is expected to be held?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The meetings of the National Development Council are convened as and when necessary.

(b) During the financial year 1978-79 the N.D.C. met once in February, 1979.

(c) The NDC at its meeting in February, 1979, deliberated on Centre-State financial relations and determined the allocation of Central Plan assistance among the States. It further decided that the provision of Rs. 6,000 crores approximately meant for the Centrally sponsored schemes in the Five Year Plan 1978-83 be modified from 1979-80 and that savings estimated at Rs. 2000 crores be distributed among the Gadgil formula States on the basis of total population multiplied by inverse of per capita income.

The Council also reviewed the States performance under the Family Welfare programme during the year 1978-79, and emphasised the need for continuing efforts to intensify its implementation. Besides, the Council discussed the recommendations of the Asoka Mehta Committee on Panchayati Raj and the power situation in States.

(d) No date has yet been fixed; however a meeting may be held in May, 1979, to finalise the Draft Plan, 1978-83.

Reinstatement of Employees, Affiliated with R.S.S.

2384. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether all those Central Government Employees who were sacked by the previous Government for their affiliation with Rashtriya Swayamsewak Sangh have been reinstated; and

(b) whether there are any pending cases; if so, the measures proposed to be taken soon for their finalisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) Instructions have already been issued for the reinstatement of those Central Government Employees whose services were terminated during the internal Emergency for their alleged links with the organisations like R.S.S.

(b) The information will be collected and laid on the Table of the House.

Allocation of Employees to Chandigarh Administration

2385. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government employees who have been serving in Chandigarh Administration since the 31st

October, 1966 were to be allocated to the Chandigarh Administration;

(b) whether Government employees belonging to Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and serving on deputation with Chandigarh Administration on or after 1-11-66 have been allocated to the Chandigarh Administration; if so, the number of employees from these States, separately and if not, the reasons therefor;

(c) the number of employees belonging to these States separately who have been reverted back by the Chandigarh Administration to respective States; and

(d) what steps are being taken to get all such employees belonging to these States allocated to Chandigarh Administration permanently along with the employees who have been reverted to these States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (d) Officers serving on 31-10-66 in connection with the affairs of the State of Punjab in the territories now comprising the Union Territory of Chandigarh and borne on localised cadres were allocated to Chandigarh with effect from 1-11-1966. And officers borne on cadres other than localised cadres were allocated to the successor States.

No employee belonging to Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and serving with the Chandigarh Administration on deputation has been allocated to the Chandigarh Administration.

The number of employees belonging to three States who have been reverted back by the Chandigarh Administration are as follows:

Punjab	.. 379
Haryana	.. 375
Himachal Pradesh	.. 10

The question of their absorption is being considered in consultation with the State Governments.

Chandigarh Rent Control Bill

2386. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to bring Chandigarh Rent Control Bill before Parliament during the current Session of Parliament;

(b) if so, by when the Bill is likely to be introduced;

(c) whether Government have received any representation from Building Owners Association, Chandigarh regarding deletion of certain provisions of the Bill;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the action Government are taking on the representations made by the Association regarding certain provisions of this Bill?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b) The Chandigarh Administration have proposed that the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949, as in force in the Union territory of Chandigarh, may be replaced by a comprehensive enactment of Parliament. The relevant Bill is being processed in consultation with the Chandigarh Administration. It is not, however, possible to indicate the exact time it will take to introduce the bill in the Parliament.

(c) to (e) The Chandigarh Building Owners Association represented that one of the provisions of the draft Bill sent by the Administration would operate harshly against owners of buildings which were constructed and let out on or before 4th November, 1976 and should be dropped. The provision in question envisages that the standard rent to be calculated in accordance with the principles laid down in the Bill shall not exceed the agreed rent (i.e. the rent actually being paid) in respect of such buildings by more than 25 per cent. This has been sent to Chandigarh Administration for the views on the matter.

Formula for Inter-State Allocation

2387. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has been able to evolve any formula for inter-State allocation of Central assistance to replace the Gadgil Formula;

(b) if so, what are its main features; and

(c) what is the reaction of the States to modify the Gadgil Formula?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) to (c) The National Development Council, which includes Chief Ministers of States as members, decided in a meeting held on 24th and 25th of February, 1979 that of the total Central assistance available for State Plans for the next four years, Rs. 1800 crores should be reserved for special category States, Rs. 600 crores for special problems of States and Rs. 4200 crores distributed among the 14 non-special category States, on the basis of the various criteria laid down in the Gadgil Formula, except the one relating to special problems. Besides, it was decided that an amount of Rs. 2000 crores to be released over the next four years by certain modifications in the Centrally-sponsored schemes should be distributed among the 14 non-special category States on the basis of income adjusted total population of each State (IATP), i.e., the inverse of per capita State income multiplied by population. Further, additional Central assistance is being given for hill and tribal areas, the programme of the North Eastern Council and externally-aided schemes.

Late Duty Allowance to Police Personnel

2388. SHRI SUKHEO PRASAD VERMA: Will the Minister of HOME

AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether police personnel are entitled for late duty allowance after completing eight hours duty as other Government Employees; and

(b) if so, what are the rates per hour and how far they are comparable to Central Government employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). The required information is being collected from the State Governments. As soon as the required information is received, it will be laid on the Table of Lok Sabha.

Deployment of CRP in Pondicherry

2389. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Reserve Police force has been deployed in Pondicherry to suppress the anti-merger agitation by the Pondicherry people;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether it is a fact that this force has not been withdrawn?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c). In addition to one company of the C.R.P. already deployed in Pondicherry, four more companies were made available to the Pondicherry administration in January, 1979 to assist them in the maintenance of law and order. With the improvement in the situation, three companies of CRP have since been returned by them. They are still retaining two companies for maintenance of law and order.

राजस्थान के पिछड़े जिलों का विकास

2390. श्री वीरलाल वटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की सूची में हैं;

(ख) ऐसे राज्यों की सूची में राजस्थान का क्या स्थान है और क्या ऐसे सभी राज्यों की पिछड़ेपन के कम में एक सूची तैयार कर रखी जायेगी; और

(ग) राजस्थान सहित इन पिछड़े राज्यों के औद्योगिक विकास के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्मोहि ब्रजलाल शर्मा) (क) निम्नलिखित राज्यों का वर्गीकरण औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों के रूप में किया गया है:—

1. आंध्र प्रदेश
2. आसाम
3. बिहार
4. हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू और कश्मीर
6. मध्य प्रदेश
7. मणिपुर
8. मेघालय
9. नागालैंड
10. उड़ीसा
11. राजस्थान
12. त्रिपुरा
13. सिक्किम
14. उत्तर प्रदेश

(ख) चूंकि पिछड़े हुए राज्य उनके लापेख रूप से पिछड़ेपन के अनुसार नहीं दिये गये हैं, इसलिए उनमें राजस्थान का स्थान कहाँ पर है यह बता सकना संभव नहीं है ।

(ग) केन्द्र सरकार राजस्थान सहित जितने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रांत घोषित किया गया है वहाँ के जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन देती है:—

1. इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया की रियायती दर पर पुनर्वित्त योजना ।
2. आयाकर में कटौती ।
3. तकनीकी सेवाओं के लिये परामर्श देना ।
4. नये एककों का पंजीयन तथा देश में अन्यथा प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में विद्यमान एककों का विस्तार करना ।
5. व्याज में राजमहाम्यता ।

6. राष्ट्रीय लघु उद्योग निवम वि० द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का संभरण करना।
7. केन्द्रीय निवेश राजसहायता।
8. कच्चे माल के आयात के लिये विशेष सुविधाएं देना।

राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित की गयी बड़ी तथा मध्यम औद्योगिक एवं खनिज परियोजनाएँ कीचे दी जाती हैं:—

1. हिन्दुस्तान कॉपर, खेतरी।
2. हिन्दुस्तान जिंकु (देवरी, बलरिया, मातव, राजपुरा, बरीबा, जवाहराला बरोरी)।
3. पायराइट्स, फॉस्फेट एण्ड केमिकल लि०, सलाधीपुरा।
4. साम्बर सॉल्ट।
5. हेथी वाटर प्लांट, कोटा।
6. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, 'ग्रजमेर'।
7. इस्ट्रुमेंटेशन लि०, कोटा।

पंचवर्षीय योजना, 1979—83 के प्रारूप में उपर्युक्त परियोजनाओं के बिल्वार कार्यक्रम की व्यवस्था कर दी गयी है। पायराइट्स निक्षेपों के विकास तथा फॉस्फेटयुक्त उर्वरक परियोजना की स्थापना के बारे में भी अध्ययन किया जा रहा है।

Manufacture of Diesel Cars

2391. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) is it a fact that Government have allowed to manufacture some diesel cars in the country;

(b) if so, how many cars have been allowed to be manufactured and what will be its price;

(c) why Government do not allow to manufacture more diesel cars when there is a great demand;

(d) is it a fact that public will not be able to get any diesel car; and

(e) how many cars have been sold so far and to whom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI-MATI ABHA MAITI): (a) and (b). M/s. Hindustan Motors Ltd., West

Bengal, have been granted *ad hoc* permission to manufacture 300 Ambassador Cars with 1489cc diesel engines and market them for selective customers for trial and demonstration purposes so that they could get feed back on the performance of the dieselised cars in actual operating conditions. The manufacturers have reported that the ex-factory price of the Ambassador Car with diesel engine is Rs. 45913.

(c) Various studies are in progress for updating the automotive industries, including improvement of fuel efficiency of passenger cars and dieselisation of cars having regard to the availability of diesel and petrol vis-a-vis demand, techno-economic and technological aspects of switch-over to diesel.

(d) and (e). The manufacturers have reported that they have so far sold 21 cars to the public.

Sick Industries taken over by Government

2392. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the names of the sick industries which have been taken over by Government in the last 3 years;

(b) how much loss has been incurred by each factory taken over by Government during the last 3 years;

(c) what is the policy of Government to hand over the industry back to the owner if they could guarantee to run it efficiently in future and against whom there are no cases of embezzlement etc; and

(d) how many complaints have been received by Government against the officers of such companies and what action has been taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The names of the industrial

undertakings the management of which has been taken over under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 during the last three years and the losses incurred or profits earned by them are given in the statement attached.

(c) The Minister of Industry in the policy on sick industries' announced in both Houses of Parliament on 15-5-1978 had clarified that the

management of an industrial undertaking once taken over under the Industries (Development & Regulation) Act, will not be returned to the same management.

(d) Complaints about the working and the officers of various such industrial undertakings are received by the administrative Ministries concerned with the undertakings. Hence information on this account is not readily available.

Statement

S. No.	Name of the industrial undertaking	Loss/ Profit (Value Rs. lakhs)	Period	
			From the date of take over	To
1	2	3	4	5
1	M/s. Plyboard Industries Ltd., Srinagar. (J&K)	—10.71	27-4-76	November, 78
2	M/s. Britannia Engineering Co. Ltd., (Tita- garh Unit)	—54.00	22-5-76	Do.
3	M/s. National Company Ltd., Calcutta .	—571.62	30-7-75	April, 78
4	M/s. Bengal Potteries Ltd., Calcutta .	—73.72	15-9-76	June, 78
5	M/s. Pulgaon Cotton Mills Ltd., Bombay.	+130.02	25-11-76	November, 78
6	M/s. Cauvery Spg. & Wvg. Mills, Pudukkot tai Distt., Tamil Nadu	—32.35	23-12-76	October, 78
7	M/s. Western India Spg. & Mfg. Co. Ltd., Bombay	+4.00	11-3-77	November, 78
8	M/s. Union Jute Co. Ltd., Calcutta .	—29.12	16-5-77	March, 78
9	M/s. Kharjai Company Ltd., Calcutta .	*N.A.	16-5-77	..
10	M/s. Alexandra Jute Mills Ltd., Calcutta .	*Do.	18-7-77	..
11	M/s. Subhixmi Mills Ltd., Cambay, Gujarat	—1.70	10-8-77	September, 78
12	M/s. Priyalaxmi Mills Ltd., Baroda, Gujarat	—22.00	23-7-77	March, 78
13	M/s. Indore Textiles Ltd., Ujjain, Madhya Pradesh	—24.11 (Prev.)	12-8-77	November, 78
14	M/s. Soma Sundaram Super Spg. Mills, Distt. Ramanathanpuram, Tamil Nadu .	+3.96	4-11-77	Do.
15	M/s. Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd., Calcutta	—57.60	15-12-77	December, 78
16	M/s. National Rubber Manufacturers Ltd., Calcutta	—144.00	23-12-77 10-2-78	November, 78
17	M/s. National Rubber Manufacturers Ltd., Kalyani Unit, Calcutta			

1	2	3	4	5
18	M/s. Sri Rama Sugars & Industries (Bobbili Unit), Distt. Srikakulam	*N.A.	4-2-78	.
19	M/s. Kottayam Textiles Ltd., Ettumanoor, Kerala	*N.A.	6-2-78	.
20	M/s. Prabhuram Mills Ltd., Chengannur, Kerala	*N.A.	9-2-78	.
21	M/s. Malabar Spg. & Wvg. Mills Ltd., Calicut, Kerala	*N.A.	9-2-78	.
22	M/s. Aloke Udyog Vanaspati & Plywood Ltd. Calcutta	*Production started on	12-78.	
23	M/s. Swadeshi Cotton Mills Ltd., Kanpur.	+158.56	13-4-78	December, 78
24	M/s. Inchek Tyres Ltd., Calcutta	(-)146.00	Do.	November, 78
25	M/s. Sri Durga Cotton Spg. & Wvg. Mills Ltd., Houghly	*Not available	Do.	..
26	M/s. Aluminium Corporation of India Ltd., Calcutta	*N.A.	1-5-73	..
27	M/s. Bengal Immunity Co. Ltd. Calcutta	(-)30.00	18-5-78	September, 78
28	M/s. Kennisen Jute Mills Ltd., Calcutta	(-)11.10	29-5-78	November, 78
29	M/s. R.B.H.M. Jute Mills Pvt. Ltd., Katihar Bihar	*N.A.	18-3-73	.
30	M/s. Apollo Tyres Ltd., Chalakudi, Kerala	Government Order has been challenged in Dth High Court.		
31	Dr. Paul Lohmann (India) Ltd., Calcutta	*N.A.	10-11-73	.
32	M/s. Sri Rama Sugars and Industries (Seethanagram Unit), Distt. Srikakulam	*N.A.	6-1-73	.
33	M/s. Breatford Electric (India) Ltd., Calcutta	*N.A.	26-2-79	.

*Reports on profit/loss from these undertakings have not been received. Most of these undertakings are being managed by Authorised Controller for less than a year.

Export of Cotton by Cotton Corporation of India

2393 SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Cotton Corporation of India was given a quota of 25,000 bales of Bengal Deshi cotton for export in or around July last;

(b) the prevailing international prices of Bengal Deshi cotton then;

(c) whether the Cotton Corporation did not sell the cotton then but sold

it much later at considerably lower prices;

(d) the quantities sold by it in each subsequent month and the average price realised; and

(e) whether Government have made any investigation into this unsatisfactory transaction and whether any action was taken against the persons responsible?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir. The Cotton Corporation of

India was granted permission at the end of June, 1978 to export 25,000 bales of Bengal Deshi cotton of the previous seasons lying in their stocks.

(b) Prices of Bengal Deshi cotton are not generally quoted in international markets.

(c) In view of answer to (b) above, does not arise.

(d) The following quantities were sold at the following average prices during the months mentioned against each:—

Month	Quantity in bales	Average price in US cents per lb.
July, 1978	766	71.00
August, 1978	2,103	75.58
September, 1978	350	52.10
October, 1978	14,585	52.81
November, 1978	1,589	40.86
	19,395	

(e) No, Sir. Price realisation is dependent on various factors like the lots offered, the quality and age of cotton and the prevalent demand in the consuming market. The cotton in reference here pertained to previous seasons and their price realisation is not comparable with that of the current season cotton. Another pertinent factor is that the cotton in reference here was originally purchased by the Cotton Corporation of India for domestic mill consumption and strictly speaking, is not comparable with exportable qualities of Bengal Deshi. The sales transactions were through invitation of tenders on a global basis, scrutinised and accepted on the basis of the recommendations of a suitably constituted Export Advisory Committee.

Making of Enriched Uranium in the Country

2394. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have studied the relative economics of making enriched uranium within the country; and

(b) if so, what are its conclusions?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Yes, Sir. Production of enriched uranium is considered uneconomical at this stage of our nuclear power programme.

Indian Explosives Ltd.

2395 SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether between 1964 and 1971 the production of the Indian Explosives Ltd. according to the Monopolies Commission exceeded its sanction capacity by 82,000 tonnes;

(b) the amounts remitted by the company abroad by way of royalty, dividends, commission on purchases, technical fees, etc. in respect of this additional production;

(c) how far is this in accordance with the Foreign Exchange Regulations Act; and

(d) the steps taken by the Government for the refund of any remittances made by the company in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Under standard accounting procedure, it is not feasible to maintain data in respect of remit-

tances by way of royalty, dividends etc., attributable to excess production.

(c) Does not arise.

Sub-Committee to enquire into the charges against Shri Kantibhai Desai

2396. SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the informal cabinet sub-committee has been constituted to go into the allegations made against Shri Kanthibhai Desai; and

(b) what are the charges that are being looked into by this Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्री कान्ति भाई देसाई के विरुद्ध आरोप

2397. श्री हुकमदेव नारायण बाबू: क्या यह सही यह बताने की हवा करेगी कि :

(क) क्या श्री कान्ति भाई देसाई के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देशित करने के संबंध में इस बीच विधि मंत्रालय की राय ले ली गयी;

(ख) क्या इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश का कानूनी सलाहकार है; और

(ग) सरकार किन कानूनी उपबंधों के अंतर्गत इन आरोपों की जांच करने के लिए उन्हे अधिकार है सकती है ?

यह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालयभराम्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटील)

(क) से (ग) सरकार ने यह निर्णय किया है कि 10 अगस्त, 1978 को राज्य सभा में पारित किए गए प्रस्ताव पर हुई बहस को भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस अनुरोध के साथ भेजा जाए कि वह यह निर्णय करें कि क्या उपर्युक्त बहस में उल्लिखित किसी आरोप के संबंध में कोई प्रामुख्यता मामला बनता है जिसका संबंध मार्च, 1977 में वर्तमान सरकार द्वारा कार्यप्रणाली करने के बाद की प्रचलित है, जिससे कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत कोई

औपचारिक जांच किया जाता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संदर्भ, मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली सलाह की प्रकृति की दृष्टि से, प्रशासनिक, अतिरिक्त-सामाजिक स्वरूप का होगा

Allegations against Shri Kantibhai Desai

2398. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister had promised that any allegation against Shri Kantibhai Desai made by a Member of Parliament will be referred to the Chief Justice of the Supreme Court;

(b) if so, the number of allegations received so far; and

(c) in view of the paucity of response whether the Prime Minister proposes to change this procedure of making allegations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) In his statement made in Rajya Sabha on the 24th August, 1978, the Prime Minister mentioned, inter alia, "in the event of any specific charges of corruption in the context of the Resolution being made to it in writing by any honourable Member since my Government took office, Government propose; to refer the same to the Chief Justice of India for being examined by him."

(b) None, Sir.

(c) Does not arise in view of the decision taken by the Government to refer the debate on the Motion that was adopted on the 10th August, 1978, in the Rajya Sabha, to the Chief Justice of India, for his examination, any of the charges referred to in the debate aforesaid, which pertain to the period after the present Government took charge in March, 1977.

**Increase in prices of Soaps of
Hindustan Lever Limited**

2399. SHRI C. K. CHANDRAPPA:
Will the Minister of INDUSTRY be
pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hindustan Lever Limited has increased the price of its popular brands of soap on the one hand and on other hand substantially reduced the total fatty matter content which dete mines the quality of soaps in December, 1977;

(b) if so, the details thereof and whether any more such steps have been taken by the company in 1978 and 1979;

(c) whether Government can provide the details of the price increase since 1973 of the mass consumption products of this company such as Sunlight, Lifebuoy (tablet; and bar), Lux and Rexona toilet soaps etc. and the fluctuations in their TFM content (total fatty matter content); and

(d) whether Government are aware of the fact that the simultaneous increasing of price and reduction of TFM content are attempts to fleece the public in two ways simultaneously, if so, whether any norms have been stipulated on companies in these matters?

THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF INDUSTRY
(SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). Yes, Sir. A statement regarding prices is appended.

There is no price control on soaps. The T.F.M. (Total Fatty Matter) content of soap is not uniform for different brands. Minimum percentage of T.F.M. has been prescribed in ISI standards. However, the ISI Certification Scheme is voluntary. Messrs. Hindustan Lever Limited have not applied for certification under this scheme.

(d) In the light of the reply to (a) to (c) the question does not arise.

Statement

Maximum Retail price per cake.

	17-1-1977	17-1-1977	23-2-1977	16-1-1978
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Lifebuoy	1'18	1'25	1'18	1'25
Lux Toilet std.	1'28	1'35	1'28	1'35
Lux Toilet Min.	0'39	0'41	0'39	0'41
Rexona Std.	1'30	1'35	1'30	1'37
Rexona Min.	0'39	0'41	0'39	0'41
Saral Janta	0'92	0'92	0'92	0'92
Lux Supreme	2'10	2'21	2'21	2'21
Pears	2'51	2'63	2'63	2'63
Liril	1'85	1'95	1'95	1'85*
Sunlight	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

*Reduced on 27th April, 1977.

**Finance by Central/State Subsidy
Institutions to Entrepreneurs in
Tripura**

2400. SHRI SACHINDRA LAL SINGHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of entrepreneurs in Tripura facing many hurdles in the matter of finance by Central and State subsidy institutions;

(b) if so, the details of the Government proposal to simplify the subsidy rules for the new undertaking in the backward areas; and

(c) the details of the scheme approved by the national Banks in the State, Branchwise for the new industry during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). For industrial development of backward areas, Government of India have announced a number of concessions and facilities. Central Investment Subsidy @15 per cent of fixed capital investment subject to a maximum of Rs. 15 lakhs, is given to industrial units set up in selected backward areas. Under the Scheme, subsidy is disbursed by the Directors of Industries and the financial institutions of the Central Government/State Governments so authorised for the purpose by the State Government concerned. The financial institutions had expressed certain difficulties in operation of Central Investment Subsidy Scheme and their consequent inability to disburse the subsidy to industrial units in backward areas. The procedure was streamlined in order to minimise delay in reimbursement of Central Investment Subsidy. In view of this streamlined procedure the financial institutions reconsidered the issue and have decided to disburse the subsidy to the units assisted by them along-

with loan and no interest would be charged for a period of 6 months on the amount of subsidy so disbursed.

Under the new programme of District Industries Centres, Investment Subsidy upto Rs. 2.25 lakhs will be sanctioned by the District Level Committees and the General Manager of District Industries Centre who is Member-Secretary of the District Level Committee, will disburse the subsidy expeditiously. This will go a long way in expediting the applications of entrepreneurs for the grant of subsidy.

The Central Government have not received any complaint either from State Government of Tripura or entrepreneurs regarding facing hurdles for getting financial assistance from financial institutions.

(c) Nationalised Banks normally do not draw up scheme branchwise. Public sector banks have been endeavouring to step up their advances to small scale industries. Recently, RBI had advised banks to provide loans to artisans, village and cottage industries and small scale industries in the tiny sector on liberalised terms. Banks have been instructed to provide credit upto Rs. 25,000/- to these borrowers without insisting on margin. The rate of interest on composite term loan should not exceed 11 per cent and 9½ per cent in specified backward districts. Banks are also not required to insist on third party guarantee and collateral securities in respect of these categories of borrowers.

**RE: QUESTION OF PRIVILEGE ON
ALLEGED LEAKAGE OF BUDGET
PROPOSALS**

MR. SPEAKER: Sarvashri Vayalar Ravi and Vasant Sethe, MPs., gave notices of question of privilege against the Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Charan Singh) re: alleged leakage of Budget proposals for 1979-80 before their presen-

tation to Parliament, as published in the *Sunday Northern India Patrika*, Allahabad, and *Morning Echo*, New Delhi.

When Sarvashri Vayalar Ravi and Vasant Sathe sought to raise the matter in the House on the 5th March, 1970, I had said that I would call for the comments of the Deputy Prime Minister and the Minister of Finance.

The Ministry of Finance has sent two detailed factual notes in respect of the two notices, with the approval of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance, in which they have concluded that the reports appearing in the newspapers concerned were purely in the nature of speculation and guess-work and were not based on any knowledge of the contents of the Budget. They have also stated that it is not unusual for economic analysts and newspapers to make such forecasts of the likely features of a forthcoming Budget particularly after the publication of Economic Survey and that the reports published in the *Northern India Patrika* and the *Morning Echo* could not possibly be based on any leakage of Budget proposals. There is also wide discrepancy between the speculations made in those papers and the actual budget proposals in major respects.

I have compared all that. There is wide divergence between the two.

I am not satisfied even *prima facie* that there has been any leakage of the Budget proposals. In this view, it is not necessary to go into the question whether the leakage of a budget is a matter coming under Rule 222.

In fact, my predecessor had given a ruling that the leakage of budget does not come under rule 222. But I am not pronouncing on it, because the matter requires further examination.

I do not, therefore, give my consent for raising the matter in the House as a question of privilege under Rule 222.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): I do not want to make any comment on the ruling. Apparently there are many many areas of similarity between the speculations and the proposals, with reference to the deficit, i.e. the amount of deficit—Rs. 2,000 crores and Rs. 2,000 crores.

MR. SPEAKER: No; there is a wide divergence. What is said is Rs. 1600 crores, but it is actually Rs. 1900-odd crores.

SHRI C. M. STEPHEN: May I make a submission here? Even if there is an actual leakage of these Budget proposals, they will be clever enough to put into it, certain items which may give an impression that every item does not agree. The point is whether in the majority of items revealed in the Press, there is a similarity between what has been placed before the House, and what has been published. In the major part of it, about 80 per cent to 90 per cent.....

MR. SPEAKER: That, again, is not correct.

SHRI C. M. STEPHEN: In a substantial part of it there is a similarity.

MR. SPEAKER: Not even substantially.

SHRI C. M. STEPHEN: I am not seeking for taking it up as a matter of privilege, but I do submit that there is sufficient material in it for the House to go into, either by appointing a Committee, or having a discussion.

It is a very, very serious matter, an absolutely serious matter, in this sense that what items are going to be taxed—that has been given. The total taxation is Rs. 566 crores or Rs. 650 crores; it is given. Everything is given. Absolutely everything is given. I would submit that the House must be given an opportunity to discuss this matter and to decide as to whether a Committee should be appointed to go into this matter.

1205 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORTS OF INDIA STATISTICAL INSTITUTE, CALCUTTA FOR 1975-76 AND 1976-77.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): On behalf of the Prime Minister,

I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Calcutta, for the year 1975-76.

(2) A copy of the Annual Report of the Indian Statistical Institute, Calcutta, for the year 1976-77.

(3) A statement (Hindi and English versions) (a) showing reasons for delay in laying above Reports and (b) for not laying simultaneously the Hindi version of the Report for the year 1976-77. [Placed in Library. See No. LT-4443/79].

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF TRIVENI STRUCTURALS LIMITED, ALLAHABAD AND HINDUSTAN CABLES LTD. FOR 1977-78

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(a) (i) Review by the Government on the working of the Triveni Structurals Limited, Naini, Allahabad, for the year 1977-78.

(ii) Annual Report of the Triveni Structurals Limited, Naini, Allahabad, for the year 1977-78 alongwith the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in Library. See No. LT-4035/79].

(b) (i) Review by the Government on the working of the Hindustan Cables Limited, for the year 1977-78.

(ii) Annual Report of the Hindustan Cables Limited, for the year 1977-78 alongwith the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (b) above. [Placed in Library. See No. LT-4036/79.]

(3) A copy of Notification No. S.O. 3354 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 25th November, 1978, making certain amendment to Notification No. S.O. 900 dated the 28th August, 1975. [Placed in Library. See No. LT-4037/79.]

DELHI SIKH GURDWARAS MANAGEMENT COMMITTEE (REGISTRATION OF ELECTORS) AMENDMENT RULES, 1978, AND A STATEMENT CORRECTING ANSWER TO U.S.Q. No. 201, DATED 21-2-79 RE CASES FILED TO INVESTIGATE INTO EMERGENCY EXCESSES

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Registration of Electors) Amendment Rules, 1978 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. 1618/78-Pt. II-Judl. in Delhi Gazette dated the 6th Nov., 1978 together with a corrigendum thereto published in Notification of even number dated the 3rd January, 1979 under sub-section (4) of section 39 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971. [Placed in Library. See No. LT-4038/79.]

(2) A statement correcting the reply given on the 21st February,

1979, to Unstarred Question No. 201 by Shri Samar Mukherjee regarding cases filed to investigate into Emergency excesses.

STATEMENT

In reply to Unstarred Question No. 201 answered on 21-2-1979, the following was stated:

"Seventeen criminal cases have been registered so far. A statement showing the requisite information is enclosed."

The word "Seventeen" occurring in the above answer may be substituted by the words "Twenty one". The following FIRs may be added as S. Nos. 18 to 21 in the Statement enclosed with the reply.

"IV. SHAH COMMISSION OF INQUIRY (CONTD.)

18. RC.2/79-SIU(SIB.I), dated 19-2-79.	1. Shri P.S. Bhinder 2. Smt. Ambika Soni and others.	Detention of Virendra Kapur.	The case has been taken up for investigation.
19. RC.4/79-SIU(SIB.II), dated 19-2-79.	1. Shri Jagmohan 2. Shri S.M. Dua and others.	Demolition of Arya Samaj Temple.	Do.
20. RC.3/79-SIU(SIB.I) dated 20-2-79.	1. Shri Krishan Chand. 2. Shri K.S. Baiwa and others.	Detention of Dr. Karunesh Shukla.	Do.
21. RC.5/79-SIU(SIB.II) dated 20-2-1979	1. Shri Jaymohan 2. Shri Satya Prakash 3. Shri Ranbir Singh and others.	Demolition of Arjun Nagar.	Do.

(3) A copy of the Sikh Gurdwaras Board Election (Amendment) Rules, 1979 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 206(E) in Gazette of India dated the 2nd March, 1979, under sub-section (3) of section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925. [Placed in Library. See No. LT-4640/79.]

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION (MEMBERS) AMENDMENT REGULATIONS, 1979 AND NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT, 1951

SHRI DHANIK LAL MANDAL:
On behalf of Shri S. D. Patil, I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under article 313 of the Constitution:—

(i) The Union Public Service Commission (Members) Amendment Regulations 1979 published in Notification No. GSR 74 in Gazette of India dated the 20th January, 1979.

(ii) The Union Public Service Commission (Members) Second Amendment Regulations, 1979, published in Notification No GSR 62(E) in Gazette of India dated the 3rd February, 1979. [Placed in Library. See No. LT-4041/79.]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951:—

(i) The Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Seventh Amendment Regulations, 1978, published in Noti-

Section No. G.S.R. 579(E) in Gazette of India dated the 17th December, 1978.

(ii) The All India Services (Provident Fund) Amendment Rules, 1979, published in Notification No. GSR 295 in Gazette of India dated the 24th February, 1979. [Placed in Library. See No. LT-4042/79.]

NOTIFICATIONS UNDER CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, 1944, CUSTOMS ACT, 1962 AND CENTRAL EXCISE RULES, 1944

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Central Excises (Second Amendment) Rules, 1979, (Hindi and English versions), published in Notification No. G.S.R. 120(E) in Gazette of India dated the 1st March, 1979, under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [Placed in Library. See No. LT-4043/79.]

(2) A copy each of Notification Nos. G.S.R. 184(E) to G.S.R. 203 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st March, 1979 regarding Customs Duty changes and exemptions as announced in Parliament while presenting the Budget for the year 1979-80, under section 159 of the Customs Act, 1962, together with an explanatory note. [Placed in Library. See No. LT-4044/79.]

(3) A copy each of Notification Nos. GSR 107(E) to GSR 119(E) and GSR 121(E) to 183 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st March, 1979 regarding Central Excise Duty changes and exemptions as announced in Parliament while presenting the Budget for the year 1979-80, issued under the Central Excise Rules, 1944, together with an explanatory memorandum [Placed in Library. See No. LT-4045/79.]

12.05 hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

MINUTES

SHRIMATI CHANDRAVATI (Bhivani): I beg to lay on the Table the minutes of the sittings relating to second, Fifth, Seventh, Ninth and Fifteenth Reports of the Committee on Public Undertakings on Central Inland Water Transport Corporation.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

I am directed to inform the Lok Sabha that the Merchant Shipping (Second Amendment) Bill, 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th November, 1978, has been passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 5th March, 1979, with the following amendments:

Enacting Formula

1. That at page 1, line 1, for the word "Twenty-ninth" the word "Thirtieth" be substituted.

Clause 1

2. That at page 1, line 3, the word "Second" be omitted.

3. That at page 1, line 4, for the figure "1978" the figure "1979" be substituted.

Clause 2

4. That at page 1, line 13, for the words brackets and figure "(Second Amendment) Act, 1978" the words, brackets and figure "(Amendment) Act, 1979" be substituted.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

MERCHANT SHIPPING (SECOND AMENDMENT) BILL

As RETURNED BY RAJYA SABHA WITH AMENDMENTS

SECRETARY: Sir I lay on the Table of the House the Merchant Shipping (Second Amendment) Bill, 1978, which has been returned by Rajya Sabha with amendments.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): You have made your observation and I fully agree.

MR. SPEAKER: You can raise it during the budget discussion.

SHRI VAYALAR RAVI: I fully agree with your observation that it is not a question of privilege. There were two cases in the British House of Commons, one in 1947 and another in 1936. At that time the Chancellor of the Exchequer admitted that he leaked out the secret. It is only a question of a parliamentary committee enquiring into it. There is similarity.

MR. SPEAKER: There are two conflicting decisions, one given by Mr. Ananthasayanam Ayyangar and another given earlier. I have not gone into that matter, because I did not want to go into that matter. It is for the House to decide.

SHRI VASANT SATHE (Akon): How will you give an opportunity to the House?

MR. SPEAKER: If there is some provision under the rule, it can be considered.

SHRI VASANT SATHE: We will give notice of a motion.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): What about the notice I have given?

MR. SPEAKER: I have got the reply. I am examining it. Probably I will take it up tomorrow.

श्री एडुआर्दो फालेरो (मोर्मुगाओ) : क्या मैं सूचना दे सकता हूँ ? कल दो बजे प्रदर्शन होगा ।

MR. SPEAKER: That is not a pending matter.

श्री एडुआर्दो फालेरो : मेरी बात सुन लीजिए । आप सुनने नहीं हैं । कल दो बजे । एक जुलूस विद्यार्थी परिषद का निकला था और एक प्रदर्शन भारतीय एम्बेसी के सामने हुआ । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है, बीयलनाम पर हमला हुआ है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है और पूरी दुनिया की निंदा है, यह बीयलनाम का मामला है । (स्वयंघान)

MR. SPEAKER: How can that be a point of order? You can give any other notice. By merely mentioning that it is a point of order, it does not become a point of order. Which rule has been breached? There must be a pending matter.

श्री एडुआर्दो फालेरो : मेरा प्वाइंट ऑर्डर इसलिए देने का है । पहले जो मैं कह रहा हूँ, उस को सुन लीजिए और समझ लीजिए । यह पूरी दुनिया की जो मासूम की निंदा है, जो गरीब है, उस का मामला है । देश भर की सारी पार्टियों के लोग बहाने बने और उन्होंने बहाने पर प्रदर्शन किया । इस तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से देखियो और टेलीविजन पर प्रसार चलता है । एक तरफ बीयलनाम का मामला है और दूसरी तरफ दुनिया भर के लोगों का मामला है ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Will you allow this sort of statement?

MR. SPEAKER: Mr. Yadav, I have been repeatedly telling you that a point of order arises when a matter is pending, which is being discussed in the House. You have other procedure. You may give notice and I will consider it.

श्री कान्वर लाल गुप्ता : मैं बयान के लिए कह दे दूंगा

की राय विज्ञापित पाठवान् हाजीर) : मेरा काल घंटेशन पर प्वाएंट आफ् चार्ज है। मैं ने पात्र प्रदेश के हरिजन एम.एल.ए. के सम्बन्ध में काल घंटेशन नोटिस दिया है जिसको आपने स्वीकृत किया है। उसके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

MR. SPEAKER: It is admitted for tomorrow.

12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DECISION OF THE ADDITIONAL
SESSION JUDGES AND MAGISTRATE IN
DELHI 10 MARCH TO PARLIAMENT
HOUSE ON THE 16TH MARCH, 1972.

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिलक्षणीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य सचिव का ध्यान दिखाना हूँ और प्रार्थना करत हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक बक्तव्य दें :—

"दिल्ली के प्रतिरिक्त सब न्यायाधीशों और इन्फ़ार्मिस्टों का अपनी मांगों पर यत्न आकषित करने हेतु 16 मार्च, 1979 को संसद भवन तक जलूस निकालने का निश्चित निर्णय।"

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Mr. Speaker, Sir, The Secretary, Delhi Judicial Service Association, vide his letter received on 25th January, 1979, intimated to Government that the General Body Meeting of the said Association had passed a resolution on 8th January, 1979 to the effect that if their demands contained in their Memorandum dated 12th October, 1977 were not accepted by the Central Government by 1st March, the Judicial Officers would be constrained to go on a march to the residence of the Law Minister.

According to subsequent report in the Press the Judicial Officers have decided to march to Parliament on 16th March, 1979.

The main demand raised in the memorandum pertains to the scales of pay of the officers of the Delhi Judicial

Service and the Delhi Higher Judicial Service including the District and Sessions Judge. In respect of the Delhi Higher Judicial Service they have demanded that the time-scale should be Rs. 2000—2250 as compared to the existing grade of Rs. 12000—2000, that the selection grade should be 2500—2750 compared to the existing selection grade of Rs. 2000—2250 and that the grade of the District and Sessions Judge should be Rs. 3000 fixed as compared to the existing grade of Rs. 2500—2750. Regarding the Delhi Judicial Service they have represented that the posts should be treated as Class I posts and that the grade of the ordinary time scale should be Rs. 700—1300 as against the existing grade of Rs. 650—1200, that a senior scale of Rs. 1200—1800 should be available after 5 years' service and that the selection grade should be Rs. 1500—2000 as against the existing selection grade of Rs. 1200—1600. They have in this connection cited the scales of pay fixed in the neighbouring States of Punjab, Haryana and Rajasthan and also the grades admissible in Karnataka, Bombay and Calcutta.

3. In this connection I would like to point out to the House that the present grades were fixed by the Third Pay Commission after keeping all relevant factors in view. Broadly the principle followed is that in so far as the Lower Judicial Service (Delhi Judicial Service) is concerned, parity is maintained with the corresponding Civil Service namely the DANI Civil Service. In so far as the Higher Judicial Service is concerned, parity of the time scale and the selection grade is maintained with the senior scale and the selection grade admissible to officers of the IAS. At the apex the super-time scale admissible to the District and Sessions Judge corresponds to the super-time scale admissible to officers of the rank of Commissioners of Divisions and Joint Secretaries to the Government of India.

These parities between the Civil Services and the Judicial Services have been settled feature for a very long

time and exist not merely in Delhi but in most States of the country including the States of Punjab, Haryana and Rajasthan mentioned by the representatives. Disturbance of the existing balance between the judicial and other services is likely to have complex repercussions not merely on the pay structure of other cadres in the Union Territory of Delhi but also on different cadres in the rest of the country. I may point out that the scales of officers of the Delhi Judicial Service were fixed on the basis of the recommendations of the third Pay Commission with effect from 1st January, 1973 when the scales of the corresponding officers in States like Punjab, Haryana, Karnataka and Rajasthan were lower. An increase in the scales of civil servants and judicial officers has occurred in these States since then. However, it would not for that reason be possible to unilaterally examine any increase in the scales of pay of any single cadre in isolation from others.

In their memorandum the Delhi Judicial Service Association have also asked for certain allowances like conveyance allowance, book allowance and dress allowance as well as for a Government house for every member of the Judicial Service. They have, besides, suggested the division of Delhi into five districts for the purpose of judicial administration an aspect which pertains primarily to the administration of justice and not to their conditions of service. Proposals regarding these have not yet been received from Delhi Administration.

SHRI ANNASAHAB GOTKHINDE (Sangli): On a point of order, Sir. The hon. Minister has referred to the names of some States in the country, that is, Punjab, Haryana, Rajasthan, Karnataka and Bombay. Is there any such State like Bombay in the country?

MR. SPEAKER: That is not a point of order.

SHRI ANNASAHAB GOTKHINDE: It is a mis-statement.

MR. SPEAKER: No point of order.

SHRI ANNASAHAB GOTKHINDE: Is it a correct statement?

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : 1974 से यह केस सिटिल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। तब से एडीशनल सेशन जज श्री मैजिस्ट्रेट आपको रिप्रिजेंटेशन देते आ रहे हैं। किसी भी मूक के लिए इससे ज्यादा दुर्भावपूर्ण बात और क्या हो सकती है कि, वहां एडीशनल सेशन जजों और मैजिस्ट्रेटों को भी आ कर डेमण्डेशन करना पड़े और उसके बाद उनकी बात सुनी जाए। इस बीच में उनके पज आपको मिलते रहे हैं। इस धक्कतुबर 1977 को अपने रिप्रिजेंटेशन में उन्होंने फैसला किया कि जनवरी के महीने तक हम इंतजार करेंगे और उससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। जनवरी में उन्होंने फैसला किया कि हम डेमण्डेशन करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बीच उनके साथ कोई डायलॉग क्यों नहीं किया गया, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं की गई? एडीशनल सेशन जजों और मैजिस्ट्रेटों को सालों साल इंतजार करना पड़े और उन से डायलॉग तक न हो यह साबित करता है कि इस तरह की बात को जितनी सीरियसली देखना चाहिये था उतनी सीरियसली देखा नहीं गया है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें के कमिशन की रिपोर्ट पर वे स्केल लागू हुए थे और इनको 1-1-73 से लागू किया गया था। लेकिन 1974 की पहली अप्रैल को

Delhi was declared a metropolitan city under the Criminal Procedure Code with effect from 1st April, 1974.

तब दिल्ली मेट्रोपोलिटन सिटी डिक्लेयर हुई। उसके बाद इनके वे स्केल भी आपकी सेंज करने चाहिये थे। मंत्री जी ने बम्बई का हवाला नहीं दिया है। वहां पर आप वे स्केल को देखें। दोनों का मकाबला आप करें। वह भी मेट्रोपोलिटन सिटी है और दिल्ली भी। बम्बई में मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट का ग्रेड 1100-1600 है जबकि दिल्ली में 650-1200 है यानी 100 परसेंट डिफरेंस है। एडीशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट को दो सौ रुपये स्पेशल वे मिलती हैं यहां नहीं मिलती हैं। चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की बेसिक वे यहां दो हजार है यहां बारह सौ है। वहां पर दो सौ रुपये स्पेशल एलाउंस भी है। जब बम्बई और दिल्ली एक जैसी मेट्रोपोलिटन सिटी हैं और पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में दिल्ली से ग्रेड कहीं ज्यादा है तो यह जो डिफरेंस दिल्ली में इन के साथ हो रहा है इसको दूर करने के लिए 1977 से ले कर अब तक आपने कौन से कदम उठाए हैं?

मैं ला कमिशन की रिपोर्ट्स की सिर्फ दो चीजें मंत्री महोदय की पड़ कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कितने और से रिफॉर्म किया है और मंत्री महोदय

ने जो यह कहा है कि यूनिवर्सिटी हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं उस संदर्भ में यह कितना गलत बैठता है इसका धारकी इससे पता चल जाएगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है :

"We would urge necessary action without delay before the Judicial Process falls into complete disrepute by its inefficiency and its unsatisfactory working. If the Rule of Law is to become and continue to be a reality in our National Life, our courts must be manned by competent and experienced and fearless judges."

Poor remuneration for Judicial Officers can never attract competent lawyers to join the Judicial Service. We confess that we are unable to decide how we should express our firm belief in this matter in order to convince the Union Government and State Governments that they are ill-serving the Judicial Administration by refusing to recognise the patent truth that for the success of the Judicial Process, we must attract competent lawyers who just will not be attracted to the Judicial Service unless the terms of their services are radically improved."

फिर वे अपनी दूसरी रिपोर्ट में लिखते हैं :

"The life of a judge, whether on the Bench or otherwise, is a difficult one. He is called upon to adjudicate on contending claims, sift truth from falsehood, uphold lawful cause and reject the rest; and in doing his duty, he even aroused hostility. He has to tread a wary path in order to have no room for any litigant to apprehend prejudice or to court favour."

"Not only has he to be impartial but he has to conduct himself in a manner so that every one can feel he is impartial."

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी बार-बार इस बात को कहा है कि उनके रेय्मनेशन बढ़ाये जाने चाहिये। और उन्होंने जो मुकामला किया है ऐम्प्लीकैटिव मैजिस्ट्रेट से, जो ऐम्प्लीकैटिव मैजिस्ट्रेट 20, 21 साल की उम्र में मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं, जब कि जूडिशियल मैजिस्ट्रेट 26, 27 साल की उम्र में होते हैं

और उनकी कोई प्रोमोशन ऐम्प्लूश नहीं है। जूडिशियल मैजिस्ट्रेट और प्रिजिडेंट सेल्स जजेज के लिये प्रोमोशन ऐम्प्लूश नहीं है। इतलिये ऐम्प्लीकैटिव मैजिस्ट्रेट्स के मुकामले में उनकी हालत बहुत खराब है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने इस बारे में क्या एक्शनप्लेन की है, और इससे पहले कि मामला बिगड़े और वह लोग डेमान्डेशन करें, मंत्री जी उनसे डाइलाग करें ताकि डेमान्डेशन को रोका जाये और उनकी हालत में सुधार किया जाये।

श्री शान्ति भूषण : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो माननीय सदस्य ने यह उठाया है कि 1974 से उनका रिप्रजेन्टेशन पेंडिंग है तो उनसे कोई डाइलाग क्यों नहीं किया गया। पहले तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो रिप्रजेन्टेशन उन्होंने किया है वह प्रमचूबर, 1977 में किया है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनसे डाइलाग नहीं हुआ। यह ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ केन्द्रीय सरकार ही नहीं घाती है, बल्कि इससे विल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन घाता है, हाई कोर्ट भी घाता है। डाइलाग कई लेवल पर हुआ है, मिनिस्ट्री के लेवल पर भी हुआ है। भूझ से भी एक दफा पहले वह मिल चुके हैं। हाल में एक पत्र लिख कर उन्होंने भूझ से ऐपीटमेंट मांगा है और बहुत जल्दी वह ऐपीटमेंट उनको दिया जाने वाला है जिससे ऐन्जोम दी टेबिल पर बैठकर बातचीत हो सके और वह समझ सकें कि कहा उनकी बात में गलती है। उनके रिप्रजेन्टेशन में कहा-कहा गलती है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है खास तौर पर जब कि सर्विस कमीशन का मामला हो तो हर भादमी यह इमेजिन कर लेता है कि हमारी हालत बहुत खराब है। यह नहीं देखता है कि उससे भी खराब हालत में और कितने भादमी हैं हिन्दुस्तान में कि जिनकी हालत उनसे भी बहुत ज्यादा खराब है।

माननीय सदस्य ने ला कमीशन की रिपोर्ट की तरफ भी मेरा ध्यान खींचा है जिसमें कहा गया है कि जजेज के रेय्मनेशनस घुघर नहीं होने चाहिये। इसमें कोई बौराये नहीं है कि जिन वेज में लोकतल होता है, रूल थाफ ला होता है, डेमोक्रेसी होती है, उस वेज में जजेज बड़ा इम्प्रीटेंट काम करते हैं। लेकिन कम क्या है और ज्यादा क्या है उसको भी सोच ना होगा। अगर प्राज एक कोई जूडिशियल सर्विस में विल्ली में भादमी रखा जाता है तो 650 रु० बेसिक पे और 400 रु० मिला कर उसको 922 रु० तनब्राह मिलती है मुझ में १ घब अगर यह कहा जाय इस गरीब वेज में

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : एक बैंक में बपरासी को ज्यादा मिलते हैं पैसे।

श्री शान्ति भूषण : एक बपरासी को जब बैंक में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो हर व्यक्ति को, जब वह किसी सर्विस में घाता है तो उसको तय करने का यह मोका है कि वह बैंक में बपरासी बनना चाहता है या मुंसिफ बनना चाहता है, या मैजिस्ट्रेट बनना चाहता है। अगर कोई बैंक बपरासी को ज्यादा तनब्राह देता है और अगर बपरासी बनने में उसको बहुत धुसी होती है कि मैं बैंक में बपरासी बन जाऊँ तो मुझे ज्यादा मिलेगा, तो

तो यह तथ करने का उसको हक है। हमने तो सुना है कि तनकबाह 10 व० कम कर दे, पर नाम धरोखा रख दे। हम चाहते हैं, और हमारे देश की यह परम्परा है कि व्यक्ति का व० से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, बल्कि व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि वह देश के लिये कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है।

मुझे खुशी है कि ग्राम तौर पर जो हमारी जूडिशियरी है देश भर में, तनकबाह उसको कितनी मिलती है उसकी परवाह नहीं करती है, वह देखती है कि हमारी इच्छा कितनी हो, और कामन सैन के मन में हमारे लिये कितनी इच्छा है। बहुत सारे वकील हैं जो 15,000 रु० 20,000 रु० कमाते हैं प्रीक्टिस में, लेकिन उसके बाद भी वह देश की सेवा करने के लिये कम तनकबाह पर जज बनते हैं। यह गरीब देश है, और इसीलिये बनते हैं 15, 20 हजार रु० की बकालत को लात मार कर...

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली मद्र) और मिनिस्टर भी बनते हैं।

श्री शान्ति भूषण दूसरे बान जिम पर माननीय सदस्य न ध्यान खींचा है वह यह कि 1974 में दिल्ली मैट्रोपॉलिटन सिटी बन गया था...

MR. SPEAKER Do not rub salt to the injury.

श्री शान्ति भूषण जहां तक वे कमोशन की बात है, 1973 में वे कमोशन ने बहुत गहराई से इस पर विचार किया। जब भी कोई वे कमोशन बनता है तो सभी गहराई से देखता है। वे कमोशन करीब करीब 10, 11, 12 साल बाद इस देश में चलता आया है, 1950, 1962, 1973 में वे कमोशन बने और जब वे कमोशन गहराई से सारी मजिस्ट्रेट के वे स्कोस में जाना है क्योंकि एक सचिव को लेकर अगर प्राइसोलेशन में हम कसीडर करे तो उसमें यह होगा, वे कमोशन ने सभी गहराई से विचार कर के यह देखा। क्योंकि जिकायत पहले यह रहती थी कि एम्प्लीक्यूटिव सचिव को तनकबाह ज्यादा दी जाती है, मकान ज्यादा दिया जाता है और एम्प्लीक्यूटिव सचिव को एक स्टैप मद्र की तरह ट्रीटमेंट मिलना है, उसको वह पेन्कोल नहीं दिया जाता जो एम्प्लीक्यूटिव सचिव को दिये जाते हैं। उसको मकान की वह सुविधा नहीं मिलती है जो एम्प्लीक्यूटिव को मिलती है। तो वे कमोशन ने यह सब विचार कर के कहा कि जूडिशियल सचिव भी वही इम्प्लायेंट काम करती है, उनको भी वही पेन्कोल मिलना चाहिये जो एम्प्लीक्यूटिव सचिव को मिलते हैं। इसलिये वे कमोशन ने उनमें पैरिटी मेंटेन की और उक्त पैरिटी के हिसाब से दोनों में और ज्यादातर स्टेट्स में एम्प्लीक्यूटिव और जूडिशियल में पैरिटी मेंटेन है। अगर आज उस वे कमोशन की रिपोर्ट को लोक पर रखकर यह कर दिया जाये

कि एक कांडर में एक सचिव को पेन्कोल बढ़ा दिये जायें तो उसकी प्रतिश्रुति हमारे पर होगी। वह भी इतजार करने कि जब पैरिटी की हमारी और उनकी बढ़ा दी गई तो हमने ही कौन सा गुनाह किया है, क्या हम मेहनत का काम नहीं करते हैं, विभाग पर और नहीं डालते हैं, जरूरी काम नहीं करते हैं? जरूरी काम हर व्यक्ति हरसंभव में करता है और सचिव जवाबन करने से पहले वह सोचना पड़ता है, उसको स्वाधीनता होती है कि वह कौनसी सचिव में जाना चाहता है।

सचिव में जाने के बाद, मेरा यह कहना नहीं है कि अगर उनकी कोई जायज मांग है तो उन पर विचार न किया जाये।

मैट्रोपॉलिटन सिटी की जो बात कही गई कि 1974 में दिल्ली का मैट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर किया गया और बम्बई मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और यहां के मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की वे में बहुत फर्क है, तो इसके बारे में मैं यह साफ कर देना चाहता हू कि नाम से पैरिटी नहीं होती है। मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एक जगह किसी को सुनिफ कहते हैं और दूसरी जगह सबोडिनेट जज कहते हैं। जिसका सबोडिनेट जज एक एस्टेट में कहते हैं, दूसरी जगह जो हायर प्रमोशन पोस्ट होती है, उनको सबोडिनेट जज कहते हैं।

बम्बई में मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पोस्ट थोरिजनल नहीं है, जहां से वह सचिव स्टार्ट करना है। यहां दिल्ली में जिसको मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं वह इनीशियल पोस्ट है जहां से कि मजिस्ट्रेट सचिव स्टार्ट करना है। वहां की पोस्ट को जूडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। चीफ मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रमोशन पोस्ट होती है, 50 परसेंट उसमें प्रमोशन से घाते हैं और 50 परसेंट डायरेक्ट रिजुल्ट में घाते हैं। जो हायर जूडिशियल सचिव की पोस्ट होती है, उसका नाम यहां पर दूसरा रखा गया है।

तो बम्बई जो प्रेसीडेंसी टाउन था, वहां पर डिपेंड उनको एक्सट्रा पावर्स थी मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को दी गई थी, और उसको एक हायर पोस्ट मानकर दी गई थी, उसका पेन्कोल से नालुक नहीं है।

इसी तरह से महाराष्ट्र की सचिव में जब कोई प्राप्ती जाता है तो पहले जूडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है। वहां को पेन्कोल से दिल्ली के पेन्कोल कम नहीं है। हा, हरियाणा में जरूर यह बात है कि जब वहां कवररो 1977 में लोक-मन्चा का चुनाव हो रहा था, शायद उस समय वहां पर पेन्कोल और डीप्रेशन एलाउंस बढ़ा दिये गये। लेकिन यह सिर्फ जूडिशियल सचिव के लिये नहीं बढ़ाये गये, वही पैरिटी मेंटेन करके एम्प्लीक्यूटिव के लिये भी बढ़ा दिये। इसी तरह से पंजाब में उसका नहीं, कुछ कम है। हरियाणा वालों के पेन्कोल दिल्ली वालों से जरूर ज्यादा हैं। पंजाब में ऐसा है कि दिल्ली में 922 से स्टार्ट होता है तो पंजाब में 814 से

होई स्टार्ट करते हैं। कभी-कभी लोग यह भूल जाते हैं कि बीधरनैस धलाउन्स असल-असल है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। कनाटक में 1 जनवरी, 1977 से स्केल बढ़ा दिये गये, लेकिन बीधरनैस धलाउन्स एवालिज कर दिया गया। वहाँ बेसिक सैलरी को देखा जाये तो वह ज्यादा है लेकिन बूकि वहाँ बीधरनैस धलाउन्स नहीं है इसलिए कुल बेतन कम है और यहाँ पर ज्यादा है।

इन सब बातों को देखने के बाद यह देखना चाहिये कि कहीं कम है और कहा ज्यादा है। यह मानना है कि हरयाणा में जो 1 जनवरी, 1977 से उन्होंने बढ़ा दिया तो कहा ज्यादा है लेकिन अगर हरियाणा की बजट से ही हम बढ़ा दें तो सारे देश में सब के लिये कठिनाई पैदा हो जायेगी और यहाँ जो एम्पायूटिव सलिस है, उसके लिये भी कठिनाई पैदा हो जायेगी। यह सब नहीं है, और हम पर गभीरता से विचार करना होगा।

श्री अन्नल राम जायसवाल (काँडाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले बम्बई हाई कोर्ट के चीफ-जस्टिस ने प्रेम को एक इन्टरव्यू दिया, जिस में उन्होंने कहा कि जजिशनल सर्विस की तन्त्राह इन्नी ऐड्रेक्टिव नहीं है कि हममें थोड़े लोग जाये जिसकी बजट से उसमें अच्छा-बुरा प्रवेश कर रहा है। मंत्री महोदय तब यह तस्लीम किया है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि रियासतों की जजिरी की लोग की तन्त्राह दिल्ली के मुकाबले में ज्यादा है। शाजादी से पहले जजिशनल सर्विस के लोगों की तन्त्राह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ज्यादा दुगुना करणी थी। एक के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा पे कमीशन बैठा। उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की लोग हावी हो रहे हैं। उनका इन्स्ट्रुट प्रिवेन किया, और हम फिर प्रो-इन्विटेशन बेज में जजिशनल सर्विस को जो बरतरी हमिल थी, शाजादी के बाद के सालों में वह नहीं रह गई।

महोदय मे जजिशनल सर्विस के लोग मारे-मारे फिरते हैं मगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको मकान नहीं मिलता है। हमने गवर्नमेंट का कोई खर्च नहीं होने वाला है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों की तन्त्राहें दूसरी रियासतों की तन्त्राहों के आधारे कले में सरकार के सामने क्या दिखत है ? क्या सरकार उन्हें यह गारन्टी दे कि उन्हें सरकारी मकान मिले ? हमने कोई फिनालल खस भी नहीं होया।

श्री शान्ति भूषण : माननीय सदस्य कहा है कि खुसरो स्टेट्स में हायर पे-स्केल है। मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बता दूँ।

श्री अन्नल राम जायसवाल : मंत्री महोदय ने पूछा है कि कहीं है।

श्री शान्ति भूषण : कि जब 1 जनवरी, 1973 से पे कमीशन ने जो पे स्केल बनाये, तो दिल्ली की किसी स्टेट से कम नहीं रखा गया था—दिल्ली को हाइएस्ट के साथ कम्पेयर कर दिया था। लेकिन 1977 में हरियाणा ने अपने यहाँ पे पे स्केल बढ़ा दिये और उसकी बजट से वहाँ पे स्केल को भी बढ़ाने के लिए कहा जाता है। बार-बार यह कहा जाता है कि स्टेट्स को यह अधिकार है कि वे अपनी सलिस के लिए जो चाहे करें। अगर माननीय सदस्य का यह कहना है कि अगर एक स्टेट किसी के पे स्केल बढ़ा दे, तो केन्द्र के लिए भी बढ़ाना जरूरी हो जाये, तो यह केन्द्रल प्रिंसिपल के कहा तक अनुकूल होगा ? स्टेट्स को हम बात की शाजादी और स्वाधीनता है कि वे अपने यहाँ क्या स्केल रखें। माननीय सदस्य हम बात पर भी विचार करें कि इन की प्रतिक्रिया क्या होगी। वह बड़े भारी और पुराने मजबूती रहे हैं। मजबूती होने की हैमियन से मैं उनमें कहा जाहूँ जब आज भी यह माना जाता है कि इन देश की पचास प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के निम्नतम स्तर से नीचे रहती है और उसका दोनो बहन का खाना भी नहीं मिलता है, तो जिन की तन्त्राह 922 रुपये में स्टार्ट होती है, उनकी तन्त्राह में और बड़ की मांग क्या नग ठीक है।

शाजादी से पहले भी ऐसा नहीं था कि जजिरी की एम्प्लोयटिव में ज्यादा मिलता था। अगर कोई सिकायत थी, तो यह भी कि एम्प्लोयटिव का ज्यादा मिलता है जजिरी की कम मिलता है। यह सिकायत रफा कर दी गई, और यह मान लिया गया कि एह सांख्यिक देश में यह नहीं होना चाहिए कि जजिरी की एम्प्लोयटिव से कम दिया जाये।

जहाँ तक मकान को सुविधा देने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तरह आकर्षित करना चाहता हूँ कि मकानों की तकनीक बहुत से लोगों को है। मकान एड्जुक्ड नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी दिल्ली में जजिरी की एम्प्लोयटिव से ज्यादा सुविधा दी गई है दिल्ली में सलिस सलिसिब के 158 लोगों में से 89 को मकान मिले हुए हैं सरकार की ओर से, जबकि हायर जजिशनल सर्विस और दिल्ली जजिशनल सर्विस, इन दोनों की संख्या 128 है और उनमें से 80 को मकान मिले हुए हैं। शासन की हमेशा यह सोचना होगी कि सब को मकान उपलब्ध किये जायें। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, कपूर और पौडन आदि, जिनमें से हर एक को मकान नहीं मिला हुआ है। तो यह सिकायत सिर्फ इन्हीं की नहीं है, यह तो जनरल सिकायत है। मकान जैसे जैसे बनें जाएंगे। शासन के पास जो साधन होंगे उन के मुताबिक वह बनाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश को जा रही है।

श्री किशोर लाल (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय यह बड़ी एक ठकदीर की विज्ञप्ति है कि इस बजट आप प्रेसाइज कर रहे हैं और शान्ति भूषण जी के मूँह

से वे अलग सुनने पड़ रहे हैं जूडिसियरी के मुताबिक बहुत लम्बा बीका भाषन हुआ। मेरे ब्यास से शांति भूषण जी कबिबन्धन से नहीं बोल रहे हैं। किसी घाबर सेक्रेटरी ने वहां पर लिख दिया होगा और उसी को उन्होंने पढ़ कर सुना दिया।

मैं बहुत घबराब से आप से यह पूछना चाहता हूँ एंजी-क्यूटिव सचिव और जूडिसियल सचिव का कम्पेरिजन किया बर्र के कमीशन ने तो बर्र के कमीशन ने एंजी-क्यूटिव बाकी को 200 रुपये स्पेशल पे दिया पाच साल की सचिव के बाद वह स्पेशल पे क्या आप जूडिसियल आफिसर को दे रहे हैं? एंजीक्यूटिव के आफिसरों को आप स्कूटर गाउट आफ टर्न देते हैं। जूडिसियल मैजिस्ट्रेट को आप स्कूटर गाउट आफ टर्न देते हैं? दिल्ली के जूडिसियल मैजिस्ट्रेट को सात साल रिगन इम्प्रोविजमेंट देने का अधिकार है और आज हालत यह है कि वह क्रिमिनल के साथ बस में एक ही सीट के ऊपर बैठ कर चलता है। किसी एंजीक्यूटिव के आफिसर को यह अधिकार नहीं है। वह ज्यादा से ज्यादा किसी को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन उसी मैजिस्ट्रेट को जिसे सात साल की सजा देनी है उसी क्रिमिनल के साथ बस में बैठ कर चलना पड़ता है और सभी होम मिनिस्टर साइबला एंड घाबर की सिचुएशन बता रहे थे कि किसी वक्त भी क्या हालत होती है। सभी प्रो एन बोहरा के साथ तीस हजारी कोर्ट में क्या हुआ? किसी एंजीक्यूटिव आफिसर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उस के पहले एक मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के साथ क्या हुआ? जुने मारे गए। वह किसी एंजीक्यूटिव आफिसर के साथ नहीं होता। इसलिए हर एक सविसेज के साथ में प्रमोशन-प्रमोशन हैजाइस होते हैं। वह हैजाइस नहीं देखे जा रहे हैं। दूसरे उन के साथ-साथ उन के प्रमोशनल एवेन्यूज नहीं हैं। मैं आप से कहना चाहता हूँ एंजीक्यूटिव के घाबर प्रमोशनल एवेन्यूज बन इडेंट फाइन है। यहा बन इडेंट 100 भी नहीं है। किनने ऐडीशनल जूडिसियल मैजिस्ट्रेट है, किनने जूडिसियल मैजिस्ट्रेट है जो आज जूडिसियल मैजिस्ट्रेट के रूप में भर्ती हुआ उसके लिए बल पाच ऐडीशनल सेशन जजेज की जरूरत है। तो वह जब रिटायर होगा तो उसी जगह से रिटायर होगा। उस को प्रमोशनल नहीं मिल सकती जब कि एंजीक्यूटिव के घाबर जो घादमी आज एक्साइट हुआ वह ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऐडीशनल सेक्रेटरी बन कर रिटायर होगा। इसलिए उन के साथ में कम्पेरिजन करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है।

Why should he be forced to sit in a particular dress in the court He has to spend on it?

दूसरी बात शांति भूषण जी के मुंह से आई। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन को एक स्पेशल ड्रेस पहन कर बैठना पड़ता है।

जो एंजीक्यूटिव का घादमी है वह 200 रुपये का सुट सिलबाएगा, बस्तर में भी उसी को पहनेगा, घर में भी पहनेगा और बाकी में भी बही पहन कर

जायगा। लेकिन एक जूडिसियल मैजिस्ट्रेट को कोर्ट के लिए घलप ड्रेस बनवानी पड़ेगी। इसका ही नहीं जिस वक्त मैजिस्ट्रेट होगा, उसे फैंसला बना होगा तो 20 किताबें जिन में हाई कोर्ट की घाद शांति भूषण जी की भी कोटेशन होती, उनको बगल में लेकर 8 मील बस में बैठ कर जाना पड़ेगा। कुछ किताबों को खरीद कर पढ़ना होगा, ला जर्नलस खरीदनी होगी जो उन को वहां से मुफ्त नहीं मिलेंगी इसलिए मैं समझता हूँ कि यह कम्पेरिजन उन के साथ कर देना, माफ कीजिएगा, बिल्कुल एक घाद ए एस ब्यूरोक्रेसी के चुगल में फामने की बात है और यह भी अनफारबुनेट है कि ऐसे लोगों का ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। एक तरफ जनता पार्टी और हम लोग कहते हैं कि जूडिसियरी इंडिपेंडेंट है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हाई काट की रिफरेंसेशन है

Why it is lying with with the Home Ministry? शांतिभूषण जी कैसे जवाब दे रहे हैं?

This recommendation of the High Court of Delhi is lying for the last one year with the Home Ministry Why are they forced to come and march to Parliament? Delhi Administration and High Court of Delhi have recommended it

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि यहा कोषा डिपेंड नहीं है। किसी घादमी ने जवाब बना दिया और उसी जवाब को यहा पर पढ़ दिया जो किसी घादमी के गले को घाबर बीज उत्तर नहीं सकती। ड्रेस का कम्पेरिजन नहीं किया, कितनी किताबें उन को लेकर चलना पड़ता है बस में टूटने लगा करना पड़ना है, उसके बाद में लाइब्रेरी उस को वहा पर बनानी पड़ती है, आज की इस पब्लिश सोसाइटी में कुछ सामान घर में रखना पड़ेगा मैं (व्यवधान) हा, वह बस में ही चलता है और जिस क्रिमिनल के साथ में बैठ कर जाता है एक घंटे के बाद उस को सात साल की सजा देता है। इतने हैजाइस हैं (व्यवधान) 90 प्रतिशत ऐसे केसेज हैं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ (व्यवधान) समाजवाद की बात हम सिर्फ जवाब देने के लिए करते हैं, वरना इस पब्लिश सोसाइटी को हम एक्सेप्ट करते हैं और सब को बिल्कुल बराबर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आफ इंडिया की सेक्रेटरी घाबर सेक्रेटरी और सेशन आफिसर को भी बराबर नहीं कर सकते। कैबिनेट मिनिस्टर को जो पे मि लती है उस को एम पी को बराबर भी नहीं कर सकते। चलिए उन्हीं का मुकाबिला कर लीजिए। इससे साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब जनता पार्टी बनी थी तब शांति भूषण जी की तरफ से लीड आई थी कि सितम्बर 1978 तक जूडिसियरी की ऐसी कडीशनस बनावेंगे।

Ninety per cent of the cases are finally disposed of by these people Five to ten per cent of the cases go to the High Court and Supreme Court It means...

90 परसेंट जनता को जस्टिस देने के लिए इस किस्म की जूडिशियरी होनी चाहिए जिसको कोई टेस्टेशन नहीं 900 रुपए में जित्त धादनी को सात साल की सजा देने का अधिकार होना यह हुमुम बीन है, कोई मजबान नहीं है, उसे टेस्टेशन की हालत में नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम बड़े वे कमीशन के साथ कम्पैरिजन कर रहे वहाँ स्पेशल-ये भी मिलती हैं और प्रमोशनल एबैल्युज भी ज्यादा होते हैं और बाकी जो जो कैसिल-टीज हैं वह भी यहाँ नहीं मिलती हैं। एकस्ट्रा जर्चा भी उनको करना पड़ता है। मंत्री महोदय इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। क्या मंत्री महोदय उनको उसी हालत में रखना चाहते हैं जिनमें वे आज हैं? इस तरह से दिसम्बर, 1978 तक का जो उनका कमिट-मेंट या उमको कैसे पूरा करेंगे?

श्री शांति भूषण : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं उनका मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो यह ठीक है कि एग्जीक्यूटिव साइड में बहुत सी ऐसी पोस्ट्स होती हैं जिनके साथ स्पेशल-ये अटैचड है, मैं मानता हूँ जूडिशियरी में भी कुछ ऐसी पोस्ट्स हो सकती हैं जिनके लिए स्पेशल-ये का जस्टिफिकेशन हो सकता है। अगर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन प्रापर प्रपोजल रखेगी कि फला 2 पोस्ट्स के साथ सुपबिजन के लिए स्पेशल-ये रखने की जरूरत है, हाईकोर्ट से कंसलेशन में ऐसा प्रपोजल धारिया तो उस पर तदनुभूति एवंक बिचार किया जायेगा (व्यवधान) वे कमीशन ने हर स्टेट में एग्जीक्यूटिव धाफिसस को इक्वाइटी किया है, उमको आज अगर हम एकदम से डिस्टर्ब कर दें तो उसके बाद हर एक की डिमाण्ड उठेगी कि सौ साल से हमारी पीरिटी मेनटेन्ड है। (व्यवधान)

प्रमोशनल एबैल्युज के बारे में जिनने धापको ज़ीफ किया है उनमें गानन ज़ीफ किया है। ऐसा नहीं है कि जूडिशियरी में देर से प्रमोशन हो रहे हैं और एग्जीक्यूटिव में जल्दी हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको फीट्स एंड फोगस दे सकता हूँ। सन् 1964 में जिन्होंने जूडिशियरी ज्वाइन की थी उनका प्रमोशन 1963 में ज्वाइन किया था उनका हुमा है, 1964 वालों का नहीं हुमा है। मैं यह बात दिल्ली के सम्बन्ध में कह रहा हूँ।

श्री किशोर लाल : 1964 के आई ए एस आज ज्वाइंट सक्लेटरी बने हुए हैं।

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य आई ए एस से इक्वाइटी कर रहे हैं। जबकि जूडिशियरी आई ए एस से इक्वाइटी नहीं होती है, पी सी एस से इक्वाइटी होती है। (व्यवधान)

SHRI KISHORE LAL: You have not been properly briefed.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I have been properly briefed, the hon. Member has not been properly briefed.

All these officers are entitled to compete for I.A.S. also. If they compete for the I.A.S., they can go into the I.A.S. If they cannot compete, or fail in that competition, and they come either for the P.C.S. (executive) or P.C.S. (judicial), then they have no business to claim parity with the I.A.S. The people who secure higher marks in I.A.S. are taken for I.A.S. If they have not got the capability to compete with I.A.S., after having failed in I.A.S. and having joined PCS Executive or PCS Judicial, saying "We should be equated with I.A.S., our promotional avenues should be the same as for I.A.S." is not justified. Suppose a person has failed in the clerkship examination and he joins as a peon. Can he say, "But the I.A.S. officer is also sitting in the same building. I also work in the same building. Why should I not get the same promotional avenues?" There is no limit for a person individually to create any kind of demands in his own heart, but so far as reasonable demands are concerned, the times are changing and if Haryana Government has increased it, therefore, within the limitations under which Government works, after seeing the repercussions on other services, it may need a new Pay Commission to go into it. But it cannot be considered in isolation. This parity has been maintained and it is a time-honoured thing. The hon. member made some reference to scooters, that scooters are easily given to members of the executive. I do not know, because I do not deal with allotment of scooters. But even this representation has not made any reference to scooters. If there is any such representation, I will contact the department concerned.

श्री बिजय कुमार मल्होत्रा : अब कोटा सिस्टम नहीं है।

श्री शांति भूषण : तब तो बात ही खत्म हो गई। आप ने खुद ही श्री किशोर लाल जी के प्रश्न का जवाब दे दिया।

श्री बिजय कुमार मल्होत्रा : लेकिन आप ने तो कहा है कि कन्सीडर करेंगे, कैसे कन्सीडर करेंगे?

श्री शांति भूषण : मैंने कहा है कि मुझे को इस के बारे में मालूम नहीं है, अगर कुछ ऐसी बात है तो देखा जा सकता है।

उन्होंने ज़ेब और किताबों की बात उठाई है। जहाँ तक ज़ेब की बात है, इस के बारे में अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है, क्योंकि हार्ड कोर्टों की तरफ से कोई स्पेशलिफ़िक् प्रॉपोज़िशन नहीं है। आप को कोई न कोई ज़ेब तो पहचानी ही पड़ेगी, काली हो, ब्राउन हो, पीली हो या सफ़ेद हो, हर भाइयों की जो किसी जगह काम करता है, उस को कोई न कोई कपड़ा तो पहनना ही पड़ना है। हो सकता है काला कपड़ा महंगा हो, सफ़ेद काड़ा सस्ता हो, लेकिन मुझे इस की जानकारी नहीं है।

जहाँ तक उन्होंने इस प्रश्न को उठाया कि ज़ोशियल सर्विस में जो लोग काम करते हैं, उस में बहुत लालच आ सकती है, इसलिये जब तक उन को ऐसी तनक्वाह नहीं दी जायगी, जिस से लालच न भाये काम नहीं चलेगा। मैं माननीय सदस्य को बतवाना चाहूँगा—अगर 922 रुपये मिलने पर लालच आ सकती है तो 1200 रुपये देने पर भी वह लालच बन्द नहीं होगा। मज़ा का एक कहानी याद आती है। जब श्री तज बहादुर सप्रू सा मिनिस्टर थे, उस जमाने में एक मिनिस्टर की तनक्वाह 6600 रुपये थी। उस समय किसी एक छोटी सी स्टेट बैंक—सायद वह स्टेट नाहन थी—चीफ़ जस्टिस मिलने भाये, उन को तनक्वाह 66 रुपये थी। श्री सप्रू ने कहा—आप को 66 रुपये तनक्वाह मिलती है, बहुत कम है मैं आप की स्टेट के राजा से बात करूँगा। उन्होंने वहाँ के राजा साहब से बात की और कहा कि आप अपने यहाँ के चीफ़ जस्टिस को 66 रुपये तनक्वाह देते हैं। राजा साहब बोले—“डाक्टर साहब, चाहे 66 बीजिये या 6600 बीजिये, खायेगा साला फिर भी।”

इसलिये मैं कह रहा था कि जहाँ तक टेम्प्टेशन का मामला है, टेम्प्टेशन का खरिज से सम्बन्ध है। इसलिए खरिज किसी का अच्छा होगा तो उस को यदि 900 रुपये तनक्वाह मिलती है तो भी नहीं खायेगा, अगर खरिज गिरा हुआ है, उस को दगनी तनक्वाह भी द दीजिए, तब भी रिश्तत लेना। इस लिये इस का खरिज से सम्बन्ध है, तनक्वाह से सम्बन्ध नहीं है। फिर भी यदि तनक्वाह में कोई कमी हो तो जितना रुपया, जितना कर लोग देने को तैयार हो, उस से जो सुविधा प्रदान की जा सकती है, वह दी जानी चाहिये।

श्री शरद यादव (जबलपुर) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जबाब दिया है, कई सवालों पर वे ठीक बात कह रहे हैं, दुरुस्त बात कह रहे हैं लेकिन उन के भावपूर्ण में बड़ा खोटा है, इस सारी सरकार के भावपूर्ण में बड़ा खोटा है। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सवाल उठाया कि किसी की तनक्वाह से ही कोई ठीक नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जहाँ की तनक्वाह मत बढ़ाएँ या दूसरे लोगों की तनक्वाह मत बढ़ाएँ लेकिन आप में बायबा किया था, जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बायबा किया था कि हम खर्च पर सीमा लगायेंगे। तो आप बेईमानी यहाँ पर यह कर रहे हैं कि निर्गुण आ कर सब को समझा रहे हैं जबकि एक तरफ़ बहुत से लोगों को कहते हैं कि तुम बहुत जादो, पिछो और एक तरफ़ इस वेब में देपासी की गुमाश्त

कोई करता है और दूसरी तरफ़ लोगों को, कहीं मास्टर को और कहीं मैजिस्ट्रेट को धादर समझाते हैं। ये जो अपने तर्कों में कई किसम का जोर लगा कर अपनी बात को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, यह कभी होगा नहीं। हमारा आप से यह निवेदन है कि जब की तनक्वाह अगर नहीं बढ़ाना है, तो बाकी हिन्दुस्तान में जो दूसरे लोग हैं जो उन की सर्विस के बराबर हैं खासकर मैं जो बैंक के एम्प्लॉय हैं और ये जो एडमिनिस्ट्रिव सर्विस के लोग हैं, इन के हाथ में जो यह मीज मस्ती है कि एक जो साधारण सा मैजिस्ट्रेट भी है वह भी एक जीप ले कर चलता है जो बका 144 लगाता है और मैं ने जिन्दगी भर देखा है कि वह जीप ले कर चलता है

एक मानवीय सदस्य : वह गोली भी खाता है और हँट भी खाता है।

श्री शरद यादव (जबलपुर) जवाब आप दे रहे हैं या मंत्री जी वे रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि हिन्दुस्तान में हर जगह यह सबब है जैसे डाक्टरों का मामला ही लीजिए हमारे यहाँ डाक्टरों की हडताल हुई कि और वह इस लिए हुई कि हरियाणा में डाक्टरों को ज्यादा मिल रहा है और हमारे यहाँ कम मिल रहा है यानी इसी हिन्दुस्तान में दो तरह के नागरिक तैयार हो रहे हैं। दो तरह के नागरिक डाक्टरों के मामले में, दो तरह के नागरिक मैजिस्ट्रेटों के मामले में और दो तरह के नागरिक हर सर्विस में आप बनाएँ तो लड़ाई कैसे नहीं होगी। एक प्राइमरी को एक नम्बर का मानेंगे और दूसरे प्राइमरी को नम्बर 2 का आप मानेंगे, एक को कहेंगे कि न० 1 रहो और दूसरे को कहेंगे कि न० 2 रहो। आप ऐसा कर रहे हैं और धादर समझा रहे हैं पूरे लोक मन में बैठ हुए सदस्यों को। आप यह सिद्धा रहे हैं कि वे ईमानदारी कहा से आती है और कहा से नहीं आती। एक एक्जेंट प्राइमरी के भाव ईमानदारी का मानव यह नहीं होता। एक एक्जेंट प्राइमरी की जो प्राथमिक स्थिति होती है, उस से वह बेईमान और ईमानदार होता है। मैं यह पुनरा चाहता हूँ कि क्या इन की सरकार में या इन की जो कैबिनेट बैठती है, उस में इस बात की ये चर्चा करते हैं कि हमारी जो लोक सभा में यह फ़ायल हो रही है, उस के लिए हम तरह का कोई बराबरी का साचा तैयार करेंगे या नहीं करेंगे?

मैं एक बात और कड़ना चाहता हूँ कि इन का जो डिपार्टमेंट है, जिस के अन्दर देश भर में ज़ूबीगियरी चल रही है—ज़ूबीगियरी के मामले में हम कहते हैं कि यह लोकतन्त्र का एक खम्बा है—वह लोकतन्त्र का खम्बा कैसे उबड़ रहा है, इन के बारे में पूरी जानकारी इन के डिपार्टमेंट को होनी चाहिए। हमारे यहाँ जबलपुर से कोई हार्ड कोर्ट के जजों के एपॉइन्टमेंट हुए। जब वहाँ पर ये एपॉइन्टमेंट हुए, तो वहाँ पर भाषण हुए। अर०००००००० का मामला है वेब में, एडिवायस का मामला है और बहुत का मामला है। हार्ड कोर्ट के प्रांमण में बैठ कर भाषण हुए कि यह हमारा गौरव है कि वो जज, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हैं, धर्म वेब में आए हैं।

MR. SPEAKER: You are completely outside the question.

— जो सरब दासब : यह कैसे रेलेबेंट नहीं है। इन के विधान की चीज है। प्रम्यल महोदय, इन्होंने डाऊट बाउंड कन्स्टेंट बात की, इन्होंने सब को धावर लिखाया। इसलिए मैं भी इन को धावर लिखना चाहता हूँ। इन को वहाँ के बहुत से बकीलो ने लिख कर दिया। मैं यह नहीं कहता कि यह बहुत का मामला है लेकिन हाई कोर्ट के प्रांगण के धावर यह धावन दिया गया औरब के साथ धीर इस की खबर इन के पास आई। बहुत से बकीलों ने लिख कर दिया धीर मैं ने भी इन से मिल कर कहा कि जूजीसियरी पर किसी विचार को हावी न होने दें बाहे बहुत समाजवादी हो, मार्क्सवादी हो या बाहे कोई धीर हो। इन्होंने मेरी बात सुनी धीर कहा कि यह प्रोटोनामस चीज है। मेरा कहना यह है कि यह प्रोटोनामस चीज जो है यह खराब चीज के लिए कैसे उपयोग में लाई जाती है, गन्दी चीज के लिए क्यों उपयोग में लाई जाती है। धाड़ी चीज के लिए प्रोटोनामस बाड़ी का उपयोग होना चाहिए, गन्दी चीज के लिए नहीं होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बड़ी तन्काह वाले जो लोग हैं, जो रोज हड़ताल करते रहते हैं, मैं इन के बहुत खिलाफ हूँ लेकिन मैं इन लोगों के भी खिलाफ हूँ जो इन लोगों को हड़ताल करने का आका देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के एक अपराधी या भगी की जो तन्काह है, उस से 10 गुना से ज्यादा हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति से ले कर, धाप से ले कर धीर सरकार के जितने भी अपसर हैं किसी को भी उस से ज्यादा तन्काह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा धाप उपाय करें धीर खास कर अपनी कैबिनेट में इस बात को ले जाए, लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं, यह जो होज-पोज बहुत चलती है, यह चलती रहेगी, तो सबकुछ भी चलती रहेगी। इसलिए मैं ने जो सवाल पूछे हैं, उन का जवाब भूसे दीजिए।

—^२ शक्ति बृषण : माननीय सदस्य ने वैसे तो प्रश्न कोई उठाए नहीं हैं, एक ही प्रश्न उठाया है कि स्ट्रेट्स में दो तरह के सिटीजन्स क्यों होने चाहिए एक जगह कुछ तन्काह मिले धीर दूसरी जगह कुछ तन्काह मिले। अपने संबिधान से हिन्दुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर रखा गया है धीर उस स्ट्रक्चर में स्टेट्स को धाधिकार दिये गए हैं कि ये अपने यहां की जजिसियल सर्विसज की तन्काह मुकार कर सकती है। हिन्दुस्तान में 22 प्रदेश हैं। उन में प्रलग प्रलग तन्काह रखी हुई है। कहीं कम है कहीं ज्यादा है। प्रब कौन से प्रदेश की मानी जाए, कम वाली मानी जाए या ज्यादा वाली मानी जाए, यह प्रश्न सामने रहेगा। इस में केन्द्र क्या करे, कम वाली माने या जिन्होंने ज्यादा रखी है, वह माने ?

श सरब दासब : जो आपने वापस किया है, उस मामले में धाप क्या कर रहे हैं ?

MR. SPEAKER: He cannot do it.

श सरब दासब : जनता पार्टी ने जो यह कहा है कि हम सभी को एक से वेतन देंगे। उसके सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

MR. SPEAKER: It is not a party question.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Shri Shanti Bhushan usually is a Minister of patience. Today he has lost all his patience, and he has uttered so many words which he should not have uttered. Today he has become Ashanti Bhushan. He was trying to compare a magistrate with a clerk in a bank, and he was also saying that magistrates were not competent to compete with IAS officers, and that is why they are occupying these posts. I want him to withdraw these two things before we proceed further.

It will be a very bad day for this country if the magistrates come in a morcha to Parliament House. I request the Minister to start negotiations with them immediately and satisfy them and see that they do not come to Parliament, that they do not come out of their offices. That will be very bad.

The magistrates are a very poor lot. We have got a Judge sitting here, Mr. Shiv Shankar. He was a lawyer and he resigned.

MR. SPEAKER: Should we go to the district judges and the High Court Judges?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: A High Court Judge is drawing more than these Judges. A man who was drawing more has resigned and come back again to the Bar. That is why I request that the Minister should not merely refer to the Third Pay Commission. Nowadays even the Vedas are being explained in a new fashion. After the Old Testament, the New Testament has come. So, I want a special treatment for the magistrates. They cannot be compared with any other man in this country. If the Minister wants any support, I think the whole House will support him. The whole judiciary should be kept above

everything, and they should not be compared with other officers. When an IAS officer goes to a village, he will get some *khana* or lunch, but the poor magistrate does not get even a cup of tea, he will also not take it. From my constituency to Hyderabad, they would not accept a lift, they prefer to go by bus.

MR. SPEAKER: Your suggestion is that they must be dealt with as a separate category.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: I want him to express regret for what he has said.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I am sorry if I have conveyed any impression that I have said anything derogatory to the judiciary of this country. On the other hand I have appreciated the judiciary of this country and said that the judiciary in this country has a very long, old and high tradition and that they conduct themselves in very difficult conditions in a very dignified manner. It does not care as I said in an appreciative way, it is not so mindful about its own incomes, salaries and so on. But it is more concerned with the respect and the esteem which it gets from its fellow being. I have paid the highest compliment to the judiciary.

When an hon. Member says that an IAS officer has more promotional avenues, then my answer is that a person, a young man, when he decides as to which profession he is going to take up, he has an option, maybe for right reason or wrong reason.

MR. SPEAKER: You have dealt with that.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I have already dealt with that.

I want to make it clear that I have not said in derogation of the great esteem in which all of us hold the judiciary. But I have to answer a particular point as to why the promo-

tional avenues are not the same for the IAS. I said, if they like to go to the IAS, they are free to go to the IAS. It is their sweet choice. If they think that this is a work which suits them, that this is the most important work....

श्री प्रमत्त राम बालसहाय (बीजावार) : 16 तारीख को जो प्रोसेशन निकलने वाला है उसको रोकने के लिए धाप ब्या करने जा रहे हैं ।

SHRI SHANTI BHUSHAN: So far as that is concerned, I have already told the House that I had met them earlier. Also, I have received recently a letter from them saying that they would like to meet and to fix a date. I would be very happy to meet them, their representatives, in order to discuss across the table so that any misunderstanding should be removed. I am going to fix a date for meeting with them to discuss all these matters, very early within a couple of days. So far as this Government is concerned, this Government believes in negotiation, discussion, talk and so on to convince each other. If they convince me, well and good, or, may be, I may be able to convince them.

A reference was made to an hon. member of this House, a former judge of the Andhra Pradesh High Court, Mr. Shiv Shankar. It is quite true that he agreed to become a judge in 1974 and, after one year, he resigned in 1975. But I can assure the hon. Member that it was not that he had forgotten, when he had accepted to be a judge in 1974, as to what emolument given to a High Court judge were. The reasons for his resignation were different. I know them. I do not know whether the hon. Member knows them.....

MR. SPEAKER: You need not go into them.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I am not going into them.

PETITION RE. DEMANDS OF STUDENTS

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (बलियाँ दिल्ली) : मैं छात्रों की मांगों के बारे में जबिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

MR. SPEAKER: The House stands adjourned till 2 P.M. 12.02 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

(MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED LOW AND UNREMUNERATIVE PRICES OF JAGGERY

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ramoowalla. He is not here. Mr. Rajagopal Naidu.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Mr. Deputy-Speaker, Sir, jaggery prices went down very low. Last year itself we had represented about this to the Government. But only 5,000 tonnes were purchased at market prices in the North.

55 per cent of the cane produced in our country is going to jaggery production. The prices are very low and unremunerative. The Government has to fix up the support price for jaggery and purchase the surpluses.

I learn that there is a proposal to purchase jaggery from Maharashtra. It is a good thing. But Andhra Pradesh also is an important State producing jaggery. There are very big jaggery markets in Vizag and Chittoor districts. Therefore, the Government should purchase jaggery from these areas also.

(ii) REPORTED NON-ALLOCATION OF WHEAT AND RICE TO BIHAR FOR "FOOD FOR WORK" SCHEME

श्री राजराजराज कपूर (दुर्गिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 377 के अधीन प्रतिस्पर्धात्मक शोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :—

कि "काम के बदले भोजन" योजना में पिछले तीन बार महीनों से बिहार में गेहूँ और चावल का आवंटन नहीं हुआ है जिससे चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इस समय खेत मजदूरों के पास कोई काम नहीं। उनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इनकी सहाय एक करोड़ से अधिक है।

इसके प्रतिरिक्त गेहूँ के प्रभाव में हजारों योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। यदि ये योजनाएं वर्षाकर्म के पूर्ण पूरी नहीं की गई तो सारी अधूरी योजनाएं वर्षा में बिनी हो जायेंगी।

अतः श्रेष्ठ मजदूरों तथा अन्य लोगों को काम देने, भूखमरी को दूर करने और अधूरी योजनाओं को नष्ट होने से बचाने के लिए बिहार सरकार को और से की गई मांग के अनुसार धन की शीघ्र आपूर्ति की जाये।

(iii) REPORTED BUS ACCIDENT IN NEPAL ON 27-2-79

श्री राज नारायण (राय बरौली) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा प्रतिमा कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अधीन मैं निम्न तात्कालिक विषय को उठाने की सूचना देता हूँ।

"एक बालक को छोड़कर काठमाण्डू गई बस के सभी यात्री मृत" वाराणसी से 26 फरवरी को रात को काठमाण्डू गई बस नम्बर यू० टी० टी० 7214 के मुनौली से 45 किलोमीटर दूरी नेपाल की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि आज 5 मार्च बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कन्हैया लाल गुप्त ने कर दी। उन्हें यह जानकारी गोरखपुर के बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वायरलेस द्वारा आज दी। पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में 11 वर्षीय एक बालक को छोड़कर सभी व्यक्ति मारे गये। बस में 55 व्यक्ति थे और यह घटना 27 फरवरी को हुई। मृतक व्यक्तियों की लाशें उनके घर वालों को नहीं मिल पा रही हैं, जबकि मृतक लोगों की पहचान भी हो गई है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास इस मामले में पूरी तरह उदासीन है और इस बीच पुर्णतया में उसमें अपना कार्य, जो उसे करना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी मैंने जानकारी करा दी है।

यह पत्र तो मैंने आपको 6 तारीख को दिया था। आज सुबह मुझे प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। उनका कहना है कि शायद यह दुर्घटना हुई ही नहीं, और ऐसी जानकारी नेपाल के दूतावास से मिली है। श्री बाजपेयी ने भी कल रात को कुछ इसी तरह की बात कही थी। मैंने वाराणसी के कमन्टर और पुलिस कप्तान से लगातार टेलीफोन से सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की, मगर वे दोनों मुझे नहीं मिल पाये।

किर जब श्री चण्ड सेखर, एम 0 पी 0 धार्य, जिन को आप जानते हैं, तो मैं ने उनसे पूछा कि आप बनारस से आ रहे हैं, क्या आपको इस बारे में जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि जानकारी तो उनको हुई है, भावय को आपसी वहाँ से लौटे हैं, और वे कुछ खबर दे रहे हैं कि बस की दुर्घटना की जो व बर पहले घाई थी, उस में कुछ दोष है, भावय बस की दुर्घटना नहीं हुई है।

अब ऐसी स्थिति है कि उन लोगों के घर के पूरे के पूरे सबस्व काठमांडू चले गये थे। जब मैं 4 तारीख को वाराणसी गया था, तो मंगलसराय रेलवे स्टेशन पर दुलहन्पुर के साहू, कैमिक्लस के बहुत से मजदूर मेरे पास आये। वे राते बिठाने लगे कि तीन घरों के लोगों में से कोई बचा ही नहीं है, हम लोगों के घरों के पचास धावमी गये हैं, लेकिन कोई लाश नहीं मिल पा रही है। मैं ने कमिश्नर और कलक्टर को फोन किया और यहाँ श्री वाजपेयी से कन्टेक्ट किया। मैं ने यह अपना कर्तव्य समझा। प्रधान मंत्री जी ने आज सुबह सूचना दी। मैं उसकी भी जानकारी आपको दे दूँ, ताकि स्थिति साफ हो। लेकिन मैं चाहता कि विदेश मंत्री इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि जब 27 तारीख को घटना घटी और तभी से इसका प्रचार हुआ, भाल इंदिया रेडियो ने समाचार प्रसारित किया और कई भारतीय समाचारपत्रों ने भी समाचार दिया, तो सरकार ने इसका पता क्यों नहीं लगाया और इस बारे में प्रकाश क्यों नहीं डाला। ये सब बहुत प्रतिष्ठित प्रश्नवार है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already finished the statement, I will call the next speaker.

श्री राज नारायण : "भाज" में यह समाचार दिया गया : "नेपाल में बस दुर्घटना में मृत्यु। लोगों के शव वाराणसी लाने का प्रयास। दुर्घटनाग्रस्त बस के 56 यात्रियों में से केवल 11 वर्षीय भाग्यशाली बालक बचा।" "सन्मान" में लिखा गया : "काठमांडू में हुई दुर्घटना की पुष्टि। 60 माली मृत। 10 वर्षीय मात्र एक बालक जीवित।" "गांधी" में यह समाचार छपा : "एक बालक को छोड़कर काठमांडू गई बस के सभी यात्री मृत।"

गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी। प्रश्न यह है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी क्यों दी। कहीं न कहीं गोलमाल है। इस गोलमाल का पता लगा कर विदेश मंत्री या घर मंत्री या प्रधान मंत्री जी इस सदन और देश की जनता को जानकारी दें दें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यरेखा कृष्ण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): A very prompt reply. We must congratulate him. I hope the other Ministers will learn from him.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): A very good example.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY (Kurnool): It is a good precedent.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Other Ministers sit in the House like a statue.

AN HON. MEMBER. Granite statue.

श्री सत्यरेखा कृष्ण : जब इस घटना की खबर हमारे पास आई, तो हम लोगों ने तत्काल इसकी खोज खबर ली। हमारे पास जो खबर है, जिस बस के बारे में माननीय सदस्य राजनारायण जी ने चिन्तित किया बस न 0 यू टी टी 7214, उस में दो यात्रियों के नाम हैं, एक है श्री पी के चौधरी जो कि सेक्योरिटी आफिसर हैं माहू, कैमिक्लस ग्रेण्ड कटिलाइजर्स में, उन्होंने खबर दी कि बस जो यात्रियों को काठमांडू से गई थी उस का ऐक्सीडेंट हो गया। लेकिन हम नहीं खबर ली तो उस के बारे में मालूम हुआ कि यह गलत बात है और उस बस का कोई ऐक्सीडेंट नहीं हुआ।

The bus that has safely visited Kathmandu has since left for India via Janakpur.

श्री यह बान भी चौधरी जी को पता है जिन्होंने पहले खबर दी।

श्री राजनारायण : कौन चौधरी ?

श्री सत्यरेखा कृष्ण : पी 0 के 0 चौधरी जी माहू कैमिक्लस ग्रेण्ड कटिलाइजर्स के सेक्योरिटी आफिसर हैं जिन का भार ने चिन्तित किया। तो हम ने तुरन्त खबर ली और उस बस में कोई ऐक्सीडेंट नहीं हुआ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why has he given such a wrong information?

श्री सत्यरेखा कृष्ण : श्री एक ऐक्सीडेंट बहुत पहले हुआ था और वहाँ पर करीब चार धावमी ऐसे मर गये थे। लेकिन उस के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह दूसरा ऐक्सीडेंट था। श्री सत्यरेखा कृष्ण : प्रश्नवार में भी जो खबर निकली है उस खबर में भी यह साफ कर दिया है—

"According to Senior Police Officer, the news was that based on the information received from the border checkposts. But, on physical verification, at the site, the news was found to be incorrect."

(iv) MANAGEMENT AND CONTROL OF POWER DISTRIBUTION IN THE COUNTRY

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the Chair for permitting me to raise under Rule 377, a matter of considerable and urgent public importance and even anxiety.

The present frequent power shedding and non-availability of power throughout the country for essential uses, both in the industrial and agricultural fields, is primarily due to deficiencies in the management and control of power distribution, although we are producing sufficient electric power to meet the needs of the country. The President of India in his Address to Parliament this year has rightly referred to the 13 per cent increase in the power generation. Yet, we are confronted with the problem of plenty and paucity so far as electric power is concerned. The machinery that was created in the shape of Regional Electricity Boards in 1964 have not been able to serve the purpose for which they were created for ensuring integrated operations of economic and efficient use of electric power. They are handicapped in their operations because they are to discharged their onerous duties with improvised load despatch centres. The International Development Association—I.D.A.—credit sanctioned in 1974 for the purchase of scientific equipment like computers, telemetres etc. for the load despatch centres has not yet been used and many extensions have been sought, which have led to adverse comments by the World Bank and other International Monetary Fund Officials about the non-utilisation of loans sanctioned to India. I am afraid there is reasonable ground for suspicion that there is bureaucratic collusion with the interested suppliers of this equipment. In 1977, the Central Electricity Authority had called for tenders and about 17 firms had submitted their tenders. Till now, the Central Electricity Authority has not finalised the tender, although the dates

of validity have been extended several times.

I have come to know that one of the tenderers is Messrs. Seimens about whose collaboration attempt with BHEL—Bharat Heavy Electricals Ltd.—has become the topic of the day and subject-matter of national debate. I would like to know whether the effort of Seimens to enter into the national power system control and management, especially in the matter of economic and efficient use of available power, has the same background as that of their collaboration with BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.). This requires urgent and highlevel investigation before their tender is accepted. It will not be in the national interest to associate any foreign multi-national with a vital and strategic sector like electric power supply and distribution. I suggest that Parliament should be taken into confidence before any decision is taken by the Government in this regard. I also demand that an immediate high-level technical probe be instituted to find out as to why the Regional Electricity Boards have not been able to deliver the goods so far.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, with your permission I want to add only one sentence because the matter has come to my notice. This morning a newspaper report points out that our Prime Minister, Shri Morarji Desai has already appointed a nine-member Janata Party Committee to examine the entire question of foreign technical and financial collaboration. If that is so, then, I am all the more worried as to why this kind of collaboration with a multi-national should not be probed or gone into in the national interest of our country?

RAILWAY BUDGET, 1979-80— GENERAL DISCUSSION—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up further general discussion on the Budget (Railways) for 1979-80.

भी लखन लाख कपूर (प्रणिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं रेलवे बोर्ड के गठन के बारे में, उसके कार्यकर्ताओं के बारे में चर्चा कर रहा था और मैं कह रहा था कि रेलवे बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, इसको भंग कर देना चाहिए। इसके बदले मैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मनेजमेन्ट की बात कर रहा था। खासकर जनता पार्टी तो इसके लिए प्रसिद्ध है। रेलवे बोर्ड इस देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जिसमें 15 लाख मजदूर लगे हुए हैं। मैंने कहा था कि जस्टिस सचिवर की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने रेकमेंड किया कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मनेजमेन्ट होना चाहिए। आपके ससदीय मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने भी सुझाव दिया था कि बोर्ड लेवल पर वर्कर्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एलेक्ट्रेड सायरकेट्स ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। उस कमेटी ने धार्य बताया है :

1. Workers are partners with shareholders in the sense that labour is a partner with capital in running the company. This partnership should extend to Board level decision making;

2 Such participation shall supply better information through employees to the Board for making better decisions, and

3. It will create a conducive environment of mutual trust and improve performance at the shop level and at other levels in the company enhancing the productivity and profitability of the company.

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसी प्रकार से मेरा सुझाव है कि आर्थिक मामलों से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक मन्त्रालय जैसे उद्योग, रसायन, विद्युत, श्रम, ऊर्जा, रस्पाके इत्यादि में वर्कर्स की साझेदारी होनी चाहिए। हमके माध्यम से कार्यों में सहूलियत हो सकती है तथा साथ ही साथ नीति निर्धारण में भी उन्नति होगी।

मे बहुत बिना से कहता था रहा हूँ कि रेलवे में बाहे बार लाख कंजूस लैबर काम करते था रहे हैं जिनको न ही दूसरे मजदूरों के मुकाबले में मजदूरी मिलती है और न ही उनको रेग्युलैरिज किया जाता है। इसी प्रकार से जो काटुबट सिस्टम है वह भी बरकरार है। इसको समाप्त करने का वायदा आपने पूरा नहीं किया है। सप्सटीद्यूट वर्कर्स 10-12 वर्षों से रहे हुए हैं लेकिन उनको रेग्युलैरिज नहीं किया जाता है। इस प्रकार लाखों मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करना चाहिए।

मन्त्री महोदय ने आपने बजट प्राषण में कहा है :

"विगत में परियोजना-परक रेल लाइने मात्र उद्योगपरक लाइनों थीं। अब राष्ट्रीय विकास के नये परिप्रेक्ष्य में हम कृषिपरक लाइनों को भी

परियोजना-परक लाइनों के रूप में मानेंगे और उन्हें प्राथमिकता देंगे।"

इसके लिए प्राप धन्यवाद के पात्र हैं। आज की मौजूदा स्थिति में समाजवादी समाज की रचना में, सामाजिक तथा आर्थिक विकेन्द्रीयकरण में रेलों को बहुत बड़ा पाठ दिया करना है। सारे देश के उद्योगीकरण तथा कृषि की उन्नति के लिए रेलें बिछाने का जो पुराना कल्पना था उसको बदलना जरूरी है। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ब्रह्मदाबाद जैसे चन्द शहरों को अपने एक्सप्लायटेशन के लिए रेलों से जोड़ा था। आज आपने इन शहरों पर खर्चा करने लिए 80 करोड़ रुपया रखा है।

आपने सुझाव दिया है कि 42 करोड़ रुपया नई लाइनों पर खर्च करेंगे। यह सन्तुलित बजट हो सकता है, लेकिन हम से देश का विकास कैसे हो सकता है? इतने थोड़े धन से हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में प्राप बाहे बां सामान्य बजट से या दूसरे स्रोतों से काफी मात्रा में पैसा लें, जिन से देश का विकास हो। यह देहातो का विकास करना है तो रेलों को वहां तक पहुंचाना होगा, उन को आवागमन की सुविधायें प्रदान करनी होंगी, तभी सन्तुलित विकास हो सकता है। जब तक देहात के लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा और चन्द शहरों का—मुम्बई से 31 शहर इस देश में ऐसे हैं जो औद्योगिक हैं, उन्ही का विकास किया जा रहा है, उन्ही में लाइने बिछाई जा रही हैं, स्टेजनी का विकास किया जा रहा है—हम तरुण से देश का सन्तुलित विकास नहीं हो सकता। 158 शहर इस देश में ऐसे हैं जो मध्यम श्रेणी के शहर हैं, उन का विकास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 80 फीसदी लोग जो देहातों में रहते हैं, उन पीने-छा आवागमन तक हम रेल पहुंचाने का काम नहीं कर रहे तो जो हमारा लक्ष्य है, वह पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अविकसित इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उन पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करें, उन क्षेत्रों में नई लाइने बिछाये, उन का अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश करें।

अब मैं बिहार की तरफ प्राप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बिहार सब से पिछड़ा प्रदेश है, जब कि बिहार में पूरे हिन्दुस्तान का 41 प्रतिशत मिनरल है। वहां पर अच्छी खेती का प्रबन्ध है, पानी का इस्तेमाल है, फिर भी वह विकसित नहीं हो रहा है। रेलों का विकास की दृष्टि से यह अभी तक पिछड़ा हुआ है। अभी तक इस राज्य में ऐसे बहुतसे महत्वपूर्ण इलाका हैं जो रेल सुविधाओं से वंचित हैं। हम लिये उस क्षेत्र को जनता को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इस मामले में इस राज्य की उपेक्षा होती रही है।

मैं सब से पहले सवाल परगना की बात कहना चाहता हूँ—यह बिहार का सब से बड़ा जिला है, लेकिन वहां एक बजट अभी तक रेल लाइन नहीं चलती है। इसाथ मेन लाइन के जो कलकत्ता से पटना जाती है। मेरा सुझाव है कि साहबगंज से गंगाबड, हुमका होते हुए बेबनर तक लाइन बिछाई जाये।

नार्थ बिहार घाज जूट का सब से बड़ा उत्पादक है। सारे हिन्दुस्तान का 20 प्रतिशत जूट हम देते हैं, पूनिया घोर सहरसा का क्षेत्र देता है और इस तरह से भारती रुपया हम उत्पादन शुल्क के रूप में केंद्रीय सरकार की देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रेल लाइन नहीं है। घाज बरौनी से लेकर कटिहार तक ब्राइगेज करने जा रहे हैं इस काम के लिये पिछले वर्ष 1 करोड़ रुपया दिया था, इस वर्ष डेढ़ करोड़ रुपया देना चाहते हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट का बजट 20 करोड़ रुपये का है, इससे घाज ब्रान्चा लगा सकते हैं कि कितने वर्षों में इसका कन्वैर्शन होगा। इस क्षेत्र में कटिहार एक बड़ा स्टेशन है, ईस्टर्न बोन में सीटर गेज का सब से पुराना स्टेशन है, लेकिन उस में घाज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, शन्ने घोर पुराने मकान हैं, वेटींग रूम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इमेनिटी बड़ा उपलब्ध नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस तर्प घाज का विशेष ध्यान जाना चाहिये।

पूनिया जिला जो जूट उत्पादन का प्रमुख जिला है, वहाँ से रेल लाइन निवाली जा सकती है। हम जब भी घाज में पहुँचते हैं घाज यही जवाब दे देते हैं कि यह पासबिल नहीं है, फ्रीज बिल नहीं है। जिस जगह में हम इतना जूट देते हैं जो सारा कलकत्ता जाता है उस को लाइन देना घाज के लिए पामिबिल नहीं है। वहाँ से सारा माल टुकी के द्वारा भेजा जाता है, जिस जगहवा पैसा खर्च होता है। अगर यह माल रेलगाड़ी के द्वारा भेजा जाये तो सस्ते दामों पर पहुँच सकता है और मोर्सेल पर इस का भार कम हो सकता है। मेरा सुझाव है कि नवगठित सा रूपौली, धमदाहा पूनिया, कमवा, कोषाधामन बहादुरगज होते हुए ठाबुरगज तक लाइन डाली जाय, साथ ही सरसी से रानीगज, कारबिसगज कुरसागाँटा, सिकटी, पलासी, टेडालाड वि.लवेंक होकर ठाकुरगज तक लाइन डाली जाये। यह सब नेपाल की तराई का इलाका है, जिस को हम बिचमिन कर सकते हैं और इस से हमारी धामदानी भी बढ़ सकती है। वहाँ बर इन्डस्ट्रीज तक नहीं पहुँचती जब तक रेलवे लाइन की व्यवस्था नहीं होती।

कटिहार से जोधबनी की जो लाइन है वह नेपाल की जोड़ती है, जहाँ से काफी चीजें आती हैं और हम भी बहुत सा माल भेजते हैं। इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की कोशिश की जाय।

घब मैं जमालपुर के कारखाने के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। वह एशिया का सब से बड़ा कारखाना है। रेलों की वायम हुए 126 सगल हो गए हैं और इस कारखाने की वायम हुए 116 साल। इस कारखाने की स्थिति को घाज देखें। माइनाइजेशन के लिए घाज कारखाना, क्लिंरजन खडगपुर, मटंगा और पेरल के कारखानों को करोड़ों रुपया देने जा रहे हैं लेकिन जमालपुर को क्या देने जा रहे हैं? क्यों नहीं घाज इसका भी माइनाइजेशन करते? इसको घाज मात्र साढ़े तीन करोड़ देने जा रहे हैं लेकिन वह भी कितने बरस में? इस साल तो केवल घाज बीस लाख ही देने जा रहे हैं। इन्जन फायर बक्स बनाने की डीजल कम्पोनेंट्स प्रादि खाने के घाईर घाज यहाँ दे सकते हैं। लेकिन

इस कारखाने का नवीकरण न करके घाज इस कारखाने के साथ धन्याय कर रहे हैं। यह धन्याय घाजको दूर करना चाहिये। वहाँ पर रोलिंग मिल चालू थी उसको भी घाज बन्द करने जा रहे हैं। यूनिवर्स और मीनेजमेंट दोनों के बार-बार प्रतिनिधि लेकर कमेटी घाजने बनाई है। यह कमेटी इसको देखेगी कि रोलिंग मिल चले या न चले। उस कमेटी की रिपोर्ट न आई है। किसी निष्कर्ष पर वह कमेटी नहीं पहुँची है। ऐसी अवस्था में घाजने उसको बाइड घाज करने का फैसला क्यों किया है। घाजको रेलवे फिटिंग पच्चीस हजार टन सालाना चाहिये। उसी तरह से पुल बनाने के लिए, विरिडिज बनाने के लिए, तमाम कामों के लिए घाजको गमिस्स चाहिये, फ्लैट्स चाहिये। ये तमाम चीजें घाजको इस कारखाने से बहुत सस्ते में मिल सकती हैं ऐसी अवस्था में क्यों इनका यहाँ नहीं बनवाया जाना है और क्यों घाज इसको बाइड घाज करना चाहते हैं।

जमालपुर के कारखाने को विकसित करने के लिए घाजको रोलिंग मिल को रखना होगा। नही रखेंगे तो वहाँ पर पलोड घाज नहीं रह पाएगी, स्टील फाउडरी चली जाएगी नट बोल्ड्स चले जाएंगे, तमाम काम खत्म हो जाएगा। घाज स्टीम इंजन खत्म करने जा रहे हैं और उनमें स्थान पर डीजल इंजन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उनको बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर मजदूरों का घाज नया करेते, उनको घाज बीन सा काम देंगे। वहीँ और एम्प्लेज घाज को चाहिए। इनका घाज बड़ा बनवा सकते हैं। मोल और टायर जो घाज इम्पोर्ट कर रहे हैं वे घाज वहाँ बनवा सकते हैं। घाजका करोड़ों रुपया सेव हो सकता है। घाजको 11000 सवारी डिब्बों की जरूरत है। मान हजार की प्राइवसन घाज के पास है। घाज देश में नए कारखाने खोलना चाहते हैं। उनको घाज जमालपुर में खोलिये। उसी तरह से डीजल कम्पोनेंट्स की घाज यहाँ पर बना सकते हैं और इसके लिए घाजको पास पड्ड करीब की योजना भी है। इनको घाज नहीं बनवाए।

भी राम घारी शास्त्री (बबौली) मैं मंत्री महींदय को तीन बरस तक घाटे के नहीं बरिड बचत के बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने मुझियाँ बढ़ाने की भी घोषणा की है। इस में दो राजें नहीं हैं कि इनको बढ़ाया जाना चाहिये। बाल बर्ष के उपलक्ष्य में इन्होंने बच्चों की भी कुछ रियायत टिकटों में दी है। यह भी स्वागत योग्य है। घाजने सुना भी कहा है कि सुपर कोस्ट माइनों में संगीत घाजने और समाचारों के प्रसारण प्रादि की भी व्यवस्था घाज करेते। मेरा निवेदन है कि जब यह स्थिति है कि दूसरे राज्यों के डिब्बों में यात्रियों को घास और पर मुफ्तिल में जब जवाह तक नहीं मिलती है खड़ा होने तक की वहाँ दूर जाने वाले यात्रियों के लिए घाज यह भी कृपा कर रहे हैं कि उनको

संघीय जुनने को मिलेगा इसका कहाँ तक प्रीविलेज है? आप सब से पहले यह तय करें, कोई न कोई एक स्कीम बनाए कि सब से पहले हम उम्र तरह के डिब्बे और उस क्लास के डिब्बे बनायेंगे कि जिससे सब को जगह मिल जाए। इतने डिब्बे बनें की हर आदमी को कम से कम बैठने की जगह तो मिल जाए। जब तक इतने सैंकिड क्लास के डिब्बे नहीं बनते हैं तब तक एक भी सैंकिड क्लास का एयर कंडिशनड डिब्बा आप नहीं बनायेंगे यह आप तय कर दें। उसके साथ यह भी तय कर दें कि सैंकिड क्लास एयर कंडिशनड डिब्बे चलाने का आपका जो विचार है जब तक उनकी व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप कोई प्रथम श्रेणी का डिब्बा नहीं बनायेंगे।

कुछ गाड़ियों का आपने नाम भी दिया है जिन में मुझे बठने का मौका भी मिला है और जिन में पीने के पानी की व्यवस्था भी है मफाई भी उनकी धण्डी होती है। लेकिन बाकी जो गाड़ियाँ हैं और खास तौर पर पूर्वोत्तर की गाड़ियाँ हैं उनकी हालत यह है कि न उनके शीशे ठीक होते हैं और न ही रिजर्वेशन ठीक होती है। बाथरूम में कपड़ा टांगने की छूटी तक नहीं है। कोई इसको देखने वाला नहीं है कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। बैठने की बात तो दूर रही, खानपान तो दूर रहा। आप कहते तो हैं मगर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दो मासों की घरेलू जो गाड़ियाँ हैं, उनमें सेकेण्ड क्लास के डिब्बे में सुविधायें कम हुई हैं। ठीक है आपने एक प्राध गाड़ी में सुविधा दी है, जैसे हिमगिरि एक्सप्रेस में सुविधा बढ़ गई है, लेकिन और जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनमें सुविधा बढ़ गई है।

मैं 2 जनवरी को तुफान एक्सप्रेस से 17.1 ज रहा था, एम० पी०डी० की पूरी टीम जा रही थी, प्रथम श्रेणी के डिब्बे का दरवाजा टूट कर गिर गया। हर स्टेशन पर उसकी रिपोर्ट की गई मगर वह नहीं बन सका। आगे वाले ने कहा कि कानपुर में ठीक होगा, कानपुर वाले ने कहा कि आगे ठीक होगा मगर वह नहीं बना और पटना तक ऐसे ही हम लोग गये। न बिड़की ठीक है, न शीशे ठीक हैं वह प्रथम श्रेणी के डिब्बों का हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक निश्चित आकार बना कर के आगे बढ़ें तो ठीक होगा। नहीं तो एक और एयर कंडिशनड डिब्बे बढ़ते जायेंगे और दूसरी तरफ साधारण गाड़ियों के सेकेण्ड क्लास के जो डिब्बे हैं, उन गाड़ियों की हालत बुरी है। आप देखें कि कोयले की कमी के कारण कौन सी गाड़ियाँ बन्द होती हैं? वही गाड़ियाँ जो सप लाइन्स पर चलती हैं, जो कि गाँवों में जायें बाकी गाड़ियाँ होती हैं। बड़े-बड़े शहरों को जाने वाली गाड़ियाँ बन्द नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ के लोग मोरचल करते हैं, नैकारे बांध वाले कुछ नहीं कह सकते।

आपने बजट स्पीच में ठीक ही कहा कि पहले की अपेक्षा 8.5 प्रतिशत की वृद्धि मान लुलाई में

हुई। लेकिन आपने सब मिश्रित किया था उससे 180 लाख टन कम की दुलाई हुई। क्या बजह है कि आपके रेट रीड ट्रांसपोर्ट से कम हैं मगर फिर भी लोग टूकों से ही सामान भेजते हैं? कहीं न कहीं बजह की कमी है। आप देखें कि बैगन के प्लाटमेट में जो देर होती है और रिजर्वेशन चलती है अधिकारियों का खुश करने के लिए, यह प्रवृत्ति बन्द होनी चाहिये। हालत यहाँ तक बढ़ गई है कि प्रथम श्रेणी के रिजर्वेशन में या जो रिजर्व सीटें चलती हैं उनमें भी बायदे से यात्रियों की रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मगर पैसा खर्च कर के रिजर्वेशन मिल जाता है। इसमें अप्पाचार मुझे लगता है कि बढ़ा नहीं तो कम भी नहीं हुआ है। इसलिए इसतरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

आपने कहा कि शहरी में या शहर से थोड़ी दूर तक ही जो सीजन टिकट हैं उनके दाम बढ़ाये हैं। मैं जानता हूँ हद नहीं तक मही है, लेकिन रनवे बोर्ड के चेयरमैन श्री राजन ने ज़ाइटव्यू दिया उसमें कहा कि 8 किलोमीटर यात्रा करने वालों को 3 रु० की जगह 19 रु० देना होगा। 21 फरवरी के 'नवभारत टाइम्स' में यह निकला है। शहर यह हाल है ता इस पर आपको विचार करना पड़ेगा।

रैल मंत्री (प्र० मधु दंडवते) 390
का सेवन होगा।

श्री रामधारी शान्त्री अगर इसमें कोई गलती है ता इसका कन्ट्रिब्यूशन भेज दें।

प्र० मधु दंडवते क्लाम कौन सी होगी यह आपने नहीं देखा होगा।

श्री रामधारी शान्त्री सेकेण्ड क्लास है। यह जो सीजन टिकट का दाम बढ़ाये हैं इसमें शहरों से दूर कौन रहता है? कोई बड़ा आदमी शहरों से दूर नहीं रहता है, वह दिल्ली में अपना मकान बनाये हुए है, लेकिन जो काम करने वाले मजदूर हैं, कामगार हैं नीचे तबके के लोग हैं, जिनको शहरों में जगह नहीं मिलती है, जो मांगी-सोपाई में रहने वाले हैं वह शहर से दूर जा कर तस्ती जगह में रहते हैं। अगर बजट का यही दुष्टकोण है, जैसा कि आप कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर से इसे रिवाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस हद तक इसे बढ़ाये। यह बहुत बड़ी वृद्धि है और इससे गरीब जनता को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, इससे उन पर बोझ ज्यादा बढ़ेगा।

इसके साथ ही मैं कटिंग के बारे में भी कहना चाहता हूँ। 7 हजार स्टेशनों में से आपकी

बिघाटमेंटल केटरिंग की सुविधा 70 स्टेशनो पर है और 144 के पासपास गाड़ियों में केटरिंग की सुविधा है जिस में से 82 गाड़ियों में बिभागीय व्यवस्था है और बाकी में दोनो मिली हुई है। यही ऐसा लगता है कि उन गाड़ियों को छोड़ कर बाकी में या तो आप पूरी तरह छोड़ दे कि प्राइवेट लोग करें, नहीं तो पूरी तरह से बिभागीय व्यवस्था हो। एक एग्जम्पल दिया जाये, दो तरह की व्यवस्था से काम नहीं चलता है। मेरा तो सपना यह होगा कि आप कृपा कर सारी व्यवस्था बिभाग के डारा करा दें जिससे इसमें प्रयोजित सुधार होगा और कस्टोमर करने में भी सावधानी होगी। कई स्टेशनो पर जहां बिभागीय और कस्टोमर दोनो की व्यवस्था है वहां ज्यादा गड़बड़ी होती है बिभागीय वाला कस्टोमर पर दोष देता है और कस्टोमर बिभागीय पर दोष देता है। इसलिए इसमें निवेदन है कि अगर आप बिभागीय व्यवस्था कर सकें तो यह अच्छा होगा और इससे लोगो की सुविधा मिल सकेगी। हमने आपकी कोई कठिनाई भी हो सकती है, लाइन जा आपने हिनाब दिया है उसमें हिसाब में उसमें फायदा है, आपका कोई नुकसान तो हुआ नहीं है।

अभी तक आपके दो होटल चलते हैं एक रात्री में और एक पुरी में। उसमें प्रोक्विरी उस से काफी कम है, जिनकी की होनी चाहिये। यह बिस्वाया है कि एक जगह तो 32 प्रतिशत रह जाती है। प्रोक्विरी गेट बहुत कम है। इन बातों की व्यवस्था करनी चाहिये बि यावो ज्यादा धाये, वैसे नुताफे पर वह व्यवस्था चल रही है।

श्री मधु दशवने प्रोक्विरी मीसम के मनाबिक होती है।

श्री रामधारी शास्त्री प्रीसत तो 32 प्रतिशत धाया है, तभी तो कहा कि मीसम के मनाबिक होता है। हममें एफीसियेसी ज्यादा धाये तो अच्छा रहगा।

अब मैं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर आपका ध्यान बिताना चाहता हूँ। मैंने कई बार आपने सामने यह प्रश्न उठाया है कि काठगोदाम से लखनऊ तक एक रेल गाड़ी जाती है। गोरखपुर के लोग या उसमें पास पास के पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग एक डेढ़ लाख लोग बहा रहते हैं और राज 500, 600 लोग बहा से जाते हैं लेकिन काठगोदाम से कीड़ा और सालकुथा तक जो स्टेशन हैं उन पर रोज गाड़ी छूटती है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी गाड़ियों में सब फस्ट क्लास हो गया है और उसके बाद से स्लीपर। जो साधारण यात्री स्लीपर नहीं लेना चाहते, उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी एक दो डिब्बे रहते हैं लेकिन काठगोदाम से लखनऊ की गाड़ी में केवल 2 डिब्बे रहते हैं। मैं परसमल आनकागे के आधार पर कहता हूँ, आप स्टेशन से किसी मनाकर देख लीजिए, राजावा

30, 35 टिकट वहाँ बरफित किये जाते हैं। लोग खिस्ते हैं, पबले हैं और परेशान होते हैं। इसलिए निवेदन था कि आप पूर्व के लिए यदि प्रलग से गाड़ी नहीं चला सकें तो कम से कम एक दो डिब्बा उसमें और लगवा दें। जो काठगोदाम एक्सप्रेस जाती है वह सिर्फ गोरख पुर जा रही है।

इसके साथ ही कई साल से व्यवस्था हो रही है रामपुर से हलद्वानी तक बड़ी लाइन से जोड़ने की। पिछले 10 साल में घनाज की दुष्टि से जिनका वह क्षेत्र विकसित हुआ है, उतना शायद हिन्दुस्तान का कोई क्षेत्र विकसित नहीं हुआ। लेकिन बड़ी लाइन न होने की वजह से वहाँ हमेशा परेशानी रहती है। इन साल में देखा है कि टोटल एक हजार रुपये के खर्चे की बात बजट में कही गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस लकीर से घाने बड़ें और जो हो सकता है उसे व्यापारिक दुष्टि और घनाज की मण्डी की आवश्यकता के अनुसार चलाये।

इसके अलावा 21-6-77 का महा एक प्रश्न के जवाब में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जोड़ने वाली एक लाइन बगहा छितीनी सम्पूर्ण परियोजना को पूरा होने में लगभग 4 हजार का समय लगेगा मगर अभी तक 2 वरस हो चुके हैं जो काम की वहाँ प्रगति है, रफार है उससे तो ऐसा लगता है कि यह काम पूरा करने का सरकार का इरादा ही नहीं है। इस लिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महादय इस ओर विशेष ध्यान दें। इस पर बिभाग का डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। फिर भी वहाँ काम बन्द हो गया है और अधिको के सारे क्वाटर उठा लिये गये हैं। इससे मुझे लगता है कि कहीं रेल बिभाग का इरादा इसे पूरी तरह से खत्म करने का तो नहीं है। मेरा निवेदन है कि इन योजना को पूरा किया जाये।

यही स्थिति समस्तीपुर से लखनऊ को बड़ी लाइन में बदलने की है। उसमें भी देर हो रही है। उस में तेजी लाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी उस का यह काम पूरा होगा। यह पिछड़ा हुआ इलाका है। बजाये इसके कि वहाँ और नई लाइनें बनाई जायें, वहाँ पर पुराने काम भी रुकें हुए हैं।

कुशीनगर एक अन्तराष्ट्रीय महत्व का स्थान है। देवरिया से कुशीनगर होते हुए टूटीबाड़ी तक, जो नेपाल की सीमा पर स्थित है, रेलवे लाइन का सख्ते हो गया था, मगर अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना कि भारत से नेपाल की सीमा तक रेल का डायरेक्ट लिग जोड़ने के लिए देवरिया से कुशीनगर होने हुए टूटीबाड़ी तक देखने लाइन की योजना को सक्रिय रूप प्रदान किया जाये।

SHRI D. B. PATIL (Kolaba): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am not inclun-

ed to congratulate the hon. Railway Minister for his surplus Budget because, according to me the surplus is immoral. Let me say how it is immoral and why it is immoral.

In the very beginning, I would like to deal with the increase which he has suggested in the suburban season ticket rates. It is argued that for the last so many years, there has been no increase in that and therefore, it is very necessary to have this increase in fares. It is true that there has been no increase for so many years but that statement is not valid because the commuters have to travel in overcrowded trains. They do not travel for the sake of the pleasure and love of travelling but they are forced to travel. If they are provided accommodation near the place of their duty, they would not travel by train. So, they are forced to travel by train. They are wasting their time, money and particularly energy disproportionate to the distance travelled because the trains are overcrowded. Some of the passengers go nanging at the risk of their lives. So, this increase is not justified and reasonable at all. I will demand that the increase should be scrapped and the commuters need not be unnecessarily taxed that way.

About the supplementary charge and withdrawal of exemption, I would like to draw the attention of the Minister to this. This withdrawal of exemption is going to have an adverse effect on the poor people because this exemption relates mainly to the poor and the higher rate is going to have an adverse effect on the poorest of the poor. In our country majority of the people are poor. They live below the poverty line and they are going to be taxed in that way. Therefore, I would urge upon the Minister to scrap this supplementary levy and the exemption which has been withdrawn should be in re-instated.

Because of this increase in fares, supplementary levy and also with-

drawal of exemption, there is a surplus. Naturally, the hon. Minister would ask wherefrom to bring much required funds?

I have my own answer to the question.

PROF. MADHU DANDAVATE:
From moral deficit.

SHRI D. B. PATIL: No, from moral surplus.

I would draw his attention to page 12 of his budget speech, where he has stated:

"The estimated surplus has been made possible through effective monitoring of expenditure and tighter budgetary control."

So far as 1977-78 is concerned, the surplus is due to "effective monitoring of expenditure and tighter budgetary control". But there is no mention of efficient railway management. Since this is very important, so far as revenue is concerned, I would like to refer to the utilisation of wagons. In 1977-78 it is 19 tonnes per wagon per day for broad-gauge and 13.7 tonnes per wagon per day for metre-gauge. As against that, what is the loading capacity? So far as broad-gauge is concerned, the loading capacity is 29.9 tonnes and for metre-gauge the figure is 21.3 tonnes. It means that even though there is shortage of wagons, the utilisation of capacity is only two-thirds or less than two-thirds. I do not understand why the utilisation of capacity of wagons should be less than two-thirds. If utilisation is increased by only 20 to 22 per cent, the increase in revenue would be to the extent of Rs. 450 crores. I want to know whether the hon. Minister has studied this point as to why this inefficiency is going on here. It is very clear that without increasing the fare, without withdrawing the exemption and without having a supplementary levy, they could have achieved a surplus if this efficiency has taken place in the administration. It is the com-

mon experience that there is shortage of wagons. Still, full capacity is not being utilised. I would request the Minister to study this point and make use of the capacity to the maximum. I know and can understand that it cannot be utilised 100 per cent, but it can be utilised at least to the extent of 85 per cent. In that case, the increase in revenue would have been to the extent of Rs. 450 crores. Instead of simply saying "we are doing very well", they should do this, because deeds are more important than words.

Coming to economy, the Railway Convention Committee in its report of 1977, placed on the Table of the House on 22nd December, 1978 has stated:

"The Committee feel that there has been more than justified increase in the strength of staff and officers in the name of developmental activities."

What has the hon. Minister to say about the remarks of this Committee? The Committee specifically say that there is an increase in the strength of the staff, which is not proportionate to the developmental activities. Has he not thought of this aspect? Will he give attention to this remark? Of course, most of these sections are organised and, if they are retrenched, they will fight tooth and nail. I do not suggest that all of them should be retrenched, but if there is any surplus staff engaged in developmental activities, they can be transferred to other sections. I want a specific answer whether he has got the courage to take cognisance of this remark of the Committee.

Then I come to the point of safety in railway traffic. About 25 thousand personnel are engaged in guarding and protecting the 61,000 kms. railway track. This, according to me, is quite

disproportionate. I would like you to examine this question. Not that the accidents are not to be warded off, not that the security is not important, but instead of getting panicky we should examine this point.

Now about fuel consumption, in comparison to 1976-77 and 1977-78 figures, there is an increase of 4.5 per cent in fuel consumption. There is no question of increase in the price of fuel. There is increase only in the consumption. Why this deficiency is there? And if it is managed well, there will be no increase in the fuel consumption. More than Rs. 12 crores could have been saved for the Railway.

The average speed of goods train has gone down. The number of wagon round days has again gone up. That means wagons are not being used to the maximum extent.

About the repairs to the rolling stock, I would like to draw the attention of the hon. Minister to page 43 of the Year Book 1977-78. There, it is stated:

"The bad order ratio is particularly high on BG in the case of diesel and electric locos 16.9 and 18.5 per cent respectively against the target of 12.5 per cent. The arrears in periodical overhaul of BG coaches though not large is (11.96 per cent) on account of inadequate workshop capacity."

From the above it is clear that capacity is there, but instead of using it properly, Sir, people are being taxed and so that is not justifiable.

Then I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Railways, attitude of partiality towards the State Transport Corporations of the different States. The Railways contribute to the State Transport Corporation in various States. I would like to read out the figures for the year 1978-79 as follows:

So far as Andhra Pradesh is concerned, for 1978-79 a provision of Rs. 2 crores has been made, but instead of Rs. 2 crores, Rs. 872.97 lakhs had been given to Andhra Pradesh State Transport Corporations?

PROF. MADHU DANDAVATE: You are referring to contributions to State Transport Corporations?

SHRI D. B. PATIL: Yes, contribution to State Transport Corporations. So far as Gujarat is concerned, a provision of Rs. 2 crores has been made, but Rs. 679.39 lakhs had been given. For Maharashtra for 1978-79 Rs. 75 lakhs have been provided, but Rs. 50 lakhs had been given.

PROF. MADHU DANDAVATE: If you permit me for a second, lest you need not develop that point and waste time, I would say that as far as these contributions are concerned, they are the contributions that have been fixed by the Planning Commission and we are merely the carrying agency just like the wagons. All that is going to happen in the future is that even this carrying agency is likely to be transferred to the Transport Ministry and not the Railway Ministry. So, we are not giving it from our own pocket and whatever is handed over to us, we do not keep it in our pocket also. Let me be very clear on that.

SHRI D. B. PATIL: I can draw the attention of the Railway Minister, but I cannot draw the attention of the Planning Commission here. The fact is that so far as Maharashtra is concerned there are arrears of Rs. 35 crores and that is not going to be made up. So, I would like the hon. Minister to go into this and get the arrears cleared though it might not be his responsibility.

It has been said that First Class is being abolished. What about A.C.? Is it not an Air-conditioned class by itself? How is it that when you are going to provide for AC, you are saying that you are having classless trains? AC is as bad as First Class

and it is even worse because passengers of Second Class at least can peep in First Class, but for AC they cannot peep in.

15.00 hrs.

PROF. P. G. MAVLANKAR: There is AC Second Class.

SHRI D. B. PATIL: Who can afford to travel by A.C.? The fare is the same for First Class and AC. That is my point.

15.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up. I am sorry you have taken much more time than you were given.

SHRI D. B. PATIL: I know that the hon. Minister is very independent, but when I had put a question for providing a station at Shelloo, he has relied on the figures of 1968 for rejecting the demand, instead of relying on the latest figures. I did not expect this from him.

The West Coast railway is very important so far as Konkan is concerned. Out of a total outlay of Rs. 11,18,60,000 for Apta-Roha section a provision of Rs. 1 crore was made for 1979-80 out of which only Rs. 20 lakhs have been spent upto 31-3-79. For 1979-80, a provision of Rs. 2.50 crores has been made. At this rate I would like to know from the hon. Minister when he is going to reach Panaji and also Mangalore and in how many years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I will call the next speaker.

SHRI D. B. PATIL: The hon. Minister has talked about tolerance and forbearance on the part of the travelling public, but I think he has forgotten the violent incidents which took place near about Bombay because of shortage and cancellation of local trains. That also should be taken into consideration.

डा० बलदेव प्रकाश (धर्मनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय को, रेल बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूँ। लगातार ती बर्षों से इस सदन का धन्यवाद जो रेल बजट पेश किये गये हैं उनमें आम यात्रियों के किरायों में बढ़ोतरी नहीं हुई। पिछले सालों का यह इतिहास रहा है कि हमें

पेन्शनर्स की प्रथम किराया देना पड़ता रहा है किराये की बढ़ोतरी के बजट ही इस सच में देखा होते रहे हैं, लेकिन हमारे रेल मंत्री ने जो बजट पेश किया, बहुत अधिक कठिनाई के बावजूद भी, उन्होंने किराये को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया और इस के लिये ये बचाई के पास हैं। लेकिन मैं एक ही बात इस के विरोध में कहना चाहता हूँ और वह यह है कि जो सबसे सजीवन टिकट के किराये में वृद्धि की गई है, वह इतनी अधिक कर दी गई है कि ग्राम भावमी के बजट पर इस का बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। ग्राम सौर पर गरीब भावमी ही सजीवन टिकट लेते हैं, छोटे कुकानदार, बूख से जाने वाले, धाकिस के बलक ही इस से प्रभावित होते। इस लिये मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ—मैट्रोपोलिटन सिटीज के बारे में प्रारंभ ० ई० टी० सी० की ओर रिकमैण्डेशन थी, उन को कम कर के वृद्धि की गई है, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब में धनूतसर से जालन्धर, जालन्धर से फगवाड़ा, जालन्धर से होशियारपुर, जो 20 किलोमीटर का सीमा में नहीं होते हैं, उन के ऊपर ही सौर वृद्धि डाल दी गई है। मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि जनता की कठिनाई को समझते हुए, जहाँ हम ने ग्राम बाज़ियों को रियायत दी है, उस के किराये में वृद्धि नहीं की है, इन को भी कुछ रियायत दें, इतना कम बॉस उनपर डालें, जिस को वे बरदाश्त कर सकें जो सुविधाओं की गई हैं उन का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन सब से बड़ी सुविधा जिस को प्राथमिकता मिलनी चाहिये वह बैठने के स्थान की है। लोग लड़कते जाते हैं, एक पांव पर खड़े हो कर जाते हैं। ऐसी व्यवस्था में गाड़ियों में किशोरे बिखाने, संगीत सुनाने, पीने के पानी की व्यवस्था कर देने का कोई धर्म नहीं रह जाता है। इसी तरह से दूसरी सुविधा यह होनी चाहिये कि समय पर गाड़ी पड़े। रेलों में एक्जिप्रेसी हो यह सब से अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं। एक्जिप्रेसी धाज कम होती चली जा रही है। मम्बाला से दिल्ली के लिये जो गाड़ी चलती है वह 50-50 मील पर जा कर धाबे धाबे चंडा खड़ी रहती है। हो सकता है कि इस का कोई कारण भी हो लेकिन कम से कम यात्री को कोई कारण नजर नहीं आता है। कब चलेगी इसका उस को पता नहीं होता है। अगर गाड़ियों में एक्जिप्रेसी न आई तो दूसरी की सुविधाएँ आप दें रहे हैं संगीत सुनाने की तो वह भी भावमी की भखरेगा। वह कहेगा गाड़ी चल नहीं रही है लेकिन संगीत चल रहा है। दिल्ली से रात में जब गाड़ी चलती है तब आप जा कर देखें कि क्या हालत होती है। एक एक सीट के लिये, रिजर्वेशन के लिये, बैठने का स्थान पाने के लिये जो रिजर्वेशन करने वाला भ्रष्टाचार होता है उस के सब विषय ही सी भावमी दीख रहे होते हैं, पचास

पचास भावमी उस के पीछे लगे रहते हैं और उन के हाथों में पांच दस के नोट होते हैं तब जाकर कुछ को सीट मिलती है। यह एक ग्राम भाव है, कोई भी जाकर देख सकता है। मैंने बहुत एक भ्रष्टाचार के स्थान में जब इस को जो लाया और उस को बताया कि वह भावमी ऐसे से रहा है और मुसाफिरो की सीट बिला रहा है तो उस ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कला इयूटी पर हूँ। इस तरह से टिकट लेने के लिये जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन को आप दूर नहीं कर सके तो दूसरी सुविधाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रेलों के लाइफ लाइन हैं। भाविक व्यवस्था ही या बिसेस का मानना है, बाब पचासी को इधर-उधर से जाने की बात को या सामाजिक जीवन हो, रेलों के बाहर सब भ्रष्टाचार हो जाता है। कोयला पूर्व में है और भाता पंजाब में है। इस के बाहर पंजाब की इस्ट्री नहीं चल सकती है। प्राथमिकता की दृष्टि से हम कहाँ खड़े हैं इस को आप देखें। रेलों के लिये फर्स्ट प्रायोर्टिटी है। नायव फर्स्ट प्रायोर्टिटी चमेल प्लांट्स की है। रेलों की उस व्यवस्था में दूसरी प्रायोर्टिटी होगी। उद्योगों की तीसरी होगी। लेकिन रेलवे की प्रायोर्टिटी का यह हाल है कि पंजाब में पिछले वर्ष 132 गाड़ियाँ सस्पेंड की गई इस बास्ते कि कोयला नहीं था। ये कीरोजपुर बिबोजन में की गई। पिछले सप्ताह मुझे उत्तर मिला था कि धाज भी 72 गाड़ियाँ सस्पेंड हैं वहाँ पर। ये कोयले की कमी के कारण है जिस को फर्स्ट प्रायोर्टिटी है। अब जिस को सिंडिक या थर्ड प्रायोर्टिटी मिली होगी उस की हालत क्या होगी इस का अनुमान आप लगा सकते हैं। पिछले साल मैं मंत्री महोदय से मिलता रहा हूँ। हमारे प्रदेश की सभी इस्ट्रीज ठप होने जा रही हैं अगर उन को कोयला नहीं दिया गया। कई कारखाने बन्द हो गए हैं। मजदूर हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं। कई बेकार हो गये हैं। यह हालत इन एक्जिप्रेसी की है। इस बास्ते रेलों की एक्जिप्रेसी को आप बढ़ाएँ। कोयला, कच्चा माल, फुडवेज धादि को इधर से उधर से जाने के लिये बैगन्ज नहीं चलेगी तो फिर सुविधाओं को कोई धर्म नहीं रह जाएगा। 72 गाड़ियाँ धाज भी बन्द पड़ी हैं। कौन उन में जाता है? बहुत साधारण। भावमी, बूख से जाने वाला, सन्ध्या से जाने वाला, बलक, किसान, कचहरी जिस को जाना होता है वह। कई बार मैं कीरोजपुर बिबोजन को फोन कर चुका हूँ गाड़ियों को चलाने के बारे में लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

विकास की दृष्टि से इस्ट्रीज को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ईंटों के भट्टे के बास्ते कोयले की जरूरत होती है। लेकिन उस को सब से बाहिर में प्रायोर्टिटी आप ने की है। और सब को कोयला मिल सकता है, लेकिन ईंट के भट्टे वालों को कोयला नहीं मिलता। अब अगर ईंट नहीं बनेगी तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? कोई नई लाइन भी बिछानी है तो वह कैसे बिछानी जायगी? मंत्री जी जानते हैं कि ब्रिक क्लिन की तब से बाहिर में प्रायोर्टिटी है और पंजाब में इन के लिये

कोयला बिलकुल न को बचावर है। हमने अपने पंजाब के अंशों के बात की, उन्होंने कहा कि हम ने ऊपर की बात की है, लेकिन कोई हम नहीं निकाला और ईंट के भट्टों के लिए ही कोयले की रोक नहीं मिल सकती। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर प्रायर्टीज को ठीक नहीं करने और ईंट के भट्टों को प्रायर्टीज लिस्ट में ऊपर नहीं लायेंगे तो काम नहीं चलेगा। वहां पर ऊर्जा मंत्री की कह रहे थे कि पिट के ऊपर कोयले पर ब्लैक नहीं है। अब धाम धादमी को हम यह समझाए कि पिट पर ब्लैक नहीं है? जब कि रोज लोग देखते हैं कि कोयले के बैगन घाते हैं और ब्लैक में उनको बेच दिया जाता है और वह ईंट के भट्टे वाले ही ले लेते हैं क्योंकि उन को खुद को अपने उद्योग के लिए कोयला नहीं मिलना। इसलिए मजबूर उन को ब्लैक में कोयला लेना पड़ता है।

मैं अपने प्रवेश की दृष्टि से मेरा निवेदन है कि बागू बंध में रेल बजट की जो योजना है वह 650 करोड़ २० की है। लेकिन मुझे खेद है कि पंजाब में एक इंच भी नई लाइन बिछाने की कोई योजना नहीं है। पिछले 32 सालों में कोई नई लाइन नहीं बनी है। जो भी है अंग्रेजों के समय की ही लाइनें हैं। सरकार की योजना है कि हर प्रदेश की राजधानी को दिल्ली के साथ मेन लाइन के साथ जोड़ दिया जाये। लेकिन चण्डीगढ़ धामी तक मेन लाइन से नहीं जुड़ सका है जो कि पंजाब हरियाणा और खुद यूनियन टैरिटरी की राजधानी है। रेल सर्वे हो चुका है, बार साल बीत चुके हैं। लेकिन यह कहा गया कि क्योंकि 22 करोड़ २० का खर्चा है जो धामी सरकार खर्च नहीं कर सकती है इसलिए यह रेलवे लाइन नहीं बन सकेगी। डिफेंस के पॉइंट आफ व्यू से भी यह लाइन प्रति आवश्यक है। सेकिण्ड डिफेंस लाइन के रूप में एक लाइन धादरी हम को मिल सकती है जो सुधियाना से चण्डीगढ़ और चण्डीगढ़ से जगाधरी की लाइन है। और धाम जगाधरी से दिल्ली के लिए रास्ता मिल सकता है। पंजाब सरकार ने सुझाव दिया है कि अगर सारी की सारी लाइन एक बरण में समाप्त नहीं की जा सकती है तो पहले बरण में चण्डीगढ़ से राजपुर तक की और दूसरे बरण में चण्डीगढ़ से जगाधरी की लाइन बना दी जाये। चण्डीगढ़ से राजपुर तक की लाइन के सर्वे का खर्च पंजाब सरकार ने जमा करा दिया है, सर्वे भी हो चुका है, शायद घाप के पाम रिपोर्ट न आई हो। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि पंजाब की प्राकृतिक स्थिति को देखते हुए और चण्डीगढ़ राजधानी होने के कारण चण्डीगढ़ से राजपुर के बरबिसान एक लाइन इसी बाबू वर्ष की योजना में शामिल कर ले। इस लाइन की स्वीकृति आवश्यक मिलनी चाहिये। यह मांग लगातार 30 साल से हम करते आ रहे हैं। पिछली सरकार से तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह जामज मांग को कभी नहीं मानती थी, लेकिन वर्तमान सरकार तो ऐसी नहीं है, उस की तो हमारी जामज मांग को जरूर मान लेता चाहिये।

चण्डीगढ़ और दिल्ली के बीच में कोई फास्ट गाड़ी नहीं है। केवल एक ही गाड़ी है जो अंग्रेजों के समय बनी थी जब वह जिनमें आते थे, और वह है दिल्ली कालका

लाइन और इस के ऊपर चण्डीगढ़ सहर से 10 मील दूर एक छोटा स्टेशन बना दिया गया है वहां पर चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन। न तो सहर के लोग उस का उपयोग कर सकते हैं, और समय भी ऐसा है कि रात की दिल्ली से चलो तो सुबह बार बने घाप चण्डीगढ़ पहुंचो। उस गाड़ी का न उपयोग है, न कोई औचित्य है और न महत्व है। वह एक गाड़ी चल रही है। यह आवश्यक है कि वहां के 3 प्रदेसों की दृष्टि से चण्डीगढ़ से दिल्ली तक एक फास्ट ट्रेन चलाई जाये जो चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सब जगह के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन की आवश्यकता को पूरा कर सके। इस में कोई कठिनाई नहीं है। मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि इन तरह लाइन पर बहुत भारी ट्रैफिक है, एक ही गाड़ी घागे चल रही है।

मंत्री महोदय ने तेज गाड़ियां बहुत चलाई हैं। उस के लिये मैं उन को बधाई देता हूँ लेकिन एक फास्ट ट्रेन पंजाब के बाइंडर धमत्तर से दिल्ली तक के लिये चलनी चाहिये। उस की सुविधा भी हमें प्राप्त होनी चाहिये।

जो फास्ट ट्रेन जम्मू से बम्बई तक चल रही है वह जम्मू से पठानकोट, पठानकोट से मुकेशिया की तरफ से जालन्धर होकर दिल्ली की तरफ जाती है। इस तरह से सारा गुरदासपुर जिला बीच में से निकल जाता है। अगर गुरदासपुर किसी व्यक्ति को जाना है तो वह जालन्धर जाये या पठानकोट जाये। मैं ने धाम भी मांग की है और फिर मांग करता हू कि कम से कम हमें यं दो दिन ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी पठानकोट से गुरदासपुर होती हुई जालन्धर जाये न कि पठानकोट से सीधे मुकेशिया होती हुई चली जाये। यह ऐसी मांग है कि जिस पर कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन झूरोकेंसी छई हुई है, नीचे से वह लोग नोट बना कर भेज देते हैं कि फिजीबल नहीं है और मंत्री महोदय हमें जवाब दे देते हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि यह कैसे फिजीबल नहीं है जो जनता की सुविधा के लिये आवश्यक हो वह हर हालत में करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धामा करता हू कि मंत्री महोदय इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री बयाराम साक्म (फरुखाबाद): सभापति महोदय सर्व प्रथम मैं रेल मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्षों में उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए जनता की अधिक गिरावा न देना पड़े, इस बात का ध्यान करते हुए अपना बजट प्रस्तुत किया है और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के निमित्त सुविधाओं का ध्यान रखा है।

पिछले 23 महीनों में 307 नई ट्रेनें चलाई हैं ऐसा उन्होंने अपने विवरण में दिया है। परन्तु जहां उन्होंने सुविधाएँ प्रदान की हैं वहां मैं कुछ बातें उन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

आज रेलवे में यात्रा करने में बड़ा असंतोष देखा जाता है। ट्रेन में उकती होती है, लोग लुट जाते हैं।

उन की सुरक्षा के लिये वहाँ आर० पी० एफ० की व्यवस्था की गई है लेकिन वह कौन इतनी कम है जिस के कारण आँखों की वह सुरक्षा नहीं हो पाती जिस के लिये उन को रखा गया है। 1 जनवरी, 1972 को 47,699 रुस आर० पी० एफ० के लोग थे लेकिन 1-11-73 को जो बयान दिया उस में बताया बढ़ाने के 3 लाख 325 आरपी की ओर से बढ़ा दिये गये। ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं। यात्रा करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, परन्तु जिस सुरक्षा की दृष्टि से उन को रखा गया है, उस अनुपात से उन को बढ़ाने के स्थान पर बढ़ाया जा रहा है। उन का बढ़ाया जाना चाहिये था। उन की सुविधा की दृष्टि से उन को सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। जहाँ आज पुलिस के एक सिपाही पर 4,691 रुपये खर्च किये जाते हैं वहाँ आर० पी० एफ० के सिपाही पर 2 198 रुपये खर्च किये जाते हैं।

आर० पी० एफ० बायो से धीरे भी काम लिये जाते हैं। मैंने टैक्स की बेजामानी, रेलवे लाइन को देखन के लिये बिजली के जो तार बिखे हुए हैं, उनको देखने के लिये वहाँ इस के समाना विभिन्न कार्य उनको दिये जाते हैं जो उन के लिये एसालन नहीं होते हैं, फिर भी उन से काम लिया जाता है। इसलिये उन की मात्रा बढ़ाई जाये, जिस से रेलवे की प्रतिरिक्त सुरक्षा हो सके।

जैसे एक बग्न ने पहले कहा भी कि सी० आर० पी० धीरे आर० पी० एफ० के लोग एक दूसरे पर बोधोत्पन्न करते हैं इन को भ्रमण भ्रमण काम एसालन होना चाहिये जो कि नहीं हुआ है। दोनों को इन तरह से काम देकरा चाहिये जिस से रेलों की सुरक्षा हो सके। मैंने कई बार यह नोट किया है कि रेल मंत्री स्वयं कोई प्रवेश देते हैं, परन्तु रेलवे बोर्ड की मनीनरी और आधिकारिक के यहाँ कारण की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में एक महीना लग जाता है, धीरे मंत्री महोदय के घाटेको का पालन नहीं होता है। पहले तो टेलीफोन पर ही काम हो जाया करते थे, मगर अब लिखित आदेश मिलने पर भी काम नहीं होता है। मेरे पास इस प्रकार के एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं कि मंत्री महोदय के आदेशों का आज तक अनुपालन नहीं हुआ है। नीचे के अधिकारी एक न एक बहाना कर के धीरे कोई न कोई प्रयत्न आज कर उन आदेशों को टालने का प्रयास करते हैं। इस कारण रेलवे कर्मचारी बड़े परेशान हैं। धीरे इस प्रकार का व्यवहार बढ़ रहा है। मेरा बुला प्रसिद्ध है कि जनता पार्टी की सरकार और जनता पार्टी के सभी महोदय होने के बावजूद जनता और कर्मचारियों के काम नहीं होते हैं, जिस की वजह से असंतोष बढ़ेगा। मंत्री महोदय स्वयं देखें कि उन के आदेशों का पालन क्यों नहीं होता है, जब कोई केस बैरेन बाउट होने के बाद मंत्री महोदय के द्वारा आदेश दिया जाये, तो उस का अनुपालन होना चाहिये।

आज देश में रेलवे बैंगन की कमी दिखाई देती है। कल्याणबाबू में हमने पिछले 8 लाख टन आरू पैदा किया और इस साल हम 12, 13 लाख टन पैदा कर रहे हैं। मगर बैंगन की कमी की वजह से वह

आरू 17, 18 या 19 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। हमने इस बारे में प्रारंभ मिलिट्र, मंत्री महोदय और विभिन्न अधिकारियों से कहा, लेकिन बहुत दिनों तक रेलवे का एक बैंगन भी नहीं मिला। इस लिए आरू की स्थिति खराब हो गई है। दूसरे स्थानों पर कल्याणबाबू की आरू 50, 60 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर मिलता है, परन्तु कामतारों को केवल 17 या 18 रुपये मिलते हैं। इस लिये कामतारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह कहा जाता है कि एम्पटी बैंगन कोलियरीज की तरफ ले जाये जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि एन० ई० आर० से हमें बैंगन न मिलने का कारण क्या है, जब कि एन० आर० हमें बैंगन दे रहा है।

कल्याणबाबू से माहजड़ापुर होते हुए गोला या मैलानी तक रेलवे लाइन का सर्वे हुए तीन बार वर्ष बीत चुके हैं। इस बारे में रेलवे प्रशासन को याद दिलाया गया है और एक लिखे गये हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दो बार सर्वे होने के बाद भी आज तक वह कार्य नहीं हो रहा है। उम्र लेज में आने-जाने के साधन नहीं हैं।

कल्याणबाबू से माहजड़ापुर होते हुए फुटहिल तक बाइमोज लाइन बनानी चाहिए। वहाँ पर उत्तर से आने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। सैनिक दृष्टि से पिछीझाड़ एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस लाइन से बहुत तक सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। मगर हम फुटहिल तक लाइन पहुँचा नहीं, तो बर्बाद से सीधा सबब हो सकता है। सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से यह लाइन बहुत उपयोगी होगी। वह ऐसा सेंस है, जहाँ आने-जाने के साधन अच्छे नहीं हैं।

जनेश्वर रोड से ऐटा तक जो छोटी लाइन है, उसे अनधिकारित लाइन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है, कनसल्टेटिव कमेटी में यह प्रश्न उठाया गया है और सदस्यों ने भी लिखा है कि मगर इस लाइन को प्रकीर्ण होते हुए मुहम्मदाबाद तक एक्सटेंड कर दिया जाये, तो यह लाइन अनधिकारित नहीं रहेगी, बल्कि उससे लाभ होने सकेगा, लोगों का हित-साधन होगा और जिस अनवेबेलन्स एरिया से वह गुजरेगी, उसका भी विकास होगा। इस लिए मंत्री महोदय इस लाइन के निर्माण की ओर ध्यान दें।

कल्याणबाबू से दिल्ली दो सी मील पर है। मैं जानता हूँ कि हमें आने-जाने में कितनी परेशानी होती है। मैंने मंत्री महोदय से कहा है कि यहाँ पर एक क्रास्ट ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाये। मगर वो बर्बाद जाने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें हम छ०, आठ, दस बजे में दिल्ली आ सकें। वहाँ के जो गाड़ी कलती है उस को 16 और 18 बजे रास्ते में लगते हैं। बार बटे, छः बटे गाड़ी बकी की गाड़ी है टूटका में या कहीं और किसी स्थान पर। कल्याणबाबू-शिरोहाबाबू तक जो लाइन है वह एक तो खराब है और दूसरे इतनी अनपेक्ष है कि जिस में अप्रैल चिन बर्कलिया होती है। ऐसा कोई, महीना नहीं जाता है जिस में बर्कलिया न पड़ती हो। अभी पिछले महीने की बात बताता आरूवा, गाड़ी को

दोकर कर दीन, लोणी को उधार लिया गया। बीप पर बैठा कर सोचने की साधन में से गए और उनको बुरी तरह से परेशान किया। पहले तो मारने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में उन की तलाशी की गई और जो पैसे निकले वह लेकर उनको वहीं पर छोड़ दिया गया। भाए दिन ऐसी घटनाएँ होती हैं। इसलिए ऐसी लाइन में जो घ-सुरक्षित हैं उन पर उन स्टेनो को छोड़ कर जहाँ पर कि टिकट बिलकुल नहीं बिकते, जहाँ पर पैसों पर धाते नहीं और टिकट लेते नहीं, उन का छोड़ कर जो प्रमुख स्टेनो हैं उन पर गाड़ी को खड़ी करें और उसे एक्सप्रेस या फास्ट पैसंजर ट्रेन कर दें। सुरक्षा की दृष्टि से भी वह ठीक रहेगा और समय भी बचेगा। फर्कबाद वह स्थान है कि जहाँ से प्रिन्स और रेडीमिड मारमेन्ट्स सलाई करने वाले सीकड़ों की सभ्यता में रोच सीधे दिल्ली जाते हैं। उन को धाने में भी सुविधा होगी और जो दूसरे पैसंजर हैं उन को भी सुविधा होगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप वहाँ से कोई फास्ट ट्रेन बनाए जिसमें फर्कबाद जो वहाँ से केवल 220 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ से धाने लगे को 6-7 घंटे का समय ट्रेन में सवने के बजाय 16 और 18 घंटे के। इस और आप ध्यान दें।

एक बात और कहना चाहूँगा कि फर्कबाद कानपुर जो कि ब्राइट नगर क्षेत्र में रहता है उस स्थान को बहुत नैप्लेक्ट किया गया है। वहाँ फतेहगढ़ से एक डी० टी०एस० ब्राफिन पहले रहा है। आज उस हिस्से में न तो लाइन ठीक रहती है और न ट्रेन के विषय में कोई ध्यान दिया जाता है। ब्राउ-ब्राउ, दल-दल और बारह बारह घंटे लेट गाड़ियाँ जाती हैं। वहाँ के कर्मचारियों को असुविधा यह होती है कि उन को जरा-जरा से काम को लिए ब्राइट नगर जाना पड़ता है। तो फतेहगढ़ में जहाँ डी० टी० एस० ब्राफिन या वहाँ ऐसीमानस डी० एस० या ब्रिस्टलेट डी०एस० का ब्राफिन रख दिया जाये तो वहाँ के लोगों को भासानी हो जायेगी। वहाँ पर सारी व्यवस्था मौजूद है बगले हैं, दस्तरो के लिए स्थान है। सब कुछ होने के बाद भी वह स्थान खानी पड़ा हुआ है और लोगो को इतनी असुविधा वहाँ होती है। यह कानपुर से लेकर कासगज तक की जो लाइन है वह इतनी नेग्लेक्टेड पड़ी है कि वहाँ पचासो ऐक्सीडेंट्स गुरुस ट्रेन्स के हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी उस लाइन पर जाये तो दसियों स्टेनो पर देखेंगे कि बैगन्स टूटे फूटे पड़े हैं। लाबो रुपये का नुकसान इस प्रकार से हुआ है लेकिन जब पूछा जाता है तो दिखा दिया जाता है कि इस हजार या 20 हजार का नुकसान हुआ है जब कि मैं बताता चाहूँगा, मंत्री महोदय नोट कर लें, 70-80 बैगन्स कानपुर से लेकर कासगज तक रेलवे लाइन के किनारे विभिन्न स्थानों पर पड़े हुए हैं जो डैमेज्ड हैं। लाबो रुपये का नुकसान इस तरह से होता है और खर जनता का सामान पट्टेबाने के लिए जो सुविधा होगी चाहिए वह नहीं हो पाती है क्योंकि बैगन्स की कमी दिखाई जाती है और बैगन्स की कमी है भी। इसलिए वह जो लाइन है उस और ध्यान दिया जाये ताकि वहाँ के लोगों को लाभ पहुँचे।

धन्य में एक बात कहना चाहूँगा कि जो कबक्टर और डी० टी० एस० हम लोगों के हित के लिए और रेलवे के हित के लिए ट्रेनों में सफर करते हैं उन को इन्डिक में न नाम कर उस प्रकार से भ्रष्टा नहीं दिया जाता

है जैसे कि गाँव को और गाँवों को दिया जाता है। डी० टी० एस० और कबक्टर धनर तक न करे तो वास्तव में हम मनुष्य करने कि जो रिबर सीट्स वा बर्थ हैं उन पर जो रिबर बन करने वाले हैं वे बैठ नहीं सकते। वह कबक्टर और डी० टी० एस० आ राउ भर जायते हैं उन को कहा जाता है कि भला नहीं दिया जायेगा जब कि वह एक ही प्रकार का काम करते हैं। गाँव भी उसी प्रकार का काम करते हैं और गाँव भर भी उसी प्रकार का काम करते हैं। गाँव भर गाड़ी जकर बसाते हैं लेकिन काम उन का भी एक ही प्रकार का है। मगर कबक्टर और डी० टी० एस० को इस प्रकार से डीन न कर के उन को साधारण और दूसरे प्रकार के जो एम्पलाईज हैं जैसे स्टेनो मास्टर या धन्य एम्पलाईज हैं उनमें मानते हुए उन को ट्रेनेन का भत्ता नहीं दिया जाना। इस और ध्यान देने की आवश्यकता है।

एन० ई० धार० की बात मैं कहना चाहूँगा। पहले क्यूम्लेटिव भत्ता उसमें उन को दिया जाता था। उस के बाद पता नहीं अधिचारियों ने क्या समझा कि बायब इससे उन को कुछ बचत हो जायगी, उन्होंने दैनिक भत्ते का तरीका चालू कर दिया। लेकिन यह क्यूम्लेटिव की बात है कि जब वह दैनिक भत्ते का काम भनना भरते हैं या बिल देते हैं तो उस के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वह कहीं ज्यादा है उससे जो कि क्यूम्लेटिव भत्ते में उनको दिया जाता था मासिक रूप में। इस के भलाबा इस में कर्मचारियों का काम भी बढ़ गया। उन को हर दूसरे तीसरे दिन अपना बिल भेजना पड़ता है और उन कर्मचारियों का भी काम बढ़ गया जिनके पास सारे बिल जाते हैं। रेलवे को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इस और ध्यान देना चाहिए और इन सारी चीजों को ठीक करना चाहिए।

एक बात और कहना चाहूँगा। जहाँ और बहुत सारी बातें कही जाती हैं, माननीय सदस्यों ने कहा कि रेल बजट बहुत सुन्दर है, अच्छा है, पैसंजर के लिए बहुत सुविधाएँ दी गई हैं, वहीं मैं यह कहना चाहूँगा कि धनक स्थानों पर देखा जाता है कि यात्री ट्रेन में घूसे की तरह भर कर जाते हैं। धनी एक बन्धु ने बताया था कि पावदान पर खड़े खड़े हो कर चलते हैं, छत पर खड़े होते हैं, यह बात सही है। मैं धनक ऐसे बिज और फोटो प्रस्तुत कर सकता हूँ। पूरी ट्रेन में हजाराँ धावपी इस तरह से चलते हैं, उन को बैठने का स्थान नहीं मिलता है। इसलिए उन लाइन पर जहाँ रथ रहता है और ट्रेन्स बढ़ाएँ, बोगीज बढ़ाएँ ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। उन धरमिल जेभा में जहाँ पैसंजर ज्यादा चलते हैं और जहाँ कि और कोई साधन नहीं है ऐसे इलाकों में ज्यादा तेज गाड़ियाँ धाप चलाई और ज्यादा बोगीज उन में जोड़ें जिससे उनको सुविधा मिल सके।

मैं समझता हूँ मंत्री महोदय इन बातों पर पूरा ध्यान देंगे। धनी तक मेन लाइन्स पर ही ट्रेन्स बढ़ाई जाती हैं, ग्रांथ लाइन्स पर भी ट्रेन्स बढ़ाई जायें ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

धन्य मैं मैं धायको धन्यवाद देते हुए जो रेल बजट वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उसका मनन करता हूँ।

भीखी रसोया हूक चौधरी (सिल्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1978-80 का जो रेल बजट रेलवे मिनिसटर में यहां पर प्रेजेंट किया है, मैं समझती हूँ जनता को उससे अभिमत हो रहा है। 1977 में जिन लोगों में जनता राज प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था उनमें जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं और 70 प्रतिशत लोग शहरों से दूर रहते हैं, जिनको उप नगर बोलते हैं, क्योंकि बड़े शहर में रहकर जो कीमत चुकानी पड़ती है उसकी सुविधा उनके पास नहीं है, उनकी इनकम 600 रुपए से ज्यादा नहीं बाल्क उससे कम है। उनको अपनी रोजी के लिए बड़े शहर में रोजी ट्रेवल करना पड़ता है। उनको सीजन टिकट का जो किराया बढ़ा दिया गया है उससे उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है। 25 परसेंट से 30 परसेंट तक किराया बढ़ गया है। जिन लोगों ने जनता राज प्रतिष्ठित करने की कोशिश की थी उनको आज इस बजट से बड़ी निराशा हुई है। इस सन्दर्भ में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मन्त्री जी इस पर फिर से विचार करें और देखें कि सीजन टिकट में यह जो बढ़ोतरी हुई है वह न्याय है या अन्याय।

रेलवे मिनिसटर ने रेलवे की कार्यकुशलता को बहुत अच्छी तस्वीर लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है और यह कहा है कि बैगन मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि जो बैगन-मुजस हैं, जैसे उच्चो-धधे को वाइटल रा-मैटीरियल, जैसे कि कोयला, वह उनको मिलना जरूरी है ही। लेकिन इस कोयले को बेजने में दिक्कत होगी, उन को समय पर बैगन नहीं मिलेगा, तो इस का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिये मैं यही महोदय से निवेदन करूंगी कि हमारे यहां बैगन की अन-सुविधा में बहुत ज्यादा कमजोरी होना है, अगर उस समय को कम करने की कोशिश करें तो वे सब दिक्कतें दूर हो सकती हैं और लोगों को राहत मिलेगी।

भापने फ्रेट पर 10 परसेंट की बढ़ोतरी की है। इस में रेलवे को 1008 करोड़ रुपया मिल तो जायगा, लेकिन इस का सारी बीजों पर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट पड़ेगा। इसका असर हमारे छोटे उद्योगों पर, जिन को स्माल-एन्टरप्रेनोर्स कहते हैं—बहुत ज्यादा पड़ेगा और वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। भाप ने जो किराया बढ़ाया है, इस का रोड-ट्रांसपोर्ट पर भी असर होगा, रोड ट्रांसपोर्ट भी कास्टलियर हो जायगा, सस्ता नहीं होगा, जो इस समय ग्राम भादमियों के लिये बहुत उपयोगी है।

हमारे मंत्री जी ने सभी पहलुओं को देखते हुए एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि उन्होंने रेल कर्मचारियों को बीगन धिये जाने के बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा है।

रेलवे-मेन इस मांग को बहुत बियों से करते आ रहे हैं, उन के अन्दर बहुत ज्यादा रिजर्वमेंट है, इसलिये मैं भाप से निवेदन करूंगी कि भाप उन के रिजर्वमेंट को खत्म करने की कोशिश करें।

इस बजट में एकीकृतबल प्रोडक्ट्स और फूड-ग्रेन्ड के लिये बहुत सी सहायितयें दी गई हैं, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीजों पर जो शुरू बढ़ाया गया है उस का ज्यादातर असर गरीब लोगों पर पड़ेगा, जो हमारे देश का प्रधान संवर्णण है, उन लोगों पर उस का बहुत ज्यादा बोझा पड़ेगा।

इस बजट में भाप ने जो दूसरे सप्लीमेंट्री चार्ज लगाये हैं, जैसे इन्जीनियरिंग उच्चाय हैं या छोट किस्म के स्टोर्स के कारखाने हैं उन के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि रा-मैटीरियल डाने के लिये इन लोगों को बैगन चार्ज देना पड़ेगा, यह बहुत ज्यादा है।

मैंने महोदय ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि नार्थ ईस्टर्न रिजन की तरफ इस बार बहुत ध्यान दिया गया है। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत मालों के बाद जिस को पूर्व पार्वती कहा जाता था और जिस रिजन से मैं आई हूँ, उसकी तरफ ध्यान दिया गया है। इसके लिए मैं भापको बधाई देती हूँ। सिल्वर से जीरीबाम इन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट एक नई लाइन बिछाने का प्रयत्न उन्होंने किया है। यह बहुत ही अच्छी की बात है। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे पूरे हिन्दुस्तान में सभी राजधानी के साथ सयोग रखने के लिए कटेंट रखने के लिए फास्ट ट्रेनज, बलाई गई हैं और हमारे यहां गोहाटी तिनसुखिया मेल है, उसका लाभ मेरे जिले को बिल्कुल नहीं मिलता है। तिनसुखिया मेल से मेरे जिले से जा कर अगर भाप टिकट लेना चाहें या उसको पकड़ना चाहें या उस में रिजर्वेशन लेना चाहें तो यह नामुमीकन है। भापको उसके लिए गोहाटी आना पड़ेगा। वहां भाप न पहुंचें तो भापको कुछ पता नहीं चलेगा कि कहा जा कर भापको यह ट्रेन मिलेगी या कब भापको मिलेगी। सिल्वर गोहाटी एक ही ट्रेन चलती है बैरकपुर बैली एक्सप्रेस। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसको छोड़ कर भाप कोई दूसरी बला में की कोशिश करें। उस में भी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इस बास्के मेरी प्रार्थना है कि कोई दूसरी ट्रेन बलाई जाए ताकि इसके ऊपर बोझ थोड़ा-सा कम हो सके और उस अचल के भादमियों की भी थोड़ी राहत मिल सके।

भापकी गोहाटी लखनऊ मेल चलती है। इस को अगर गोहाटी से न चला कर सिल्वर से भाप चलाए तो मणिपुर, मिजोरम आदि सब जगह के लोगों को बहुत सहायितयें हो सकती हैं। इससे दूर के अंचलों के लोगों को गोहाटी बरीह स्पाको की आगे में सहायितयें होगी।

ईस्टर्न रेलवे पर एक बहुत बड़ा अंकगण है लमडिंग। भापको कभी मीका मिले तो भाप उसको जा कर दर्शन कर आलियेगा। पहली बात तो यह है कि लमडिंग से सिल्वर तक नई फास्ट ट्रेन चले और दूसरी यह है कि

इस संवत्सन का जो वेटिंग कम है, वह बहुत पुराना है और अंग्रेजों के जमाने से आज तक इस में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ पर मुसाफिरों को पांच-पांच और बस बस बंद तक रुकना पड़ता है दूसरी गाड़ियों को एकड़ने के लिए। जंकमन की हालत बहुत ही खराब है। अंग्रेजों के जमाने से आज तक वेटिंग कम में कोई बेंच नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। आप उसको देखें तो देख कर हैरान रह जायेंगे और आप उस में बैठना पसन्द नहीं करेंगे। इसको आप देखें। साथ ही लमडिंग से दूसरी गाड़ी आप बलाएँ सिल्वर तक ताकि उस पिछड़े हुए इलाके के लोगों को भी कुछ लाभ मिल सके।

दूसरी बात यह है कि माल गाड़ी के बैगन नहीं मिलते हैं। घामान में काफ़ी रा-मीटीरियल है, लेकिन बैगन घासानी से न मिलने का कारण छोटे घंघे नहीं चल सकते। बड़े घंघों की बात तो दूर रही। इसलिये आपको एमा इंतजाम करना चाहिये कि रेलवे बैगन घासानी से घाम घादमी को मिल सकें। लमडिंग और बदरपुर सैक्शन पर फास्ट ट्रेन चलायी जाय।

दूसरी बात यह है कि नई लाइन बिछाने की बात मंत्री जी ने कही है कि बोनगईगांव से सोहाही तक ब्रोडगेज लाइन 1980 तक पूरी हो जायगी। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक जो छोटी लाइन आप बना रहे हैं उसके बदले घमर बड़ी लाइन बनाये तो अच्छा रहेगा क्योंकि एक तो उस पर खर्चा कम होगा और दूसरे लोगों को भी अधिक सुविधा होगी।

रेलवे क्लेम्स में काफ़ी देर होती है। आप घमर क्लेम करो तो रोज आपको जाना पड़ेगा पता करने के लिये और रेलवे कर्मचारी आपको बताने के लिये तैयार नहीं है कि आपका क्लेम किस स्टेशन पर है। यद्यपि मंत्री जी ने कहा है कि अब क्लेम सैटिल करने में 46 दिन के बजाय 37 दिन ही लगेंगे, लेकिन घमनवित्त यह है कि रोज घादमी जाता रहे फिर भी क्लेम का पता नहीं लगना कि क्या हुआ। इस और आपको ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों को जल्दी क्लेम मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ।

श्री डी. जी. शर्मा (बुलडाना) : मम्मानवीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर बोलने के लिये जो आपने मुझे अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अर्पण करता हूँ। हमारे रेल मंत्री जी बड़े धनपूबी हैं और उनके विचार भी कानिकारी हैं। उन्होंने दो सरप्लस रेलवे बजट बनाये और रेलवे यातायात में जो सुधार किया उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे रेल मंत्री जी ने रेल प्रशासन को सुधारने के लिये और रेलवे के प्रति हर बाड़ी की सहभावन प्राप्त करने के लिये बड़ा प्रयास किया है, जिसके लिये वह बधाई का पात्र है।

सीजन टिकट पर इन्होंने ब्यादा किराया लगाया है, कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया है और बहुत से तत्वों ने उसका विरोध भी किया और कहा कि कई जगहों पर उसने किये विकटिंग हुआ, धान्यीकन हुआ। लेकिन मैं सचस्वी के ज्वाल में एक बात सना चाहता हूँ कि

जो अच्छा काम होता है, उसकी सराहना जरूर करते हैं, लेकिन जो थोड़ा गलत होता है, वह किस लिये होता है, उस पर भी विचार करना अच्छा होता है।

रेल मंत्री जी ने 3 माल के बजाय 5 साल तक के बच्चों को जो रेलवे में फ्री घमने की सुविधा दी है वह क्या कोई कम बात है? आज गरीब घादमी अपने 5 साल के बच्चे को फ्री ले जा सकता है, इसके लिये मैं रेलवे मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि बुढ़ाया और बचपना एक-सरीखे होते हैं। जब घादमी बुढ़ा होता है तो वह भी बच्चे जैसा ही होता है। मैं उन से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसकी उम्र 70 साल के ऊपर है, उसको भी फ्री ट्रेवल करने की सुविधा दे दी जाये क्योंकि उनको भी कही जाना पड़ता है। यह मेरा सजेशन है।

इसके अलावा रेलवे में जो बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसका कारण असमाजिक तत्वों का बढ़ते जाना है। वह लोग फिज-वैलेंट की निकासते हैं, लाइन तोड़ते हैं और डेमेज करते हैं। इन सब बातों को रोकने के लिये, रेलवे यातायात की सुविधा अच्छी रखने के लिये और इन तत्वों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिये जो गंमन काम करते हैं पटरियों पर और लाइनों को देखने का, उस सारे लोगों को चाहे वह ट्रेड हों या धन-ट्रेड हों, उन सब को युनिकार्म मिसनी चाहिये जिससे जनता समझ सके कि यह रेलवे का कर्मचारी है या असामाजिक तत्व है, उधम करने वाला घादमी है जो कि जानबूझकर पोसिटिवली रेलवे को गिराने की कोशिश कर रहा है। इसके लिये सारे कर्मचारियों को युनिकार्म मिसनी चाहिये। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह मेरी बात को नोट कर लें।

जहां रेलवे प्रशासन में कई सुधार हुए हैं, वहां रेल मंत्री जी को मैं एक दोष भी देना चाहता हूँ। सराहना तो की है, लेकिन दोष भी देना चाहता हूँ कि रेलवे सर्विसेज में शड्यूल कास्ट्स का परसेंटेज मेटेन नहीं होता है। कोई डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या और जो ऐसी ऊंची-ऊंची जगह है वहां शड्यूल कास्ट्स में घादमी नहीं है।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं 3 तारीख को रेलवे भवन में गया। वहाँ एक घादमी रोते हुए घाया। मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक घादमी रोते हुए घाया कि साहब मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे बाल बच्चे पूछे मरेंगे, मेरा कोई अपराध नहीं था, हुनाह नहीं था, क्यों निकाल दिया गया? तो अफसर ने उसको क्या उत्तर दिया कि हिन्दुस्तान का पीपुलजन कितना है? वह बोला कि 65 करोड़। फिर उसने कहा कि क्या 65 करोड़ लोग रेलवे में नौकरी करते हैं? रेलवे में नौकरी कितने करते हैं? 65 करोड़ को रेलवे नौकरी नहीं दे सकता है, बले जाओ, गेट घाउट। उसको बाहर निकाल दिया गया। वह नेबारा रोता, लड़पता हुआ फिर घुस गया कि बचाओ, मेरे बाल-

बच्चे मर जायेंगे, छोटे-छोटे बाल-बच्चे हैं, लेकिन उस अधिकारी ने कोई कदम नहीं की। मैं उसका नाम मिनिस्टर साहब के पास भेज दूंगा, लेकिन यहां नहीं बोलूंगा।

मैंने महोदय को यह हुक्म देना चाहिए कि प्रशासन पूरी ईमानदारी और रेलवे के प्रति बकाशारी के साथ काम करे, क्योंकि रेलवे एक ऐसा माध्यम है, जो सब लोगों को एक-साथ ले कर चलता है, चाहे मिनिस्टर हो, एम.पी. हो, कोई झाड़ू लगाने वाला हो और चाहे कोई भ्रष्ट गरीब आदमी हो। रेलवे प्रशासन और आक्रामकों को इस बारे में बड़ा मतकं होना चाहिए।

महाराष्ट्र के जिस इलाके से मैं आता हूँ, वहां बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में खामगांव एक तहसील है। ब्रिटिश जमाने में 1900 में खामगांव-जालना रेलवे लाइन का सखे हुआ था। 1934-35 में उसका अचलक भी हो गया। रेलवे की हजारों एकड़ जमीन वहां पड़ी हुई है। वहां की जनता बहुत समय से यह माग कर रही है कि इस पुरानी रेलवे लाइन को बनाया जाय, लेकिन रेलवे बोर्ड ने इस का कोई खयाल नहीं किया है। लोग आन्दोलन करते करते थक गये हैं। कहा जाता है कि अब जनता सरकार धा गई है, ईमानदार लोग धा गये हैं। तो फिर वे बेईमानी कैसे करने लगे। कांग्रेस वाले बेईमान होएँ, लेकिन जनता पार्टी के लोग तो ईमानदार हैं। जिस लाइन का सखे लगभग 79 साल पहले हो चुका है, उसका निर्माण क्यों नहीं किया जाता है। अगर सरकार इस लाइन को नहीं बनायेगी, तो वहां की जनता आन्दोलन करेगी और लाखों लोग जेलों में जायेंगे। मैंने रेलवे मंत्री को भी लिखा है कि मेरे पास इस प्रकार के पत्र आये हैं कि लाखों लोग आन्दोलन करने पर तुले हुए हैं। जिस लाइन के लिए रेलवे का करोड़ों रुपये खर्च हो, गया है, उस लाइन को छोड़ दिया जायगा और नई लाइनें बनाई जायेंगी? इस लिए इस पुरानी लाइन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

हम बहुत दिनों से रेलवे प्रशासन को कह रहे हैं कि जो लोग पत्थर तोड़ते हैं, साब डोते हैं, लाइन पर काम करते हैं, रंगमैन हैं या झाड़ू लगाने वाले हैं, वे खिन्दगी भर टेम्परेरी रहते हैं। जब वे नौकरी से निकलते हैं, तो रेलवे प्रशासन उनको कोई पेन्शन या रीचुइटी नहीं देता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस आदमी को साविस पांच साल की हो जाय, चाहे वह कोई भी काम करता हो, उसका पर्सनल कर देना चाहिए, क्योंकि उसका और उसका बाल-बच्चा का भविष्य उसपर निर्भर करेगा।

मैंने पहले भी कहा है कि रेलवे में कैंटीन का इंट्रेक्ट एक ही कम्पनी को दिया जाता है, जिस तरह की स्टील एंड कम्पनी की मानोपसी बनी हुई है। इस मानोपसी को खत्म कर के छोट छोट कंटेनरर्स की कंटेनर शिप जाय, जिनमें शिड्यूल्ड कार्ट्स की बोलियों का ज्यादा

परसेंटेज हो। इस वेब में जात-जात की मिठाई के बिस्कुट ब्राकसक है कि लोग शिड्यूल्ड कार्ट्स के; लोगों के हाथ का खाना खाना सीखें।

श्री रामानंद तिवारी (बक्सर) : श्रीमान्, रेलवे विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें सम्बन्ध में मैं दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूँ। पहले मैं रेलवे विभाग के उस धंग के बारे में कहना चाहता हूँ जो अधिक से अधिक उपेक्षित, अस्वीकृत, दुश्चित और पीड़ित है। वह धंग है जिस पर रेलवे विभाग के माल गोदामों की और गृहस ट्रेन की रक्षा का वायित्व है। आप जानते हैं 1959 में इसी सदन में एक एक्ट पारित हुआ—रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम। उस के अनुसार उस का प्रधान कर्तव्य यह है कि रेलवे विभाग में जो माल गोदाम हैं और जो गृहस ट्रेन हैं उन की रक्षा करना, चोरी से बचाना।

16.02 hrs.

(Shri N.K. Shejwalkar in the Chair)

ये धार पी एक के वह जवान हैं जो गरीब हैं, दुबिधों के लड़के हैं। इन लोगों के सम्बन्ध में मैं चन्द बातें आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्यो ये उपेक्षित और अस्वीकृत हैं। धार पी एक के जवानों से आज कम से कम 12 से 18 घंटे तक लगातार काम लिया जाता है। मगलसराय का यादें देखा जाय, पांच छ. या मात माइन लग्ना है। जाड़े की कड़ाके की सर्दी में जब मारा संसार हो जाता है वे धरायी धार पी एक के जवान बाम की लाठी लेकर उस की रक्षा करते हैं। धरायी धार पी एक, उन गरीबों को पकड़ कर, सीत तोड़ कर धार पी एक रोक कर सामान ले जाते हैं। उनके बाद विभाग के अधिकारी उन्हें दंडित करते हैं।

धार पी एक को बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। जिस धनुषात में काहम बड़, रेल की ट्रेनें बड़ी और धार नब काम हुआ उस धनुषात में इन की संख्या नहीं बढ़ाई गई। परिणामस्वरूप ये 18 घंटे तक लगातार काम करते हैं। इतना ही नहीं, इन की आलोचना की जाती है। आलोचना हो, लेकिन स्वस्थ हो। कभी आप ने विचार किया कि तीन माइन का यादें है? एक आदमी उस की रक्षा करता है, वह कभी उठे बचा सकता है? साब ही जहां उन्हें गृहस ट्रेन और माल गोदाम की रक्षा करना था, वही उनसे दूसरा काम भी लिया जाता है। रेलवे विभाग में बिधि और व्यवस्था, ला एंड आर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर निर्भर करती है, उस की रक्षा का वायित्व उन पर है। जो काहम रेलवे विभाग में होते हैं उन का भी वायित्व रेलवे पुलिस के ऊपर है। लेकिन आज इनसे ला एंड आर्डर भी सेट्टेन कराया जाता है जो इन की द्यूटी नहीं है, जो धार पी एक एक्ट में नहीं है। उस के प्रतिफल, नियम को धंग कर के वह काम इन से कराया जाता है। मान सीजिए किसी स्टेट में हिन्दी एक्जिबिशन हुआ, बिहार और उत्तर प्रदेश में आरक्षण के वक्त में धार आरक्षण के विरीड में आन्दोलन

बसा। उसमें भी उनसे काम लिया जाता है। किसी भी दल का धान्योत्पन्न हो उस में रेलवे काइन की सीढ़ फाईर का जो काम होता है उसका धारित्व, ला एंड फाईर का धारित्व उस स्टेट की सरकार पर है। लेकिन 18 घंटे काम करने के बाद धाप इन को बिबल करते हैं। यह काम करने के लिए। इन से यह काम धाप लेते हैं। मैं पूछता हूँ उस को धाप बेतन क्या देते हैं? सबसे दुःखद स्थिति यह है कि मैं वे रेलवे कर्मचारी लेकिन उन पर डिस्टिन्गुइश पुलिस फोर्स का लागू किया जाता है परन्तु सुविधा पुलिस फोर्स की नहीं दी जाती है। जब वे सुविधा मांगते हैं तो कहा जाता है कि धाप रेलवे कर्मचारी हैं। जब वे रेलवे कर्मचारी की सुविधा मांगते हैं तो कहा जाता है धाप पर कर्तव्य धीर धनु-धासन नहीं लाया जायेगा जोकि पुलिस विभाग का है। मैं समझता हूँ धापको यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि रेलवे सुरक्षा दल के जवान रेलवे के कर्मचारी हैं या पुलिस के कर्मचारी? यदि धाप उनको पुलिस का मानते हैं तो धाप उनका वे सारी सुविधायें दें जोकि पुलिस विभाग के जवानों को दी जाती हैं। यदि धाप यह नहीं देते हैं तो धापको उन्हें वह सारी सुविधायें देनी चाहिए जो कि रेलवे के तृतीय धीर वतुर्च श्रेणी के कर्मचारियों को दी जाती हैं। रेलवे कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का रैस्ट दिया जाता है, एक दिन की छुट्टी दी जाती है लेकिन सुरक्षा दल के कर्मचारियों को धाप छुट्टी नहीं देते हैं। धाप इस सबन में भले ही जवाब दें हैं—मैंने यहां पर प्रश्न किया था जिसका उत्तर मिला, उसको यदि मैं आधार-हीन धीर धसत्य कहूँ तो प्रतिन्योक्ति नहीं होगी, धापने कहा कि रविवार को उन्हें छुट्टी दी जाती है लेकिन वास्तव में उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती है, उस दिन भी उनसे काम लिया जाता है। रेलवे कर्मचारियों को रात्रि में काम करने के लिए प्राधिकर पैसे दिए जाते हैं लेकिन सुरक्षा दल के कर्मचारियों को यह पैसा भी नहीं दिया जाता है।

इसी प्रकार से पुलिस कर्मचारियों को प्रत्येक स्टेट में जाहूँ वह राजस्थान हो, हरियाणा हो, बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, कपड़ा दिया जाता है। मैं यहां पर जर्सी लाया भूल गया, रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को जो जर्सी दी जाती है उसमें पटसन मिक्स होता है। वह जर्सी 3-4 साल के बजाय 6 या 8 महीने धाते धाते बर्बाद हो जाती है।

धाप उन्हें एसोसिएशन बनाने नहीं देते हैं। धापने उन्हें केवल क्षेत्रीय आधार पर संगठन बनाने की अनुमति दी है लेकिन जब वे सारे भारत में उसको एक सूत्र में पिरोकर महासंघ बनाने की मांग करते हैं तो धाप उससे इनकार करते हैं जबकि संविधान उनको इस बात की अनुमति देता है। इसका कारण यह है कि वे गरीब हैं, कमबोर हैं, बुद्धिया हैं। इसीलिए धाप उनको उनके अधिकार से वंचित रखते हैं। धापने स्ट्राक काउंसिल दे दी लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। मैं जानना चाहता हूँ, धाप क्यों उन पर शक करते हैं, क्यों उनसे डर करते हैं? उसका कारण क्या है? धाप उनके महासंघ को अनुमति क्यों नहीं देते हैं, माधता प्रदान क्यों नहीं करते हैं। हमारे देश में भी बी समाजवादी हैं, उनका धारण धीर

बलि समाजवादी है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम सोमलिस्ट पार्टी में थे, 1952 में सोमलिस्ट पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में हम को धारवत्त किया था कि पुलिस के विपारिणों को भी एसोसिएशन बनाने की मान्यता दी जायगी। लेकिन जो धाप के बड़े धफसर हैं, वे ऐसा नहीं चाहते हैं, धाप को ऐसी सलाह देते हैं कि इन के महासंघ को मान्यता न दी जाये। क्या कारण है कि धाप धाई, पी.एस की एसोसियेशन है, धाई.ए.एस. की एसोसियेशन है, तो फिर धा.पी.एफ. के जवानों को महासंघ बनाने की मान्यता नहीं दी जा रही है? क्या इसे बदल नहीं सकते हैं, जब कि क्षेत्रीय आधार पर धापने मान्यता दी है।

इसी तरह से कल्याण निधि का मामला है, इस में जवान से ले कर बड़े धफसर तक, सब उस के मेम्बर हैं। जवानों से दो-दो रुपया मासिक काटा जाता है। 46,000 जवान हैं धीर 15—20 अधिकारी हैं। लेकिन उन का जो बोर्ड है उस में सब अधिकारी हैं, धायद एक जवानों का प्रतिनिधि है। मेरा यह कहना है कि उन की सदस्यता उन की संख्या के अनुपात से होनी चाहिये। मैं धाप से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सतह है उस की तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। जैसे यह भवन है, इस की नींव में जो ईंट लगी है उस की तरफ हमारी नजर नहीं जाती है, यदि नींव हिल गई तो सारी इमारत गिर पड़ेगी। इसलिये मेरा फिर से बड़ी धनुरोध है कि उन्होंने महामय धनाने का जो गठन किया है, उस को मान्यता दें।

धाप रेलवे की क्या स्थिति है? रेलवे में धाप ने बहुत से सुधार किये हैं, धाप का बजट बहुत भण्डा है, लेकिन धाप बिहार में जाइये, उत्तर प्रदेश में जाइये, वहां चलने वाली गाड़ियों से जगह का इतना धभाव है, कि गरीब धावमी गाड़ियों की छत पर, इन्जनों पर बड़ कर धावा करते हैं। क्या धाप ने कभी सोचा कि जो गरीब का बेटा है, बुद्धिया का बेटा है, धगर वह इन्जिन पर बड़ कर जायगा, डिब्बों की छत पर जायगा धीर यदि वह गिर जाय तो कहां जायगा? उन पर बड़ने वाले कीन हैं? देहात का सीमांत किसान है, खेतहुर मजदूर है, समाज का निचला गरीब उन पर बड़ता है, उस के लिये धाप ने क्या किया? उस को धाप ने कीन दी बुद्धिया दी है?

धाप ने कहा था कि धाप ने रेल विभाग के अधिकारियों के लिये सैन्यों का उपयोग बन्द कर दिया है—लेकिन वह कहां बन्द हुआ है? इस देश के गरीब के के लिये, बुद्धिया के लिये गाड़ियों में बैठने का स्थान नहीं है, लेकिन अधिकारियों को सैन्य देते हैं। क्या वे एयर-कन्डीशन में नहीं जा सकते, क्या प्रथम वर्ग में नहीं जा सकते? धंधेजों के लिये सैन्य होते थे, क्योंकि वे विदेशी थे, वे हमारे ऊपर शासन करते थे, लेकिन बड़ी परम्परा धाप भी बड़ी तेजी से चल रही है। मुझे बड़ी बुद्धी हुई थी जब माननीय मंत्री जी ने बड़े साहस के साथ कहा था कि मैंने धावेले दे लिये

हैं कि सैकड़ों में बसकर नहीं चलेंगे, लेकिन प्राज भी सैकड़ उसी रूप में व्यवहार में आ रहे हैं, जिस रूप में पहले आते थे। जिस देग की 50 फीसदी जनता प्राज भी गरीबी की रेखा के नीचे है, उस देग के अधिकारी सैकड़ों में उसी तरह से चलें, जैसे ग्रंथी साम्राज्य में राजे-महाराजे जाते थे—यह बड़े दुख की बात है। इस लिये मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप इस की नन्द करें।

बिहार में पटना और बक्सर के बीच में एक बनावी स्टेशन है। पहले वहाँ पर गुब्बन की बैगज लाई जाती थी, उन को वहाँ काटा जाता था। लेकिन अब उस व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब जो भी बैगज आती है, वे पटना या बक्सर भेज दी जाती हैं और बाद में बनावी पहुँचती हैं, तब में एक महीना लग जाता है। मैं आप से निवेदन करूँ कि आप प्रबलितम्ब भावेश दें कि बनावी स्टेशन के लिये जो बैगज पटना या बक्सर से आये, उनको तुरन्त वहाँ काटा जाय। उसको वहाँ काटा जाए और जब उसको वहाँ काटा नहीं जाता है तो इससे किसनों को बहुत नुकसान होता है, उनको अपनी ईज्जत जलानी पड़ती है, वह बरबाद होती है।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आर०पी०एफ० के जवानों के साथ ध्याय करें। उनको आप मनुष्य समझे, इंसान समझे। उनकी झुपड़ी भाट घंटे से ज्यादा न हो। रहने के लिए जो उनको बंदरक बी जाती है उस में 58 वर्ग मीटर जमीन तो उनको मिलनी ही चाहिये। जहाँ रेल कर्मचारियों को अपने परिवार रखने के लिए आप आवास देते हैं वहाँ उसी तरह से इन लोगों को अपने परिवार साथ रखने के लिए आपको आवास देने की व्यवस्था करनी चाहिये। समय पर इनकी बढ़ियाँ भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये। उनके वेतन में वृद्धि करनी चाहिये। कम से कम इतना तो आप उनको दें जिस में उनका भरण पोषण ठीक से हो सके।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr. Chairman, Sir, the hon. Railway Minister is a very soft spoken, dynamic and amiable person, but when he presented the Railway Budget the railway users, the railway employees and workers were disappointed.

Sir, while proposing increase in fares, the First Class passengers are given a softer deal. As against 105 per cent increase at 21 to 25 kilometres range and 88 per cent in the rest up to 120 kilometres in Second Class over the old rates, one finds that increase in First Class is between 80 per cent at 21 to 25 kilometres range

which progressively goes down to 58 per cent at 120 kilometres range on a difference of 25 to 30 per cent between these two classes as far as increase is concerned.

Sir, the Minister yesterday said that he has performed a hat-trick by presenting surplus budget consecutively three years in a row. At the same time he is hitting on the head of the commuters, on the head of the monthly season ticket-holders, the working people and ordinary commuters by increasing the fare of monthly season tickets. You know, Sir, that in Howrah and Sealdah section more than 20 lakhs of season ticket-holders come to Calcutta for their daily work and in Asansol, Raniganj and Durgapur industrial area, lakhs of employees have to go to their respective place of work. Due to lack of residential accommodation, they cannot stay at the place of their work. Similar is the case with Madras, Bombay and Delhi. In Delhi people far away from Meerut come daily to perform their duties in Delhi. So, I strongly protest against raising the fare of the monthly season ticket.

Sir, the Minister has stated that in 1978-79 the surplus will be Rs. 88.49 crores and he has increased it by Rs. 28.96 crores by increasing fares. So, if the fare of the monthly season ticket holders is reduced and if status quo is maintained, then there will be about Rs. 59.53 crores of surplus. Members of Parliament from all parties have already protested against this rise in fares and have requested him to reduce the fare. I am sure that the Minister for Railways, who is democratic-minded, will definitely concede the demand of Members and at the time of reply to the Budget will announce a reduction in fares for at least the second class monthly ticket holders, maintaining the status quo.

The Janata Government had assured that the policy of favoured recognitions will go, and this has been implemented

in the Steel, Coal, Labour and other Ministries, but the Railways continue as before refusing to recognise the CIW Labour Union, DREU and LRSA which have already proved their majority following.

The Railway Ministry decided that all those who were imprisoned under MISA and DIR and were victimised during the emergency would be reinstated and paid full wages. The Railway Minister himself assured us that all those victimised under rule 14(ii) during the emergency would be reinstated. But the Railway Board did not do so in respect of many in the N.E. Railway despite High Court judgements. Even when they were forced to accept the workers back, they served penal transfer orders on them.

The Central Contract Labour Advisory Board decided in December, 1977, that use of contract labour in loading and unloading of coal including cinder picking should be prohibited, but no notification has so far been issued.

Although the Railway Minister wants to assure the House that the labour relations are extremely satisfactory, the position in reality is not good. The AIRF has decided to forge a broad-based unity for struggle, the NFIR has conducted a strike ballot, the Railway Employees' Confederation has decided to resort to work-to-rule from May 8, 1979, the LRSA has decided to resort to agitation, and the CLW Labour Union has also conducted a strike ballot. There have been struggles at various centres for their just demand for bonus.

I shall once again emphasize the need for the declaration of the Burdwan-Asansol section as suburban. This was unanimously resolved upon at the West Bengal Vidhan Sabha on 23rd November, 1978 and also recommended by the World Bank Consultant in December, 1974, November, 1975 and March, 1976 during his survey tours of the Eastern Railway.

People have been pressing for a long time for the plying of EMU coaches in the Burdwan-Asansol section.

The Minister has stated that double decker trains would be introduced in the Howrah-Asansol section. May I know whether they would be introduced in 1979?

The railways conducted surveys for the construction of new railway lines between Bankura and Raniganj and a railway-cum-road bridge over the river Damodar. This will serve Bankura and Purulia which are two backward districts. Most of the people there are scheduled castes and scheduled tribes. The Energy Ministry is trying to develop Mejia coal field there in a big way. So, this railway will cater to the needs of not only these two districts, but the whole area.

We will be able to carry coal from Dhanbad, Raniganj to Haldia via Bankura directly. The progress of work of Howrah-Amta and Howrah-Sheekhala line is disappointing. People have started losing faith on the earnestness of the Railways in the matter. Unless the assurances are backed by action, this may be coined as a joke.

I would demand the construction of a double line from Katwa to Bandel and electrification of Katwa-Bandel suburban section of Eastern Railway. I want to mention that a unanimous resolution was adopted in the West Bengal Assembly.

I would like to mention about three narrow gauge lines—Burdwan-Katwa, Ahmadpur-Katwa and Bankura-Damodar—which are going through the backward areas. They have been neglected for long in spite of my inviting the attention of the Railway Minister to this last year. Bankura-Damodar Railway line which runs from Raina to Bankura is in a bad shape. I would request that these should be improved. After the devastating floods, now the trains are running from Katwa to Kirnahar and not upto Ahmadpur. The railway bridge over the river Kuo was washed away

during the last floods. The bridge should be reconstructed immediately. Steps should be taken to run the trains from Katwa to Ahmadpur.

There is disparity in fares between the broad gauge and narrow gauge sections, particularly for distances over 15 kms. In narrow gauge sections, the fares are more. The passenger fares all over the same Railway network should be charged at uniform rates. The Grand Chord line is over saturated. This Burdwan Sahebganj loop section is going to play an important role in the future and in that line we have Vishvabharati University established by Gurudev Rabindra Nath and this section will carry more goods traffic in future.

Construction of a double line from Burdwan to Sainthia is absolutely essential. The rail users are waiting for a long time for the introduction of a Burdwan—Rampurhat train. Its introduction has been delayed for one reason or the other. The proposed train should be introduced positively by April, 1979.

Previously from Lalgola to Howrah, there was an express train, but it has been stopped. I would request that this should be restored as it was the only inter-city express train in Sealdah Division.

The construction of Krishnagar-Shikarpur Railway line along the Krishnagar-Shikarpur Out Agency bus route should be undertaken immediately. It is a very important commercial centre. Besides that, it is strategically important from the military point of view also. It lies along the border of India and Bangladesh. Electrification of Ranaghat-Gede, Ranaghat-Lalgola section is urgently needed.

As regard the shortage of wagons, only yesterday the Minister of Energy, Mr. Ramachandran, was telling the House that for want of wagons, he cannot carry coal to the thermal power station, to the factories from the east to the west, from the north to the

south. Here, in Delhi, the management of the Hindustan General Industry Ltd. has declared a lock-out from 8th January, and about 1000 workers and employees have been thrown out on the street and they are starving. I would request the hon. Minister to intervene in the matter so that the lock-out is lifted. This concern manufacture wagon which are required for carrying coal and other essential commodities.

I would now draw the hon. Minister's attention to a matter which requires serious attention and adequate action because unless it is checked in time, it will spoil the whole image and the good work done by the Ministry. On 31st January, 1979, one Shri Bhat-tacharya purchased three tickets Nos. 205058, 205059 and 034804 for Rajdhani Express for 10th February, 1979 and they were allotted seat Nos. 18, 19 and 20 in coach No. 3 for 10th February, 1979. But when they reached the New Delhi station, they found that their names were not there in the reservation list and three other names were mentioned against these seats. They were in a very difficult position. After 5 hours only, they got the accommodation. I would request the hon. Minister to enquire into it and stop this type of mal-practice.

I conclude by saying, after this Budget, what is the reaction of the people. The under-developed areas who clamour for new lines, the saturated areas who want additional lines, additional trains, the commuters who want an efficient suburban service so that it does not upset their attendance at the place of work or home life, the railwaymen who want their basic demands of comparable wages and bonus etc. and their policy about recognition and labour relations, the people who want relief from overcrowding and a fair freight and fare structure—all are really disappointed and rather angry.

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Members to cooperate with me. Instead of 10 minutes, if every hon. member takes more time, others

cannot be accommodated. The total time is fixed and it has to be distributed amongst all the hon. members. I do not want to disturb the hon. members when they are speaking. After 10 minutes are over, they themselves should wind it up.

श्री अमन बबे (कच्छ) : सभापति महोदय, मैं दस मिनट से पहले ही खत्म कर दूँगा ।

सभापति महोदय : धन्यवाद । इस से किसी अन्य माननीय सदस्य को भी मौका मिल जायेगा ।

श्री अमन बबे : सभापति महोदय, रेलवे मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ । कहीं कहीं जो सुटियाँ रह गई हैं, जिन की धीरे धीरे तक ध्यान नहीं दिया गया है, उन की धीरे धीरे मंत्री महोदय का ध्यान बीचन चाहता हूँ और धाना करता हूँ कि इस बारे में विचार कर के आवश्यक कार्य-वाही करेंगे ।

मंत्री महोदय जानते होंगे कि गुजरात स्टेट में कच्छ जिला बिल्कुल पाकिस्तान के बाहर पर है । वहाँ जब पहले रेलसे वे तो उन्होंने 60 किलोमीटर की एक लाइन बिछाई थी । उसके उपरान्त भाजारी के बाद आज दिन तक बहुत थोड़ी मात्रा में काबला तक एक नई लाइन गई है, उसके अलावा एक बूच भी रेलवे लाइन हमारे जिसे मैं नहीं गई है । कई वर्षों से हम डिमांड करते आए हैं कि एक नयी लाइन जहाँ लाइन गांधी धाम से मुंदरा-मांडवी होते हुए लखपत तक बिछाई जाये जो कच्छ के पश्चिम में है जहाँ पर कि हमारा बाहर पड़ता है । वहाँ हमारे पुराने [तीर्थ स्थान] में नारायण सरोवर और कोटेश्वर और इस के अलावा वह ऐसी जगह है कि जहाँ दो तीन साल पहले 50 हजार करोड़ रुपये का लिम्नाइट मिला है । धाप को जान कर ताज्जुब होना कि धाप की वहाँ से हर रोज़ तो टूकें लिम्नाइट ले कर चलती हैं और गुजरात के कई कारखानों में जहाँ कोयला नहीं मिलता है कोयले की जगह इस मिनरल को वह यूज करते हैं । यह सफ़ेद-फुल एक्सपेरिमेंट वहाँ हुआ है कि कोयले की जगह लिम्नाइट काम देता है और कई छोटे छोटे कारखाने हैं जो लिम्नाइट यूज करते हैं । मैं ने कई बार लिखा है कि एक बड़ी इंडस्ट्री वहाँ खड़ी की जा सकती है, धाप वहाँ आएँ और देखें कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री की धाप गुंजायूँ है । गांधी धाम से ले कर वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह 150 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है । धाप आएँ और देखें कि यह नयी लाइन बालन के नायक है या नहीं । एक जवाब हमारे पास थाया है कि इस का सर्वे हो चुका है । वह कहते हैं कि हमें रेवेन्यू रिटर्न दूँगा नहीं मिलेगा । रेवेन्यू रिटर्न हमें मिले तो हम इस काम को करें । एक तरफ़ तो यह बात कही जाती है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ हम रेवेन्यू रिटर्न की कोई किता नहीं करेंगे, रेवेन्यू रिटर्न नहीं भी 'मिलेगा' तब भी वहाँ हम रेल लाइन बालन और दूसरी तरफ़ ऐसी बात कही जाती है मनु दण्डवते जी का यह भाषण सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उस में कहीं पर भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा है । जो डिस्ट्रिक्ट

बैकवर्ड हैं, जो बाहर पर स्थित है और वहाँ बड़ी मात्रा में लिम्नाइट, कोल्साइट और बेंडोनाइट पड़ा हुआ है, जिन को हम वहाँ से ला कर देश के अन्य भागों में इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ के लिए लाइन बिछाने की बात कही जाती है तो उस का जवाब नहीं धाता है । एक ही जवाब अभी तक थाया है कि रेवेन्यू रिटर्न नहीं मिलता है ।

इसी तरह काटन की बात हो, साल्ट की हो उस को भी वह ध्यान में नहीं लेते हैं । साल्ट हमारे देश में जितना उपयाय होता है उस में से 60 प्रतिशत कच्छ में होता है और मुंबरा और बच्चक से विदेशी स्ट्रीमर आ कर साल्ट ले जाते हैं । लेकिन रेलवे मंत्रालय में साल्ट की बैल्यू नैगेटिव बैल्यू है । उन के आफिसर ऐसा कहते हैं कि हम साल्ट की बैल्यू निगेटिव मानते हैं, इसलिये कितना भी साल्ट बाहर जाय उस को हम ध्यान में नहीं लेंगे । मैं प्रार्थना करूँगा कि साल्ट की भी कुछ बैल्यू है, साल्ट एसेसियल कमोडिटी है, उस के बिना जीवन नहीं चलता है, ऐसे महत्व की चीज को धाप को निगेटिव बैल्यू में नहीं गिनना चाहिए ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि गांधी धाम से भुज तक जो छोटी लाइन है उस के कन्वर्शन का सवाल है । कुल 60 किलोमीटर की बात है । उस का एस्टीमेट पहले 4 करोड़ का था, आज वह 6 करोड़ हो गया है । लेकिन धाप के अफसरान कहते हैं कि 22 करोड़ खपया इस पर खर्च लगेगा । वह गांधी धाम से लखपत वाली बात इस में जोड़ देते हैं । जब हम बड़ी लाइन की बात करते हैं तो धाप कन्वर्शन की बात को उस में जोड़ देते हैं इन दोनों बातों को जोड़िए मत । दोनों अलग अलग बातें हैं । कन्वर्शन की बात हम कई सालों से करते आ रहे हैं । 60 किलोमीटर यह हो जायगा तो उस से काम चल जायेगा और वह 6 करोड़ रुपये का काम है । डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भुज तक धाप इस को ले जायें । गांधी धाम से भुज तक 60 किलोमीटर का ही सवाल है । बहुत दिनों से हम यह मांग कर रहे हैं लेकिन धाप ने उस पर आज तक सोचा नहीं । मैं धाता करता हूँ कि धाप इस पर जरूर विचार करेंगे ।

बम्बई से गांधी धाम तक एक ट्रेन चलती है । हमने मांग की है फास्ट ट्रेन की । अफसरान ने ऐसा जवाब दिया कि 85 परसेंट रेवेन्यू ट्रैफिक मिलना है, 15 परसेंट गांधी खाली जाती है । मैं कहता हूँ कि 15 परसेंट गांधी खाली जाती है तो धाप धाप का टिकट हमें ले दीजिये । कभी भी टिकट नहीं मिलता । गांधी धाम से बम्बई जाने क लिये भी टिकट नहीं मिलता और वह 8 परसेंट धाम पर भी टिकट नहीं मिलता । 8-10 दिन तक के टिकट नहीं मिलते हैं । फिर भी कहा जाता है कि 85 परसेंट स्ट्राफिक है । मैंने पूछा कि इसके असेसमेंट का धाप का क्या तरीका है तो बैस्टन रेलवे के एक आफिसर, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बताया कि एक स्टेशन पर हम खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कितने धादमी उतरे, उनको गिन लेते हैं और उसके बाद असेसमेंट करते हैं कि स्टेशन ट्रैफिक है । ट्रैफिक असेस करने का वह कोई तरीका नहीं है, हमको बचलना चाहिये । यह जो 85 परसेंट की बात कही गई है वह गलत । यह केवल फास्ट ट्रेन न देने का

बहाना करना माफ है। मैं चाहूँगा कि फिर से सर्वे किया जाये। कच्छ जिले के 8 लाख लोग बम्बई में रहते हैं उनके लिए कच्छ जाने के लिये केवल यही एक सुविधा है। बम्बई से माण्डवी तक पहले स्टीमर चलते थे जिससे लोग आते जाते थे लेकिन आज जाने जाने के लिये केवल एकट्रेन ही है। मंत्री जी को एक फास्ट ट्रेन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस से वहाँ की जनता को लाभ होगा तथा रेलवे को भी लाभ होगा। मैं बड़ी लाइन के सम्बन्ध में बात कह रहा हूँ।

आप की 1977-78 की भारतीय रेल, वार्षिक पुस्तक में आप ने बताया है :

“कि काण्डला के लिये बड़ी लाइन सम्पर्क ब्रूड से बनाया जाये। इस लाइन से 9.4 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होने की प्रत्याशा की गई थी और इस से 40 प्रतिशत से भी अधिक प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। यातायात में भारी वृद्धि हो जाने के कारण ऐसा हुआ है।”

इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आप ने 9 प्रतिशत प्रतिफल की आशा रखी थी उस की जगह पर आप को 40 प्रतिशत प्रतिफल मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप को अधिक रेवेन्यू प्राप्त हो सकेगा। वहाँ पर जो मिनरल्स पड़े हुए हैं वह आप की नोस्टिस में नहीं आये हैं। 1971 में जो सर्वे हुआ था तब लिम्साइट का पता नहीं चला था, अभी तीन साल पहले ही इसका पता चला है। मैं चाहूँगा कि आप फिर से ट्रैकिंग सर्वे करावें। वहाँ पर करोड़ों का मिनरल पक्का हुआ है जिससे देश को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

तीसरी बात यह है कि कच्छ जिले में पहले घाउट-एजेंसी चल रही थी, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो उसको बन्द कर दिया गया और फिर किसी को कांस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस पर आप पुनः विचार करें क्योंकि पूरे वैस्टर्न कच्छ में इसकी कोई सुविधा नहीं है। अभी गांधीग्राम तक 130 किलोमीटर की मुसाफिरी करनी पड़ती है। अगर भूज, माण्डवी में घाउट एजेंसी हो जाये तो लॉग टिकट भी लें सकेंगे और सामान भी ला सकेंगे।

दूसी प्रकार से करमरिया स्टेशन का फ्लैग स्टेशन बनाने की बात है। अभी बौद्ध स्टेशन चल रहा है। हमने कहा कि हमका आप ने गलती से बना दिया है, वहाँ से कोई बस्तु रेवेन्यू नहीं मिलती है। वहाँ पर भ्रमरान गाँव, उन्हीने सर्वे किया और रिपोर्ट दी कि रेवेन्यू नहीं मिल रही है। हमने कहा कि करमरिया नाम का गाँव, जिस की आबादी 5 हजार है, उसको फ्लैग स्टेशन बनायें और तीन महीने तक एक्सपेरिमेंटल सेन्सि पर देखें। भ्रमरान ने कहा कि जो सुविधा दी हुई है वह वापिस नहीं लेंगे। मेरा निवेदन है कि जब वहाँ पर रेवेन्यू नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर तीन महीने के लिए बतौर एक्सपेरिमेंट देखें।

अन्त में वैस्टर्न रेलवे को हैडक्वार्टर बम्बई को बारे में नहीं के बराबर कहा है और माबलंकर जी भी कहत रहे हैं।

आखरी बात यह है कि कैंटरिंग के मिनिस्टर इस वक्त यहाँ बैठे हैं, यहमदाबाद से गांधी ग्राम तक आज तक कैंटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जो गांधी दिन में चलती है उस में भी नहीं है। यह 12-13 घण्टे का सफर होता है—इस में ऐसी व्यवस्था आप को करनी चाहिये।

बम्बई से जो पैनेलर 800 किलोमीटर की मुसाफिरी करते हैं—उनके बैठने की व्यवस्था भी आप जरूर करेंगे—इतना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।

SHRI BHAUSAHEB THORAT (Pandharpur): Mr. Chairman, Sir, really I wanted to speak in Marathi because the Minister comes from Maharashtra...

PROF. P. G. MAVALANKAR: Why don't you speak?

SHRI BHAUSAHEB THORAT: But the Minister is not there.

Sir, the railway budget presented by the Minister is very disappointing to all sections of the community and all over the country. So far as my constituency is concerned, it is situated on the Miraj-Latur narrow gauge line. Sir, Pandharpur is a pilgrimage station. People from Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Orissa and other places of the country come to Pandharpur. But the Railway Minister has not paid any attention to the demand that is there right from 1973 that this narrow gauge line should be converted into broad gauge. That proposal for conversion into broad gauge has been technically sanctioned, the estimate has been prepared and it has been administratively approved but what happened in the Ministry, I do not know. It had not included it in the Budget. Probably it is because of the fact that right from Miraj to Latur there is no Janata Member elected from that area. That is why the Janata Government has neglected and ignored this demand of conversion of that narrow gauge into broad gauge.

PROF. P. G. MAVALANKAR: You are asking the people of those areas to elect Janata Members only. This is very dangerous for you.

SHRI BHAUSAHEB THORAT: If the line is not converted into broad gauge

the people of the area will be very angry and they will agitate and will not allow you to run the trains. The region through which this railway line runs is a backward area of Marāthwada. Then, Sir, if you go from Latur to Miraj, you will have to spend two nights for covering only 250 miles. So if this conversion is not taken up soon, there will be no course left open to the people but to agitate.

The second thing I want to draw the attention of the Minister to is about reservation in the Railways. So far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are concerned, there are so many posts which are vacant and which are not filled from Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. So I request the hon. Minister to look into the matter and see that so far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, the reservations made are fulfilled.

Another thing that I would like to suggest is this. There is a double-line from Pune to Dhond and from Dhond to Sholapur—hardly one hundred miles—if a double line plan is prepared and completed then the line right from Bombay to Sholapur will be doubled.

There is a workshop at Kuruduwadi and that workshop is running like a private shop of the Workshop Manager. In that workshop casual labours are being employed but all of them are forward people and no one from the scheduled caste or scheduled tribes community residing in that area has been recruited. There is, therefore a race for the casual labour job. If you pay Rs. 500 for the recruitment, then anyone will be appointed. This is what is happening in that workshop. I am just bringing this to the notice of the Minister so that he may see that they are appointed from the scheduled castes or scheduled tribes community. Those who have put in more than six years service have not yet been taken on a regular basis. They are neglected because they belong to the scheduled tribes or scheduled castes community. Why should the others be regularised

and these people are not regularised?

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Is any minister taking notes.

MR. CHANRMAN: Somebody must be taking down notes.

SHRI BHUSAHEB THORAT: The departmental enquires are only conducted against the scheduled castes and tribes people. After that, they are removed from service but no mercy or humanitarian consideration is shown to forgive them. While the others are reinstated in service, they are not being reinstated in the Central Railways in Sholapur Division. This is my personal experience. So, I request the Minister to see that as far as these people are concerned, they should be reinstated in service from the point of view of humanitarian consideration.

So far as Miraj-Latur line is concerned, something must be done to start that. Of the lines sanctioned, two lines namely Vani Chanak-Konkan and Manmad-Bherkhed have been started. But the Miraj-Latur line is yet to be started. I request the Minister to start the line as early as possible.

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) : सब से पहले मैं रेल मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। जनता राज में जनता मंत्री सबसे साबित हो रहे हैं, इस में कोई शक नहीं है। चाप देवें पिछले तीस साल से रेलों में बराबर बाटा होता चला आ रहा था। लेकिन जब से उन्होंने इन को सम्भाला है इस में शक नहीं है कि नफा होता आ रहा है। 1976-77 में 87 करोड़ का नफा हुआ है और 1977-78 में 126 करोड़ का। 1978-79 का नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मुझे भी संदेह हुआ है इस सब रेकार्ड्स को देखने के बाद कि हमको कितना फायदा होगा। वैसे उम्मीद थी कि 65 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन इतने पलटते घाये, पानी बरसा, माल ड्रॉर उधर नहीं आ रहा, रेल गाड़ियाँ बन्द रहीं, तो नहीं कहा जा सकता कि हमको इत बर्ब कितना फायदा होगा। और घर घर अनुमानित फायदा नहीं होगा तो उसके लिए हम रेलवे की बोली नहीं मारेंगे।

जिस कार्यकुशलता और मेहनत से रेल मंत्री इस मंत्रालय को चलाइ कर रहे हैं उसके लिए मैं उनकी हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को और समस्त रेल कर्मचारियों को बधाई देता हूँ क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह सम्भव नहीं है। जनता राज्य में जैसा चाहिये वा बैसा ही हो रहा है, अर्थात् लोकतन्त्र कायम के जो बाबी हैं उनकी सुविधाओं

का अधिक ध्यान होना चाहिये। अभी हमारे पूर्वी क्षेत्र के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे जो पूर्वी क्षेत्र की बबबर गिला गोरखपुर होकर प्रवास जाना का तो पक्षी बार मैंने देखा कि स्त्रियां भी डिब्बे की छत पर बैठी हुई थीं, और ठंड के दिन थे, जनवरी महीने में मैं गया था। तो मैं तो समझता था कि मुंदेलखण्ड ही रेलवे के मामले में पिछड़ा हुआ है और बार बार मैं कहता हूँ कि हमीरपुर जिला रेलवे मैप में है ही नहीं, लेकिन जब मैं गोरखपुर से निकला तो बंग रह गया और तो को छत पर बैठे हुए देख कर, और कपड़े भी उनके पास नहीं थे, इस प्रकार की गरीबी है। हमारे रेल राज्य मंत्री उसी क्षेत्र के हैं इनको कुछ गाड़ियां बढ़ानी चाहिये। आपने 64 नई गाड़ियां बढ़ाई हैं 42 गाड़ियों की दूरी बढ़ाई, 307 गाड़ियां जनता राज्य में बढ़ी हैं और यह सब इसीलिए किया गया है ताकि सेक्वेन्स बसाते की यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा बैठने की सुविधा मिले। लेकिन उसके बाद भी हम यह नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? जो लोग रुद्ध हैं उन पर तो कुछ सुविधा बढ़ रही है, लेकिन जो बाल्य लाइनें हैं पिछड़े क्षेत्रों में हैं उन पर ध्यान नहीं जाता है। उधर भी ध्यान जाना चाहिये, यह हमारा निवेदन है।

बीजल इंजनों के धांके देखे तो मासूम हुआ कि 125, 150 इंजन हर साल बनते हैं, 55 से 60 बिजली के इंजन हर साल बढ़ते हैं, 400, 500 सवारी डिब्बे भी बढ़ते हैं, इसी तरह से माल डिब्बे भी बढ़ते हैं इनको क्यों नहीं ऐसे क्षेत्रों में और लाइनों पर लगाया जाता है जिससे यातायात की सुविधाएं बढ़ें और तमाम यातायात को सुविधाजनक बना सकें? लेकिन अभी उधर ध्यान नहीं जाता है।

यह जो रेल बजट है, रेल उद्योग है, ठीक है इसमें कुछ सुविधा बढ़ रही है, लेकिन 6,000 करोड़ रु० का टोटल इनवेस्टमेंट इस उद्योग में है। लेकिन हमारी बचत क्या हो रही है? छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, छोटे उद्योग और व्यवसाय करने वाले लोग भी इतना कमते हैं कि करीब-करीब 3, 4 प्रतिशत तक उनको मुनाफा होता है। हमने इसे देखा कि 6 हजार करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है और हमारी धावनरी जो हुई है, अगर 100 करोड़ हो हम फायदा मानें जो कि अभी हमारे इस जनता पार्टी के राज्य में धान से जब से कार्य-भार संभाला है, तभी से हुआ है, उससे पहले तो घाटे में चलते थे, तो भी यह 1.5 परसेंट हमारा मुनाफा होता है जो कि बहुत कम है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, हालांकि उसमें नई रेलवे लाइनें बिछती हैं, कुछ जन-इकनामिक और धन-मनुवरेटिव रेलवे लाइनें भी हैं और बैबल-मैटल एक्टिविटी के कारण हमारे यहां बनाई गई हैं और बनानी चाहिए, लेकिन यह जो 1.5 परसेंट प्रता है, इसमें कहीं कुछ दोष जरूर है। इसमें गहराई से रेल मंत्री जी को देखना चाहिये कि बाह्य 6 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ भी मुनाफा हमारा न हो, इसमें कहीं बड़ा भारी दोष है।

17.00 hrs.

इस दोष को मैं देखा हूँ कि कुछ एक्सपैडिशन हमारे बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि उनकी धोर

रेल मंत्री ने जरूर ध्यान दिया है, तभी यह कम हुआ है और हमारे माफिदस बने हैं। सन् 1976-77 में स्टाफ का कास्ट 924 करोड़ रुपये था और 1977-78 में यह बढ़ कर 959 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह से एक ही वर्ष में 35 करोड़ केवल स्टाफ पर खर्चा बढ़ा है, यह बहुत प्रतिशत और बहुत ज्यादा है, प्रवीनेट्स की ठीक नहीं है। बीजल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ा है, रॉनिंग एक्सपेंसेज भी बढ़े हैं लेकिन 35 करोड़ तो केवल स्टाफ पर खर्चा बढ़ गया है। यह बहुत ज्यादा है, 3.8 परसेंट है। हमारे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन पर इतना खर्चा नहीं होना चाहिये। इस पर गहराई से देखना चाहिये। प्रवीनेट प्रवासन जो है, हैब-माफिडस जो है, उस पर एक-डेढ़ करोड़ का खर्च हुआ है। यह देखना चाहिये कि यहां कुछ कमी हो सकती है। हम यह नहीं कहते हैं कि सुविधा नहीं हो। हमारे इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्नीकल प्रसिस्ट्स बहुत अच्छे हैं। यात्रा करते-करते जब कभी रेल में छोटा-सा घक्का लगता है तो नाजुब होता है, और समझ में आता है कि रेल प्रवासन के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स और टेक्नीशियन्स जो कोषेज बनाते हैं, पहिये बनाते हैं, वह कितनी कुशलता से बना रहे हैं कि वह बराबर चल रहे हैं, कभी टूटते नहीं हैं। आप देखिए हमारे देश में जा दूसरे सामान बनते हैं, उनकी क्या दुर्घटना हो रही है, यह सभी जानते हैं। आप एक साइकिल भी देहात में ले जायें, उसको जरासा झटका लगा तो उसका फ्री-व्हील टूट जाती है। अगर कहीं रेल में ऐसा होने लग जाये तो क्या होगा? मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे इंजीनियर्स बहुत महान हैं, और बहुत योग्य व कुशल हैं बरना स्टेशन में कहीं कास्ट धायरल मिला दें तो एक्सल ही टूट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जहां 6 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसमें केवल 100 करोड़ भी हमारा शुद्ध मुनाफा न हो, इस पर देखने की जरूरत है। यह दोष हमारा दूर होना चाहिये।

हमारे यहां बैबलपमेंट फंड होता है, हमारी एमेनिटीज और सुख-सुविधाओं के लिये उसमें क्या बचा है? उसमें 24 लाख का प्रोपनिंग बैलेंस है। जहां 35 करोड़ स्टाफ पर खर्च हुआ है, वहां एक वर्ष में केवल 3, 4 करोड़ हमारी एमेनिटीज पर खर्च किया गया है, 3.79 करोड़। यह बात भी गलत है कि हमारा 24 लाख प्रोपनिंग बैलेंस हो, बैबलपमेंट फंड में। हम हर साल जनरल एक्सचेंजर से कर्जा लेते हैं और उसको प्रदा करते हैं। बैबलपमेंट के मायने हैं कि हमारी एमेनिटी बढ़ें, सुख-सुविधा हो लेकिन वह कहाँ से होगा जब कि हमें उसमें कोई मुनाफा ही नहीं होता है? तो इतने बड़े उद्योग में इस फंड का 24 लाख होना बड़े गर्म की बात है इस बात को देखना चाहिये और हमारा बैबलपमेंट-फंड बढ़ना चाहिये।

रिजर्व फंड में भी हम जनरल एक्सचेंजर के, केन्द्रीय सरकार के, कर्मदार हैं—उसका कर्जा भरा करते मैं लगे रहते हैं। रिजर्व फंड का मतलब

यह है कि जब कोई विपत्ति आ जाये, बाढ़ में कोई रेलवे लाइन या पुल टूट जाये, तो उसका उपयोग हो। यह बाक एंबाबेयर का काम करता है, वह उसका सहता है। लेकिन हमारा यह रिजर्व फण्ड धक्का देने वाला है। यह एक ऐतिहासिक घटना है कि 1977-78 में मुनाफे से 91 करोड़ रुपये रिजर्व फण्ड में डाला गया है, लेकिन 180 करोड़ दरमा हम ने व्यय की प्रदायी करने में सँटुल सर्वेमेंट को दे दिया है। हम फिर बहा के तहाँ रह गये। इस वर्ष हमें फिर से 94 करोड़ रुपये का कर्जा लेना पड़ेगा। फण्ड्स की इतनी दुर्दशा हो, यह ठीक नहीं है। यह बजट बहुत अच्छा है, लेकिन इन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

जहाँ तक टिकटलेस ट्रेवलिंग का प्रश्न है, ये धाकड़े दिये हुए हैं कि 1976-77 में 97,000 और 1977-78 में 1.09 लाख बेंस किये गये। 1976-77 में 42 लाख केंसिज पकड़े गये और 1977-78 में 40 लाख केंसिज पकड़े गये। 1976-77 में 4.50 करोड़ रुपये और 1977-78 में 4.24 करोड़ रुपये को प्रामवनी हुई। लगभग दस, बारह हजार बेंस बड़े हैं, लेकिन नवीजा क्या हुआ? नवीजा यह निकाला जाता है कि बैकिंग और छान-बीन की वजह से टिकटलेस ट्रेवल में कमी हुई है। लेकिन स्थिति यह नहीं है, बल्कि हर माल यात्री बढ़ते हैं और उनकी वजह से टिकट ज्यादा बिके हैं। बेंस का कोई प्रायदा नहीं हो पा रहा है।

मैंने देखा है कि टिकटलेस ट्रेवल को रोकने के लिए सी रुपये का इनाम दिया जाता है। जो धाममी टिकटलेस ट्रेवल करने वालों से लाखों रुपये की धामदमी बसूल करते हैं, उन्हें केवल सी रुपये का इनाम दिया जाता है। मंत्री महोदय को इस और ध्यान देना चाहिए।

बताया गया है कि 1977-78 में 70 स्टेशनों और 41 गाड़ियों में डिपार्टमेंटल कंटेनरिज है और वहाँ 62.32 लाख रुपये का प्रायदा हुआ है। इसकी तुलना में 2880 स्टेशनों और 31 गाड़ियों में यह काम ठेकेदारों को दे रखा है, मगर वहाँ मुनाफा हुआ है 56.66 लाख रुपये का। कितनी लूट हो रही है। वे लोग रेलवे के प्रेमिसिस में काम कर रहे हैं और वहाँ इतने लोग काम पर लगे हुए हैं। मगर इन को तीन हजार स्टेशनों पर भी डिपार्टमेंटल कंटेनरिज की व्यवस्था कर दी जाये तो करोड़ों रुपये का प्रायदा हो सकता है।

अन्त में मैं नई लाइनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे यह बेच कर भयान्त प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष नार्थ-ईस्टर्न रिजन की और पर्याप्त ध्यान दिया गया है। यह देखा गया है कि डेनोकेसी में जिस जेल से कम प्रतिनिधि भाते हैं, उसकी और कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे प्रचारक का यह बीष है। इस वर्ष मुझे उस जेल में जाने

का अवसर हुआ। नागालैण्ड, मिशोराम और त्रिपुरा के लोग मिले, वे कहते हैं कि आप तो क्लर्क हैं, आप तो बहुत बड़ी स्टेट्स के हैं, हमारी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। उस जेल के केवल तीन चार प्रतिनिधि लोक सभा में हैं। उस जेल की और पर्याप्त ध्यान दिया गया है, इसके लिए मैं सरकार को धमाई देना चाहता हूँ। मैं मणिपुर में, इम्फाल में जा रहा था तो मैंने देखा कि केरोसिन आयल नहीं पहुँचा। तो यातायात के साधन न होने से कठिनाई होती है। इसलिए ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में जो स्ट्रेटेजिक भी हैं, उनमें करोड़ों रुपये भी व्यय करना पड़े तब भी उधर ध्यान देना चाहिये। उस से उन का कल्याण होगा और यह भावना भी हटेगी कि यहाँ से कम मेम्बर भाते हैं इसलिए उन को उनका हिस्सा नहीं मिलता है। वहाँ आप रेलवे लाइन विधायक तो उनका हिस्सा भी उन्हें मिलेगा और उन का भी वेवलपमेंट हो सकेगा।

बुन्देलखण्ड और अपने जिले के बारे में छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। हम को एक जवाब दिया गया कि 75 में खुजराही महोबा लाइन का सर्वे हो चुका है। खुजराही आप जानते हैं कि बिस्व प्रसिद्ध स्थान है। लेकिन वह कहते हैं कि महोबा से एक धाममी नहीं बैठेगा और वह रेम्युनरिटिव नहीं होगा, एक पैसा इससे बापस धाने वाला नहीं है। यह कितना झूठ और गलत है। आप को बनाना नहीं है तो आप न बनाएँ लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोलिए। इतनी इम्पार्टेंट लाइन जिसका सर्वे हो चुका है और कुल पांच छः करोड़ में यह बनने वाली है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मेरे पास और बहुत कुछ कहने को है लेकिन समय नहीं है।

*SHRI A. V. P. ASAITHAMBI (Madras North): Mr. Chairman, Sir at the very outset I would like to say that this year's Railway Budget has caused disappointment and distress among the workers and employees of the Railways because their long outstanding demand of tonus has not been conceded by the hon. Railway Minister. Last year, Shri Madhu Dandavate presented a surplus budget without resorting to increase in fares and freights. But this year his surplus budget is based on steep increase in fares and freights. In other words, a deficit railway budget has been converted into a surplus budget.

The increase in the fares and freights is about Rs. 178 crores and hon. Finance Minister through his budget

*The original speech was delivered in Tamil.

has proposed Rs. 946 crores tax levy. Totally the tax burden is of the order Rs. 1124 crores. I wonder whether our people would be able to bear this back-breaking burden. I do not know whether we can draw any picture without the wall.

We should acknowledge the briskness that Shri Madhu Dandavate brought in the working of the Railways. I thought that he would infuse the same spirit of earnestness in the matter of augmenting the revenues of the Railways, which would obviate the necessity of levying increase in fares and freights. My hopes have been belied by this year's budget. He could have averted this steep increase in fares and freights, if only he had taken energetic steps to reduce to the minimum the thefts and pilferages taking place on the Railways. We are spending Rs. 30 crores on the Railway Protection Force. But the protection offered by the Force to both passengers and goods from dacoities and robberies is negligible. It is not that in the stations alone thefts take place. As dacoities are common on the running trains, thefts from running goods train are also on the increase. The compensation being paid by the Railways for thefts and pilferage of goods is staggering. Now we are sending armed police alone with the passengers on the trains. I suggest that such armed police should also accompany the goods trains and then only the Railways would be able to save on the compensation claims, running into several crores of rupees.

I should say that malpractices are omnipresent over the Railways. The Railways lose crores of rupees on account of under-weighting of goods. We have Ticket Examiners to check ticketless travelling and flying squads are also sent to supervise the ticket examiners. The Railways have taken this to plug the loopholes, resulting in increased passenger earnings. I suggest that steps should be taken to check

the under-weighting of goods offerings which results in substantial loss in freight earnings.

I would also refer to poor wagon turn-round which contributes heavily to the loss of freight earnings. The businessmen are hand-in-glove with the Railway employees and they do not unload goods from the wagons; the wagons are in fact utilised as their godowns for days together. The former Railway Minister Shri T. A. Pai introduced a very effective scientific wagon turn-round system which yielded substantial gains to the railway earnings. Besides loss of revenue to the Railways, the businessmen are enabled to create artificial scarcities of essential goods which lead to violent price fluctuations. If the Railway Board had taken effective and energetic steps to control the movement of wagons, there would have been no necessity to increase fares and freights to the tune of Rs. 178 crores.

Many hon. Members have referred to the abominable increase in the suburban ticket fare. The commuters from suburbs contribute to the lessening of congestion and overcrowding in the metropolitan cities. The Railways propose to collect Rs. 70 crores more from them. This will tempt them to come back to the cities. On behalf of the D.M.K. I appeal to the hon. Railway Minister to withdraw this steep increase in the suburban passenger fare, which would hit hard the have-nots who happen to live in the outskirts of the cities.

The Rayapuram Railway-line in Madras city divides the city into North Madras and South Madras. Along this railway-line on the one side there is Stanley Hospital and on the other Maternity Hospital. The railway gale at this point is closed for half-an-hour many times in a day. This causes great inconvenience to the general public. It also hinders free flow of vehicular traffic. I have repeatedly written to the Railway Minister and also to the General Manager. I got written assurances

that this would be looked into. But so far no action has been taken. I demand that an over-bridge must be constructed forthwith at this point.

Rameswaram is a place of pilgrimage for all the Indians. This island gets all the essential commodities from Ramanathapuram. On account of coal scarcity, so many trains had recently been cancelled. If for every one hour a shuttle is run between Rameswaram and Ramanathapuram it would not only help in the quick to-and-fro traffic of pilgrims coming from many northern cities but also in maintaining the price-line of essential commodities. I request that the hon. Minister should do the needful in this matter.

In Mardas Madurai and Rameswaram, in order to facilitate the passengers coming from all over the country announcements in Hindi are made frequently in these Railway stations about the movement of trains. But I am sorry to say that there is no reciprocity in North Indian pilgrim centres like Patna, Mughalsrai, Banaras and Allahabad to help the pilgrims from southern parts. In these Railway Stations all announcements about movement of trains are made in Hindi only. The pilgrims from southern parts of the country are greatly handicapped. If you don't want them to visit these places, like the Health Officers who make announcements appealing to the people not to visit places afflicted by communicable diseases like Cholera etc. Let the Railways announce loudly that the South Indians need not visit these places of pilgrimage in North. If you do not want to do that, why should you not arrange for announcements to be made in four South Indian Languages in these pilgrim centres? I appeal to the hon. Minister to look into this and do the needful.

I came across recently a directive from the Railway Board stating that those employees who use to the maximum extent Hindi in their day-to-day

official work be awarded Rs. 3,000, 2,000, 1,000 etc. and also that their wards would be given educational allowance of Rs. 100 a month. If this is not direct imposition of Hindi on non-Hindi speaking people, what else is it? In course of time, the job opportunities for non-Hindi speaking people would also dwindle. I am afraid that this would create a serious imbalance in the country, which would become difficult for the Government to set right.

Many hon. Members demanded Railways in their areas. I would like to ask: divide the country into two—north and south. Find out the length of broad-gauge track in North and South, the number of trains that are run in the North and South, the extent of double lines in North and South, the electrification of track in North and South. South does not mean Tamil Nadu alone; it means Tamil Nadu, Kerala, a Karnataka and Andhra Pradesh. You will find that the southern region is neglected completely. Surveys are conducted everywhere. Why should you not order a survey for the purpose of assessing Railway developmental work undertaken in North and South during the past 30 years? I have no hesitation in saying that you will find yourself that one side is waning and the other side is waxing. I demand that the future railway developmental work should be undertaken two to one ratio for South and North if you want to do justice for South.

In conclusion, I would say that all the languages of the country should be given due importance by the Railways, which itself is an instrument of national integration; Hindi should not be imposed. The constitutional guarantee for backward classes should be fulfilled, as is being done in regard to Scheduled castes and Scheduled Tribes, on the Railways by giving them reservation for jobs. The increase in the

suburban train fares must be withdrawn. The increase in the freight of foodgrains must be withdrawn.

With these words I conclude my speech.

श्री हीरा बाई (बांसवाड़ा) : सभापति जी, जो बजट हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। परन्तु साथ-साथ मैं यह निवेदन करता हूँ कि हमारी रेलवे में बम्बई से दिल्ली के लिए जो बड़ी लाइन है, उस में नागदा से लेकर, बड़ोदा तक छोटे स्टेशनों के लिए सिवाय एक गाड़ी के जो बम्बई से देहरादून जाती है, दूसरी गाड़ी नहीं है। लोग डिब्बों के ऊपर चढ़ कर यात्रा करते हैं, जिस से कई जगहों पर उनके गिर जाने से मृत्यु हुई है। उस लाइन पर दो-तीन सुपरफास्ट गाड़ियाँ हैं, लेकिन ग्राम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए कोई गाड़ी नहीं है। मेरा सुझाव है कि उस लाइन पर देहरादून वाली गाड़ी के मुकाबले की एक और गाड़ी चलाई जाये, तब ही वहाँ के लोगों की समस्या हल हो सकती है।

इसी के साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि वहाँ पर एक उदयगढ़ स्टेशन है, जहाँ डबल-लाइन है। मैंने कई वक्ता मंत्री महोदय से प्रार्थना की है कि वहाँ एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बीच में कई बार दो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, माल गाड़ी खड़ी होती है, बैगज खड़े होते हैं। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने लिए बहुत कठिनाई होती है। आप वतना खर्च करते हैं लेकिन वहाँ के लिए आपके पास पैसा नहीं है, इसका क्या मतलब है? बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लिए आप धन की व्यवस्था करने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन प्राद्विवासी लोगों को वाली नारों के बल पर आप जिन्दा रखना चाहते हैं, यह चीख चलने वाली नहीं है। वे नारे तीस साल तक काबिज लगाती रही हैं और लोगों को धोखा देती रही हैं, मुर्ख बनती रही हैं। आप भी उसी मार्ग को पकड़ेंगे तो आपकी जनता ठीकर मार देगी। आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिये। वहाँ पर बराबर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और लोग मरते रहते हैं, ट्रेन के नीचे से होकर एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जब वे जाते हैं तो टकरा कर मर जाते हैं। इसके बारे में कई बार किसानों की वा चुकी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकार कहती है कि पैदल बिज बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है लेकिन कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में खंवर ग्राउण्ड लाइन बिजाने के लिए आपके पास पैसा है। चूंकि वह प्राद्विवासी एरिया है इस बास्ते आप वहाँ धन नहीं सपाना चाहते हैं। लोक-कट कर मरते हैं लेकिन आप धन की कमी बताते नहीं सकते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि आप गहरी विकास ही करना चाहते हैं और बेहोती विकास का नारा आपका बोधा नारा है। अगर आप चाहते हैं कि देश का भला हो तो उस तरफ

आपको ध्यान देना होगा, प्राद्विवासी इलाकों की तरफ आपकी ध्यान देना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देश आपकी भी टुकरा देगा।

रतनाम से बांसवाड़ा बंगलपुर के लिए जब भी एस० के० डे मंत्री हुआ करते हैं उन्होंने प्राश्वासन दिया था कि एक लाइन बिछायेंगे। उसका सबे भी दो तीन बार हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्राश्वासन दिया, श्री गुलजारी लाल नन्दा आए तो उन्होंने दिया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। चुनाव के भीके पर प्रापेगण्डा करने के लिए, लोगों को मुर्ख बना कर चुनाव में वोट लेने के लिए इस प्रकार के प्राश्वासन दिए गए और यही तरीका तीस साल तक चलता रहा है और आपने भी यही तरीका अपनाया तो यह आपके हित में नहीं होगा। उस तरह से हमको नहीं चलना चाहिये। मैंने मंत्री महोदय से पूछा कि वहाँ दो तीन बार सबे हो चुका है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। मैंने इसका उत्तर यह दिया गया कि जब धन की उपलब्धि होगी तब उस पर विचार किया जाएगा। धन क्या भगवान ला कर आपके खजाने में डालेगा? धन की व्यवस्था करना राज करने वालों की जिम्मेदारी होती है। दूसरी जगह आप डबल लाइन कर रहे हैं, और तरीकों से उनका विकास कर रहे हैं लेकिन जब प्राद्विवासी इलाकों का विकास करने की बात होती है तो धन की कमी बता दी जाती है। वहाँ पर मार्ग है, खदानें हैं, उद्योग भी हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डैम का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वहाँ रेलवे लाइन नहीं बाली जाती है। तब तक वहाँ उद्योगपति उद्योग स्थापित नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने उद्योग शुरू किए भी हैं, बिजनेस बना भी है, उनके वहाँ भी उत्पादन कुछ नहीं हो रहा है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि उनको रा मेट्रियल जब सी सी दो दो सी किस्कीमीटर दूर से लाना पड़ता है तो उनके लिये अपने उद्योगों को चलाना सम्भव नहीं रह जाता है। इस सब की और आपका ध्यान जाना चाहिये। आपकी कम्पनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क रह तो प्राद्विवासी और हरिजन कल्याण और उत्थान का जो आप नारा लगाते हैं उसको लगाना आप बन्व कर दें और यह कह दें कि वही जिन्दा रहें जो जिन्दा रहने की स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं, जिन्दा रहने की ताकत रखते हैं और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पिछमनों की तरफ से आप हमें अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर न करें, प्राद्विवासी, हरिजन, प्राद्विवासी हरिजन का नारा वे कर वोट लेने की जातिर जो बोंडा प्यार आप हमारे प्रति दिखाते हैं और सहानुभूति हमारे प्रति प्रदर्शित करते हैं उससे काम नहीं चलेगा अगर बाध में सारी बातों को आप भूल जाएँगे। बड़े शहरों का विकास आप आज भी करते जा रहे हैं। ईश्वर साहब और मैं दोनों सोशलस्ट पार्टी में हैं। यह सब मंत्री हुआ करते थे। लेकिन मैं देखता हूँ कि उनका भी विनाश आज बड़े लोगों की सरकार ही जा रहा है। जो बड़े बड़े प्राद्विवासी हैं वे भी बड़े

बड़े शहरों से ही आते हैं। वे जब योजना बनाएंगे तो ऐसी बनायेंगे कि जो व्यय है वह बड़े शहरों पर ही हो। इस वास्ते संविधानों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। वे अगर यह कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे हैं—और उनकी लाजबंदी है तो मैं समझता हूँ कि यह उनकी बेइज्जती है। इस तरह की योजनाओं को पिछला मासन तीस साल तक चलाता आया है और आप भी इस तरह की योजनायें ही चलाते रहेंगे तो प्राविवासीयों का और हरिजनों का, उनके इलाकों का कभी विकास होने वाला नहीं है, उनका कभी उत्थान होने वाला नहीं है। हमारे राज्य मंत्री को विकास की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। प्राविवासीयों को केवल बूझ करने के लिए उनको कोई न कोई प्रलोभन दिया जाता है ताकि वह हमारे साथ चिपके रहें। विकास का काम केवल बड़ी जाति के लोगों को, बड़े घराने के लोगों का ही है। इस प्रवृत्ति को हमको बदलना होगा। अन्यथा मना कर बीजिए कि अपना विकास हम खुद करें ताकि हम आपके पीछे न पीड़ित रहें। आप इस बात को भूल जायें कि गलत प्रलोभन दे कर हरिजन प्राविवासीयों की आवाज दबी रहेगी। उनकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। आज सबसे ज्यादा गरीबी और बेकारी उनमें है और 80 प्रतिशत उनकी तादाद भी है। आज हर गाँवों में कोई न कोई सालबंदी कर अपने साथ मिलाए हुए हैं और उनका बिखराव कर रहा है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर यह बिखराव समाप्त हो कर हम एक ही आँख उस दिन आपका क्या हाल होगा इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिये। हमारा सामान्य विकास करना है तो प्राविवासी इलाके में और पिछड़े एरिया में प्रायरेटी के हिसाब से विकास करो। इसलिए बांसवाड़ा में रेल ले जाने के लिए धन की कमी बता कर उसको न टालो। इस साइन का सबेरे भी दो, तीन बार हो चुका है, ऐस्टीमेट बन चुका है, और रतलाम से मलाना—बांसवाड़ा बाया दूधपुर या हिम्मतनगर और मोदरा को मिला बीजिए, रेल लाइन बना कर। अभी इन क्षेत्र का यह हाल है कि 200 किलोमीटर की दूरी तक कोई आवागमन का साधन नहीं है। आपने रोड आने जाने वाली का सीजन टिकट बढ़ा दिया है उससे जो आपके आमदनी होगी उससे पिछड़े क्षेत्रों का भी कल्याण कीजिए। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में इंदौर धार और बारिया पिछड़े इलाके हैं उसी तरह से राजस्थान में सीपीड, बांसवाड़ा और दूधपुर का भी इलाका पिछड़ा हुआ है और वहाँ रेल लाइन बिछाना बहुत आवश्यक है।

एक गाड़ी अहमदाबाद से दूधपुर—उदयपुर हो कर दिल्ली तक चल रही है जो कि मीटर गेज है। उसको शीड गेज में किया जाय। पहले इस गाड़ी में दूधपुर से एक बोगी लगती थी जो अजमेर जयपुर होते हुए दिल्ली जाती थी। लेकिन अब वह बोगी लगना बन्द हो गया है, उसको फिर से कल्याण जाय। दूधपुर जिला है और अधिकतर प्राविवासी लोग हैं। अब अगर उनकी रिजर्वेशन कमान है तो कहाँ जायें? उदयपुर जायेंगे या अहमदाबाद जायेंगे इस काम के लिए? अगर

रिजर्वेशन कराने के लिए किसी को इतनी दूर जाना हो तो वैसे ही वह पैदल चला आया, उसको रेल से जाने की क्या जरूरत है। इसलिए हर डिस्टिक स्तर पर आप रिजर्वेशन का कोटा कायम करें और रिजर्वेशन के लिए बुकिंग कायम करें। तभी आकर लोगों को सुविधा मिल सकती है, वरना बाली नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे दूधपुर से दिल्ली के लिए जो स्पेशल बोगी लगाई जा रही थी, वह वापिस लाकर चालू करें, ऐसी मैं रेल मंत्री से मांग करता हूँ। फिर बाद में मैं यह भी भर्ष कर रहा हूँ कि हमारी भादों बहुत बुरी है, या तो हम भूखा मरना संजूर कर लेते हैं, लेकिन चमचागीरी संजूर नहीं करते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि जनता के हित को देखते हुए प्राविवासी एरिये के विकास के लिए आप कुछ कार्य अवश्य करें।

SHRI GEORGE MATHEW (Muvattupuzha): Mr. Chairman, Sir, at the outset I would like to compliment the Railway Minister for his past performance and I also hope that his future performance will be as good as it was in the past. 1977-78 and 1978-79 budgets were surplus budgets with no additional burden on the railway users. But 1979-80 budget cannot be considered as such because there is an additional levy of about Rs. 178 crores to obtain a surplus of about Rs. 88.49 crores. The Railway Minister really tried hard to impress on the Members that he had no choice but to enforce these new taxes on the railway users. I am not going into the merits or demerits of the case, but I must thank the Minister for not increasing the fares of long distance passenger trains.

Another thing I want to comment on is regarding the increase in facilities for Second Class passengers. It is appreciable that the amenities have increased and the fares have not gone up. The idea of classless trains is also commendable. What is really happening is that the amenities for the First Class passengers are being extended to the Second Class passengers on long distance trains. This is really a progressive step and of course, the increase from 13 bogies to 21 bogies and the double-decker trains is also commendable. What the Minister should do is to ask the Railway people

to introduce these new systems in all those areas where the traffic is very heavy.

Another thing I want to stress is regarding the running of trains on time. It is really a pity that most trains are not running on time at present.

Another matter of importance is that the expansion of Railways is not taking place on the desired level. There is a lot of hue and cry for new railway lines and also for conversion of railway lines from metre gauge to broad gauge and so on. It is understandable that each State will fight for its own railway lines because it is only through railway lines the industrialisation can be achieved. What I want to say is that those States where road transport will be cheaper than the railway transportation, they should be told to develop their own transportation system and the other States where road transport is costlier due to the difficult terrain, and due to monsoon the maintenance is very costly, and speedy traffic is impossible due to winding roads, should be given preference when actual new railway lines are given.

Regarding electrification of railway lines, those States which have surplus electricity should be given priority.

I am sorry to note that all the above aspects have not been taken into account when presenting the railway budget. Of course, I am not referring to the Alleppy-Ernakulam railway line which is a long pending one. My only doubt is that when the Minister said that the Alleppy-Ernakulam railway line is going to come into being, there was a rider on it. The rider was that the National Transport Policy Committee should decide whether this is feasible or not. I read in the newspapers that on 16th April 1979, the construction of this new railway line is going to be inaugurated. I hope the National Transport Policy Committee will not make this railway line a ghost one because after the new railway line work is declared open, if the National

Transport Policy Committee says that the railway line is not feasible, then what will happen? It will be a ghost railway line. I want the Minister to take a bold step and declare that whatever is the decision of the National Transport Policy Committee, this line will go ahead. Of course, after completing the line up to Alleppy, this line will have to be connected to Kayamkulam on the old railway network, just to complete the network. Otherwise, there will not be any purpose served behind this connecting line.

I am very happy about the policy change in the railways from industry-oriented lines to agriculture-oriented lines. In my State of Kerala there are lots of industry-oriented as well as agriculture-oriented areas. In my constituency especially, there is hardly an inch of railway track. I have been asking the Minister for the last two years for a new railway line, especially the Cochin-Madras railway line. There has not even been a survey, and he has simply said that it is not possible because it has to pass through the Western Ghats. I do not know how he came to this conclusion. Actually, only a small distance of the line has to pass through the Western Ghats. There are several other possibilities of developing this area. I have got a few proposals regarding this. Before coming to a conclusion, I would like the Railway Ministry to make detailed surveys. The State Government is also willing to support them. They will also propose that the following lines should be surveyed:

(1) Angamaley, Perumbavoor,
Muvattupuzha, Kothamangalam,
Adimali line.

(2) Muvattupuzha, Koothattukulam, Uzhavoor, Marangattupally, Palai, Erattupetta, Kanjirappally, Mundakayam, Peruvanthanam line, to be connected to Madurai at a later stage.

(3) Muvattupuzha, Thodupuzha, Muttom, Moolamattom line.

(4) Tellicherry—Mysore line.

The first three proposals are interconnected and they are absolutely essential for the transport needs of Kerala. Kerala is like a suburb of a huge city. There is really the problem of a traffic bottleneck in the whole of Kerala. It is so congested. You can see that in many parts of Kerala there is bumper to bumper traffic. How to overcome this problem? We have to have speedy traffic for that. Due to monsoon, winding roads and because of Kerala's terrain, it is not possible to have more roads. It is only through the development of railway lines that we can have speedy traffic there. We have been clamouring for the realignment of National Highway No. 47 from Angamally to pass through Muvattupuzha, Kottayam Kottarakara and Trivandrum, but even this has not been accepted by the Transport Minister. So, the only solution is to have new railway lines in this area. There is also another line for which survey has been completed, and that is the Kottipuram-Guruvayoor line. The Minister should take immediate steps to see that work on this line is started immediately.

As regards the new railway division at Trivandrum, I think the railways are going against the desire of the Kerala Government. There may be some sectarian feelings that if this new division, comes up, the Olavakot division may go away from Kerala. I think the Minister should give an assurance that the Olavakot division will not be abolished and will be maintained. The new division at Trivandrum should be set up immediately. There should be no dilly-dallying by saying that there is opposition; that unless all the opposition is cleared, this new division will not come. The Minister must see that the proposal for a new division is implemented immediately.

There is a proposal for a new railway workshop at Olavakot. This should be taken up immediately so that speedy repairs can be undertaken there.

As regards the new 21-bogies trains, the best place to try them out is Kerala because of the heavy traffic. The 'Venad Express' between Ernakulam and Trivandrum should be converted into 21-bogies, double-decker compartments and it should be completely electrified because we have surplus of electricity. In the 'K.K. Express' there are two classes. It should be made into a classless train. It should be completely air-conditioned, and the number of bogies should be increased from 13 to 21.

If possible, it should also be made a double decker with two engines. Only then, the position will improve.

Since last year we have been asking for a direct train from Trivandrum to Calcutta. So far this has not been accepted. I do not know why. There is a lot of rush from Kerala to Calcutta. Passengers find it difficult after reaching Madras to get a connecting train to Calcutta. So, a new train should be introduced from Trivandrum to Calcutta.

Regarding conversion of metre gauge to Broad gauge, after the conversion of the metre gauge to broad gauge of the Ernakulam-Trivandrum line, the revenue of the Railways has gone up. This is how the revenues of the Railways could be increased. All the lines in Kerala should be immediately converted from metre gauge to broad gauge. Regarding the supply of coal wagons, I would like to say that we are really having a shortage of coal wagons with south. I hope the Minister will look into this also.

Lastly I come to a very important thing viz., bonus to railwaymen. I think it is the policy of the Government that bonus is a deferred wage and that every worker is entitled to 8 1/3 per cent bonus. If the Government really believes what it preaches.

they should declare that the railway-men, who are working in the biggest undertaking in the country, will come under the purview of the Bonus Act.

श्री धर्मिका प्रसाद पांडेय (बांदा) : तथा पति महोदय, हमारे रेल मंत्री निश्चित ही बधाई के पात्र हैं जो लगातार तीसरी मर्त्या लाभ का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस के पूर्व हमारी कनिंसी सरकार लाभ का बजट नहीं प्रस्तुत कर रही थी। यह सन्देश का विषय हो जाता है कि जनता सरकार के भाते ही लगातार तीन साल से लाभ हीनाम रेलवे में हो रहा है, तकनीकी उन्नति बढ़ रही है जिस से केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशी सरकारें भी लाभान्वित हो रही हैं। यह सम्पुर्ण में एक सराहनीय काम है। रेलवे प्राप्ति निर्भरता की धोर बढ़ रही है। 6 गुना यात्रियों और 7 गुना मान के रूप में रेलवे की जो प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है वह हमारी मौजूदा जनता सरकार की कार्यकुशलता की धोर इंगित करता है कि किस ङग से जनता सरकार कार्य कर रही है।

जहां रेलवे में सरकार लाभ की धोर बढ़ रही है धोर यह दावा भी किया जाता है बहो जैसा कि अभी हमारे एक बन्धु कह रहे थे यह भी कहा गया कि हम पिछड़े क्षेत्रों की धोर ध्यान देंगे, पिछड़े, हरिजन धोर गिरिजन जो हैं उनकी धोर ध्यान देंगे लेकिन जब हम वास्तविकता में जाते हैं तो हमें उस में निराशा ही नजर आती है। जो बजट पेश हुआ है, जो सुविधाएं दी गई हैं, सेकंड क्लास के लोगों को वह सराहनीय हैं। लेकिन जो रेलों का विकास होना है, जो नई लाइनें खोलनी हैं उस में पिछड़े क्षेत्रों की अवहेलना की गई है। बाहे वह रेलवे लाइन की प्राप्ति बकाने की बात हो, नयी रेलवे लाइन खालनी हो, विद्युतीकरण करना हो या डबल लाइन करना हो या धोर कोई नया काम करना हो इस विषय में पिछड़े क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं मिला है। यह सब से बड़ी कमी हमारे रेल बजट में है जिसे रेल मंत्री को मानना पड़ेगा। यहाँ हम दावा करते हैं कि हमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखना है, वह लाभ में रहे या भाटे में लेकिन जब हम उनकी वास्तविकता को देखते हैं तो यह देखते हैं कि सेकंड क्लास की जो प्राप्ति लाइनें हैं उनसे 38.8 परसेंट का लाभ होता है धोर जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं सेकंड क्लास की उन से 42.2 प्रतिशत लाभ होता है। लेकिन जब बजट का एकीकरण प्रत्येक साल का करते हैं तो एक्सप्रेस गाड़ियों को ध्यान में रख कर करते हैं क्योंकि उन से उन्हें लाभ ज्यादा होता है धोर प्राप्ति लाइनों से लाभ कम होता है इसलिए जो ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पिछड़े प्राप्ति उन प्राप्ति लाइनों में जाता करते हैं धोर पिछड़े लोगों को जिस से सुविधा मिलनी है, उस की दृष्ट में अवहेलना की जाती है। यह उनके धोर बजट की बात है। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस धोर ध्यान में धोर जो दावा किया है या जो जनता के बीच में वह कहते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों की धोर हम ध्यान देंगे उस की बह दूर करें।

इसके अलावा मैं मंत्री की जो दूसरा सुझाव यह देना चाहूँगा कि चेकिंग स्टॉफ को कि एक ही जगह पर एकमुल्लेटेड है जिसके कारण बेटिकट यात्रियों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, उस स्टॉफ को प्राप्ति डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसे या तो प्राप्ति जबलपुर में, झांसी में, इलाहाबाद में या दूसरी जगह विकेंद्रित कर दीजिए। इससे चेकिंग में भी सहयोग मिलेगा धोर साथ ही साथ बेटिकट यात्रियों पर धंक्रुल लग सकेगा।

एक सबसे बड़ी बात हमें देखने को यह मिलती है कि रेलवे के क्वार्टर्स तो बहुत हैं रेलवे कर्मचारियों के लिए लेकिन उसके बावजूद छोटे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर की कमी है। जहाँ प्राप्ति लाभ का बजट पेश करते हैं वहाँ कार्यरत कर्मचारियों को सुविधाएं देना भी बहुत प्राप्ति है। जिन कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स नहीं हैं उनके लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था की जानी चाहिये। प्राप्ति लाभ का बजट पेश करके सदन में बाहवाही जरूर खूट लेंगे लेकिन जो कर्मचारी हैं जो दिनरात सेवा करते हैं, उनके बच्चों के रहने के लिए जगह नहीं है उनकी धोर भी प्राप्ति ध्यान जाना चाहिये। उनके लिए धगर रहने की सुविधा नहीं है तो उनके लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसी प्रकार से खासकर कासिन्ध पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके सम्बन्ध में कानूनी मुद्दा लेना कि स्टेट गवर्नमेन्ट्स करेंगी, इसको छोड़ कर प्राप्ति स्वयं इनीशिएटिव लेना होगा। जो धंक्ररिजिज या धोर - बिज बनाने की बात है उसके लिए प्राप्ति स्वयं इनीशिएटिव लेकर तत्परता से काम करना पड़ेगा। जहाँ तक 50 परसेंट देने की बात है, यदि प्राप्ति इनीशिएटिव लेंगे तो प्रवेश सरकारों की प्राप्ति प्राप्ति की। यदि प्राप्ति प्रवेश सरकारों पर ही छोड़ देंगे कि बड़ी इनीशिएटिव से तभी प्राप्ति प्राप्ति बहो तो मैं समझता हूँ यह सम्भव नहीं हो पायेगा। रेलवे कासिन्ध पर जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनकी रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा धंक्ररिजिज या धोर बिज बनाने की धोर प्राप्ति ध्यान देना चाहिये। झांसी-मानिकपुर लाइन पर हमारे बहो बांदा में तबान सरकार की कार्यलय, धंक्रताल धोर विद्यालय एक धोर हैं धोर दूसरी धोर पूरा बाहर है, बीच में रेलवे लाइन है वहाँ पर न तो कोई धंक्ररिजिज है धोर न कोई धोर - बिज है। तीन तीन धंक्रे तक रेलवे का फाटक बन्द रहता है जिससे जनता को बड़ी परेशानी होती है, वहाँ पर बाई सै-तीन सै हद साल एक्सीडेंट्स होते हैं। मानवता की दृष्टि से भी वहाँ पर धोर - बिज या धंक्ररिजिज की धंक्र बनाना जाना प्राप्ति है। कहीं में अभी तीन महीने पहले ट्रेक्टर जा कर रेल से टकरा गया, फाटक भी बन्द नहीं था। इस लिए जब तक प्राप्ति इस धोर ध्यान नहीं देंगे, दुर्घटनाओं से नहीं बचा जा सकेगा। मेरा प्राप्ति जो सामयिक सुझाव है कि इस सम्बन्ध में प्राप्ति स्वयं इनीशिएटिव से धोर स्टेट्स को मजबूर करें कि वे 50 प्रतिशत प्राप्ति दें। यदि कानूनों में कोई बाधा हो, तो उसमें भी परिवर्तन करें, तभी इस दुर्घटनाओं को रोक किया जा सकता है।

रेलवे में जो चोरियां बढ़ रही हैं उस धोर की ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने कमेटी में भी सुझाव दिया था, लेकिन उस पर, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने कहा था कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो क्षेत्र में तैनात रहते हैं, वे मैन्ड से मिल कर चोरियां कराते हैं, वे चाहे धोर 0 पी 0 एफ 0 के लोग हों या रेलवे स्टाफ के हों, उन के मिले रहने से ही चोरियां होती हैं। उन को दूर से दूर ट्रान्सफर करने की आवश्यकता है, तभी चोरियों को रोक करना सम्भव हो सकेगा :

जहां तक बेमेज की बात है, पिछले वर्ष 1976-77 में 13.56 करोड़ की क्षतिपूर्ति रेलवे ने की। 1977-78 में 14.24 करोड़ की क्षतिपूर्ति की। एक दम 68 लाख रुपये की वृद्धि हो गई। यह बात मोचनीय है। यह धाप के स्टाफ की कमजोरी के कारण होना है, माघ हो क्रसेज को निपटाने वाली की कमजोरी के कारण भी होता है। यदि 14 करोड़ रुपये क्रसेज को निपटाने में, क्षतिपूर्ति में ही चला जाय, तो यह धाप की प्रभुता का द्योतक है। यदि इस को ही धाप रोक लें तो बहुतों का माघ बदल सकता है। सबबेन एरियाज में जो धाप ने सीजनल टिकट के किराये में वृद्धि की है, उससे बचा जा सकता है। मेरा धनुरोध है कि सीजनल टिकटों का किराया बढ़ाने के बजाय इस प्रकार से रेलवे को जो क्षति हो रही है, उस को रोकने का प्रयास धाप को करना चाहिये।

धब में बुलेलखण्ड क्षेत्र की धोर धाप का ध्यान धाकित करना चाहता हूँ, जहां 80 वर्ष पूर्व एक छोटी लाइन चलाई गई थी, वही धाज तक चली आ रही है। जो स्टेशन बने थे, वही धाज भी चले आ रहे हैं, उन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पैसेन्जर्स के लिए जो ह्यमन फैसिलिटीज होनी चाहिये, वे भी धाज वहां उपलब्ध नहीं हैं। पिछकट बैसा पवित्र स्थल है, वहां लाखों यात्री हर साल जाते हैं, लेकिन उस स्टेशन पर न फास्ट क्लास के लिए धोर न सैक्रेड क्लास के लिए कोई मुसाफिरखाना है। हमारे यहां धतरा उत्तर प्रदेस में धान धोर पावल की सब से बड़ी मंडी है, वहां पर स्टेशन के नाम पर एक पुराना सेड बना हुआ है, वहीं से सारा काम धापरेंट हो रहा है। मेरा धाप से धाग्रह है कि धाप इस धोर ध्यान दें, 80 साल पुराने जो स्टेशन बने हुए हैं उन में ज्यादा साधन जुटाये जायें। वहां यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उनकी सुविधाओं की धोर ध्यान दें।

जहां तक स्टाफ की गल्ली से जो बुर्बटनायें होती हैं—मैं धपने क्षेत्र को देखता हूँ तो पूरे सेफ्टल रेलवे में छोटे छोटे स्टेशनों पर एक ही स्टेशन मास्टर होता है, वही एग्जिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, वही बुकिंग क्लर्क है, वही सब काम करता है। गाड़ी के जाने से पहले वही टिकट बांटता है, गाड़ी जाने पर वही टिकट कलैक्ट करता है धोर जिस समय गाड़ी जाती है ठी वही गाड़ी को लाइन-फिलवर देता है। यदि धाप चाहते हैं कि स्टाफ की गल्ली से कोई बुर्बटना न हो, तो धाप थोड़ा सोचिये—एक धाकसी की फिलती कार्यकुशलता हो सकती है, एक ही साथ, एक ही समय उडे सब काम करने पड़ते हैं। मेरा

धनुरोध है कि धाप हर स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क धोर टिकट कलैक्टर धलग-धलग दें ताकि उस पर बर्बेन कम हो धोर वह कुशलता पूर्वक यात्रियों को चला सके।

इस समय जो सब से गम्भीर समस्या है, वह मालगाड़ी के डिब्बों की कमी है। यू 0 पी 0 में इस समय यह कानून चल रहा है कि कोई भी व्यापारी 500 किबटल से ज्यादा का स्टाक नहीं रख सकता। दूसरी तरफ किसान अपनी उपज ले कर बाजार में धाता है, जब वे व्यापारी देखते हैं कि बैगन्ज नहीं मिल रही है, माल ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं धोर साथ ही 500 किबटल से ज्यादा माल रखने का कानूनी शिकंजा है तो वे किसान से उस की उपज नहीं खरीदते हैं, जिस से किसान बहुत परेशान होता है धोर उस को अपनी उपज कम दामों में दूसरों को बेचनी पड़ती है। इस लिए मैं रेल मंत्री जी से धाग्रह करूंगा कि वे इस धोर विशेष ध्यान दें। इस समय किसान की पैदावार दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है, लेकिन जब माल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है तो व्यापारी किसान को परेशान करता है, बुकि वह स्वयं भी कानून के बन्धन में रहता है। हमारे यहां धाज दो महीने से व्यापारियों को मालगाड़ी के डिब्बे नहीं मिले हैं—मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय तुरन्त बुकिंग बोल कर मालगाड़ी के डिब्बे उपलब्ध करायें...

समापति महोदय : धाप धभी कुछ धोर समय लेना चाहेंगे ?

श्री धन्निबा प्रसाद पांडेय : मैं थोड़ा समय धोर लेना चाहता हूँ, क्योंकि कल में यहां नहीं रहूंगा।

समापति महोदय : धाप फौरन समाप्त कीजिए।

श्री धन्निबा प्रसाद पांडेय : धन्तिन बात मुझे वही कहनी है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बहुत परेशान किया जाता है। 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको स्थायी नौकरी नहीं मिल पाती है, जब तक पैसा न दिया जाय। इस की धोर भी ध्यान दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को उन के बजट के लिए धाग्रह देता हूँ।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE THIRTY-FIRST REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Sir, I beg to present the Thirty-first Report of the Business Advisory Committee.

18.01 hrs.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11-00 a.m. tomorrow.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 8, 1979/Phalguna 17, 1900 (Saka).